

हमारे कुछ अनुपम ग्रन्थ

आर्थिक विकास का सापेक्ष चित्रण	जॉन केनेथ गैलब्रेथ	2 00
समृद्ध समाज	जॉन केनेथ गैलब्रेथ	4 00
समय की प्रगति	कैथराइन वी० शर्पैन	2 00
आधुनिक व्यावसायिक संगठन	प्रो० जयप्रकाश रस्तोगी	2 00
आर्थिक विकास एक प्रारम्भिक विवेचन	रावर्ट जे० एलेक्जेंडर	5 50
अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था	गेर्हार्ड कोम व थियोडोर गाइगर	6 00
सुगम सामान्य अर्थ-शास्त्र (प्रश्नोत्तर)	प्रो० वी० एम० भाटिया	6 00
भारत के प्रमुख उद्योग	वेदप्रकाश सिंह	7 00
दस महान अर्थ-शास्त्री	जोसेफ ए० शुम्पीटर	6 50
कार्यालय की कार्य विधि	रामचन्द्रसिंह सागर	6 00
आर्थिक प्रगति की कुजी	डी० जी० वसूलस	1 00
भारत और पश्चिम	बारबारा वार्ड	4 50
मच्चे दोस्त और बहादुर दुश्मन	रावर्ट एफ० कैनेडी	4 50
अमरीकी राजनैतिक प्रक्रिया	लेवि राश	7 50
अमरीका की विदेश नीति	आर्नेस्ट आर० मे	7 50
राजनीति-शास्त्र के मूल सिद्धान्त	योगेन्द्र मल्लिक	12 00
भारतीय राजनीति और शासन	के० आर० वम्बवाल	10 00
ग्रेट ब्रिटेन का संविधान	योगेन्द्र मल्लिक	4 00
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान	योगेन्द्र मल्लिक	4 00
संयुक्त राज्य परिचय	कालीदास कपूर	3 00
नयी राह	चेस्टर बीट्स	6 00
संयुक्त राष्ट्र प्रवेशिका	एडना एप्स्टीन	2 75
अमेरिकी सभ्यता	मैक्सलनर	10 00
टॉमस जैफर्सन	विन्सेण्ट शिएन	3 00
हमारा नया देश	एँजेलो एम० पेलेग्रिनी	2 00
एक जीवन्त अधिकार-पत्र	विलियम ओ० डगलस	2 00
मेरा देश : मेरे देशवासी	परम पावन दलाई लामा	10 00

आत्माराम एण्ड सेंस, दिल्ली-6

गेरहार्ड कोम : थियोडोर गाइगर

अमेरिकी जनता

की

अर्थ-व्यवस्था

(सचित्र)

अनुवादक

कृष्ण चन्द्र

1965

आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली-6

AMRIKI JANTA KI ARTHA-VYAVASTHA

(Hindi Version of *The Economy of the American People*)

by

Gerhard Colm : Theodore Geiger

Translated by

Krishan Chander

Rs 5 00

~~Copyright ©-1958, 1961, National Planning Association.~~

प्रकाशक

रामलाल पुरी, सचालक

आत्माराम एण्ड सन

काश्मीरी गेट, दिल्ली-6

शाखाएँ

हौज खास नई दिल्ली

चौडा रास्ता, जयपुर

विश्वविद्यालय क्षेत्र, चण्डीगढ़

महा नगर, लखनऊ-6

रामकोट, हैदराबाद

मूल्य पाँच रुपये

प्रथम संस्करण

मुद्रक

युगान्तर प्रस,

मोरी गेट

दिल्ली-6

निवेदन

संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ आज संसार के दो नव से शक्तिशाली राष्ट्र हैं। दोनों की अर्थ-व्यवस्थाएँ परस्पर-विरोधी हैं। किन्तु अमेरिकी आर्थिक प्रणाली के आलोचक मार्क्सवादी भी यह स्वीकार करते हैं कि अमेरिका ही आज आर्थिक दृष्टि से सब से अधिक उन्नत राष्ट्र है और वे उसकी आर्थिक प्रणाली की कुछ विशेषताओं से सबक लेने का भी प्रयत्न करते हैं।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की सब से बड़ी विशेषता यह है वह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और आर्थिक उन्नति, दोनों का समन्वय करती है। सोवियत संघ ने भी निस्सन्देह आर्थिक क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में असाधारण उन्नति की है, लेकिन इसके लिए उसे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बलिदान के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है।

अर्थशास्त्रियों ने अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को प्रचलित पद्धति से किसी विशिष्ट वर्ग में रखने का प्रयत्न किया है, लेकिन वह पूर्णतः सगत नहीं है। उसे न सर्वथा पूंजीवादी प्रणाली कहा जा सकता है और न सर्वथा समाजवादी। इसीलिए प्रस्तुत पुस्तक के लेखकों ने उसे 'अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था' के नाम से अभिहित किया है।

अमेरिका की आर्थिक उन्नति का नव से बढ़ा कारण यह है कि वहाँ विभिन्न उपायों से उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। दूसरा कारण यह है कि कृषि और उद्योग, दोनों क्षेत्रों में प्रबन्ध-कीर्णन को बहुत अधिक महत्त्व दिया जाता है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की कुछ कमजोरियाँ भी हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा और तज्जनीकी प्रशिक्षण की ओर संयुक्त राज्य अमेरिका ने उतना ध्यान नहीं दिया, जितना सोवियत संघ ने दिया। अब अमेरिका

इस कमी को दूर करने के लिए प्रयत्न कर रहा है।

प्रस्तुत पुस्तक संयुक्त राज्य अमेरिका की नेशनल प्लैनिंग एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट है, जो अमेरिकी अर्थ व्यवस्था के उपर्युक्त गुण-दोष के अलावा उसके आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं को विशद रूप में प्रस्तुत करती है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को समझने के लिए इसकी उपयोगिता के कारण न केवल अमेरिका में इसके दो सस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, बल्कि स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन और जापानी भाषाओं में भी इसका अनुवाद हो चुका है।

हमें विश्वास है कि इसका यह हिन्दी अनुवाद भी हिन्दी भाषियों को अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था को समझने में सहायता देगा और पाठक भारत की वर्तमान मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के लिए उससे आवश्यक निष्कर्ष निकाल सकेंगे।

प्रकाशक

पृष्ठभूमि

संयुक्त राज्य की नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन (राष्ट्रीय आयोजन संघ) की यह रिपोर्ट उसके कर्मचारी मण्डल द्वारा तैयार की गई अन्य रिपोर्टों से बिल्कुल भिन्न प्रयोजन की पूर्ति करती है। ये रिपोर्टें आम तौर पर नीति-सम्बन्धी वक्तव्यों के लिए तथ्यात्मक पृष्ठभूमि और विश्लेषण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से तैयार की जाती हैं, ताकि हमारी समितियों में कृषि, व्यवसाय, श्रम और विभिन्न पेशों के प्रतिनिधि उनका अध्ययन कर उन वक्तव्यों पर सहमत हो सकें। परन्तु 'अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था' नामक यह प्रकाशन केवल जानकारी देने के लिए ही प्रकाशित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अमेरिकी प्रणाली के स्वरूप और भावी सम्भावनाओं का विश्लेषण कर यह बताना है कि कैसे हमारी निजी उद्यम वाली अर्थ-व्यवस्था उत्पादकता और रहन-सहन का इतना ऊँचा स्तर प्राप्त कर सकी है, क्योंकि कम्युनिस्टों और अन्य समाजवादी भविष्यवक्ताओं की विनाश की भविष्यवाणियों के बावजूद वह जीवित रह सकी है, और उसकी वास्तविक समस्याएँ और भावी सम्भावनाएँ क्या हैं।

हम नेशनल प्लैनिंग एसोसिएशन के सदस्य हमेशा यह अनुभव करते रहे हैं कि विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत संयुक्त राज्य की यात्रा करने वाले विदेशी नेताओं, टैकनीशियनों और छात्रों के दलों के साथ अपने निरन्तर सम्बन्धों के कारण हमें इस प्रकार का एक अध्ययन प्रस्तुत करना चाहिए। अन्य देशों से आने वाले इन लोगों ने हमसे अनेक बार यह अनुरोध किया है कि हम अमेरिकी अर्थ व्यवस्था की जानकारी देने वाली एक पुस्तक प्रकाशित करें जो आसानी से उपलब्ध हो सके। हमारे अनेक अमेरिकी मित्रों ने

भी हमसे कहा है कि क्योंकि नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन के सदस्यों में सभी वर्गों के प्रतिनिधि हैं, उसका अनुभव बहुत लम्बा है और वह एक निष्पक्ष और गर-राजनीतिक संस्था है, इसलिए हम इस प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत और प्रकाशित करने के लिए सबसे अधिक अच्छी स्थिति में हैं।

इन कारणों से प्रेरित होकर नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन के ट्रस्टी-मण्डल ने यह रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया। मण्डल यह जानता था कि यह काम आसान नहीं है और अन्य संगठनों और व्यक्तियों ने भी अनेक बार ऐसी रिपोर्टें तैयार करने के प्रयत्न किये हैं। लेकिन साथ ही हमने यह भी अनुभव किया कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का अध्ययन अनेक भिन्न-भिन्न पहलुओं से किया जा सकता है और यह सम्भव है कि नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन जिस दृष्टिकोण से इसका अध्ययन करेगी, उससे दूसरे लोग अध्ययन न करें। इसके अलावा हमें इस तथ्य में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली कि हमारे कर्मचारी मण्डल में से कुछ लेखक भी हैं जो हमारी योजना के अनुसार रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं।

इन लेखकों में से एक श्री गेरहार्ड कोम नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन के मुख्य अर्थशास्त्री हैं और साथ ही वह वाशिंगटन, डी० सी० के जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्राध्यापकीय व्याख्याता भी हैं। नेशनल प्लैनिक एसोसियेशन के कर्मचारी मण्डल में शामिल होने से पूर्व और उसके बाद डा० कोम ने अनेक विदेशी अतिथियों के समूहों के सन्मुख भाषण दिये हैं और उन्हें अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के बुनियादी तथ्यों और समस्याओं की जानकारी दी है। यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किये हैं, उनसे उन प्रश्नों की विशेष रूप से जानकारी हो गई है जिनका उत्तर अवसर अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के विदेशी प्रेक्षक खोजना चाहते हैं।

दूसरे लेखक श्री थ्योडोर गाइगर नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन के

अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन विभाग के प्रमुख है। उन्होंने एक आर्थिक और सामाजिक इतिहासकार के रूप में शिक्षा प्राप्त की है और खास तौर से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक अर्थशास्त्री के रूप में अनुभव प्राप्त किया है। डा० गाइगर ने ऐतिहासिक और समाज-विज्ञान सम्बन्धी पहलुओं की दृष्टि से इस अध्ययन में विशेष योग दिया और अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के अन्तर्राष्ट्रीय पहलुओं को प्रस्तुत करने का मुख्य उत्तरदायित्व लिया।

नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन के सहकारी अर्थशास्त्री श्री मैनुएल हेल्ज़नर ने इन दोनों लेखकों को बहुत अच्छी सहायता दी। उन्होंने सांख्यिकी सम्बन्धी आंकड़ें देने के साथ-साथ अन्य अनेक रूपों में भी इस अध्ययन में सहायता दी।

नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन की संचालन समिति ने इस रिपोर्ट पर विचार-विनिमय किया और उसके बाद उसके प्रकाशन की अनुमति दी। श्रीमती टी० पार्कर ने इसकी पाटुलिपि को पठनीय रूप प्रदान किया, जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। हम उन अनेक अमेरिकी और विदेशी मित्रों के प्रति भी कृतज्ञ हैं, जिन्होंने प्रकाशन से पूर्व इस रिपोर्ट को पढ़ा और उस पर अपनी सम्मति दी।

एच० क्रिश्चियन सन

अध्यक्ष, नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन, ट्रस्टी मण्डल

प्रस्तावना

हाल के दशको में औद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) में जो भारी परिवर्तन हुए हैं, वे आज हर व्यक्ति को नजर आते हैं। आकाश में उड़ते जेट विमान, घरों में रखे टेलीविजन सेट, रसोई घरों में इस्तेमाल किए जाने वाले बिजली और इलेक्ट्रॉनिकी के उपकरण, कारखानों में प्रयुक्त स्वचालित नियन्त्रण यन्त्र और बिजलीघरों में परमाणु शक्ति पैदा करने वाले प्रतिक्रियावाहक यन्त्र (रिएक्टर)—ये सभी वस्तुएँ, बल्कि और भी-बहुत सी वस्तुएँ आज हर व्यक्ति देख सकता है।

लेकिन इस बात की लोगों को उतनी जानकारी नहीं है कि हमारी आर्थिक प्रणाली में भी भारी परिवर्तन होते रहे हैं। उन्नीसवीं शताब्दी की पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में से एक नई अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था धीरे-धीरे विकसित होती रही है। इस अर्थ-व्यवस्था की पुरानी पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था के साथ उतनी ही समानता है जितनी कि आज के जेट विमान की राइट बन्धुओं के प्रारम्भिक विमान के साथ। इसके बावजूद हमारी वर्तमान आर्थिक प्रणाली के सम्बन्ध में बहुत-सी चर्चा इस ढंग से की जाती है, मानो कोई परिवर्तन हुआ ही न हो। इसका कारण शायद यह है कि अधिकतर अमेरिकी लोग इन परिवर्तनों के मध्य में रहते और काम करते हुए इतने अधिक व्यस्त रहे हैं कि उन्होंने उनके महत्त्व पर या सभ्यता के विकास पर पड़ने वाले उनके महत्त्वपूर्ण प्रभाव पर विचार ही नहीं किया।

इस विवरण का प्रयोजन हमारी नई आर्थिक प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। हम यहाँ यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था किस ढंग से चलती है, उसकी कौन-सी बड़ी फलतें या कमज़ोरियाँ हैं, कौन-सी समस्याएँ अभी हल करनी हैं

सांस्थानिक रचनाएं कैंसी भी हो, क्योंकि इसका सम्बन्ध हर सामाजिक और आर्थिक प्रणाली को विशिष्ट क्षमताओं के साथ है।

किंतु यथा-सम्भव अधिकतम उत्पादन और उपभोग ही किसी आर्थिक प्रणाली का एकमात्र उद्देश्य नहीं होता। आर्थिक प्रणाली अपने आप में कुछ अन्य अधिक बुनियादी सामाजिक और वैयक्तिक मूल्यों की उपलब्धि का साधन है। अर्थ-व्यवस्था किसी ऐतिहासिक संस्कृति का अविच्छिन्न अंग होती है और उससे किन विशिष्ट मूल्यों की उपलब्धि होती है, यह उस संस्कृति पर ही निर्भर है। हर समाज के लोगों में अपने सामान्य उद्देश्यों के सम्बन्ध में तो अक्सर मोटे तौर पर एक आम मतव्य होता है, किन्तु आर्थिक साधनों के द्वारा सिद्ध किये जाने वाले विशिष्ट लक्ष्यों के सम्बन्ध में उनमें मतभेद रहते हैं—ये मतभेद उस समाज के अलग-अलग वर्गों के भिन्न-भिन्न हितों और परम्पराओं के कारण होते हैं।

जहाँ तक अमेरिका का सम्बन्ध है, अमेरिकी गणराज्य की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों में आर्थिक प्रणाली के उद्देश्यों के बारे में परस्पर-विरोधी विचारों को लेकर राष्ट्रीय नीति के सम्बन्ध में एक बड़ा विवाद चला। टॉमस जैफर्सन का मत था कि “जीवन, स्वतन्त्रता और सुख प्राप्ति का प्रयत्न” ही समाज के अन्तिम मूल्य हैं। उनका विश्वास था कि इन मूल्यों की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन स्वतन्त्र पारिवारिक फार्म और छोटे कारखाने हैं। उनके विरोधी अलेग्जेंडर हैमिल्टन की धारणा थी कि अमेरिका अपनी आबादी को बढ़ाकर उसकी शक्ति और दौलत से और अपने उद्योगों के विशाल विस्तार से ही एक महान् राष्ट्र बन सकता है। सौभाग्य से अमेरिकी लोगों ने कभी भी मजबूर होकर अपने आपको पूर्णतः किसी एक उद्देश्य के साथ नहीं बाँधा। पिछली डेढ़ शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने हैमिल्टन की कल्पना से भी कहीं अधिक राष्ट्रीय शक्ति और दौलत हासिल कर ली है और इसके लिए उसे जैफर्सन के व्यक्ति स्वतन्त्रता और उत्तरदायित्व के आदर्शों भी परित्याग नहीं करना पड़ा।

इन परस्पर-पूरक और साथ ही परस्पर-विरोधी आदर्शों की प्राप्ति के लिए चाहे कितनी ही लगन और व्यग्रता के साथ प्रयत्न किया गया हो, किन्तु उन्हें सामाजिक संस्थाओं के रूप में मूर्त रूप देते हुए बहुत कट्टरता और सैद्धान्तिकता से नहीं, बल्कि व्यावहारिकता और लचकीलेपन से काम लिया गया। राष्ट्र के इतिहास में सुधार की अनेक लहरें उठती रही हैं। किन्तु इन सबसे जैफर्सन और हैमिल्टन के उद्देश्यों में एक सामंजस्य कायम रहा, जो तत्कालीन सम्भावनाओं और सीमाओं का परिणाम था। अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में जैफर्सन के व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आदर्श के मूर्त रूप में अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था छोटे-छोटे फार्मों वाली कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था थी। किन्तु बीसवीं शताब्दी के मध्य में ऐसी स्थिति आ गई कि कोई इक्के-दुक्के आदमी ही ऐसे होंगे जो पुराने भूले-बिखरे दिनों की याद करते हों और फिर से कृषि-प्रधान समाज की स्थापना करना ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के उद्देश्य की प्राप्ति का साधन समझते हों।

आज भी जैफर्सन के स्वतन्त्रता और आत्म-निर्भरता के आदर्शों और हैमिल्टन के वैभव और शक्ति के आदर्शों की एक साथ प्राप्ति के लिए प्रयत्न जारी है, किन्तु आज उसके लिए सामाजिक सम्भावनाएँ और सीमाएँ बिल्कुल भिन्न हैं। आज आर्थिक उन्नति और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता सरकार के अथवा कुछ व्यक्तियों के हाथों में बड़े पैमाने पर केन्द्रित रहे। किन्तु साथ ही स्वतन्त्रता और व्यक्तिगत सत्ता की रक्षा के लिए यह भी जरूरी है कि निश्चय और कार्रवाइयाँ करने का काम प्रधानतः व्यक्तिगत रूप में लोगों के हाथ में रहे और उसका केन्द्रीकरण न हो। इसलिए आज यह आवश्यक है कि इन दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाय।

यदि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि का अर्थ समाज को मानवीय यन्त्रों का समाज बना देना हो, तो अमेरिकी लोग उसे अपना लक्ष्य स्वीकार

करने के लिए तैयार नहीं है और भविष्य में भी वे इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। यदि मानव-समाज केवल ऐसे नर-नारियों का ही समाज बन जाय जो महज मजीने हो, तो चाहे ये मानवीय मजीने कम्युनिस्ट देशों की भाँति सर्वशक्तिमान् राज्य (सरकार) के द्वारा संचालित हो और चाहे सर्वशक्तिमान् उद्योगपतियों द्वारा, जैसा कि उन्नीसवीं शताब्दी की बन्धनहीन स्वतन्त्रता वाली पूँजीवादी प्रणाली के आज भी कायम रहने पर होता, दोनों में कोई अन्तर नहीं होगा। अन्तिम विश्लेषण में हम इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि अमेरिका की वर्तमान पीढ़ी के नामने आज यह सवाल नहीं है कि वह कृषि-प्रधान अर्थ-व्यवस्था को चुने या उद्योग-प्रधान अर्थ-व्यवस्था को, अथवा समाजवाद को चुने या पूँजीवाद को। सवाल यह है कि क्या अमेरिकी समाज एक ओर आर्थिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में बड़े पैमाने के संगठन के लाभों का और दूसरी ओर व्यक्तिगत चयन की अधिकतम सम्भव प्राप्ति का परस्पर समन्वय कर सकता है ? अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की प्रवृत्तियों और भावी सम्भावनाओं पर पुनः दृष्टिपात करने का हमारा प्रयोजन इस निर्णायक प्रश्न का उत्तर खोजना ही है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पर 'समाजवाद बनाम पूँजीवाद' के दृष्टिकोण से बार-बार विचार और अध्ययन किये जाने का परिणाम यह हुआ है कि यह निर्णायक प्रश्न बहुत विकृत हो गया है। इन अध्ययनों और विचार-विनिमयों में दोनों पक्षों के लोग बहुत चरम-सीमा तक पहुँच जाते हैं। एक ओर, अमेरिका में और अमेरिका से बाहर भी, ऐसे लोग हैं जो अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की खूब तारीफ करते हैं किन्तु उनकी तारीफ इस गलत धारणा पर आधारित होती है कि वह पूर्ण स्वतन्त्र और बन्धनहीन व्यापार के विस्तृत आदर्श का मूर्त रूप है। उनका मत यह है कि जब हर व्यक्ति और संगठन को अपने-अपने आत्म-हितो के साधन की स्वतन्त्रता मिल जाती है तो अधिकतम लोगों के अधिकतम हित का शय स्वतः ही सुरक्षित हो जाता है। उनका ख्याल है कि अन्याय और

अपर्याप्तताएँ तभी पैदा होती हैं जब कि कोई दखलन्दाज सरकार समाज-व्यवस्था में हस्तक्षेप कर उसके स्वतन्त्र और निर्बाध कार्य में रुकावट डालती है और यदि सरकार ऐसा न करे और हर चीज को स्वतन्त्र छोड़ दे तो सब समस्याएँ स्वयं समाप्त हो जाएँ।

दूसरी ओर मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, पर वह अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का जो चित्रण करता है या उसके लिए जो नुरा पेश करता है वह उपर्युक्त विचारधारा से भी कम सही है। मार्क्सवादी सिद्धान्त इस बात पर बराबर जोर देता रहा है कि अमेरिकी 'पूँजीवाद' के परिणाम-स्वरूप 'ग्राम जनता' के वर्गों का निरन्तर बढ़ते जाना अनिवार्य है, क्योंकि धन-दीलत कुछ 'एकाधिकारवादी' पूँजीपतियों के हाथ में अधिकाधिक केन्द्रित होती जाती है। लेकिन समस्त प्रमाण इसके विपरीत है। मार्क्सवादी अपने इस सिद्धान्त में चिपटे हुए हैं कि पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था अन्त में एक दिन खोखली होकर अवश्य टूट जाएगी, लेकिन अगर वह अभी तक टूटी नहीं तो उसका कारण सिर्फ यह है कि अमेरिका ने विदेशी बाजारों पर कब्जे, विदेशों में अपने पूँजी-निवेश और युद्धों के 'साम्राज्यवादी' प्रयत्नों से क्रायन के उम्र दिन को कुछ समय के लिए टाल दिया है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप और उसकी समस्याओं ने इस हास्यास्पद चित्रण की विगुह प्रचार कहकर उपेक्षा की जा सकती थी, किन्तु कठिनाई यह है कि सभार के अन्य देशों में अनेक गैर-साम्राज्यवादी युद्धजीवी भी, पूर्णतः नहीं तो कम से कम अंशतः, उन समस्याओं से विश्रान्त रहते हैं।

है कि मनुष्य अतिशयोक्तियों से और अपनी कमियों की ओर ने गाँवें फेरने की प्रवृत्ति से विलकुल बच नहीं सकता और हम यह बात भी निसकोच स्वीकार करते हैं कि हमारा एक प्रयोजन यहाँ यह बनाना है कि हमारे ख्याल में वह कौन-सी चीज है, जो अमेरिका की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों में जीवन को जीने योग्य बनाती है। फिर भी, अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की सम्भावनाओं पर गर्व करते हुए भी, हम उसकी कुछ कमियों और अवशिष्ट समस्याओं को स्वीकार करते हैं। अमेरिकी अर्थ व्यवस्था के सम्मुख अभी तक जो समस्याएँ विद्यमान हैं उन्हें और उनके समाधान के लिए उसकी अब तक की उपनदियों को जानना जरूरी है। अपनी प्रणाली की जो चीज हमें सबसे ज्यादा पसन्द है वह शायद यह है कि, जैसा कि सभी लोकतन्त्रीय देशों में होता है, हर नागरिक की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने देश की अर्थ-व्यवस्था की कमियों को पहचाने और उन्हें दूर करने के लिए प्रयत्न करे। निरुक्त इसी प्रक्रिया से अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था अपनी सम्भाव्यताओं की पूर्ति की दिशा में अग्रसर हो सकती है।

विषय सूची

निवेदन
पृष्ठभूमि
प्रस्तावना

क
ग
च

प्रथम भाग

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकता
और उपभोग के उच्च स्तर के कारण

1.	कुछ तथ्य और आंकड़े	1
	संयुक्त राज्य में हाल में हुए परिवर्तन	5
	अन्तर्गष्ट्रीय तुलनाएँ	15
2	प्राकृतिक साधन	22
	कृषि के साधन	22
	खनिज सम्पदा	33
3	श्रम	39
	श्रमशक्ति की रचना	41
	अमेरिकी श्रमजीवियों का स्वास्थ्य और प्रशिक्षण	45
	श्रमिकों का खर्चा	50
4	व्यावसायिक प्रवृत्ति	55
	छोटे और बड़े व्यवसायों की विशेषताएँ	57
	प्रतिस्पर्धा की मात्रा	62
	व्यावसायिक प्रवृत्ति के स्वरूप में परिवर्तन	65
5	अनुसन्धान और औद्योगिकी	70
	आवृत्ति और मूल विज्ञान	70

	अनुसन्धान के लिए कार्यकर्ता और व्यय	75
6.	पूँजी	81
	विदेशी पूँजी का योगदान	81
	आन्तरिक पूँजी के स्रोत	83
	पूँजी का उपयोग	88
7	शासन	90
	प्राकृतिक साधनों का विकास	93
	उद्योगों को प्रोत्साहन	95
	पूँजी की उपलब्धि में वृद्धि	97
	पूर्ण रोजगार और आर्थिक अभिवृद्धि की समुन्नति	99
	सरकारी कार्यवाही के प्रति रवैया	101
8	मूल्य और सस्थाएँ	104
	अमेरिका में एक नई शुरुआत	104
	प्रारम्भिक अमेरिकी परिस्थितियाँ	107
	अमेरिका की देशज विशिष्टताओं का प्रभाव	110

द्वितीय भाग

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की समस्याएँ और सभावनाएँ

9.	आर्थिक उन्नति में सन्तुलन	127
	सम्भावित उत्पादन वृद्धि और उसका उपयोग	127
	आर्थिक उतार-चढ़ाव	137
	मूल्य-वृद्धि की समस्या	149
	गतिशीलता और जड़ता	152
10	रहन-सहन का स्तर और आय का विभाजन	158
	गरीबी के अवशेष	160

कर-प्रणाली	161
आर्थिक और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम	166
गैर-सरकारी सस्थाओं के परोपकारी कार्य	170
जीवन-पद्धति में परिवर्तन	172
11 संयुक्त राज्य के उद्योगों में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण	180
केन्द्रीकरण की मात्रा	180
केन्द्रीकरण के सम्बन्ध में चिन्ता के कारण	183
विशालता और एकाधिकार	186
कम्पनी-गुट-विरोधी कानून	189
बड़ी कम्पनियों का गठन और कार्य	192
लघु उद्योग नीतियाँ	198
12 अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत् में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान	203
संयुक्त राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप	206
व्यापार की समस्याएँ और नीतियाँ	210
प्राइवेट विदेशी निवेश	226
वैदेशिक सहायता कार्यक्रम और नीतियाँ	230
संयुक्त राज्य का अदायगी सन्तुलन और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-निधि	236
संयुक्त राज्य की विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	251
13 अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था : स्वरूप और भविष्य	256
अमेरिकी व्यक्तिवाद और शासन का कर्त्तव्य	257
अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में आयोजन का स्थान	261

सन् 1930 के दशक की मन्दी और सन् 1960 के	
दशक की अभिवृद्धि	264
भावी जीवन-निधि	268
माक्सवादी सिद्धान्त और अमेरिकी प्रणाली	271
अमेरिकी आर्थिक प्रणाली का नाम क्या हो ?	275
अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था—क्या वह अन्य देशों	
में भी अपनायी जा सकती है ?	280
14. परिशिष्ट तालिकाएँ	287

प्रथम भाग

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकता और उपभोग के उच्च स्तर के कारण

अमेरिका ने जिन उपायों से अपनी उत्पादकता को अभूतपूर्व स्तर तक पहुँचाया है और रहन-सहन का ऊँचा स्तर प्राप्त किया है, उसकी सीधी-सादी और सुस्पष्ट व्याख्या करना बहुत आनन्ददायक होगा। किन्तु अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था एक जटिल मशीन की भाँति पेचीदा है। उसका उत्पादन बहुत-से अलग-अलग हिस्सों पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि इस बात पर भी निर्भर है कि उनमें परस्पर समन्वय और सन्तुलन रहे। एक लोकतन्त्रीय देश में एक-दूसरे से बहुत भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से तरह-तरह के दबाव और खिचाव पड़ते हैं, और संयुक्त राज्य में विद्यमान विशिष्ट हितों वाले विविध वर्गों की भारी सख्या भी अनेक प्रकार के दबाव और खिचाव डालती रही है, फिर भी यह कुछ हद तक आश्चर्य की बात है कि इन से यह जटिल मशीन खड़-खड़ नहीं हुई। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यह मशीन सिर्फ चलती ही नहीं रही, बल्कि इन वर्षों में उसके ढाँचे में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ है और उसकी सुचारुता में सुधार और वृद्धि हुई है। प्रथम भाग में हम यह बताने का प्रयत्न करेंगे कि यह कैसे हुआ।

पहले अध्याय में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में उत्पादन, आय और उपभोग के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के तथ्य और आंकड़े दिये गए हैं। इस संक्षिप्त सर्वेक्षण में दिये गए आंकड़े अनेक पाठकों को नये

या आवश्यक प्रतीत न हो, यह सम्भव है, किन्तु फिर भी सब मिलाकर वे अमेरिकी उत्पादकता के परस्पर-सम्बद्ध कारक-तत्वों को समझने के लिए प्रारम्भिक बिन्दु का काम दे सकते हैं।

दूसरे अध्याय से आठवें अध्याय तक दो प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया गया है। पहला यह कि वे मुख्य-मुख्य कारक-तत्व कौन-से हैं जिन्होंने अमेरिका की उत्पादकता को इतना बढ़ाया है और अमेरिका के रहन-सहन के स्तर को इतना ऊँचा उठाया है। दूसरा यह कि भविष्य में भी इन रुझानों के कायम रहने की क्या सम्भावनाएँ हैं। यह सारा विवेचन और अध्ययन प्राकृतिक साधन, श्रम, प्रबन्ध, अनुत्तवान और आर्थिकी, पूँजी और सरकार आदि कारक-तत्वों द्वारा उत्पादकता की वृद्धि में दिये जाने वाले योग पर केन्द्रित है और साथ ही इसमें अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में इन तत्वों को प्रभावित करने वाले सस्थानों, प्रयोजनों और मूल्यों का भी विवेचन किया गया है।

प्रथम भाग का उद्देश्य सिर्फ यह बताना है कि इनमें से हरेक तत्व कैसे उत्पादकता की वृद्धि में योग देता है—इसका उद्देश्य उनका समर्थन या आलोचना करना नहीं है। किन्तु हम यहाँ यह स्पष्ट कर दें कि हमें इनमें से किसी भी कारक-तत्व में पूर्णता दिखाई नहीं दी। हरेक में ही सुधार की गुंजाइश और सम्भावना है। इन कमियों का सकेत हर तत्व के वर्णन में दिखाई पड़ता है। किन्तु इन समस्याओं पर अपना विश्लेषण और साथ ही सरकारी और निजी नीतियों द्वारा उनके समाधान के लिए किये जा रहे उपायों का विवरण हमने द्वितीय भाग के लिए रख छोड़ा है।

कृष्ण तथ्य और आंकड़ें

संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन और उपभोग का स्तर कितना ऊँचा है और अन्य देशों की आर्थिक उपलब्धियों की तुलना में उसकी क्या स्थिति है, इसकी जानकारी के लिए निम्न तथ्य दिये जा सकते हैं :—

- * संयुक्त राज्य में कुल उत्पादन इस समय सन् 1929 के भारी व्यावसायिक उत्कर्ष के वर्ष के उत्पादन से ढाई गुना है और यह आशा की जा सकती है कि अगले दस वर्षों में वह इससे भी अधिक तेज गति से बढ़ता रहेगा ।
- * पिछले 30 वर्षों में प्रति मानव-घण्टा उत्पादन 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ता रहा है और औद्योगिक विधियों में हो रहे नये-नये सुधारों को और अधिक तीव्र गति से अपनाते से भविष्य में वृद्धि की यह दर और भी ऊँची होगी ।
- * अमेरिका में बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभ पहले की अपेक्षा अधिक व्यापक क्षेत्र में उठाये जाते हैं । और किसी भी देश में ये लाभ इतने व्यापक रूप में नहीं उठाये जाते ।
- * सन् 1929 के बाद, यदि मूल्यों को स्थिर मान लिया जाय, तो प्रति व्यक्ति उपभोग में 60 प्रतिशत वृद्धि हुई है । वृद्धि की यह दर किसी भी अन्य देश से अधिक है ।
- * देश आज आर्थिक अस्थिरता का सामना करने के लिए पहले की अपेक्षा कहीं अधिक तैयार है ।
- * यद्यपि संयुक्त राज्य की आबादी सारे संसार की आबादी का कुल छः प्रतिशत है फिर भी उसका औद्योगिक उत्पादन विश्व के कुल औद्योगिक उत्पादन का एक तिहाई है ।

ये कथन सामान्य कथन मात्र है। किन्तु अन्य आकड़ों से यदि इनकी पुष्टि की जाय तो इनसे इस बात की कुछ भलक मिल सकती है कि अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था परिमाण की दृष्टि से कितनी विशाल है और अन्य देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं से वह किन-किन बातों में भिन्न है।

इन और बाद में आने वाले आकड़ों की व्याख्या के सम्बन्ध में कुछ चेतावनी देना उपयुक्त होगा। कुल आय और अर्जित आय, खाद्य सामग्री, आवास एवं सयुक्त राज्य के रहन-सहन के स्तर के अन्य पहलुओं के सम्बन्ध में जो आकड़े दिये गए हैं वे 'औसत' अमेरिकी के आंकड़े हैं। कुछ अमेरिकी लोगों की आर्थिक स्थिति इन औसत आकड़ों से प्रदर्शित स्थिति से भी बेहतर है, किन्तु दूसरी ओर कुछ अमेरिकी लोग औसत अमेरिकी लोगों से गरीब भी हैं। साथ ही उत्पादन और उपभोग के विभिन्न देशों के आंकड़ों की तुलना में भी कुछ खतरा है। इन तुलनाओं से सयुक्त राज्य अमेरिका में या अन्य देशों में जीवन-स्तर की उन्नति या ह्रास की सही तस्वीर नहीं मिलती। फिर भी विभिन्न देशों के आकड़ों की तुलनाओं से अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के कुछ पहलुओं की भाँकी मिलती है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है।

आकड़ों और उनकी तुलनाओं पर बहुत अधिक भरोसा करने में एक और भी गम्भीर बाधा है। उनसे सभी देशों में विद्यमान महत्त्वपूर्ण और दूरगामी अप्रत्यक्ष विशेषताओं की सही भाँकी नहीं मिलती। केवल धन-सम्बन्धी और भौतिक तुलनाएँ न तो उत्पादक प्रक्रियाओं द्वारा साधे जाने वाले आर्थिकेतर (नैतिक आदि) मूल्यों की और न उपभोग की विभिन्न किस्मों और स्तरों के गुणात्मक पहलुओं की पर्याप्त भाँकी दे सकती है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और उपभोग का मूल्य बाजार दर के हिसाब से निकाल लेना ही आर्थिक गति-विधि के सम्पूर्ण सामाजिक महत्त्व को नहीं नाप सकता। उदाहरण के लिए यह सम्भव है कि एक वैज्ञानिक का अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य जब तक चल रहा है तब तक उसका मूल्य बहुत ऊँचा न हो, लेकिन जब उसके अनुसन्धान और आविष्कार पूरे हो जाएँ तो वे भविष्य के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हों। चिकित्सा सबधी बहुत-सी खोजें ऐसी हैं जिनसे उनके अनुसन्धान कर्त्ताओं

को बहुत ही कम पैसा मिला है। यह बात आमतौर पर सभी जानते हैं कि अध्यापकों के काम का समाज के लिए जितना महत्त्व है, उसकी तुलना में उन्हें पैसा बहुत कम मिलता है, फिर भी आत्मार्पण की भावना से काम करने वाले अध्यापक छात्रों में एक ऐसी उत्कण्ठा, कल्पना शक्ति और साहस की भावना पैदा करते हैं जो समाज को उन्नति और परिवर्तन की ओर ले जाती है। इसी प्रकार जो कलाकार अपनी कलाकृतियों को तुरन्त नहीं बेच देता, उसके कार्यों का मूल्य विशुद्ध पैसे की दृष्टि से विलकुल शून्य होगा, भले ही वह राष्ट्र के सांस्कृतिक जीवन में अमूल्य योगदान कर रहा हो।

लेकिन आकड़ों के द्वारा दिये जाने वाले विवरणों में इन द्रुतियों और अपर्याप्तताओं के वावजूद, कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण मात्रात्मक तुलनाएँ अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उपलब्धियों और साथ ही उसमें अभी तक विद्यमान कमियों के कारणों को समझने में सहायता दे सकती हैं।

संयुक्त राज्य में हाल में हुए परिवर्तन

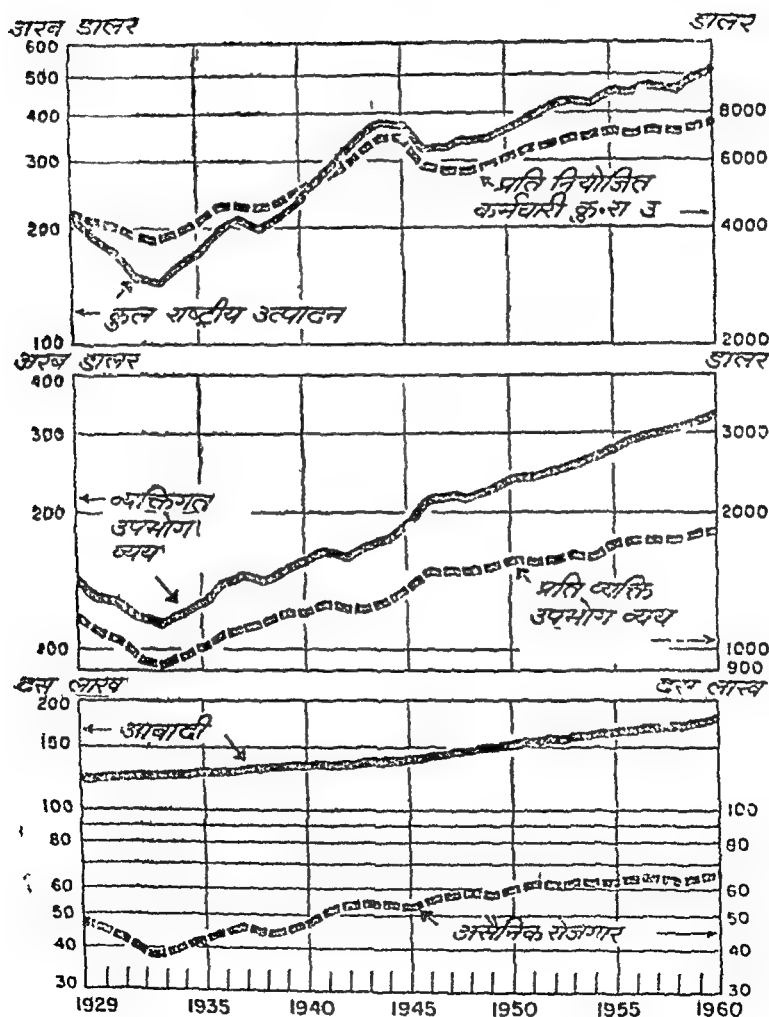
पिछली एक पीढ़ी में अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था में कुछ बहुत बड़े उतार-चढ़ाव आये हैं। सन् 1920 से प्रारम्भ दशक में उसके व्यापार में खूब उत्कर्ष और तेजी आई और उसके बाद 1930 से प्रारम्भ दशक में जबर्दस्त मन्दी रही। इसके पश्चात् सन् 1940 में प्रारम्भ दशक में उसकी अर्थ-व्यवस्था पहले युद्धकालीन अर्थ-व्यवस्था नहीं और फिर युद्ध समाप्त होने पर उसमें पुनः परिवर्तन आये। सन् 1960 के दशक के दस वर्षों में उसकी अर्थ-व्यवस्था का फिर विस्तार हुआ और हल्की-सी

घटा उत्पादन का, अधिक ऊँचा होना है। इस उत्पादकता की वदीलत

चार्ट 1

आर्थिक वृद्धि के सूचक

1929-1960 (1960 के मूल्यों के हिसाब से डालरो में)



नोट:—देखें पारिशिष्ट तालिका—1

ही अमेरिका इस समय उपलब्ध साधनों से वस्तुओं और सेवाओं का अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन कर सका है। यद्यपि सप्ताह के काम के घंटे कम हो गए हैं तो भी इस ऊँची उत्पादकता के कारण ही अमेरिकी लोगों का उपभोग का स्तर ऊँचा बना हुआ है। और हाल के वर्षों में अमेरिका में जो आर्थिक विकास हुआ है और अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक स्थिरता रही है, उसका भी बड़ा कारण यह उत्पादकता ही है।

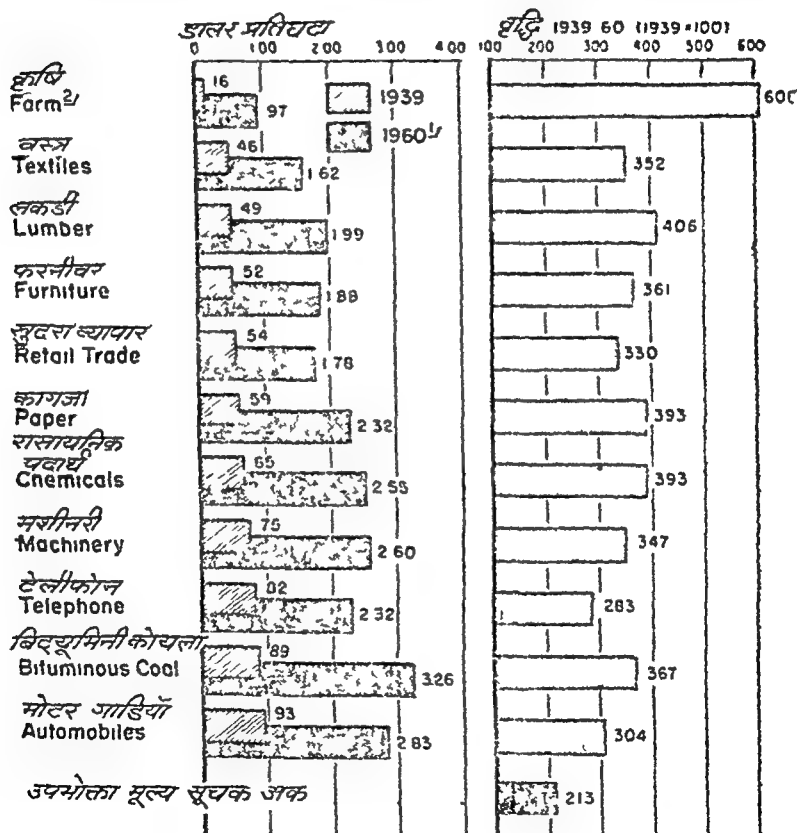
पिछले पचास वर्षों में अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता सब मिलाकर तीन गुनी हो गई है और सन् 1929 के बाद वह दुगुनी हुई है (देखिए परिशिष्ट तालिका 3)। इसका अर्थ यह है कि इन पचास वर्षों में उत्पादकता में वृद्धि की दर 2.2 प्रतिशत वार्षिक रही और सन् 1929 के बाद तो यह दर 2.5 प्रतिशत वार्षिक हो गई। किन्तु द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद की अवधि में यह वार्षिक दर औसतन 3 प्रतिशत से भी अधिक रही है। इस वृद्धि का कारण निर्माण उद्योगों (मैन्यूफैक्चरिंग इंडस्ट्री) की उत्पादकता का काफी बढ़ जाना था। सन् 1947-49 के बाद निर्माण-उद्योगों में प्रति मानव-घंटा उत्पादन औसतन 3.5 प्रतिशत वार्षिक बढ़ा है। इसी बीच कृषि की उत्पादकता भी बढ़ती रही है, हालांकि अब भी वह निर्माण-उद्योगों की उत्पादकता से आगे स्तर पर है। पिछले दस वर्षों में उसमें औसतन 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि होती रही है।

उत्पादकता में वृद्धि की दर हर उद्योग में अलग-अलग है (देखिए परिशिष्ट तालिका 4)। उदाहरण के लिए कुछ खान उद्योगों में हाल के वर्षों में प्रति मानव-घंटा उत्पादन बहुत थोड़ा-थोड़ा बढ़ा है और तार उद्योग (टेलीग्राफ इंडस्ट्री) में प्रति कर्मचारी उत्पादन बढ़ने के बजाय उल्टा कम हुआ है। इसके विपरीत रेयन, कृत्रिम रेशा, सीमेंट और खाद्य पदार्थों को ढिंवा बन्द और सुरक्षित करने आदि के उद्योगों में उत्पादकता न केवल अन्य अनेक निर्माण-उद्योगों की अपेक्षा अधिक तीव्र गति से बढ़ी है, बल्कि सब मिलाकर अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता वृद्धि का जो औसत है उससे भी वह अधिक है। इसके अलावा अधिक उत्पादकता वाले इन उद्योगों का आपेक्षिक महत्त्व भी

बढ़ गया है। कारण, मजदूरों की एक बड़ी संख्या कृषि से हटकर अधिक उत्पादकता वाले इन निर्माण-उद्योगों में लग गई है जिससे सब मिलाकर अमेरिका का प्रति मानव-घंटा उत्पादन और भी ऊँचा हो गया

चार्ट 2

कुछ चुने हुए उद्योगों में प्रति घंटा श्रमिक आय में वृद्धि (1939-1960)



1. प्रारम्भिक

2. बिना भोजन और रिहायश के औसत प्रति घंटा मजदूरी की दर जो औसत दैनिक मजदूरी की दर को काम के घंटों से बाटकर निकाली जाती है।

है। इसलिए जहाँ उत्पादकता में आम वृद्धि का अधिकतर कारण उत्पादन की विधियों में औद्योगिकी (टैक्नोलॉजी) और प्रबन्ध सम्बन्धी सुधार है, वहाँ उसका एक आंशिक कारण यह भी है कि बहुत-से मजदूर कम उत्पादकता वाले उद्योगों से हटकर अधिक उत्पादकता वाले उद्योगों में लग गए हैं।

अमेरिका के उपभोग सम्बन्धी ढाँचे में सबसे अधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन यह हुआ है कि लोगों में अधिक समानता आने लगी है और अधिकाधिक लोग अधिकाधिक जीवन के आराम के साधनों का उपभोग करने लगे हैं। पहले जहाँ अपेक्षाकृत कम अमेरिकी लोगों के हाथों में बहुत बड़ी मात्रा में धन-दौलत केन्द्रित थी, वहाँ अब आय का वितरण अधिक व्यापक क्षेत्र में होने लगा है। उदाहरण के लिए, सन् 1929 में अमेरिका में खर्च करने या बचाने के लिए उपलब्ध कुल आय का 33.8 प्रतिशत भाग देश के कुल 5 प्रतिशत लोगों के हाथों में था। इन 5 प्रतिशत व्यक्तियों की गिनती सर्वाधिक आय वाले वर्ग में थी। सन् 1952 में इसी सर्वोच्च आय-वर्ग के लोगों को देश की कुल उपलब्ध आय का केवल 15.2 प्रतिशत भाग मिला और सन् 1952 के बाद पिछले कुछ वर्षों में इस स्थिति में कोई दिनेश परिवर्तन नहीं हुआ है (देखिए परिशिष्ट तालिका 5)। इनका एक आंशिक कारण 1920 और 1930 के दशकों की तुलना में नहीं अधिक ऊँचे सम्पदा शुल्क और आयकर हैं। किन्तु आय के इस अधिक व्यापक और अधिक समान वितरण का हमें भी ज्यादा महत्वपूर्ण कारण यह है कि कम आय वाले सभी वर्गों की आय में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि हुई। रोजगार के अवसरों के बढ़ने और श्रमिकों और प्रबन्धकों के सम्बन्धों में सामूहिक सौदेबाजी के अभियांत्रिक प्रभावकारी ढंग से लागू होने और सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी के स्तर निर्धारित किये जाने का परिणाम यह हुआ कि कम मजदूरी पाने वाले वर्गों की आय भी बहुत अधिक मजदूरी पाने वाले वर्गों की आय के निकट आ गई है।

पूर्व कम आय वाले परिवार के मुखिया को, अगर वह रोजगार पर लगा होता, आज की अपेक्षा काम अधिक घटे करना पड़ता या और उसे मजदूरी कम मिलती थी। उस समय परिवार का कामचलाऊ निर्वाह तभी हो पाता था जबकि उसके कई सदस्य पूरे समय के या कुछ समय के रोजगार पर लगे रहते। उस समय समस्या यह थी कि पूरे समय के काम के अनेक घन्टों में मूल वेतन की दरें नीची थी। किन्तु सन् 1930 के दशक के बाद से अमेरिकी श्रमिकों की प्रति घंटा औसत आय काफी बढ़ गई है—खासकर उन उद्योगों में जिनमें मजदूरी की दरें अपेक्षाकृत नीची थी। उदाहरण के लिए सन् 1939 से 1960 तक उपयोग्य वस्तुओं के मूल्य सूचक अंक में जहाँ दुगुने से कुछ ही अधिक वृद्धि हुई, वहाँ मजदूरी की दरें फार्मों में युद्ध-पूर्व के स्तर से छ गुनी हो गई और कपड़ा मिलों में साढ़े तीन गुनी बढ़ गई। अधिक ऊँची मजदूरी की दरों वाले उद्योगों में भी मजदूरियाँ काफी बढ़ी। उदाहरण के तौर पर, मोटर-निर्माण-उद्योग में औसत मजदूरी 204 प्रतिशत और टेलीफोन-उद्योग में 183 प्रतिशत बढ़ गई। आज यह स्थिति है कि पूरे समय काम करने वाले करीब-करीब सभी श्रमिकों को इतनी आय अवश्य है कि वे अपना निर्वाह भली भाँति कर सकें और बहुत-से श्रमिक तो इससे भी अधिक कमा लेते हैं। इसके अलावा जीविकोपार्जन की क्षमता के नष्ट हो जाने की दशा में लोगों को सरकार से भी सामाजिक सहायता और वीमा-लाभों की प्राप्ति होती है और प्राइवेट उद्योगों की पैगन योजनाओं और प्राइवेट कल्याण मण्डलों से भी लाभ प्राप्त होता है।

कम आय वाले परिवारों की संख्या बराबर घट रही है, इसका आभास इस बात से मिलता है कि सन् 1929 में जहाँ 2,000 डालर से कम व्यक्तिगत आय वाले परिवारों की संख्या कुल अमेरिकी परिवारों की संख्या का 32 प्रतिशत थी, वहाँ सन् 1960 में वह घटकर 13 प्रतिशत रह गई। फिर भी संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यह समस्या है कि इसके कुछ इलाक़े अल्पविकसित हैं और अलग-अलग क्षेत्रों में आय और उत्पादन के स्तर अलग-अलग हैं। कुछ अल्पविकसित इलाकों में सरकारी

और गैर-सरकारी नीतियाँ विकास को बढ़ाने में सफल सिद्ध हुई हैं। ऐसा एक क्षेत्र टैनेसी घाटी क्षेत्र है, जो अनेक राज्यों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में 1929 में प्रति व्यक्ति व्यक्तिगत आय सारे अमेरिका की औसत प्रति व्यक्ति आय से 49 प्रतिशत कम थी, किन्तु विकास कार्यों के फलस्वरूप 1960 में वह इस औसत से केवल 36 प्रतिशत नीची रह गई। फिर भी दक्षिण के अनेक क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय देश के अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है।

किन्तु आय के वितरण के आकड़े इस बात को पूरी तरह प्रकट नहीं करते कि किस प्रकार मोटर गाड़ी आदि आधुनिक जीवन के आराम और मुख-भुविधा के साधन अधिकाधिक व्यापक क्षेत्र में वितरित हो रहे हैं। सन् 1949 में कुल अमेरिकी परिवारों में से 51 प्रतिशत ऐसे थे, जिनके पास एक मोटर गाड़ी थी और 3 प्रतिशत ऐसे थे जिनके पास दो या दो से अधिक मोटरे थी। सन् 1960 तक ये दोनों अनुपात बढ़ कर क्रमशः 77 और 13 प्रतिशत हो गए। यद्यपि अधिक धनी लोग आज भी दूसरों से अधिक विलासितापूर्ण और गानदार मोटर गाड़ी रख सकते हैं, किन्तु कैडिलक गाड़ी और फोर्ड गाड़ी रखने की क्षमताओं में उतनी अममानता नहीं है जितनी कि एक गाड़ी रखने की क्षमता और अक्षमता में है।

आवास के क्षेत्र में बेहतर जीवन-स्तर का और भी अधिक प्रमाण मिलता है। सरकार के आवास कार्यक्रमों के फलस्वरूप अमेरिका के लाखों परिवारों के लिए उसमें भी बेहतर मकान खरीदना सम्भव हो गया है, जैसा कि वे उन कार्यक्रमों के बिना अपनी निज की सामर्थ्य से खरीद पाते। औसत अमेरिकी परिवार अपने मकानों के स्वयं मालिक है। सन् 1940 में 43.6 प्रतिशत गैर-कृषिजीवी परिवार अपने निज के मकानों में रहते थे। सन् 1960 तक यह अनुमान बढ़कर 62 प्रतिशत हो गया। इनके अनायास सम्स्त अमेरिकी परिवारों में से 89 प्रतिशत के पास टेलीविजन सेट और 95 प्रतिशत के पास एक से अधिक रेडियो सेट थे।

रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने वाली और भी कई बातें हैं।

सरकारी गति-विधियाँ, जिनमें सघीय, राज्यीय और स्थानीय—तीनों प्रकार की गति-विधियाँ शामिल हैं आज जनता को अनेक आवश्यक सेवाएँ उपलब्ध कराती हैं, जैसे कि शिक्षा, समाज कल्याण, जन-स्वास्थ्य, पार्क और अन्य मनोरजन सुविधाएँ आदि। पहले मुख्यतः धनी लोग ही अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिला सकते थे। यद्यपि संयुक्त राज्य आज भी उस स्थिति से बहुत दूर है जिसमें कि उच्च शिक्षा केवल छात्र की योग्यता पर ही निर्भर हो, फिर भी विश्वविद्यालयी शिक्षा का असाधारण विस्तार हो गया है। मोटे तौर पर हमारे तमाम हाई स्कूल पास छात्रों में से 40 प्रतिशत कालेजों या विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, हालांकि इनमें से आधे ही अपनी शिक्षा डिग्री प्राप्त करने तक जारी रख पाते हैं। सन् 1960 में 18 से 24 वर्ष तक की आयु के अमेरिकी तरुणों में से लगभग 17 प्रतिशत कालेजों या विश्वविद्यालयों में भरती थे, जब कि सन् 1900 में यह अनुपात 3 प्रतिशत से भी कम था। एक और उदाहरण लीजिये एक पीढ़ी पहले आज की अपेक्षा बहुत ही कम अमेरिकी लोग छुट्टी मनाने या मनोरजन के लिए यात्रा कर सकने की स्थिति में थे किन्तु आज अधिकतर अमेरिकन को सवेतन अवकाश मिलता है और वे मनोरजन या आमोद-प्रमोद के लिए इतनी बड़ी सख्या में इधर-उधर जाते हैं कि उनकी छुट्टी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक बड़ा सेवा-उद्योग ही स्थापित हो गया है। चिकित्सा और चिकित्सालय सेवाओं को भी अधिकाधिक अमेरिकी लोगों के लिए सुलभ करने का प्रयत्न किया जा रहा है, और इस बात का कोई खयाल नहीं किया जाता कि वे उसके लिए पैसा चुका सकते हैं या नहीं।

इस प्रकार संयुक्त राज्य में अनेक तत्वों ने मिलकर जीवन की सुख-सुविधाओं को बढ़ाने और उनका अधिक समान वितरण करने में योग दिया है ताकि कम आय वाले लोग भी उन्हें प्राप्त कर सकें। ये तत्व हैं—आय के वितरण में विद्यमान असमानता में वास्तविक कमी, आय और उपयोग के स्तरों में आम वृद्धि और सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं में वृद्धि।

द्वितीय विश्व-युद्ध की समाप्ति पर यह भय व्यापक रूप से फैल गया।

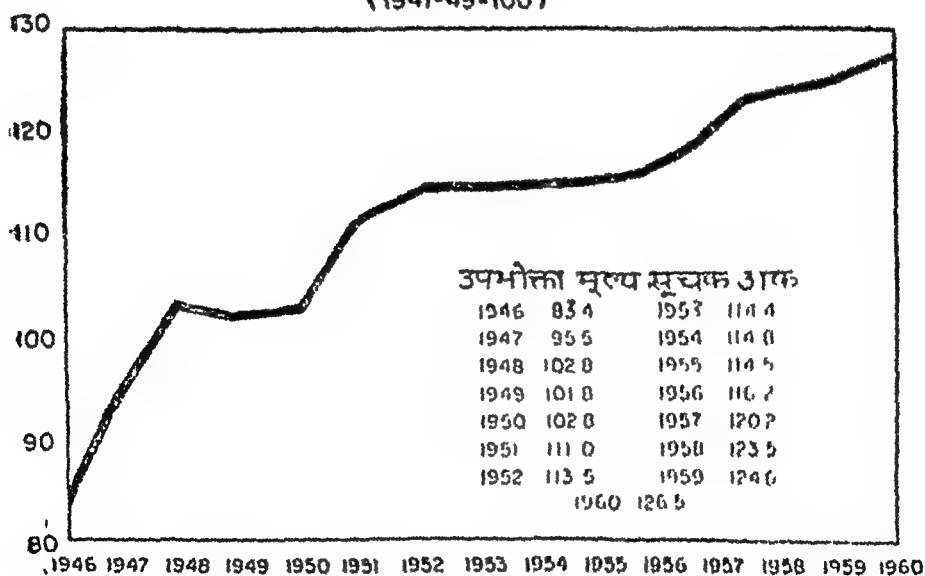
कुछ तथ्य और आकड़े

था कि युद्धोत्तर कालीन व्यापारिक उत्कर्ष और तेजी के बाद कही सन् 1930 के दशक की भाँति फिर जबर्दस्त और व्यापक बेरोजगारी न पैदा हो जाय। किन्तु यह भय निर्मूल सिद्ध हुआ और अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था निरन्तर विकसित होती रही, सिर्फ कुछ थोड़े-से समय के लिए ही उसमें रुकावट पड़ी। हाल के वर्षों में आर्थिक अशिवृद्धि की गह गति कुछ धीमी पड़ गई है और बारह वर्षों की अवधि में चार बार मन्दी आई है। ये मन्दियाँ बहुत हल्की थी और बहुत कम समय तक रही; किन्तु उन्होंने वृद्धि की गति को मन्द प्रपश्य किया है। यही नहीं, बल्कि बेरोजगारी भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रही है।

चार्ट 3.

उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1946-60)

(1947-49=100)



किन्तु पिछले दशक की बेरोजगारी उससे पहले के जमाने की बेरोजगारी से भिन्न किस्म की है। इस बेरोजगारी का अर्थ पूर्णतः अश्रम हो जाना नहीं है। इस दशक में पहले के मन्दियों के जमानों की भाँति व्यक्तिगत निराशा और हताशापूर्ण कठिनाइयाँ नहीं आईं, वैसे अमेरिका अच्छी तेजी के दिनों में भी बेरोजगारी के

न-कुछ वृद्धि अनुभव करता रहा है। खास कर, बेरोजगारी, कुछ ऐसे इलाकों में, जो मन्दी के पुराने मरीज रहे हैं, और जहाँ रोजगार के अवसर अधिकतर उन्हीं उद्योगों तक सीमित रहे हैं, जिनमें हास हो रहा है, एक गम्भीर समस्या बन गई है। वह अपेक्षाकृत पुराने और बूढ़े कर्म-चारियों, अश्वेतों (नीग्रो) और बेहुनर और कम शिक्षित नीजवानों के लिए भी एक समस्या रही है। इस तरह की विशिष्ट बेरोजगारी पिछले दशक में अधिक बढ़ी है किन्तु गैर सरकारी और सरकारी संस्थानों द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने की जोरदार कोशिशें की जा रही हैं। सरकार ने क्षेत्र पुनर्विकास प्रशासन के नाम से एक नया संस्थान स्थापित किया है जो मन्दी के शिकार अवकसित क्षेत्रों के विकास की समस्याओं पर ध्यान देता है। इसके साथ ही बेरोजगार होने वाले श्रमिकों के पुनर्वास और उन्हें नये कामों का पुनः प्रशिक्षण देने की सुविधाओं की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। श्रमिकों के वेतन इतने ऊँचे रहे हैं कि उनमें से बहुत-से स्वल्पकालिक बेरोजगारी के दिनों के लिए कुछ पैसा अपने वेतनों में से बचाकर सुरक्षित रख सके हैं। इसके अतिरिक्त 60 प्रतिशत से अधिक बेरोजगार व्यक्ति अपना रहन-सहन का स्तर कायम रखने के लिए सरकार से मिलने वाला बेरोजगारी बीमा का लाभ प्राप्त करते हैं। कुछ मजदूर यूनियन और कुछ बड़ी फार्में अपने बेरोजगार सदस्यों और कर्म-चारियों को पूरक आय भी प्रदान करती हैं। बेरोजगार मजदूर जानते हैं कि सरकार रोजगार के स्तर को निरन्तर ऊँचा बनाये रखने और बढ़ाने की नीति से बधी हुई है और इसलिए वह रोजगार के नये-नये अवसर पैदा करने के लिए बराबर कोशिश कर रही है।

पिछले अनुभव के आधार पर कुछ प्रेक्षकों ने यह मत प्रकट किया है कि तीव्र गति से बढ़ते आर्थिक विस्तार से या तो काफी आर्थिक अस्थिरता आयेगी या वस्तुओं की कीमतें बढ़ेगी। द्वितीय विश्व युद्ध और कोरियाई युद्ध दोनों के बाद—यानी युद्धोत्तरकालीन वर्षों में—कीमतें वास्तव में ही काफी तेजी से बढ़ी और हाल के वर्षों में भी संयुक्त राज्य अमेरिका और ससार के और बहुत-से देशों में कीमतों में वृद्धि जारी रही है। यद्यपि 1951 के वसन्त से 1960 के अन्त तक कीमतों

मे वृद्धि बहुत अधिक विक्षुब्ध कर देने वाली ही रही, तो भी उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं किया जा सका कि सब लोगों को रोजगार देने वाली और मूल्यों को स्थिर रखने वाली अर्थ-व्यवस्था कैसे स्थापित की जाय।

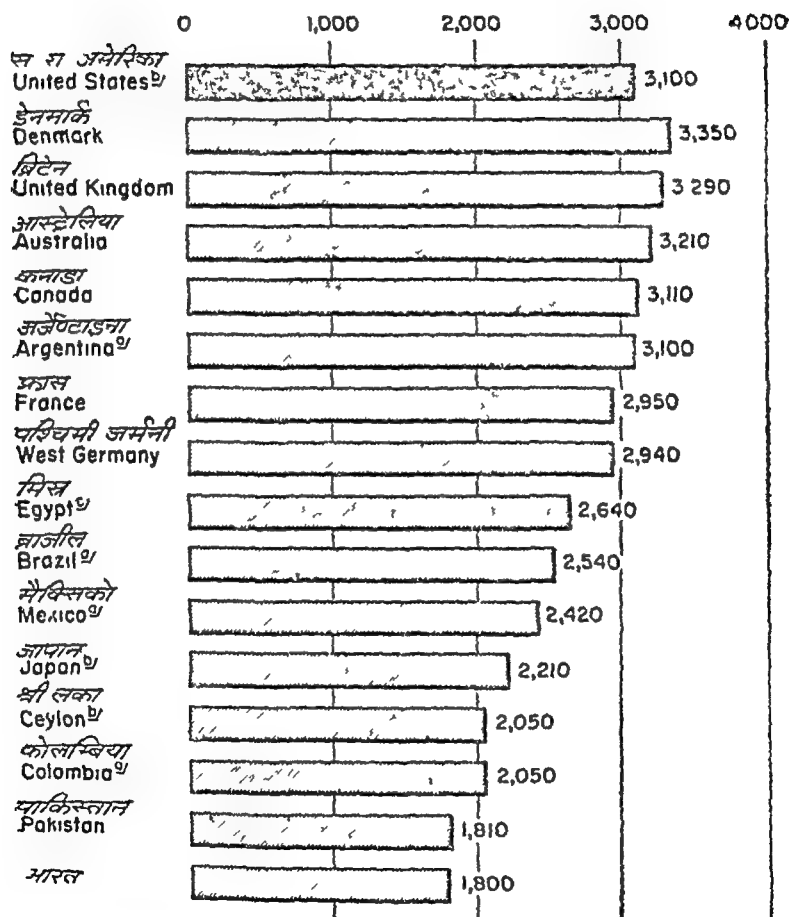
संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक ऐसे सुदीर्घ काल का उपभोग किया है जिसमें उसके यहाँ रोजगार उत्पादन और वस्तुओं की खपत का स्तर न सिर्फ ऊँचा रहा है, बल्कि उसमें बराबर वृद्धि भी होती रही है। किन्तु हाल के वर्षों में उत्पादन और रोजगार में वृद्धि की रफ्तार सन्तोषजनक नहीं रही। इसके अलावा इस बात का कोई पक्का भरोसा नहीं है कि भविष्य में गम्भीर आर्थिक उतार-चढ़ाव नहीं आएँगे। इस तरह का भरोसा कर लेना वैसा ही गलत होगा, जैसा कि 1930 से प्रारम्भ दशक की मन्दी के वर्षों में यह भय मान लेना गलत था कि अब अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में अनिश्चित काल तक मन्दी ही जारी रहेगी। सरकार, व्यापारी, मजदूर और आम अमेरिकी लोग स्पष्ट रूप से यह महसूस करते हैं कि आर्थिक अभिवृद्धि को दृढ़ता से कायम रखने और रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने के लिए अधिक प्रभावकारी उपाय अपनाने की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएँ

विभिन्न देशों के रहन-सहन के आँकड़ों की तुलना से यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिकी लोग दूसरों की अपेक्षा न केवल वस्तुओं और सेवाओं का अधिक उपभोग करते हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लाभों में भी वे अन्य देशों के लोगों की अपेक्षा अधिक समान हिस्सा बँटाते हैं। फिर भी जीवन-स्तर के कुछ विशिष्ट पहलुओं—उदाहरण के लिए भोजन में कैलोरियों की मात्रा, मकान और पुरुषों की औसत आयु (जीवन की आशा)—की दृष्टि से तुलना करने पर एक या अधिक औद्योगिक देशों का स्थान संयुक्त राज्य से ऊपर रहता है। और यदि इन तुलनात्मक आँकड़ों को जिनमें कुछ कम विकसित देशों की अपेक्षा संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान ऊँचा रहता है, हर देश की विकास की स्थिति

चार्ट 4

उपलब्ध आहार की मात्रा कैलोरियो मे 1958-59
(प्रति व्यक्ति प्रति दिन कैलोरियाँ)



a) 1957

b) 1957

c) 1957—58

पर विचार किये बिना स्वीकार कर लिया जाय, तो वे अन्य देशों की वास्तविक आर्थिक उपलब्धियों को बहुत फीका कर देते हैं। इसलिए वास्तविकता पूर्ण अध्ययन और मूल्यांकन के लिए यह जरूरी है कि उन समस्याओं, कठिनाइयों और बाधाओं को भी ध्यान में रखा जाय, जिनका कम विकसित देशों को अपने प्रति-व्यक्ति उत्पादन और उपभोग में मामूली-सी वृद्धि के लिए भी सामना करना पड़ता है और जिन पर विजय पाये बिना वे अपना यह स्वल्प-सा लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सकते।

फिर भी यदि संयुक्त राज्य और अन्य देशों में लाभयुक्त रोजगार पर लगे हर व्यक्ति के पीछे उत्पादन की और कुल आबादी के हर व्यक्ति के पीछे उपभोग की तुलना पैसों में की जाय तो हम देखेंगे कि संयुक्त राज्य में इन दोनों का स्तर यूरोप के अनेक देशों के स्तर से दो से तीन गुना तक ऊँचा और दूसरे बहुत-से देशों के स्तर से आठ से दस गुना तक ऊँचा है। यदि पैसों के बजाय भौतिक वस्तु की दृष्टि से ये तुलनाएँ की जाएँ तो भी यही असमानताएँ नजर आएँगी। इस उदाहरण के लिए लोगों के आहार के तत्वों की तुलना की जाय तो यह प्रतीत होगा कि ससार की 60 प्रतिशत के लगभग आबादी ऐसे इलाकों में रहती है, जहाँ खाद्योत्पादन वहाँ के हर व्यक्ति को 2,200 कैलोरी भी प्रतिदिन उपलब्ध नहीं करा सकता, जबकि अधिकतर स्थानों की परिस्थितियों की दृष्टि से पोषक तत्वों की यह मात्रा न्यूनतम वाछनीय या उससे भी कम है।

संयुक्त राज्य में और ससार के अन्य अधिक उद्योग सम्पन्न देशों में लोगों को पोषण की आवश्यकता से भी अधिक आहार मिल जाता है, जब कि अधिकांश कम विकसित देशों में कैलोरियों की दृष्टि से पोषक आहार की मात्रा आवश्यक या वाछनीय मात्रा से कम रहती है। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि संयुक्त राज्य में अल्पपोषण या आहार की कमी जैसी चीज है ही नहीं; लेकिन यह बात जरूर सही है कि अमेरिका में पोषण की पर्याप्तता का स्तर संसार के और बहुत-से क्षेत्रों के स्तर से काफी ऊँचा है।

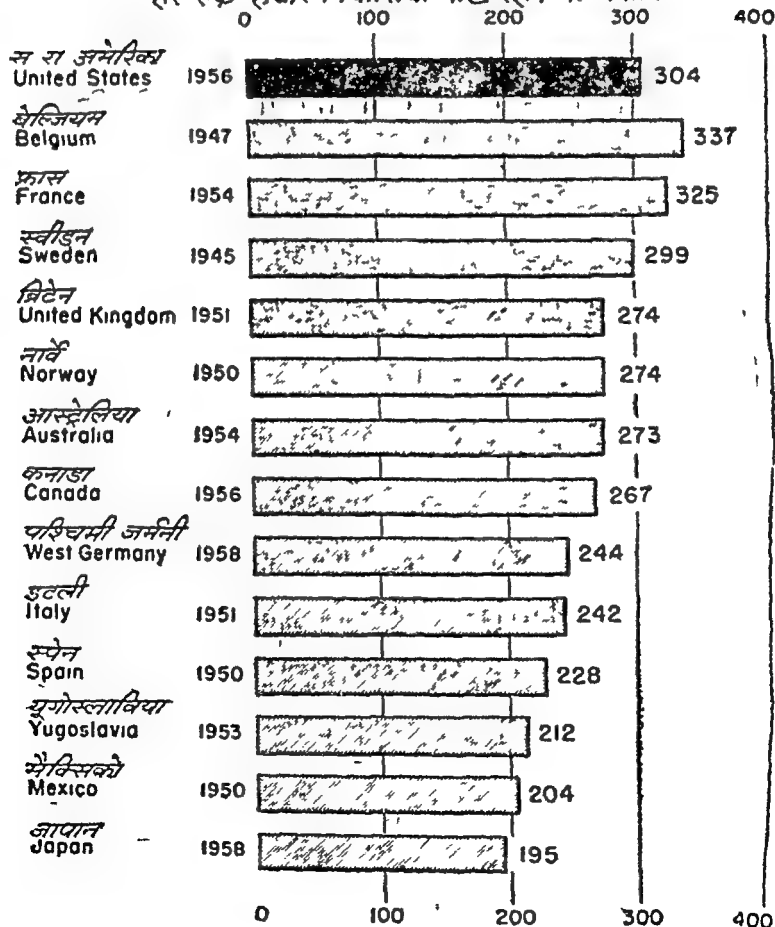
भौतिक जीवन-मान की दूसरी तुलना विभिन्न देशों की आवास

सबकी परिस्थितियों की तुलना में दृष्टिगोचर होती है। संयुक्त राज्य में यूरोप और लैटिन अमेरिका के अनेक भागों की अपेक्षा प्रति-व्यक्ति घर 10 से 50 गुना तक अधिक है। अन्य बहुत-से देशों की तुलना में यह संख्यात्मक अन्तर इससे भी अधिक बड़ा है और स्वच्छता सम्बन्धी सुवि-

चार्ट 5

उपलब्ध रिहायशी मकान

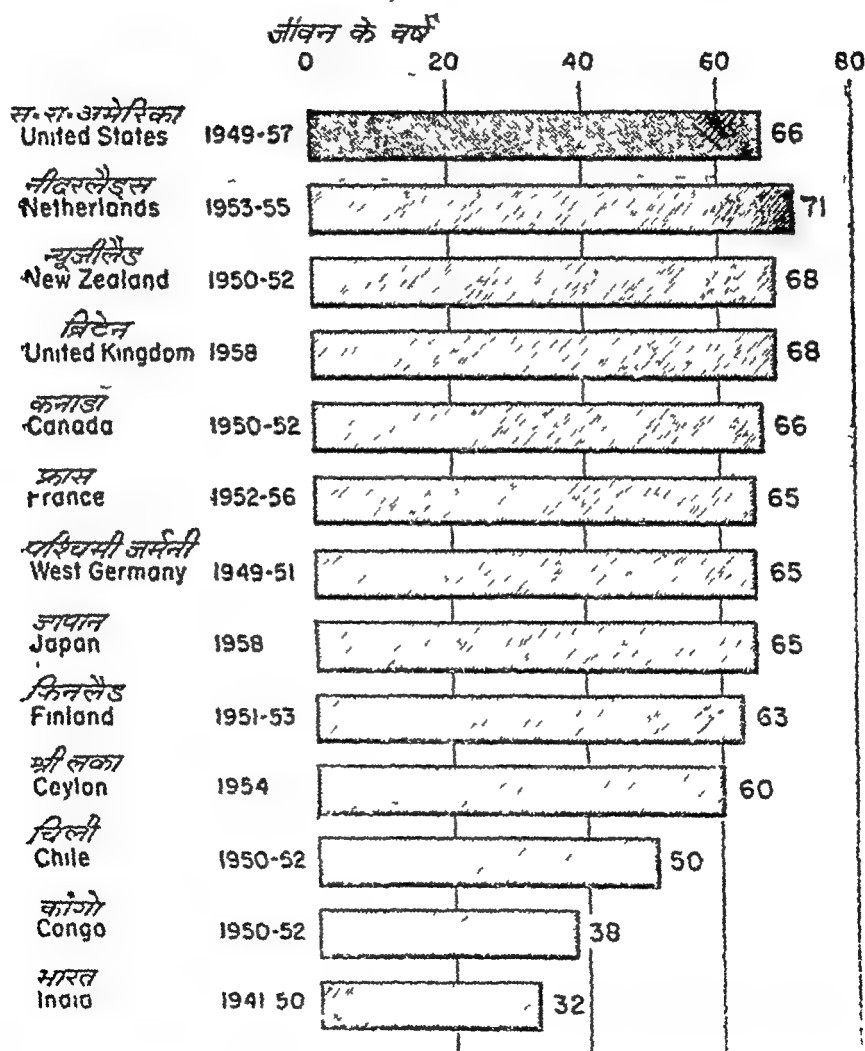
हर एक हजार निवासियों पीछे रहने के मकान



आध्रों, रोशनी, पानी और मनोरजन के स्थान की दृष्टि से जो गुणात्मक अन्तर है, उसका तो कहना ही क्या । लेकिन इससे यह अर्थ निकालना

चार्ट 6

जन्म के समय पुरुषों की जीवन की आशा



कि संयुक्त राज्य में भीड़ भरी और गन्दी रिहायशी बस्तियाँ है ही नहीं, आंकड़ों के धोखे में पड़ना है ।

आय के स्तर विषयक आंकड़े अपने आप में पूर्ण रूप से यह सिद्ध

नहीं करते कि संयुक्त राज्य और अन्य देशों में मजदूरी के स्तरों में कितनी असमानता है। एक ही वस्तु के मूल्य-स्तर और उपभोग के ढाँचे अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं। इस अन्तर के बावजूद संयुक्त राज्य एवं अनेक यूरोपीय देशों में औसत मजदूरी की क्रय-शक्ति का अनुमान लगाने के प्रयत्न किये गए हैं। यह हिसाब लगाया गया है कि विभिन्न प्रधान खाद्य पदार्थों को खरीदने लायक पैसा कमाने के लिए किस देश में मजदूरों को कितने घण्टे काम करना पड़ता है। इस हिसाब से यह मालूम हुआ है कि यूरोप के अनेक अधिक उद्योग सम्पन्न देशों में भी एक वस्तु की उतनी ही मात्रा खरीदने के लिए औसत मजदूर को संयुक्त राज्य के औसत मजदूर की अपेक्षा चार या पाँच गुना अधिक समय तक काम करना पड़ता है। (देखिए परिशिष्ट तालिका 8)।

जब हम औसत जीवन-आशा की दृष्टि से तुलना करते हैं तो रहन-सहन के स्तर के ये अन्तर और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यद्यपि चिकित्सा विज्ञान और सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता की उन्नति से लोगों की औसत आयु में सर्वत्र वृद्धि हुई है, तो भी ये औसत आयु अलग-अलग देशों में अलग-अलग हैं। कुछ कम विकसित देशों में लोगों के जीवन का औसत-विस्तार अधिक उद्योग-सम्पन्न देशों के लोगों के जीवन के औसत विस्तार से बहुत कम होता है। लोगों की जिन्दगी के कम या अधिक होने का यह अन्तर बहुत हद तक आराम के साधनों के अन्तर के कारण होता है, बशर्ते कि आराम के साधनों का अर्थ केवल मोटर-गाड़ी और टेलीफोन ही न समझा जाय बल्कि उसमें डाक्टर, चिकित्सा-सुविधा, सार्वजनिक स्वच्छता और विश्राम का समय आदि भी शामिल किये जाएँ।

सारांश

इस अध्याय में दिये गए आंकड़े, यद्यपि वे संक्षेप में और मोटे तौर पर दिये गए हैं, इस बात को काफी हद तक पुष्ट करते हैं कि अमेरिका में उत्पादकता और उपभोग के स्तर ऊँचे हैं और हाल के दशकों में

उनमे काफी वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के परस्पर-सम्बद्ध कारणों के बारे में लोगो को काफी जानकारी नहीं है। अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था पर विचार करते हुए कुछ कारणों पर बहुत अधिक बल दिया गया है और कुछ पर बहुत ही कम ध्यान दिया गया है। इस जटिल आर्थिक तन्त्र के अधिक महत्वपूर्ण भागो पर अगले अध्यायो मे विचार करते हुए हम यह देखेगे कि हर भाग क्या काम करता है, उन सबका एक-दूसरे के साथ कैसे समन्वय है और क्या अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था मे उत्तरोत्तर अभिवृद्धि जारी रखने के लिए उनमे से कुछ मे कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

प्राकृतिक साधन

आमतौर पर कहा जाता है कि जो देश ऊँचे जीवन-स्तर का उपभोग करता है, उस पर प्रकृति की अवश्य विशेष कृपा रही होगी। क्या सयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में यह बात सही है? क्या अमेरिका की जलवायु इतनी अनुकूल है, यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ है और खनिज स्रोत इतने समृद्ध है कि सयुक्त राज्य का अधिक आवादी वाला और अधिक उत्पादक राष्ट्र होना अनिवार्य हो?

सयुक्त राज्य की दूर तक फैली सीमाओं के भीतर समशीतोष्ण कटिबन्ध के प्रायः सभी किस्म के मौसम पाये जाते हैं—गर्म, सर्द, नम, खुश्क और इनके बीच के। सब मिलाकर सयुक्तराज्य का जलवायु अन्य कई देशों के, उदाहरण के लिए पश्चिमी यूरोप के, अपेक्षाकृत हल्के जाड़ों और हल्की गर्मियों के मौसम के मुकाबले में, अधिक देर तक और अधिक कड़ी मेहनत का काम करने के लिहाज से अच्छा नहीं है। फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि उष्णकटिबन्ध के अनेक देशों की तुलना में वह कड़ी शारीरिक मेहनत करने के लिए अधिक अच्छा है। लेकिन मौसम के इस सामान्य प्रभाव को यदि छोड़ दिया जाय, तो अमेरिका का मौसम यहाँ की कृषि के लिए विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

कृषि के साधन

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि अमेरिका की कृषि की उत्पादकता इस समय बहुत ऊँची है, लेकिन इसका कारण यहाँ की भूमि का असाधारण तौर पर उपजाऊ होना और मौसम का अनुकूल होना है, यह एक गम्भीर सन्देह का विषय है।

अपने विकास के प्रारम्भिक युगों में तो अमेरिकी कृषि को उपजाऊ-

पन और अनुकूल मौसम के लाभ प्राप्त थे। उस समय सारा प्रदेश खुला था, खेती के लिए चाहे जितनी भूमि उपलब्ध हो सकती थी, जमीन उपजाऊ तत्वों से भरी हुई थी, क्योंकि उस पर पहले कभी खेती नहीं हुई थी, दूर-दूर तक घास के हरे-भरे मैदान और घने जंगल थे जो जमीन के भीतर नमी को कायम रखते थे और उसका क्षरण नहीं होने देते थे। उस समय वहाँ भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने की प्रवृत्ति ससार के अधिक सघन आबाद भागों की अपेक्षा कम थी। कारण, जब किसी एक जगह खेती करने पर जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो जाती तो किसान उसे छोड़कर नई जमीन पर खेती करने के लिए आगे बढ़ जाते। नई जमीन को खेती के लायक बनाने और उस पर नये सिरे से आबाद होने में खर्च भी अधिक नहीं पड़ता था। किसान के परिवार के पास यदि खेती के कुछ थोड़े-से सादे औजार, बीज और कड़ी मेहनत करने की आकांक्षा होती तो वह आसानी से अपना नया घर आबाद कर सकता था। लेकिन इस अच्छी और गहरी मिट्टी के बावजूद किसान अपने परिवार की अन्न-वस्त्र की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त अनाज और कपास आदि पैदा नहीं कर सकता था। उदाहरण के लिए सन् 1820 में संयुक्त राज्य में एक कृषि-मजदूर केवल चार ही व्यक्तियों की आवश्यकता के लिए उत्पादन कर सकता था।

लेकिन यह स्थिति बहुत पहले ही बदल चुकी है। आज एक कृषि-मजदूर लगभग तीस व्यक्तियों की अन्न-वस्त्र की आवश्यकताओं के लायक अनाज और कपास आदि पैदा कर लेता है। अच्छी कृषि-भूमि की कीमतें ऊँची हैं और बराबर चढ़ रही हैं और बड़े-बड़े फार्मों की आवश्यकता और आकांक्षा बढ़ती जा रही है। एक अमेरिकी को आज एक सफल कृषक बनने के लिए केवल जमीन खरीदने के लिए ही काफी पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खेती के यन्त्र, उत्कृष्ट किस्मों के बीज, अच्छी नस्ल के पशु, उर्वरक, कीटाणुनाशक दवाएँ, भूमि-संरक्षण और सिंचाई के साधनों पर भी काफी पैसा लगाने की जरूरत होती है। उनके उपयोग के लिए उसमें प्रवन्ध-सम्बन्धी और

तकनीकी योग्यता भी होनी चाहिए। अधिक उत्पादन की उसकी क्षमता बहुत हद तक दूसरे लोगो के काम पर भी निर्भर है—यानी वह रासायनिक पदार्थ, मशीनरी, विजली का सामान और ट्रैक्टर आदि आवश्यक वस्तुओं और औजारों के कारखानों में काम करने वालों, कृषि-उत्पादनों के अनुसन्धान-कर्त्ताओं एवं वितरकों और उसे हर समय नई उत्पादन-विधियों और तकनीकी पद्धतियों की जानकारी देते रहने वालों के काम के साथ बधी हुई है।

खासकर पिछले पच्चीस वर्षों में, कृषि सम्बन्धी उत्पादकता में काफी वृद्धि हुई है और उसका कारण फार्मों में काफी बड़ी मात्रा में धन का निवेश (इन्वेस्टमेंट) और तकनीकी विधियों में द्रुत गति से सुधार है। संयुक्त राज्य की अधिकांश फसलों में प्रति एकड़ उपज सन् 1940 से प्रारम्भ दशक के शुरू वर्षों की अपेक्षा आज अधिक है। प्रति एकड़ उपज में वृद्धि से भी अधिक महत्वपूर्ण प्रति कृषक उत्पादन में वृद्धि है। प्रति-मानव-घटा कृषि उत्पादन आज सन् 1940 की तुलना में तीन गुना और सन् 1929 की तुलना में लगभग चार गुना हो गया है। अमेरिका में कृषि-मजदूरों की संख्या सप्ताह के कुल मजदूरों की संख्या का 15 प्रतिशत है, किन्तु उसका कृषि-उत्पादन सप्ताह के कुल कृषि-उत्पादन का 16 प्रतिशत है। प्रति मानव उत्पादन, प्रति एकड़ उत्पादन, उपज की किस्म, फार्मों का विस्तार, उनमें किया गया पूंजी का निवेश, फार्मों के कर्मचारियों का जीवन-स्तर या किसी भी अन्य दृष्टि से तुलना करने पर मालूम यह होगा कि अमेरिकी कृषि में हाल के वर्षों में असाधारण परिवर्तन हुए हैं।

जहाँ एक ओर ये दूरगामी परिवर्तन होते रहे हैं, वहाँ अमेरिका की कृषि की एक बुनियादी विशेषता ज्यों की त्यों अपरिवर्तित रही है। अमेरिकी कृषि में पारिवारिक फार्मों का, जो वहाँ की एक परम्परागत वस्तु रही, अब भी प्रधान स्थान है। यह अमेरिका के लिए बहुत लाभकारी बात है, क्योंकि प्राइवेट पारिवारिक फार्मों में काम करने के ५ जितना प्रोत्साहन मिलता है, उतना और किसी भी प्रकार के

फार्मों में नहीं मिलता । इसी प्रकार नये-नये तकनीकी अनुसन्धान करने और उनसे लाभ उठाने की प्रवृत्ति भी अमेरिकी लोगों के लिए नई नहीं है । पिछले सौ वर्षों में अमेरिका की सघीय और राजकीय सरकारों ने कृषि-अनुसन्धान, कृषि-शिक्षा और कृषकों की कौशल-वृद्धि के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किये हैं । कृषकों और उनकी हर नई पीढ़ी को शिक्षा-प्राप्ति और शिक्षा सेवाओं के पहले से अधिक अवसर मिलते रहे हैं । उन्हें कृषि सम्बन्धी हाई स्कूलों, कालेजों और प्रयोग केन्द्रों में अध्ययन करने का और सरकारी विशेषज्ञों से तथा फार्मों से उपज खरीदने और उन्हें उनकी आवश्यकता की वस्तुएँ मुहैया करने वाले व्यापारियों की व्यक्तिगत सलाह से लाभ उठाने का मौका मिला है । वे फार्मों के सगठनों में भाग लेते हैं । उन्हें कृषि सम्बन्धी सभी कार्यों के विषय में कितनी ही पुस्तिकाएँ, पत्रिकाएँ और बुलेटिन आदि मुफ्त या नाममात्र के मूल्य पर वितरित किये जाते हैं । इन सभी चीजों ने पारिवारिक फार्मों की उत्पादकता और लाभकारिता बढ़ाने और उनसे कृषकों में सन्तोष पैदा करने में योग दिया है ।

इसमें सन्देह नहीं कि अब भी मौसम, जमीन और स्थलाकृति के कारण हर फार्म पर कुछ-न-कुछ प्रतिकूल असर पड़ता है और किसी-किसी वर्ष और किसी-किसी इलाके में यह असर बहुत अधिक प्रतिकूल भी होता है । फिर भी तीन अन्य कारण ऐसे हैं जो अमेरिकी कृषि की उत्पादकता को बढ़ाते हैं और उन पर इन प्राकृतिक विपर्ययों का बहुत असर नहीं पड़ता, क्योंकि इन कारणों का मौसम और भूमि की मूल उर्वरा शक्ति से सीधा सम्बन्ध नहीं है । ये तीन कारण हैं : पारिवारिक ढंग के फार्म; पारिवारिक ढंग के फार्मों का अपेक्षाकृत बड़ा होना; और इन पारिवारिक फार्मों में नई-नई तकनीकी विधियों का अधिकाधिक उपयोग और बहुत अधिक पूंजी का निवेश ।

संयुक्त राज्य की वर्तमान कृषि-पद्धति और उसके कृषकों के बारे में बहुत-से लोगों की धारणाएँ वास्तविकता से बहुत दूर हैं । कुछ लोग यह समझते हैं कि संयुक्त राज्य में कृषि का घन्घा बहुत सीधा-सादा है और कोई भी व्यक्ति बिना किसी विशेष प्रशिक्षण के और मामूली-सी

पूँजी से कृषि का धन्वा अपना सकता है। दूसरी ओर इससे ठीक उल्टा विचार रखने वाले लोग भी हैं जो यह समझते हैं कि यहाँ पारिवारिक फार्मों का अन्त हो रहा है और उनकी जगह बड़े-बड़े संयुक्त फार्म बन रहे हैं और उन्हीं के कारण यहाँ अन्न और कपास आदि का उत्पादन बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। ये दोनों सर्वथा परस्पर-विरोधी धारणाएँ सत्य से बहुत दूर हैं। अन्य देशों के लोगों में अमेरिकी-कृषि व्यवसाय के बारे में सही जानकारी न होने का एक कारण भी है। सन् 1959 की कृषि सम्बन्धी जनगणना में अमेरिका के 37 लाख फार्मों का जो विवरण दिया गया है, वह बहुत विविधतापूर्ण है। ये फार्म विस्तार की दृष्टि से एक एकड़ से लेकर दस हजार एकड़ तक की और वार्षिक उपज की बिक्री के लिहाज से पचास डालर से लेकर दस लाख डालर से भी अधिक तक की विविध श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं। इन फार्मों में पैदा होने वाली फसलों और पाले जाने वाले पशुओं में भी बड़ी विविधता है। इनमें यांत्रिक औजारों और भाड़े पर रखे जाने वाले मजदूरों के उपयोग की दृष्टि से ही नहीं और भी बहुत-सी दृष्टियों से असमानता और विविधता है।

सन् 1959 की जनगणना के विवरण में एक औसत अमेरिकी फार्म की तस्वीर मिलती है। और साथ ही आर्थिक दृष्टि से उनका वर्गीकरण करके उनका परस्पर एक-दूसरे से अन्तर भी बताया गया है। पहला अन्तर यह है कि कुछ फार्म 'व्यापारिक' हैं और कुछ नहीं हैं। व्यापारिक फार्म वे हैं जो सारे समय चलने वाले फार्म हैं और आर्थिक दृष्टि से उन्हें छ वर्गों में बाँटा गया है। छोटे-से-छोटे फार्म की वार्षिक उपज की बिक्री 50 डालर और बड़े फार्मों की अधिकतम वार्षिक उपज की बिक्री 40 हजार डालर या इस से भी अधिक है। 'व्यापारिक' श्रेणी में न आने वाले फार्म वे हैं जिनमें सारे वर्ष काम नहीं होता अथवा जो लोगों ने अपने निवासस्थानों पर ही बनाये हुए हैं। इन फार्मों के मालिक वर्ष में 100 या इससे भी अधिक दिन फार्मों से बाहर काम करते हैं और उनकी फार्मों से बाहर के काम की आमदनी फार्मों की आमदनी से अधिक है। इस श्रेणी में ऐसे फार्म भी आते हैं जिनके मालिकों की आयु

65 वर्ष से अधिक होती है और उनके वार्षिक उत्पादन की बिक्री 2500 डालर से अधिक नहीं होती ।

सन् 1959 में सारे वर्ष चलने वाले व्यापारिक फार्मों में से 80 प्रतिशत की वार्षिक उत्पादन की बिक्री 2500 डालर से 40,000 डालर तक थी, जबकि तमाम व्यापारिक फार्मों में से कुल 4 प्रतिशत ही ऐसे थे जिनकी वार्षिक उपज की बिक्री 40,000 डालर से अधिक थी । फिर भी इन चार प्रतिशत बड़े फार्मों के वार्षिक उत्पादन की बिक्री संयुक्त राज्य के कुल कृषि-उत्पादन का एक चौथाई थी ।

यदि एक औसत अमेरिकी व्यापारिक फार्म की तस्वीर खींची जाय तो वह इस प्रकार होगी कृषक परिवार के पास 320 एकड़ के लगभग भूमि होगी जिसमें से 40 प्रतिशत में फसल बोयी जाती होगी उसकी 33,000 डालर की पूंजी जमीन और फार्म की इमारतों में, 4,000 डालर की मशीनरी में और 3,600 डालर की पशुओं में लगी हुई होगी । मशीनों और मजदूरों को भाड़े पर रखने में उसका 1,000 डालर और व्यय होगा । और इसके बाद उसके वार्षिक उत्पादन का विक्रय मूल्य 7,500 डालर होगा ।

इस औसत दर्जे के फार्म में बिजली और बहते पानी का उपयोग न केवल उसके कामों को अधिक सुचारु ढंग से चलाने में सहायक होता है, बल्कि कृषक परिवार के घरेलू काम भी उससे अधिक अच्छी तरह हो सकते हैं, परिवार के लोग अधिक स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं और उन्हें विश्राम का समय भी अधिक मिलता है (अमेरिका के 97 प्रतिशत से अधिक फार्म बिजली का उपयोग करते हैं) टेलीफोन और रेडियो उन्हें पत्र-पत्रिकाओं में छपने वाले समाचारों और अन्य ज्ञातव्य बातों की जानकारी देते रहते हैं । यदि कोई टेलीविजन स्टेशन आसपास हो तो कृषक-परिवार की बैठक में एक टेलीविजन सैट भी होता है । संचार और परिवहन के साधनों में सुधार के कारण कृषक बाजारों के रुख के अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर सकता है । कृषक परिवार के पास वाहन होने से उसके सदस्य शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सामाजिक अवसरों का अधिक लाभ उठा सकते हैं ।

औसत अमेरिकी फार्म का वर्णन करने से भी अधिक कठिन काम यूरोप या एशिया के औसत फार्मों के साथ उसकी तुलना करना है। ससार के अन्य भागों में एक कृषक परिवार के पास अपेक्षाकृत कम कृषि योग्य भूमि होती है। उदाहरण के लिए, बेल्जियम में मोटे तौर पर तीन चौथाई फार्म २.५ एकड़ से भी कम भूमि वाले हैं। फार्म इतने छोटे होने पर उनके काम में बहुत कुशलता नहीं आ सकती और न मशीनरी का अधिक उपयोग हो सकता है। लेकिन फार्म छोटे होने के कारण इनमें कृषक परिवार अधिक उत्पादन के लिए सघन कृषि करता है। यही कारण है कि अमेरिका में कुछ फसलों का प्रति एकड़ उत्पादन ससार के अन्य भागों के प्रति एकड़ उत्पादन की तुलना में कम है। इसलिए यह सम्भव है कि विभिन्न देशों के फार्मों के औसत परिमाणों की तुलना से सयुक्त राज्य और अन्य अनेक देशों के पारिवारिक फार्मों की विशेषताओं की सही तुलना न हो सके।

कुछ फार्म इतने बड़े होते हैं कि उनमें मजदूरी पर मजदूर रखने पड़ते हैं और यह देखा गया है कि कुछ किस्मों के फार्म उत्पादन में स्वयं परिवार के लोगों द्वारा किये जाने वाले श्रम की अपेक्षा मजदूरों का यह श्रम कम कुशल होता है। किन्तु फिर भी सयुक्त राज्य में अधिकतर बड़े पारिवारिक फार्म भी उन्नत कृषि विधियों और साधनों के कारण बाहर के बहुत कम मजदूर रखकर स्वयं परिवार के सदस्यों द्वारा ही चलाये जा सकते हैं। फार्मों में श्रम की बचत करने वाले साधनों के अधिकाधिक उपयोग से यह मालूम हो जाता है कि किस प्रकार अमेरिकी पारिवारिक फार्म का संचालन मानवीय हस्त-श्रम की गतिविधि के बजाय एक तकनीकी गतिविधि बन गया है। उदाहरण के लिए सन् 1959 में 75 प्रतिशत व्यापारिक फार्मों में ट्रैक्टर और 59 प्रतिशत में मोटर-ट्रैक्टर इस्तेमाल होते थे। यही बात इस प्रकार भी समझी जा सकती है कि फार्मों में 1959 में 30 लाख घोड़े या खच्चर थे, जबकि 1920 में उनकी संख्या 250 लाख थी।

तालिका 1

कृषि जोतो का परिणाम और वर्गीकरण—1950

देश	औसत कृषि जोत (हैक्टेयरों में)	एक हैक्टेयर से कम की जोते (प्रतिशत)	दस हैक्टेयर से कम की जोते (प्रति- शत)
संयुक्त राज्य अमेरिका	122 3	1 ¹	28 ⁴
बेल्जियम	1 9	75	95
कनाडा	113 1	2	4 ⁵
कोस्टारिका	42 1	अनुपलब्ध	54
डेनमार्क	17 5	1	46
एल साल्वेडोर	8 8	40	89
फिनलैंड	33 3	44 ³	84
पश्चिमी जर्मनी	10 9	14	76
होण्डुरास	16 1	10	75
जापान	1 6	67	99.5
नीदरलैंड्स	5 7	41	82
नार्वे	20 2	46	94
फिलिपाइन	3 5	19	94
उरुग्वे	199.7	अनुपलब्ध	26

सन् 1950 और 1959 के बीच व्यापारिक फार्मों में ग्रेन कम्बाइन मशीनें 47 प्रतिशत और कॉर्न पिकर मशीनें 75 प्रतिशत बढ़ी। इसी प्रकार दूध दुहने, गांठे बाँधने, फसल काटने आदि की मशीनें भी काफी

1. 1.2 हैक्टेयर से कम की जोतें। (हैक्टेयर—2.47 एकड़)
2. .5 प्रतिशत से कम।
3. 2 हैक्टेयर से कम की जोतें।
4. 11.7 हैक्टेयर से कम की जोतें।
5. 4 हैक्टेयर से कम की जोतें।

बढ़ी। इस प्रकार फार्मों में कृषि के अधिकाधिक यान्त्रिकीकरण से खेती के लिए मजदूरों की आवश्यकता कम हो गई है और वे निर्माण-उद्योगों और सेवा-व्यवसायों में काम कर सकते हैं।

तालिका 2

संयुक्त राज्य में फार्मों की संख्या में परिवर्तन की निर्देशिका

वर्ग	1930	1940	1950	1959
कुल फार्म	100	97	86	59
व्यापारिक फार्म	100	89	70	46
बड़े ¹ (पहले वर्ग के)	100	93	80	80
मध्यम ² (दूसरे वर्ग से पाँचवे वर्ग तक के)	100	85	66	45
छोटे ³ (छठे वर्ग के जिनकी वार्षिक बिक्री 250 डालर से 1200 डालर तक है)	100	110	89	47
गैर-व्यापारिक फार्म (कुछ समय चलने वाले या घरों पर स्थापित)	100	137	166	130

पिछले 25 वर्षों में फार्मों की उत्पादकता में वृद्धि होती रही है, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई है पर संख्या में कमी होने से भी जोत-भूमि में कमी नहीं हुई। इसका अर्थ यह है, कि कुछ लोग कृषि का धन्धा छोड़कर दूसरे कामों में लग गए और उनकी जमीनें बड़े फार्मों ने उनसे लेकर अपनी जमीनों में मिला ली। सन् 1959 से पूर्व 25 हजार डालर से कम वार्षिक बिक्री वाले फार्मों की और 1959

* 1959 की और उससे पहले के वर्षों की परिभाषाएं एक-सी नहीं हैं।

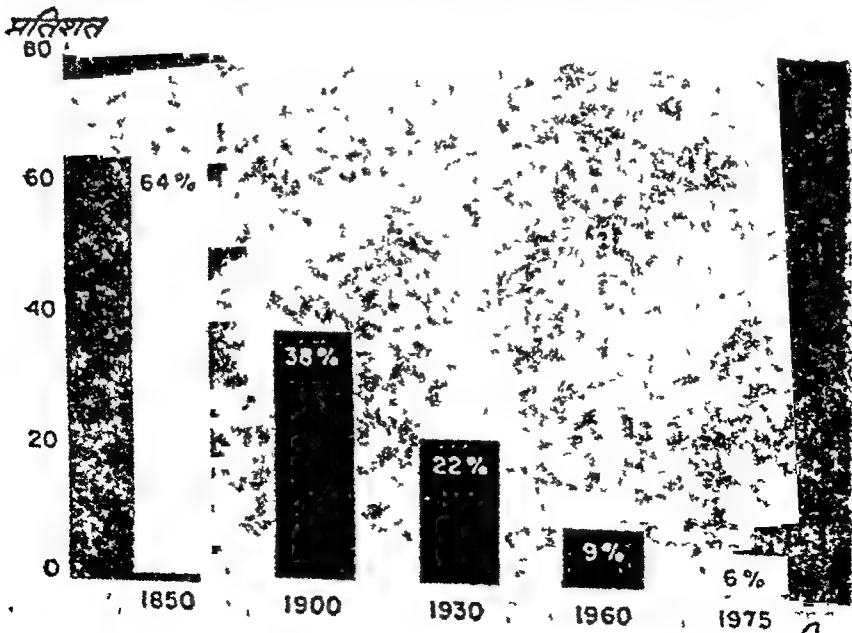
- 1 25 हजार डालर या अधिक की वार्षिक बिक्री (1959 में 40 हजार या अधिक की)
- 2 1200 से 25 हजार डालर तक की वार्षिक बिक्री (1959 में 2500 से 40 हजार डालर तक की)।
- 3 250 से 1200 डालर तक की वार्षिक बिक्री (1959 में 50 डालर से 2500 डालर तक की)।

में 40,000 डालर से कम वार्षिक बिक्री वाले फार्मों की संख्या बहुत तेजी से गिरी है। फिर भी बड़े पैमाने पर काम करने वाले फार्मों की संख्या में उतनी तेजी से कमी नहीं आयी, हालांकि इनमें ऐसे फार्मों की संख्या बहुत कम है जो बड़ी-बड़ी कंपनियों या वेतन-भोगी प्रबन्धकों द्वारा चलाये जाते हैं और यह एक महत्वपूर्ण बात है।

अमेरिका में कृषि की उत्पादकता निरन्तर बढ़ रही है, अतः यह आशा है कि फार्मों में कृषि-मजदूरों की संख्या कम हो जाने पर भी कुल कृषि-उत्पादन में वृद्धि ही होगी। कृषि सम्बन्धी रोजगारों का महत्त्व 1860 के दशक के गृह-युद्ध से पूर्व ही कम होने लगा था और अब बीसवीं शताब्दी में भी यही स्थिति है। पिछले बीस वर्षों में यद्यपि कृषि उत्पादन ढ्योढ़े से भी अधिक हो गया है तो भी फार्मों में रोजगार पर लगे कृषि-मजदूरों की संख्या 35 प्रतिशत घट गई है और यह सम्भावना है कि वह भविष्य में और भी घटेगी। हालांकि संयुक्त राज्य की आबादी बढ़ने से अन्न की माँग बढ़ेगी तो भी आशा यही है कि इस संख्या में निरन्तर कमी होगी। कारण यह है कि अगले एक दशक में,

चार्ट 7

फार्मों में काम करने वाले श्रमिकों का प्रतिशत अनुपात



कम से कम कुछ मुख्य पदार्थों के बारे में कृषि की उत्पादकता देश की आन्तरिक माँग से ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त माँग में होने वाली अधिकतर वृद्धि ऊँचे दर्जे के खाद्य पदार्थों की माँग में होगी। इसलिए इन पदार्थों को तैयार करने, डिब्बों में बन्द करने और वितरण करने के लिए जरूर अतिरिक्त श्रमिकों की आवश्यकता होगी, किंतु कृषि के काम के लिए नहीं। इस प्रकार फार्मों में काम करने वाले लोगों की प्रतिशतता में भी कमी की सम्भावना है।

यद्यपि अमेरिका में कृषि से भिन्न व्यवसायों की उत्पादकता की अपेक्षा कृषि व्यवसाय की उत्पादकता का स्तर नीचा है, फिर भी अमेरिकी फार्मों में काम करने वाले व्यक्तियों की उत्पादकता हमारी अपनी आन्तरिक माँग से अधिक है। यह एक विचित्र तथ्य है कि अमेरिका जैसे अत्यधिक उद्योग-सम्पन्न देश में, कृषि उत्पादन भी अपनी आवश्यकता से इतना अधिक होता हो कि वह उसका दस प्रतिशत निर्यात के लिए निकाल सके। कृषि-उत्पादन की यह ऊँची सामर्थ्य दोनों विश्व-युद्धों के बाद विशेष रूप से उपयोगी और महत्वपूर्ण सिद्ध हुई, क्योंकि युद्ध के कारण ससार के अनेक भागों में खाद्य पदार्थों की बहुत कमी हो गई थी। यदि ससार की आबादी बढ़ने से अति सघन आबादी वाले किसी देश में अन्न की कमी गम्भीर समस्याएँ पैदा कर दे तब अमेरिका की इस ऊँची उत्पादकता का महत्व भविष्य में भी बना रहेगा। संयुक्त राज्य का 'शान्ति के लिए अन्न' कार्यक्रम इस समस्या के समाधान के लिए ही बना है।

इस प्रकार संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी कृषि का उत्पादकता का स्तर इतना ऊँचा होने का कारण यहाँ का असाधारण रूप से अनुकूल मौसम या असाधारण तौर पर उर्वरा भूमि ही नहीं है, बल्कि इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ के अपेक्षाकृत बड़े पारिवारिक ढंग के फार्मों में प्रति व्यक्ति उत्पादन का स्तर ऊँचा है, और यह ऊँचा स्तर अनेक कारणों के सम्मिश्रण का परिणाम है—जैसे कि हर व्यक्ति का अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहकर अधिक श्रम करना, तकनीकीज्ञान, ऊपरी देखरेख पर कम व्यय और बहुत बड़े पैमाने पर यान्त्रिकीकरण।

खनिज सम्पदा

सयुक्त राज्य को जिस विशाल ऐतिहासिक विकास ने ससार का सबसे अग्रणी औद्योगिक राष्ट्र बना दिया है, उसमें उसकी कोयला, तेल और अन्य खनिज सम्पदाओं एवं जल और लकड़ी आदि प्राकृतिक साधनों के प्राचुर्य ने महत्वपूर्ण योग दिया है। लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर बाकी प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से यह स्थिति अब बदल गई है। अब अमेरिका के उद्योगों में केवल देश के भीतर उत्पन्न कच्चे माल की ही भारी माँग नहीं है, बल्कि वे अन्य देशों में भी यह माल मगाते हैं। इस स्थिति का एक परिणाम यह भी हुआ कि अमेरिका में अब ऐसी कृत्रिम वस्तुओं की शोध करने और उन्हें तैयार करने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया जा रहा है, जो प्राकृतिक वस्तुओं का स्थान ले सकें। ये वस्तुएँ प्रभूत मात्रा में पाई जाती हैं और उन्हें कुछ प्रक्रियाओं की सहायता में अधिक बेहतर उपयोग के लायक बनाया जा सकता है।

विभिन्न कच्ची सामग्रियों को उपयोगी वस्तुओं में परिणत करने में सहायता देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक यह है कि अमेरिका में मन्नी शक्ति (एनर्जी) पैदा करने वाले अनेक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनमें से कोयला। सयुक्त राज्य में कोयला एक ऐसी महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री है जिसका प्राकृतिक भण्डार अब भी उसकी माँग में काफी कम है। देश के दक्की में ईंधन के रूप में कोयले की माँग में वृद्धि जिस प्रकार से होती रही है, यदि वही स्तर भविष्य में भी जारी रहे तो भी सयुक्त राज्य में कोयला मौ रफ़ या खनने की शक्ति सम्भवतः पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा, भले ही उसका उत्पादन-प्रणाली बदल जाय। एक अन्य सयुक्त राज्य में कोयले का वैकल्पिक उत्पादन प्रणाली है वह उत्पादन का तेल जिसका है, अब कि हमारा कोयले का वैकल्पिक उत्पादन प्रणाली है कोयले के कुछ प्राकृतिक भण्डार का परीक्षण है।

सयुक्त राज्य में कोयले के उत्पादन की मात्रा में बहुत बड़ी-बड़ी वृद्धि हो चुकी है। इसका कारण है कि कोयला (विद्युति-

नस कोल) जमीन के नीचे एक हजार फुट से कम की गहराई में ही मिल जाता है, जब कि ब्रिटेन और जापान में वह इससे भी कहीं अधिक नीचे जाकर मिलता है और कुछ खानें तो चार हजार से पाँच हजार फुट तक गहरी हैं। इसके अलावा अमेरिका के कोयले के उत्पादन का लगभग एक तिहाई भाग तो जमीन की ऊपरी तह में ही प्राप्त हो जाता है, जिसके लिए जमीन के नीचे खुदाई का काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रकृति के इन लाभों एवं खानों की ऊँची उत्पादकता के कारण संयुक्त राज्य के अनेक हिस्सों में उद्योगों को बहुत-से अन्य देशों की तुलना में सस्ता ईंधन प्राप्त हो जाता है।

किन्तु जब हम संयुक्त राज्य में निर्मित वस्तुओं के कुल उत्पादन व्यय को दृष्टि में रखकर विचार करते हैं तो संयुक्त राज्य में कोयले के सस्तेपन का लाभ, अपने आप में काफी बड़ा होने पर भी, बहुत बड़ा प्रतीत नहीं होता। वस्तुओं के उत्पादन-व्यय में अन्य कच्चे माल, श्रम, प्रबन्ध और पूंजी का भी हिस्सा होता है और उन सब पर विचार करना पड़ता है। निर्माण-उद्योगों में एक औसत वस्तु को तैयार करने में ईंधन का खर्च मोटे तौर पर चार प्रतिशत होता है। लेकिन जिन उद्योगों में ताप या पावर का इस्तेमाल बहुत अधिक होता है, उनमें ईंधन पर व्यय अधिक होना स्वाभाविक है। इसके अलावा और अधिक औद्योगिक विकास के लिए शक्ति के सस्ते स्रोतों की उपलब्धि का महत्व अधिकाधिक बढ़ना सम्भव है। ससार की जनसंख्या जैसे-जैसे बढ़ती जाती है और औद्योगिक उन्नति अधिकाधिक हो रही है, वैसे-वैसे हमारी पृथ्वी के कच्चे माल के प्राकृतिक स्रोतों का अधिकाधिक दोहन किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप अब ऐसी कच्ची सामग्रियों का इस्तेमाल जरूरी हो गया है जो कम आसानी से उपलब्ध होती है या घटिया श्रेणी की है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक कच्चे माल की जगह पर इस्तेमाल करने के लिए कृत्रिम वस्तुओं का भी धीरे-धीरे विकास किया जा रहा है। घटिया किस्म के प्राकृतिक कच्चे माल को इस्तेमाल करके सुधारने और कृत्रिम कच्चा माल तैयार करने के परिणामस्वरूप प्रति उत्पादित

प्राकृतिक साधन

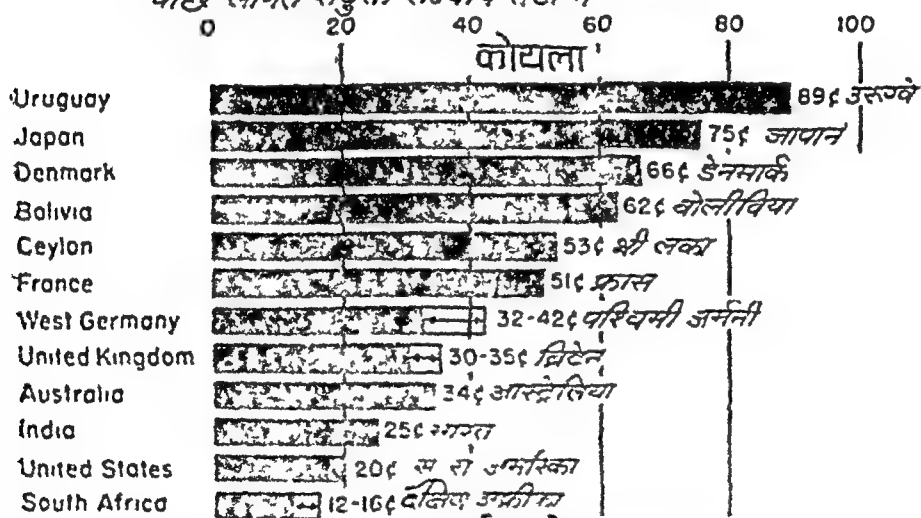
वस्तु पर शक्ति (एनर्जी) का औसत व्यय अधिक बढ़ गया है।

कोयला एवं बहुत-सी कृषि-जन्य कच्ची सामग्रियों को छोड़कर, शेष प्राकृतिक कच्ची सामग्रियों की खपत देश के आन्तरिक उत्पादन से अधिक बढ़ गई है और भविष्य में वह और भी बढ़ेगी। पचास वर्ष पूर्व यह स्थिति थी कि संयुक्त राज्य की कृषि-जन्य वस्तुओं से भिन्न 15 प्रतिशत प्राकृतिक कच्ची सामग्रियाँ अन्य देशों को निर्यात की जाती

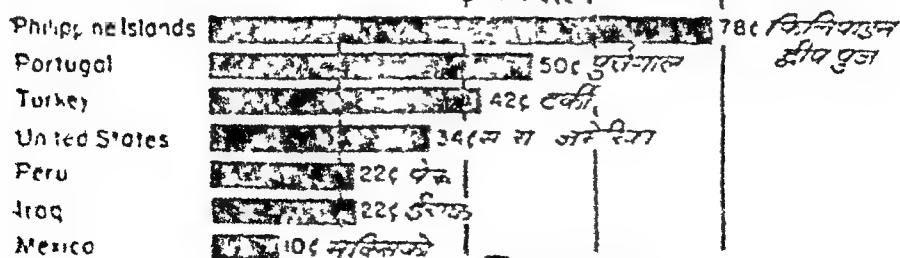
चार्ट 8

कुछ चुने हुए देशों में ईंधन की लागत

प्रति दस लाख ब्रिटिश तापीय इकाई
पीछे लागत संयुक्त राज्यीय सेटो में



ईंधन तेल



प्राकृतिक गैस

United States 4

थी। आज यह प्रतिशत आधी रह गई है और बहुत-सी कच्ची सामग्रियों का काफी मात्रा में आयात आवश्यक हो गया है और वह निरन्तर बढ़ रहा है। अमेरिकी उद्योगों ने हाल के वर्षों में कृषि-जन्य वस्तुओं और सोने को छोड़कर अपनी शेष कच्ची सामग्रियों का 10 प्रतिशत अन्य देशों से आयात किया है और यह अनुमान किया जाता है कि अगले बीस वर्षों में विदेशी कच्चे माल पर यह निर्भरता बढ़ती ही जाएगी। ऐसी कच्ची सामग्रियों की सूची बहुत बड़ी है, जिनकी मयुक्त राज्य में होने वाली उपलब्धि का 50 प्रतिशत अन्य देशों से आयात करना पड़ता है। इस सूची में से कुछ वस्तुएँ पृष्ठ 37 पर तालिका 3 में दी गई हैं।

एक और प्राकृतिक सम्पदा, जो पहले सयुक्त राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, अब चिन्ता का विषय बन गई है। इस समय सिंचाई और व्यक्तिगत एवं औद्योगिक कामों के लिए पानी का जिस गति से उपयोग किया जा रहा है, उसे भविष्य में सयुक्त राज्य की निरन्तर विस्तृत हो रही अर्थ-व्यवस्था में तब तक कायम नहीं रखा जा सकेगा, जब तक कि उसके उत्पादन और अधिक उचित उपयोग के लिए बेहतर व्यवस्था न कर ली जाय। इसके लिए काफी बड़ी मात्रा में धन लगाकर ऐसी व्यवस्थाएँ करनी पड़ेंगी, जिनसे एक बार प्रयुक्त किये गए पानी को इकट्ठा कर और वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से सुधार कर पुनः प्रयोग के लायक बनाया जा सके। यही नहीं, पानी को दूर-दूर तक पहुँचाने का प्रबन्ध और भविष्य में आगे चलकर समुद्र के खारी और नमकीन पानी को नमक-रहित करके उपयोग में लाने की व्यवस्था की भी जरूरत होगी। पानी की उपलब्धि और समुचित उपयोग की समस्या पर सयुक्त राज्य में अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा है।

ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो अमेरिका के विविध और प्रचुर प्राकृतिक साधनों ने अतीत में बहुत-से आव्रजकों को अमेरिका के तट की ओर आकृष्ट किया है और इन प्राकृतिक साधन-सम्पदाओं ने अमेरिका के द्रुत आर्थिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण योग भी दिया है। सयुक्त

तालिका 3

संयुक्त राज्य में उपलब्ध कुछ कच्ची सामग्रियों का अन्य देशों से आयातित प्रतिशत भाग—1959

कच्ची सामग्री	प्रतिशत	कच्ची सामग्री	प्रतिशत
खाद्य पदार्थ		लकड़ी और कागज	
केला	100	कच्चा कार्क	100
कहवा (काँफी)	100	अखवारो कागज	73
चाय	100	अलौह खनिज और धातुएँ	
दूधना मछली	61	रागा (टीन)	100
कच्चा रबड़, गोद, बिरोजा		निकल	91
लाख और चपड़ा	100	वाँक्साइट और एल्युमीनियम	84
प्राकृतिक रबड़	100	सीसा	61
वानस्पतिक उत्पादन		जस्त	57
नारियल और नारियल का तेल	100	अधात्विक खनिज	
बवेब्रैको का सत	100	ग्रभ्रक	95
गुल्म-रेखा		ऐस्बेस्टस	94
पूट (पटंगन)	100	पलोरस्पार	75
बच्चा रेगम	100	लौह धातुएँ और खनिज	
मीनन और मैनिता	100	क्रोम ¹	90
कच्ची डन	57	मैंगनीज खनिज	87
अधिकतम देश की रई	52	टारटन	61

1. 1958 के लिये

राज्य में औद्योगिकीकरण का जो उफान आया उसने प्रकृति के इस अक्षय भण्डार का नई-नई वस्तुएँ तैयार करने और यहाँ के निवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के लिए उपयोग किया। लेकिन इन प्राकृतिक साधनों से सम्पन्न होने पर भी, अमेरिकी उद्योग अन्य देशों की तुलना में अब अधिक अच्छी और लाभ की स्थितियों में नहीं हैं, क्योंकि कोयले को छोड़कर शेष सब प्राकृतिक साधनों का भण्डार धीरे-धीरे क्षीण होता जा रहा है। जैसे-जैसे सारे ससार में प्रति व्यक्ति उपभोग का स्तर ऊँचा होता जाएगा, वैसे-वैसे कच्चे माल की माँग भी बढ़ती जाएगी। अगर यह आशा न हो कि कुछ दुर्लभ खनिज पदार्थों की कमी की पूर्ति उनके स्थान पर उपयोग के लिए नये पदार्थ खोजकर कर ली जाएगी तो कुछ महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्ची सामग्रियों की भविष्य में उपलब्धि की स्थिति वास्तव में ही बहुत निराशापूर्ण हो जाएगी।

सारांश

यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का उत्पन्नता का स्तर ऊँचा होने का मुख्य कारण मौसम का अनुकूल होना, जमीन का असाधारण तोर पर उपजाऊ होना या खनिज और अन्य कृषि-भिन्न प्राकृतिक सम्पदाओं का प्राचुर्य नहीं है। प्राकृतिक साधनों का प्राचुर्य सहायता अवश्य करता है, किन्तु अकेला नहीं, अन्य कारक तत्वों के साथ मिलकर।

श्रम

जनता ही किसी राष्ट्र की सब से बड़ी आर्थिक सम्पत्ति होती है। प्राकृतिक साधन-सम्पदा के प्राचुर्य का अपने आप में कोई अर्थ नहीं, जनता के साथ मिलकर ही उस का कुछ अर्थ होता है। किसी देश की उन्नति और विकास तभी अधिक सम्भव है, जबकि उस देश की जन-शक्ति और प्राकृतिक साधनों का परस्पर समन्वय और सतुलन के साथ विकास किया जाय।

सयुक्त राज्य इस लिहाज से भाग्यशाली है कि उसे प्रकृति ने अपनी वटती हुई जन-संख्या के पालन-पोषण के लिए साधन-सम्पदा प्रदान की है। औद्योगिक विकास ने जैसे-जैसे रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध किये, वैसे-वैसे ससार के अन्य भागों से अधिकाधिक लोग इस नये देश में अपने श्रम और कौशल अर्पित करने के लिए आने लगे। इस प्रकार एक ओर श्रमिक शक्ति की वृद्धि ने और दूसरी ओर प्राकृतिक साधन-सम्पदा और उद्योगों के विकास ने मिलकर सयुक्त राज्य में प्रति व्यक्ति आय का ऊँचा स्तर स्थापित करने में योगदान किया।

तालिका 4

आबादी की घनता और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय

देश	आबादी की घनता ¹	प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय (अमेरिकी डालरो में)
संयुक्त राज्य अमेरिका ²	48	2,722
कनाडा	5	1,983
स्विटजरलैंड	324	1,510
ऑस्ट्रेलिया	3	1,424
ब्रिटेन	547	1,272
फ्रांस	209	1,146
पश्चिमी जर्मनी	543	1,140
नीदरलैंड्स	893	898
इटली	417	578
दक्षिण अफ्रीका	30	412
न्यूवा	148	389
जापान	641	375
मैक्सिको	43	293
ब्राजील	20	210
टर्की	87	167
फिलिपाइन	209	166
श्रीलंका	375	131
नाइजीरिया	96	79
भारत	314	74
बर्मा	77	53

1 प्रति वर्गमील आबादी (1959 में) ।

2 अलास्का और हवाई भी सम्मिलित है ।

का ऊँचा स्तर मुख्यतः उनकी अन्य देशों से आयातित कच्चे माल से तैयार माल बनाने की क्षमता का परिणाम है। और इस तैयार माल का बड़ा भाग उन्हें फिर अन्य देशों को निर्यात करना पड़ता है।

श्रमशक्ति की रचना

संयुक्त राज्य की जनसंख्या इस समय 18 करोड़ 20 लाख है और हाल के वर्षों में वह 1.8 प्रतिशत वार्षिक की रफ्तार से बढ़ती रही है। सन् 1960 में संयुक्त राज्य की सक्रिय असैनिक श्रम शक्ति (श्रम जीवियों की संख्या) 7 करोड़ 20 लाख थी, जिनमें से लगभग 4 करोड़ 70 लाख पुरुष और 2 करोड़ 50 लाख स्त्रियाँ थी। इस असैनिक मानव शक्ति का लगभग 25 प्रतिशत निर्माण उद्योगों में, 20 प्रतिशत वितरण, थोक और खुदरा व्यापार में, लगभग 10 प्रतिशत कृषि में, लगभग 15 प्रतिशत सरकारी सेवाओं में और करीब 30 प्रतिशत खानों, भवन आदि के निर्माण और अन्य धंधों में लगा हुआ है।

यद्यपि श्रमजीवी वर्ग में 16 वर्ष से लेकर 65 वर्ष से भी ऊपर की आयु तक के लोग हैं, फिर भी अधिक बड़ी संख्या 20 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के लोगों की है। बाल-श्रम (बच्चों से मजदूरी कराना) की बुराई का संयुक्त राज्य में एक प्रकार से खात्मा कर दिया गया है। यह केवल बाल-श्रम विरोधी कानूनों का ही परिणाम नहीं, बल्कि अधिकतर राज्यों में इस आशय के नियम बनने का भी परिणाम है कि 15 या 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को नियमित रूप से स्कूल में उपस्थित होना होगा। इस प्रकार 15 या 16 वर्ष तक की आयु के बच्चे स्कूलों में पढ़ाई के दिनों में केवल अश-कालिक श्रम कर सकते हैं। उनके लिए पूरे समय काम करना गर्मियों की छुट्टियों के दिनों में ही सम्भव है। श्रमजीवियों की उम्र के पैमाने में जो लोग सबसे ऊपर आते हैं, यानी बूढ़े हैं, उन्हें बुढ़ापे की पेन्शन और व्यक्तिगत सुरक्षा की पहले से अधिक सुविधाएँ दी जाती हैं, जिनमें वृद्धावस्था की सहायता, पेन्शन योजनाएँ और प्राइवेट बीमा आदि शामिल हैं। इनका परिणाम

यह होता है कि बहुत-से श्रमजीवी अधिक उम्र हो जाने पर स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन इसके विपरीत कुछ अधिक उम्र के व्यक्ति, यह अनुभव करते हैं कि बुढ़ापे में सहायता देने की ये सब योजनाएँ उन्हें काम के अवसरो से वंचित करती हैं, हालांकि उनका स्वास्थ्य इतना अच्छा होता है कि वे काम करते रह सकें। यद्यपि चिकित्सा विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप आज आदमी में पहले से अधिक लम्बी आयु तक अशकालिक (पार्ट टाइम) या पूर्णकालिक (फुल टाइम) काम करने की क्षमता आ गई है, फिर भी अमेरिका की श्रम सम्बन्धी व्यवस्थाओं में उसके अनुरूप परिवर्तन नहीं किया गया है तथापि श्रमजीवी वर्ग में स्त्रियों की, खासकर अधिक आयु की विवाहित स्त्रियों की, सख्या काफी बढ़ गई है।

अमेरिका के श्रमजीवी वर्ग की एक बड़ी विशेषता उसकी बहुजातीय विविधता है। प्रारम्भ में अमेरिका की आबादी अन्य महाद्वीपों से यहाँ आकर बसे लोगों की थी। उसके बाद भी उसका एक खासा भाग बाहर से आकर बसे लोगों और उनके वीवी-बच्चों का रहा है। यद्यपि सन् 1920 के दशक से कानून बनाकर अमेरिका में बाहर से बड़े पैमाने पर आप्रवासियों के आगमन को रोक दिया गया है, फिर भी सन् 1950 की जन-गणना में यह देखा गया कि संयुक्त राज्य की कुल गोरी आबादी की चौथाई सख्या बाहर से आकर बसे लोगों और इनके अमेरिका में उत्पन्न बच्चों की थी। इसी तरह इस जन गणना में संयुक्त राज्य की कुल गोरी श्रमिक सख्या का तिहाई ऐसे ही आप्रवासी लोगों का था (देखिए परिशिष्ट तालिका 9)। यद्यपि आबादी की यह बहुजातीय विविधता संयुक्त राज्य की ही विशिष्टता नहीं है, तथापि यहाँ के आर्थिक विकास में उसका योग महत्वपूर्ण रहा है। भिन्न-भिन्न देशों और भिन्न-भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों से आये आप्रवासी लोगों के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार की योग्यताएँ और हुनर आये। यही नहीं, ये लोग एक नई दुनिया में अपने लिए जगह बनाने का हठ सकल्प भी कर आये।

अमेरिकी श्रम शक्ति की एक और विशेषता भी है जो उसकी

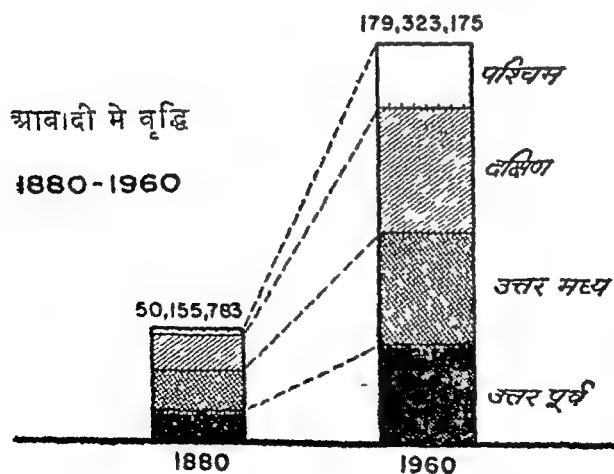
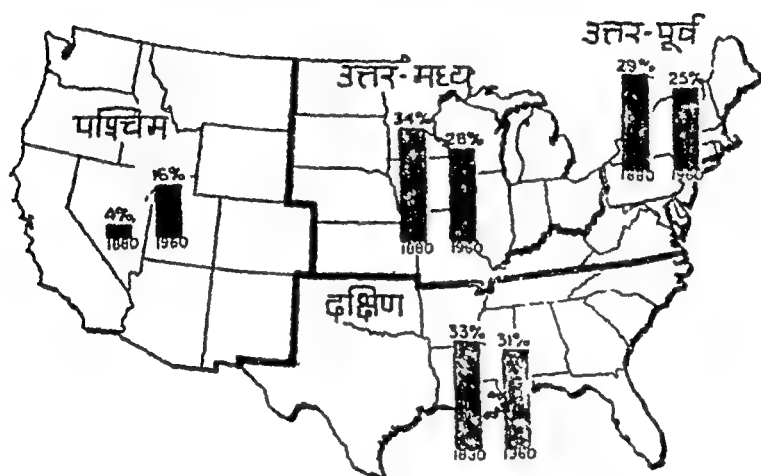
उत्पादकता को बहुत बढ़ाती है। यह विशेषता है संयुक्त राज्य का भौगोलिक दृष्टि से बहुत विस्तृत होना और उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के एक विशाल भाग में फैला होना। यदि एक व्यक्ति न्यूयार्क से सानफ्रांसिस्को तक यात्रा करे तो 2,500 मील का लम्बा सफर करने पर भी उसे कहीं संयुक्त राज्य की राष्ट्रीय सीमा को लाघना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यूरोप में उसे लिस्बन से मास्को तक इतना ही लम्बा सफर करना पड़े तो उसे सात राष्ट्रों की सीमाओं को पार करना होगा, आठ तरह की मुद्राओं का उपयोग करना पड़ेगा। आज के जमाने में उसे एक 'लौह-आवरण' को भी भेदना पड़ेगा।

महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक संयुक्त राज्य के बसे होने का परिणाम यह है कि उसके निवासी और श्रमजीवी वे-रोकटोक डघर से उधर आ-जा सकते हैं, जब कि यूरोप में यह बात इतनी आसान नहीं रही। इसका एक और लाभ यह हुआ कि जैसे-जैसे आबादी की वृद्धि और अर्थ-व्यवस्था का विकास हुआ, वैसे-वैसे लोगों को फैलने के लिए नये-नये इलाके मिलते रहे। यूरोप में पिछले दस वर्षों में विभिन्न देशों की आबादियों के घटने-बढ़ने का मुख्य कारण पूर्वी यूरोपीय देशों की आबादियों में हुई स्वाभाविक वृद्धि और उनका एक देश से दूसरे देश में जाना था, जबकि संयुक्त राज्य के विभिन्न घटक राज्यों में आबादियों के घटने-बढ़ने का कारण देश के भीतर ही लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्यों में आना-जाना था।

अधिक उत्पादकता वाले और अधिक मजदूरी वाले कामों में जाने की सर्वदा प्रेरणा दी। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अमेरिका में उत्पादकता का स्तर इतनी तेजी से ऊँचा बँसे हो गया जबकि अन्य

चार्ट 9

संयुक्त राज्य अमेरिका की आबादी
क्षेत्रवार विभाजन 1880 और 1960



देशो मे, उत्पादन के औद्योगिक तरीके वैसे ही होने पर भी वह उतना ऊँचा नहीं हुआ।

अमेरिका और कुछ अन्य देशो के श्रमिको की उत्पादकता मे जो अन्तर है उसका कारण यह नहीं है कि उनके श्रमिको को योग्यताओ मे अन्तर है। हर देश की अपनी कुछ अलग ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है जिनसे उनके श्रमिको की क्षमताओ, कौशलो और हुनरो मे फर्क होता है। उदाहरण के लिए स्कैंडिनेवियायी देशो की भाति समुद्र तटवर्ती देशो के लोग बहुत अच्छे नाविक और मछुवे होते है, क्योंकि एक तो वे समुद्रतट के नजदीक रहते है और दूसरे आबादी बढ़ने पर स्थल पर जीवन के जिन साधनो की उन्हें पर्याप्त उपलब्धि नहीं हो सकती, उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्हें सागर मे जाना पडता है। इसी तरह यूक्रेन के किसान के लिए गेहूँ की फसल पैदा करना उतना ही स्वाभाविक है, जितना, कि कन्सास के किसान के लिए क्योंकि दोनो प्रदेशो की समतल भूमि और महाद्वीपीय जलवायु गेहूँ पैदा करने के लिए अत्यधिक उपयुक्त है।

अमेरिकी श्रमजीवियों का स्वास्थ्य और प्रशिक्षण

परिपक्व श्रमजीवी को शारीरिक दृष्टि से सबल और स्वस्थ बनाये रखने के लिए संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे अच्छी खुराक मिले, रहन-सहन की अच्छी परिस्थितियाँ मिले और बचपन तथा जवानी मे उसे काफी ताजा हवा और मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते रहे हो। हाल के दशको मे अधिक अच्छी और पोषक खुराक विकसित करने और सभी आयु-वर्गों के अमेरिकी श्रमिको को अधिक स्वस्थ जीवन-परिस्थितियाँ और चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने की दिशा मे काफी प्रगति हुई है। इससे श्रमिको की शारीरिक शक्ति और काम करने की सामर्थ्य मे वृद्धि हुई है और परिणामतः उससे उनकी उत्पादकता (उपादन सामर्थ्य) बढ़ी है।

लेकिन इस का अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि अमेरिकी

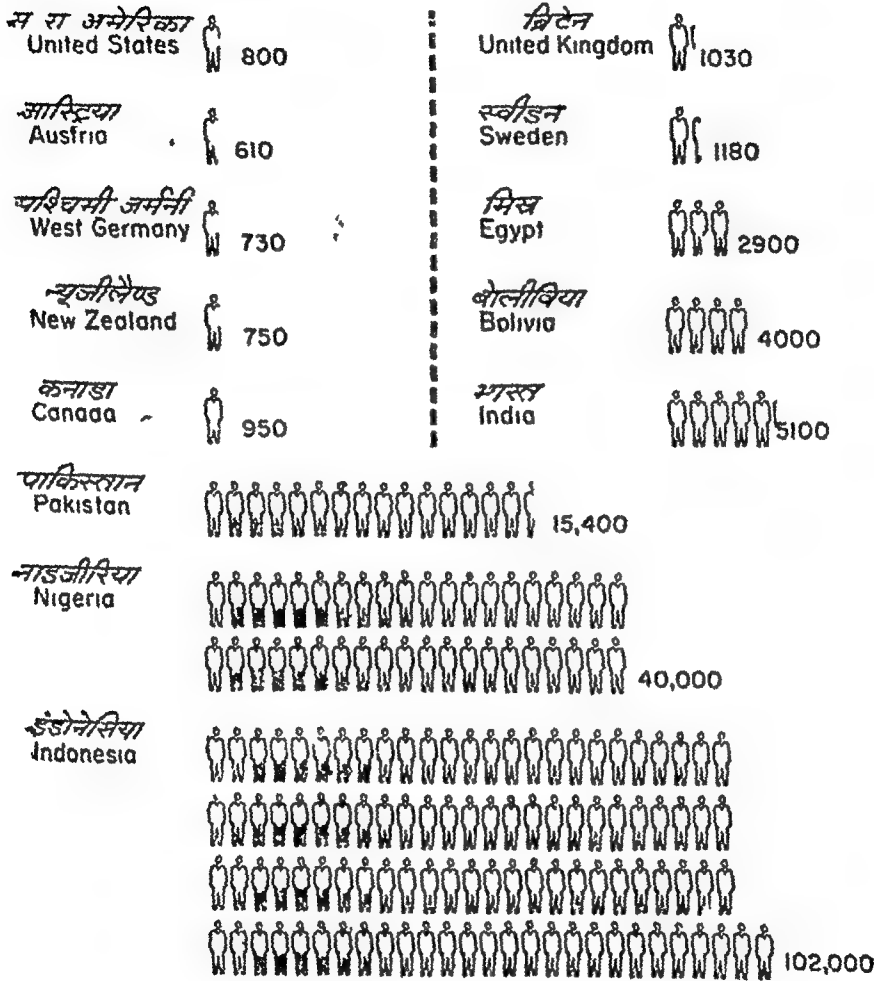
लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति में अब और किसी सुधार की जरूरत या गुंजायश नहीं है। यह अनुमान लगाया है कि लगभग 2 प्रतिशत मानव घटे ऐसी अस्थायी दुर्घटनाओं या बीमारियों के कारण, जिनका श्रमिक के व्यवसाय से कोई सम्बन्ध नहीं है, बरबाद हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं, देख-भाल और अनुसंधान को जारी रखने की अभी आवश्यकता है। स्वास्थ्य के जिस अंग की ओर हाल के वर्षों में अधिक ध्यान दिया जाने लगा है, यद्यपि वह भी पर्याप्त नहीं है, वह है मानसिक स्वास्थ्य—यानी यह समस्या कि किस प्रकार लोगों के शरीर के साथ-साथ उनके मन को भी स्वस्थ रखा जाय। द्वितीय विश्व-युद्ध में संयुक्त राज्य में सेना ने 25 प्रतिशत से भी अधिक उम्मीदवारों को सेना में लेने से इसलिए इन्कार कर दिया कि उनमें सैनिक सेवा के लिए आवश्यक न्यूनतम शारीरिक योग्यता का अभाव था। इसके अलावा 5 प्रतिशत अन्य उम्मीदवार शिक्षा या मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी योग्यताओं की कमी के कारण अस्वीकृत कर दिये गए। अकेली ये दोनों बातें ही यह साबित करने के लिए काफी हैं कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं में सुधार की अभी बहुत आवश्यकता है।


जैसे-जैसे कारखानों और दफ्तरों में नयी-नयी आधुनिक औद्योगिक विधियाँ अपनायी जाने लगेगी, वैसे-वैसे औसत कर्मचारियों की प्रतिभा, शिक्षा और प्रशिक्षण के स्तर को ऊँचा उठाने की जरूरत भी बढ़ती जाएगी। यह बात शायद सही है कि यूरोप का श्रमजीवी विशिष्ट परम्परागत शिल्पों की दक्षता और हुनर में और अमेरिकी श्रमजीवी सामान्य दक्षता और सूझ-बूझ में आगे बढ़ा हुआ है। इस प्रकार अमेरिकी श्रमिक आधुनिक स्वचालित मशीनों के काम को झटपट आसानी से सीख लेता है, किन्तु इस समय ऐसे अमेरिकी कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है जिन्हें सूक्ष्म काम वाले उद्योगों का प्रशिक्षण और दक्षता हो।

‘संयुक्त राज्य में हर व्यक्ति के लिए, न केवल प्राथमिक स्कूलों में

चार्ट 10

प्रति डाक्टर देशवासियों की संख्या—1957



 = 1000 निवासी

बल्कि माध्यमिक स्कूलों में भी निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है और अनेक शहरों में कालेज और विश्वविद्यालय स्तर तक भी निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। संयुक्त राज्य के स्कूलों में भर्ती की अधिक प्रतिशतता से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की शिक्षा की अद्वितीयता के

वारे में पता चलता है तथा बच्चों की स्कूल आयु से ही कालेजों और स्कूलों की बढ़ती हुई विद्यालय सख्या का पता चलता है। सन् 1960 में संयुक्त राज्य के कुल अर्थनिक श्रमिकों में से आधे ऐसे थे जिन्होंने कम से कम चार साल की हाई स्कूल की शिक्षा पूरी कर ली थी। सन् 1940 और 1960 के बीच ऐसे श्रमिकों की सख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई जो कम से कम चार वर्ष की कालेज की शिक्षा पूरी कर चुके थे। फिर भी इस समय संयुक्त राज्य में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ इतनी नहीं हैं कि छात्रों की बढ़ती हुई सख्या को प्रभावकारी ढंग से शिक्षा दे सकें और आधुनिक औद्योगिक विधियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरी कर सकें। संयुक्त राज्य ने अपनी इस कमी को अनुभव किया है और वह उसे पूरा करने का प्रयत्न प्रारम्भ कर रहा है। अन्य अनेक उद्योग सम्पन्न अथवा कम विकसित देश भी अपनी शिक्षा-पद्धतियों और शिक्षा के स्तर को आज के युग की आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने के लिए हठसंकल्प के साथ अग्रसर हो रहे हैं।

किन्तु शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में विभिन्न देशों से प्राप्त आकड़े अपने आप में इस बात का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने के लिए काफी नहीं है कि उनके श्रमिकों की प्राप्त प्रशिक्षण की स्थिति क्या है (देखिये परिशिष्ट तालिका 10)। उदाहरण के लिए यूरोप के अनेक भागों में ऐसे लोगों की विधिवत् शिक्षा, जिन्हें बाद में श्रमिक बनना होता है 14 या 15 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाती है अर्थात् वे केवल आठ या नौ वर्ष तक ही स्कूल में पढ़ पाते हैं। वहाँ अनेक बच्चों को प्राथमिक (प्राइमरी) शिक्षा समाप्त करके ही किमी रोजगार में लग जाना पड़ता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती और वे माध्यमिक स्कूल की फीस नहीं चुका सकते। किन्तु फिर भी बहुत-से देशों में, जहाँ बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के दौरान में पर्याप्त तकनीकी शिक्षा नहीं मिल पाती, उन्हें प्रशिक्षु (एप्रेण्टिस) के रूप में रखकर काम सिखाने की और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अलग कक्षाएँ चलाने की व्यापक व्यवस्था की जाती है, ताकि अधिक उत्पादक श्रम-शक्ति

तयार की जा सके ।

उदाहरण के लिए जर्मनी में परिपक्व प्रशिक्षुओं (एप्पेन्टिसी) को अधिक उन्नत प्रशिक्षण और तालीम देने के लिए तकनीकी संस्थाएँ (फाखशुलेन) खोली जाती हैं । इंग्लैंड में जूनियर तकनीकी स्कूल तरुण श्रमिकों को खास-खास उद्योगों और व्यवसायों के लिए तैयार करते हैं । सोवियत संघ में विशिष्ट प्रशिक्षण के स्कूल (तेकनिकम) खोले गए हैं जो सामान्य और विशिष्ट शिक्षा के लिए चार-वर्षीय पाठ्यक्रम चलाते हैं । ये स्कूल ग्राम सार्वजनिक स्कूलों में दी जाने वाली न्यूनतम शिक्षा से आगे की शिक्षा देते हैं और साथ ही सैद्धान्तिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करते हैं । यूरोप में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूलों और प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य प्रयोजन आधुनिक कारखानों की जटिल मशीनों के कौशलपूर्ण संचालन और रख-रखाव के लिए आवश्यक दक्ष श्रमिकों और अर्ध-पेशेवर टेक्नीशियनों को तैयार करना होता है । संयुक्त राज्य में ऐसे स्कूलों की संख्या अपेक्षाकृत कम है ।

संयुक्त राज्य में इस तरह का तकनीकी प्रशिक्षण स्कूलों में देने के बजाय कारखानों में ही देने की पद्धति का सहारा अधिक लिया जाता है । अनेक कारखानों और औद्योगिक संस्थानों ने ऐसे विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किये हैं जिनके द्वारा वे अपने यहाँ नये आधुनिक ढंग के काम सभालने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर तैयार करते हैं । ये कार्यक्रम अतिरिक्त अध्ययन कार्यक्रम नहीं समझे जाते, बल्कि कर्मचारियों को अपने काम की शिक्षा देने के कार्यक्रम के ही अविच्छिन्न अंग समझे जाते हैं । कारखानों में काम करते-करते प्रशिक्षा देने के इन कार्यक्रमों का मुख्य प्रयोजन 'तेकनिकमों' और 'फाखशुलेन' की तरह अर्ध-

कार कर्मचारियों की मांग बढ़ने से यह संभव है कि यहाँ ऐसी तकनीकी शिक्षा पर अधिकाधिक जोर दिया जाने लगे जो पूरे डीजॉनियरो के पाठ्य-क्रम के स्तर पर न पहुँचने पर भी आज के व्यावसायिक प्रशिक्षण से ऊँचे दर्जे की हो।

इस प्रकार, यह संभव है कि अमेरिका का श्रमिक वर्ग अन्य अनेक देशों के श्रमिकों की तुलना में अधिक स्वस्थ और अधिक प्रशिक्षण प्राप्त हो, तो भी यह नहीं कहा जा सकता कि उनका शारीरिक स्वास्थ्य और कार्यक्षमता अब अधिक अच्छी शिक्षा और प्रशिक्षण ही अन्य देशों के श्रमिकों की तुलना में उनकी अधिक उत्पादकता का एकमात्र कारण हैं। उत्पादकता के इस अन्तर के और भी महत्वपूर्ण कारण हैं।

श्रमिकों का रवैया

संयुक्त राज्य में श्रमिकों की कोई ऐसी विशिष्ट अभिवृत्ति नहीं है जिसे समग्र रूप से अमेरिकी श्रमिकों का रवैया कहा जा सके। इसके विपरीत यहाँ श्रमिकों के विभिन्न वर्गों के अलग-अलग रविये हैं। जो श्रमिक हाल में अन्य देशों से आकर अमेरिका में बसे हैं, उनके और अमेरिका में ही उत्पन्न श्रमिकों के विचारों और मतों में अन्तर है, अलग-अलग क्षेत्रों के श्रमिक विचारों में एक-दूसरे से अलग-अलग हैं, और गोरे तथा काले श्रमिकों में भी विचार-भेद है। इसी प्रकार के और भी अन्तर हैं। फिर भी अमेरिकी श्रमिकों के भिन्न-भिन्न प्रकार के रवियों में कुछ सामान्य लक्षण पाये जा सकते हैं। ये सामान्य लक्षण अधिकतर ट्रेड यूनियनों (श्रमिक संघों) के उद्देश्य और कार्यों के सम्बन्ध में उनके विचारों में पाये जाते हैं।

संयुक्त राज्य के 7 करोड़ 20 लाख श्रमजीवी-वर्ग में से सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख के लगभग यूनियनों के सदस्य हैं। किन्तु निर्माण-उद्योगों में यूनियनों के सदस्यों की संख्या उनके कुल श्रमिकों की आधी के लगभग होती है। एक आम अमेरिकी ट्रेड यूनियन एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य श्रमिकों को अच्छे वेतन और अच्छे काम की

परिस्थितियाँ दिलाना होता है। यह एक सर्वथा स्वतन्त्र सगठन है, जिसकी स्थापना या नियन्त्रण में सरकार या मालिकों का कोई हाथ नहीं होता।

अन्य देशों में, खासकर मध्य यूरोप के देशों में, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाय तो ट्रेड यूनियनों का विकास श्रमिक आन्दोलन का केवल एक भाग ही रहा है—राजनीतिक दल, उपभोक्ता सहकारी समितियाँ और सांस्कृतिक एवं खेल सगठन उसके अन्य अंग थे। इन देशों में श्रमिक आन्दोलन के इतना व्यापक होने का कारण यह था कि इन देशों के श्रमिकों का, बल्कि दूसरों का भी, यह खयाल था कि वे एक सर्वथा अलग वर्ग हैं और बाकी समाज, यानी उच्च वर्ग, समाज के वरदानों में उन्हें हिस्सा नहीं देता, और इसीलिए उन्हें अपने लिए एक अलग सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन का विकास करना चाहिए।

इसके विपरीत अमेरिकी श्रमिक अपने आप को एक पृथक् वर्ग या राष्ट्र के शेष वर्गों से अलग नहीं समझता। वह सिर्फ यह मानता है कि श्रमजीवी होने के नाते उसके कुछ विशिष्ट आर्थिक हित हैं और उन्हें वह एक शक्तिशाली श्रमिक सगठन के जरिये सक्रिय रूप से पूरा करना चाहता है। लेकिन इन अव्यवहित और विशिष्ट उद्देश्यों को छोड़ दिया जाय, तो अन्य अमेरिकी नागरिकों की भाँति वह भी अपने लिए चाहे जिस राजनीतिक दल, चर्च या अन्य सगठन को चुन सकता है। इस चुनाव में उसके व्यवसाय या उसकी आर्थिक स्थिति से किसी भी तरह की बाधा नहीं आती। संयुक्त राज्य में लोगों के सामाजिक सम्बन्धों का आधार बहुत कुछ यह होता है कि कोई व्यक्ति मूलतः किस राष्ट्र से या किस प्रकार की संस्कृति से वहाँ आया है, वह किस धर्म में आस्था रखता है अथवा किस प्रदेश और किस इलाके का वह रहने वाला है। इसका आधार यह उतना नहीं होता कि उत्पादन की प्रक्रिया में उसकी क्या स्थिति है।

यद्यपि अमेरिकी मजदूर श्रमिक आन्दोलन को जीवन की सर्व-समावेशी पद्धति नहीं मानता तो भी वह यह जरूर चाहता है कि उसकी ट्रेड

यूनियन उसके आर्थिक हितों के लिए जवर्दस्त संघर्ष करे। सन् 1930 के दशक के बाद से यूनियनों की सदस्य संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है और यूनियनों ने श्रमिकों को अधिक वेतन, काम के घंटों में कमी और इसी प्रकार के और अनेक लाभ प्रदान कराये हैं। यद्यपि औसत अमेरिकी श्रमिक को जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम वेतन से कहीं अधिक वेतन मिलता है तो भी वह भविष्य में अधिकाधिक भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है। जब उसे अवसर मिलता है तो वह काम के घंटों के बाद भी अतिरिक्त काम करता है, क्योंकि इस अतिरिक्त काम के लिए उसे नियमित काम के घंटों की अपेक्षा ज्योड़ी मजदूरी मिलती है। कुछ उद्योगों में, जहाँ कि काम के साप्ताहिक घंटे घटाकर कुल 35 कर लिये गए हैं, श्रमिक अपना नियमित काम करने के बाद फालतू समय में दूसरी जगह अश-कालिक काम ले लेते हैं, हालांकि उन्हें उक्त उद्योगों के नियमित काम से ही काफी आमदनी हो जाती है।

संयुक्त राज्य में भी, अन्य सभी देशों की भाँति, जहाँ कि श्रमिकों को अपने अभ्युदय के लिए प्रयत्न करने की स्वतन्त्रता है, मजदूरों और मालिकों में झगड़े होते रहते हैं। पिछले दो दशकों में श्रम-सम्बन्धों में सुधार होने के कारण, सामूहिक सौदेबाजी और पंच-निर्णय से अनेक विवादों का निवटारा होता रहा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि इन वर्षों में हड़तालें हुई ही नहीं हैं, लेकिन यह जरूर सही है कि जो हड़तालें हुईं, उनमें श्रमिक आन्दोलन के प्रारम्भिक युग की भाँति कटुता और हिंसा नहीं थी। सन् 1956 से 1960 तक की अवधि में मजदूर-मालिक विवादों के कारण काम बन्द होने से कुल मानव-दिनों में से औसतन एक प्रतिशत का भी तिहाई भाग ही नष्ट हुआ। संयुक्त राज्य में यह स्थिति अन्य देशों की, जहाँ मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार है, स्थिति से भिन्न नहीं है (देखिये परिशिष्ट तालिका 11)।

अमेरिकी श्रमिक यह समझते हैं कि श्रम के ठेके में मालिक दूसरा पक्ष है, इसलिए वे उनसे अच्छी से अच्छी शर्तें अपने लिए प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन साथ ही वे यह भी महसूस करते हैं कि बुनि-

यादी तौर पर मानिको के और उनके हित एक ही है और जिस उद्योग या व्यवसाय में वे काम करते हैं वह उन्हें ऊँचे वेतन और अन्य लाभ तभी दे सकता है, जबकि वह खूब फले-फूले और उन्नति करे। उनके इस रचये के महत्त्व को दृष्टि में रखकर प्रबन्धक लोग श्रमिकों के लिए काम की अच्छी परिस्थितियाँ बनाए रखने के लिए काफी पैसा खर्च करते और मेहनत करते हैं। श्रमिकों के लिए काम की अच्छी शारीरिक और मानसिक परिस्थितियाँ पैदा कर बहुत-से उद्योगों ने प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ा लिया है और ऐसे उद्योगों की संख्या अब बराबर बढ़ रही है।

उमका परिणाम यह हुआ है कि अनेक कारखानों में श्रमिकों ने यह भावना विकसित कर ली है कि बड़िया किस्म की चीज तैयार करना उनके लिए शिल्पिक वर्ग की वस्तु है और अनेक मामलों में उन्होंने प्रबन्ध के सुधार में भी सक्रिय और रचनात्मक दिलचस्पी ली है। राष्ट्रीय आयोजन संघ (नेशनल प्लैनिंग एसोसियेशन) ने कई मामलों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट में यह निष्कर्ष प्रकट किया है कि श्रमिक और मालिक, दोनों की ओर से पारस्परिक हित और सहयोग का रुख अपनाये जाने से न सिर्फ बहुत-से विवादों को सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा हल करने में मदद मिली है, बल्कि उससे श्रमिकों को उत्पादन के कामों में सुधार के लिए अधिक दिलचस्पी लेने का प्रोत्साहन मिलने से उनकी उत्पादकता भी बढ़ी है।

हैं जिससे कुछ उद्योगों में श्रमिकों की मर्यादा तो बढ़ जाती है, परन्तु उत्पादन में उसके अनुरूप वृद्धि नहीं होती। जिस जमाने में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर रही है, खासकर सन् 1930 के दशक में, भवन-निर्माण, परिवहन और मनोरंजन सम्बन्धी उद्योगों में इस प्रकार का श्रम का अपव्यय बहुत हुआ है। किन्तु पिछले दशक में, जबकि रोजगार का स्तर बहुत ऊँचा रहा है, इस प्रकार की अपव्ययकारी प्रवृत्तियाँ बहुत घटी हैं, हालांकि उनका पूरी तरह अन्त नहीं हुआ है।

सब मिलाकर अमेरिकी श्रमिकों ने अब यह अनुभव कर लिया है कि उत्पादकता में वृद्धि केवल वास्तविक वेतन में वृद्धि के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि वह आर्थिक अभिवृद्धि को जारी रखने के लिए भी आवश्यक है। फिर भी यूनियनों के नेताओं ने इस बात पर निरन्तर बल दिया है कि प्रबंधकों की और सरकार की नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जिनसे नई तकनीकी विधियों के फलस्वरूप श्रमिकों को रोजगार बदलने में कठिनाइयाँ न हों और सब लोगों को पूरा रोजगार मिल सके। उनका यह बल देना उचित भी है। अन्य देशों के जिन श्रमिक नेताओं ने अमेरिका में आकर स्थिति का अध्ययन किया है, आधुनिक और नवीनतम तकनीकी विधियों के प्रति, जिनमें स्वचालित यन्त्रों का उपयोग भी शामिल है, अमेरिकी श्रमिकों के इस रुख को देखकर आश्चर्य प्रकट किया है।

सारांश

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि अमेरिकी श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि का कारण सिर्फ ऐसी ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियाँ ही नहीं हैं जो उनकी विविधता और सफलता को प्रभावित करती हैं। वह श्रमिकों की शारीरिक श्रम करने की सामर्थ्य, उनकी तालीम और प्रशिक्षण एवं काम, आराम और नई औद्योगिक विधियों के प्रति उनके रवैये पर भी निर्भर है। अमेरिका श्रमिकों का यह रवैया अमेरिकी उद्योगों में प्रति मानव-घंटा उत्पादन में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण कारण है। किंतु इसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद, विभिन्न देशों में श्रमिकों की उत्पादकता की जो विभिन्नता पाई जाती है, उसकी व्याख्या के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं है।

व्यावसायिक प्रबन्ध

पिछले पचास वर्षों में अमेरिकी आर्थिक जीवन के किसी भी अन्य पहलू में उतने बुनियादी परिवर्तन नहीं हुए जितने कि व्यावसायिक प्रबन्ध के कार्य और स्वरूप में हुए हैं। ये परिवर्तन नि सन्देह अमेरिकी उत्पादकता में तीव्र वृद्धि का एक बड़ा कारण हैं। यह शायद बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सोवियत रूस के नेताओं ने अनेक बार इस बात पर जोर दिया है कि साम्यवादी देश मयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन के प्रबन्ध की विधियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। किन्तु साथ ही वे मार्क्सवादियों का यह मिद्धान्त हमेशा दोहराते रहे हैं कि उत्पादन के 'अराजकतापूर्ण' मगटन में एक के बाद एक मकट पैदा होते रहेंगे और अन्ततः एक दिन उनसे पूँजीवादी प्रणाली का अन्त हो जाएगा।

साम्राज्य खड़े किये। ये लोग 'कठोर व्यक्तिवादी' थे और अक्सर प्रति-स्पर्धात्मक संघर्ष में पूरे जोर से उतरते थे। इन लोगों ने विशाल सम्पदाओं का संग्रह किया, अक्सर एकाधिकार वाले (मोनोपलिस्टिक) तरीके अपनाये और जनता की आलोचना के लक्ष्य बने। यह आलोचना खास तौर से उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में खूब जोर-शोर से हुई, क्योंकि उन दिनों इन तथा-कथित 'लुटेरे सामन्तों' के पास सम्पत्ति और ऐश्वर्य के ढेर लग गए थे और वे खूब शान और ठाठ से खर्च करते थे, जबकि किसान कृषि-जिन्मों की कम कीमतों के कारण, और अन्य देशों से आकर बसे मजदूर कम मजदूरी और काम की खराब और असुरक्षित परिस्थितियों के कारण, अत्यधिक सकटग्रस्त थे। इन विशाल औद्योगिक साम्राज्यों की सार्वजनिक आलोचना का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने अनेक कम्पनियों को मिलाकर बनाये गए बड़े-बड़े ट्रस्टों पर रोक लगाने के कानून और अन्य नियामक उपाय अपनाये। यद्यपि इन कानूनों ने अनेक आपत्तिजनक हरकतों पर रोक लगा दी किन्तु इन औद्योगिक और वित्तीय उद्यमों के निर्माण से अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के विकास में जो योग मिला था उसमें कोई रुकावट नहीं पड़ी। इनमें से बहुत-से लोगों की दूर तक कल्पना करने की प्रतिभा और उत्कृष्ट आत्म लाभ की भावना सृजनात्मक और विनाशात्मक, दोनों प्रकार की थी। उन्होंने छोटे-छोटे किसानों, अभिजात वर्ग के बागान मालिकों और छोटे पैमाने पर काम करने वाले दस्तकारों के राष्ट्र को एक महान् और समृद्ध औद्योगिक ताकत में परिणत कर दिया जिसका विस्तार महाद्वीप-व्यापी था और महत्त्व विश्वव्यापी।

यह एक विचित्र बात है कि आधुनिक व्यावसायिक प्रबन्ध पर चर्चा और विचार करते हुए कुछ लोग एक तरह से यह स्वीकार करके चलते हैं कि हमारा अब भी उन्नीसवीं शताब्दी के उन लुटेरे सामन्तों से साबिका पड़ रहा है। मौजूदा अमेरिकी आर्थिक प्रणाली के आलोचक मार्क्सवादी ही नहीं, दूसरे लोग भी इसी प्रकार की बातें लिखते और कहते हैं। यही गलती अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के कुछ प्रशंसक भी करते हैं, हालांकि

उसका कारण बिलकुल उलटा होता है। वे इन पुराने कठोर व्यक्तिवादियों की, जो अब लुप्त हो गए हैं और जिनके वर्तमान उत्तराधिकारी प्रबन्धकों ने सगठनात्मक अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व और जन-मत की चिन्ता करने के मामले में सर्वथा भिन्न किस्म के पैमाने अपनाये हैं, स्वकेन्द्रित उपक्रमी प्रवृत्ति और उद्यमशीलता की सराहना करते हैं, जैसे कि वे अब भी हमारे बीच विद्यमान हो।

छोटे और बड़े व्यवसायों की विशेषताएँ

आज के अमेरिकी आर्थिक क्षेत्र के दृश्य पर एक सरसरी नजर डालने से भी आदमी के मन पर यही छाप पड़ेगी कि यहाँ उत्पादन और वितरण मुख्यतः बड़ी-बड़ी व्यावसायिक कम्पनियों के हाथ में है। किन्तु अधिक सावधानी से विचार करने पर यह मालूम होगा कि बड़ी कम्पनियों का महत्त्वपूर्ण स्थान अवश्य है, किन्तु उनका प्राधान्य नहीं है। जून, 1959 को समाप्त कर-वर्ष में संयुक्त राज्य में लगभग दस लाख सक्रिय कम्पनियाँ थी, जिन्होंने आय-कर के लिए अपनी आमदनी के हिसाब दाखिल किये। इनमें से करीब 2200 कम्पनियाँ ऐसी थी जिनकी परिसम्पत्तियाँ (ऐसेट) पाँच करोड़ डालर से अधिक की थी। इन 2200 बृहत्तर कम्पनियों की परिसम्पत्तियाँ और शुद्ध आय, दोनों समस्त अमेरिकी व्यावसायिक कम्पनियों की कुल परिसम्पत्ति और शुद्ध आय का 62 प्रतिशत थी, लेकिन समस्त अमेरिकी कम्पनियों की कुल वार्षिक बिक्री में इन कम्पनियों का हिस्सा 40 प्रतिशत ही था। इन आँकड़ों से जहाँ यह पता लगता है कि इन 2200 विशाल कम्पनियों का स्थान महत्त्वपूर्ण है, वहाँ यह भी मालूम होता है कि अमेरिका में ऐसी कम्पनियों की संख्या भी बहुत बड़ी है जिनकी गिनती विशाल कम्पनियों में नहीं की जा सकती।

अमेरिका एक ऐसे समाज का स्वप्न देख रहा है, जिसमें कोई भी साहसी और सूर्य-वृद्ध वाला व्यक्ति, जिसमें प्रतिभा भी हो और हिम्मत भी, व्यवसाय स्थापित कर सके और स्वयं अपना मालिक बन सके।

तालिका न० 5

1958-59 के कर-वर्ष में विभिन्न परिसम्पत्ति वर्गों की कम्पनियों द्वारा
दिये गए कम्पनी आय-कर के विवरण

विवरणों की संख्या हजारों में	कुल परिसम्पत्तियाँ		कुल		शुद्ध आय
	%	%	प्राप्तियाँ	%	%
10 लाख डालर से कम परिसम्पत्ति वाली कम्पनियाँ	867 0	87 6	10 7	28 8	9 8
10 लाख से 5 करोड डालर तक की परि- सम्पत्ति वाली कम्पनियाँ	58 4	5 9	27 3	30 2	27 8
5 करोड या अधिक परिसम्पत्ति वाली कम्पनियाँ	2 2	2	62 0	40 0	61 9
योग	927 6	93 7	100 0	99 0	99 6
जिन कम्पनियों की परिसम्पत्ति 0 थी या बताई नहीं गई	62 7	6 3	—	1 0	4
कुल योग	990 3	100 0	100 0	100 0	100 0

आज किसी के लिए भी यह सम्भव नहीं है कि वह अकेला इस्पात सयंत्र, मोटर कारखाना या तेल-शोधक कारखाना खड़ा करने के लिए आवश्यक साधन जुटा सके। किन्तु उद्योग, व्यापार और सेवाओं की दूसरी 19 0 में छोटे या मध्यम व्यवसाय स्थापित करने के लिए काफी

अवसर है। यद्यपि आँकड़ों से यह निष्कर्ष पूरी तरह नहीं निकलता तो भी ऐसा प्रतीत होता है कि हाल के कुछ दशकों में छोटे व्यावसायिक उद्यमों की संख्या में कोई विशेष कमी नहीं हुई है।

किन्तु लाभ सम्बन्धी आँकड़ों को देखने से यह ज्ञात होता है कि आर्थिक उतार-चढ़ावों का असर बहुत बड़ी कम्पनियों के वजाय छोटी कम्पनियों पर अधिक पड़ता है और निवेश की गई पूँजी या शेयरों की संख्या की दृष्टि से औसतन छोटी कम्पनियों की लाभ की दर बड़ी कम्पनियों की लाभ की दर की अपेक्षा कम होती है। लाभदर कम होने का कम से कम एक आशिक कारण यह अवश्य है कि इन छोटी कम्पनियों के मालिक अवसर अपने शेयरों के लाभांश (डिविडेंड) के रूप में जो लाभ लेते हैं, उससे भी अधिक बड़ा लाभ प्रबन्धक की हैसियत से अपने या अपने परिवार के लोगों के लिए ले लेते हैं।

इस बात पर काफी विवाद रहा है कि बड़े व्यवसायों का काम अधिक कुशलता और दक्षता में चलता है या छोटे व्यवसायों का। यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता रहा है कि बड़ी कम्पनियाँ आवश्यक वित्त की व्यवस्था अधिक प्रासंगिकता में कर सकती हैं और उनमें अनुसन्धान और विकास कार्यो एवं विज्ञापन के लिए खर्च करने की क्षमता अधिक होती है। लेकिन दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि इन कम्पनियों का कारोबार बहुत विनाश और फैला हुआ होने के कारण उनमें दूसरी नौकरशाही बहुत चलती है और लक्ष्मीलापन

करने की आवश्यकता है।

पिछले कुछ वर्षों में छोटे और मध्यम व्यवसायों की कठिनाइयों को देखने से इस कथन की निश्चय ही पुष्टि होती है कि वे अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए, खासकर उधार-प्राप्ति की कठिनाई के समयों में, धन प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों की अपेक्षा अधिक मुश्किल अनुभव करते हैं। स्वभावतः ही उधार देने वाले मस्थान, खासकर बैंक, बड़े उधार लेने वालों को, जो बहुत समय से उनमें उधार लेते रहे हैं और जिनके पास काफी बड़ी परिसम्पत्तियाँ हैं, उधार देते समय प्राथमिकता देते हैं। किन्तु इस बात को छोड़ दे तो भी छोटे व्यवसायों की कठिनाई का एक कारण यह भी है कि उन्हें अपने पूँजी के आन्तरिक स्रोतों—मूल्य हानि निधि और अवितरित लाभ आदि—से पर्याप्त धन नहीं मिलता, जबकि बड़े व्यवसायों की बहुत-सी वित्तीय आवश्यकता इन स्रोतों से ही पूरी हो जाती है।

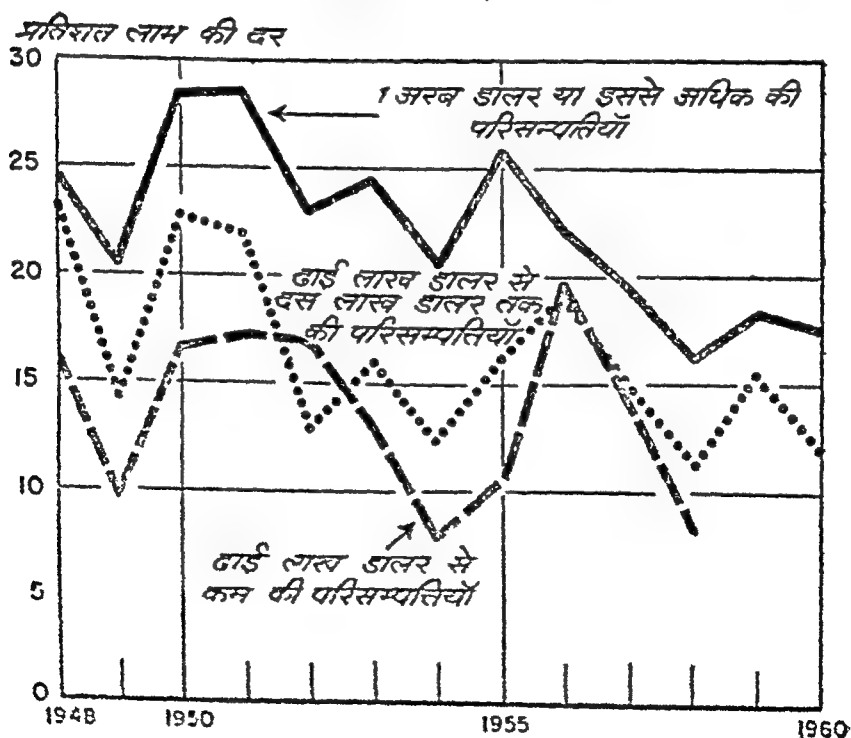
किन्तु छोटे व्यवसायों की कुछ विशेषताएँ ऐसी भी हैं जो बड़ी कम्पनियों की इस लाभपूर्ण स्थिति को बहुत कुछ बराबर कर देती हैं। अधिक प्रसिद्ध छोटी कम्पनियों की सफलता और बड़ी एवं सम्पन्न कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता का कारण यह है कि उनकी कार्य-मचालन विधि में लचकीलापन होता है और उनके प्रबन्धकों में विविध प्रकार के कार्य कर सकने की क्षमता और योग्यता होती है। छोटी कम्पनियाँ अनेक नये औद्योगिक क्षेत्रों में, उदाहरणार्थ इलैक्ट्रानिकी, यन्त्रों को स्वचल (ऑटोमैटिक) बनाने के उपकरणों, नियन्त्रित मिसाइलों के कुछ पुर्जों और सामग्रियों एवं अन्य प्रकार के प्रतिरक्षा-सम्बन्धी कार्यों में, तकनीकी प्रगति में आगे रही हैं। इसके अलावा अनेक नई चीजों के विकास से, उदाहरणार्थ टेप-नियन्त्रित मशीनी औजारों और कम महँगे इलैक्ट्रानिक गणक यन्त्रों (कम्प्यूटर) से, मध्यम दर्जे के उद्योगों के लिए भी स्वचल विधियाँ अपनाता सम्भव हो गया है। जिन व्यवसायों में वित्त की प्राप्ति, अनुसन्धान और

सापन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उनमें व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की

क्षमता का निर्णय इस बात से नहीं होता कि सम्बद्ध व्यवसाय छोटा है या बड़ा। लेकिन साथ ही यह बात भी स्वीकार की जानी चाहिए कि हाल के वर्षों में अधिकतर नये और कल्पनापूर्ण साहसिक कार्यों का श्रेय बड़े व्यवसायों को ही रहा है। उदाहरण के लिए ट्राजिस्टर्स का आविष्कार एक बड़ी कम्पनी की प्रयोगशाला में हुआ था। किन्तु मूल आविष्कारक से लाइसेंस लेकर उसके उत्पादन की विधियाँ विकसित करने और उन्हें क्रियान्वित करने का श्रेय छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की कम्पनियों को है।

चार्ट II

कर अदा करने से पूर्व औसत वार्षिक लाभ की दर विभिन्न परिसम्पत्तियों वाली अमेरिका निर्माता कम्पनियों (शेयर होल्डरों के शेयरों पर प्रतिशत लाभ)



यद्यपि छोटे और बड़े व्यावसायिक सस्थानों का साथ-साथ अस्तित्व ही उत्पादकता में वृद्धि का एक मात्र कारण नहीं है, तो भी यह जरूर

कहा जा सकता है कि उसके बिना यह असाधारण वृद्धि सम्भव न होती। इस कथन का अभिप्राय यह नहीं है कि संयुक्त राज्य में बड़े और छोटे व्यवसायों का मौजूदा मिश्रण ही सर्वोत्तम सम्भव मिश्रण है। वास्तविकता यह है कि वित्तीय दृष्टि से अधिक अच्छी स्थिति में होने के कारण बड़ी कम्पनियों ने अनेक बार छोटी कम्पनियों के विकास में बाधा डाली है। यह बाधा न डाली जाती तो ये छोटी कम्पनियाँ उनके साथ अच्छी तरह प्रतिस्पर्धा कर सकती थीं।

प्रतिस्पर्धा की मात्रा

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में बड़े व्यवसायों की वृद्धि से प्रतिस्पर्धा (कॉम्पीटीशन) का स्थान एकाधिकार (मोनोपली) ले लेगा, यह भय सत्य सिद्ध नहीं हुआ। अमेरिका में अन्य औद्योगिक राष्ट्रों की अपेक्षा अधिक बड़ी कम्पनियों के अस्तित्व का कारण सिर्फ यह है कि अमेरिकी उद्योग अपेक्षाकृत अधिक बड़े क्षेत्र की आवश्यकताएँ पूरी करते हैं। फिर भी सारे महाद्वीप के बाजार की जरूरत पूरी करने के बावजूद, बल्कि अंशतः इसी कारण से, अमेरिकी उत्पादकों में किसी भी अन्य देश के उत्पादकों की अपेक्षा अधिक पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है।

कभी-कभी लोग यह बात भूल जाते हैं कि जिन उद्योगों में थोड़े-से ही बड़े उत्पादक हैं उनके और ऐसे उद्योगों के, जिनमें सैकड़ों या हजारों छोटे उत्पादक हैं, प्रतिस्पर्धा अधिक होगी। इसके अलावा, एक ही वस्तु के विभिन्न उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ मूलतः एक ही काम में आने वाली विविध वस्तुओं में—उदाहरणार्थ सूती कपड़े और कृत्रिम रासायनिक धागे से बने कपड़े में—भी प्रतिस्पर्धा हो जाती है। कुछ क्षेत्रों में यह एक विचित्र विरोधाभासपूर्ण स्थिति है कि जब तक उनमें छोटे-छोटे उत्पादक थे तब तक उनमें परस्पर इतनी प्रतिस्पर्धा नहीं थी किन्तु अब उनमें बड़े-बड़े उत्पादक आ गए तो प्रतिस्पर्धा खूब बढ़ गई। यह बात खास तौर से खुदरा व्यापार के क्षेत्र में पायी जाती है और इसकी वृद्धि का कारण कुछ हद तक यह है कि न केवल

मोटरो की संख्या बढ़ जाने के कारण लोग कहीं भी जाकर वस्तुएँ खरीद सकते हैं बल्कि टेलीफोन और डाक से आर्डर देकर भी सामान मँगा सकते हैं।

भण्डार शृङ्खला (चेन स्टोर) डाक से सामान का आर्डर देने और बट्टा-घरो (डिस्काउण्ट हाउस) की प्रणाली स्थापित होने और सारे राष्ट्र में विज्ञापन करने की पद्धति अपनायी जाने से पूर्व बहुत-सी छोटी खुदरा विक्री की दुकानें, जिन्हें कुछ खाम चीजों के व्यवसाय में विशिष्टता प्राप्त होती थी, इस बात का लाभ उठाती थी कि ग्राहकों के लिए उनका स्थान अन्य दुकानों के स्थानों की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। इस प्रकार वे अपनी प्रतिद्वन्द्वी दुकानों से इस आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं करती थी कि उनके माल की कीमत कम है, या किस्म बढ़िया है, या उनकी उधार माल देने की शर्तें आसान हैं, बल्कि इस आधार पर करती थी कि जिस जगह वे स्थापित हैं, वह ग्राहकों के लिए अधिक सुविधाजनक है। आज भी अनेक देशों में यही स्थिति है। किन्तु संयुक्त राज्य में आज मूल्यों के आधार पर प्रतिस्पर्धा खूब चल रही है। उदाहरण के लिए सेफवे, ए० एण्ड पी० आदि खाद्य पदार्थों की बड़ी-बड़ी भण्डार शृङ्खलाओं में आज उस जमाने से कहीं अधिक पारस्परिक प्रतिस्पर्धा है, जब कि उनकी स्थापना से पहले की छोटी-छोटी दुकानें अपने स्थानीय और बँधे हुए ग्राहकों की सेवा किया करती थी। विक्री की मात्रा में बहुत अधिक वृद्धि हो जाने के कारण मूल्यों की प्रतिस्पर्धा बहुत उग्र हो गई है और इस प्रतिस्पर्धा की वजह से खुदरा व्यापार में मुनाफे का गुंजायश घट गई है। इस प्रतिस्पर्धा से ग्राहकों के सामने बहुत अधिक किस्मों की चीजें आने लग गई हैं, जिनमें से वे अपने मन के मुताबिक चीजें छांट सकते हैं। इससे खरीदारों की सुविधाएँ भी बढ़ी हैं और कम खर्च पर उन्हें दुकानों में अधिक सुविधाएँ भी प्राप्त होने लगी हैं।

अन्य क्षेत्रों में भी नई-नई तकनीकों के विकास से और प्रतिस्पर्धा के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनी रहने से कीमतों पर ऐसे दबाव पड़

रहे हैं जिनसे ब्रूंक रुख नीचे की ओर रहे । मोटर और टेलीविजन सैट इसके प्रमुख उदाहरण हैं । इन क्षेत्रों में नई औद्योगिक तकनीकों के विकास से पहले की अपेक्षा अधिक बड़े कारखानों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है और जब कारखाने बड़े होते हैं तो उन पर ऊपरी खर्च भी अधिक आते हैं । परिणाम यह होता है कि उनमें इजीनियरी, पूंजीगत सामग्री, विज्ञापन और सामान्य प्रशासन का खर्च उनके कुल खर्च का अधिक बड़ा भाग होता है, जबकि उनके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल और श्रम का हिस्सा कुल खर्च का कम भाग होता है । इसलिए इन उद्योगों को अधिक बड़े पैमाने पर काम करने की प्रेरणा मिलती है । उनके उत्पादन पर ऊपरी खर्चों समेत जितनी लागत आती है, उससे जरा भी अधिक मूल्य पर अगर उनकी एक भी वस्तु बिके तो उनके कुल मुनाफे में वृद्धि और कुल घाटे में कमी आती है । इन प्रोत्साहनों को देखते हुए यह बात शायद आश्चर्यजनक है कि जैसे ही इन उद्योगों में उत्पादन की क्षमता जरा-सी भी बढ़ती है, वैसे ही कीमतें इतनी क्यों नहीं गिर जाती कि उनमें एकदम गड़बड़ और अराजकता-सी पैदा हो जाय । इसका उत्तर यह है कि मूल्य-नीति निर्धारित करते समय उद्योगों के प्रबन्धक केवल तात्कालिक प्रतिफल (या तात्कालिक न्यूनतम हानि) को ही नहीं देखते, बल्कि उसके दूरगामी प्रभाव को भी देखते हैं । हर फर्म सिर्फ यही नहीं देखती कि उसके उत्पादन की कीमत ऊपरी खर्चों सहित कुल लागत से ऊँची रहे, बल्कि वह यह भी देखती है कि एक निश्चित अवधि में उसकी यथासम्भव अधिक बिक्री हो ।

बड़ी अमेरिकी कम्पनियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा खूब है, इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ किसी खास क्षेत्र में किसी एक कम्पनी या कम्पनियों का एकाधिकार है ही नहीं और वे उससे मनमाने मूल्यों का फायदा नहीं उठाती, और न ही इसका यह अर्थ है कि कम्पनियों को अपने बड़े-बड़े सब बनाकर एकाधिकार स्थापित करने की प्रवृत्ति की ओर सजग रहने की अब कोई जरूरत नहीं है । यद्यपि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का एक

भाग—रोजगार और उत्पादन, दोनों की दृष्टि से—विकेन्द्रित और

छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों के क्षेत्र में व्याप्त है, जो भी कुछ उद्योगों में केन्द्रीकरण काफी मात्रा में है और वह चिन्ता का विषय बना हुआ है। उद्योग के बड़ा होने का अर्थ—जिसका हम ग्यारहवें अध्याय में अधिक विस्तार से विवेचन करेंगे—आर्थिक शक्ति का केन्द्रित हो जाना है। परन्तु आर्थिक शक्ति का यह केन्द्रीभूत होना आर्थिक या सामाजिक दृष्टि से बुरा ही होगा, यह जरूरी नहीं है, क्योंकि शक्ति का उपयोग जैसे समाज के लिए अहितकर हो सकता है, वैसे ही रचनात्मक भी हो सकता है। अमेरिका की नीति यह है कि इसके हानिकर उपयोग को रोका या निरुत्साहित किया जाय और इसके रचनात्मक पहलू को प्रोत्साहन दिया जाय।

व्यावसायिक प्रबन्ध के स्वरूप में परिवर्तन

बड़ी कम्पनियों द्वारा आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण सरक्षता व्यावसायिक प्रबन्ध के स्वरूप में परिवर्तन है। पिछले बीस वर्षों में बड़े और छोटे, दोनों प्रकार के उद्योगों में व्यावसायिक प्रबन्ध के स्वरूप में परिवर्तन हुआ भी है। यह महज सयोग ही नहीं है कि आज हम व्यवसाय के क्षेत्र में राँकफेलर, कारनेगी, ऐस्टर और वेडरविल्ट जैसे नाम कम सुनाई देते हैं, और जनरल मोटर्स, जनरल इलैक्ट्रिक, स्टैंडर्ड ऑयल और अमेरिकन टेलीफोन एण्ड टेलीग्राफ आदि नाम अधिक सुनने को मिलते हैं। यह सच है कि आज भी कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने विशाल सम्पत्तियाँ संचित कर ली हैं, किन्तु वे अपवाद हैं, और आय-कर और सम्पदा-कर आदि की ऊँची दरों को देखते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपवाद ही रहेंगे। आज अधिकतर बड़े व्यावसायिक संस्थान ऐसे लोगों के हाथों में हैं जिन्हें आम लोग नाम से शायद ही जानते हैं।

व्यावसायिक प्रबन्ध का एक पेशे के रूप में अपनाया जाना अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की हाल की शायद सबसे महत्वपूर्ण घटना है। इस नये पेशे के लोग अपने पूर्ववर्तियों के समान न तो शान-शौकत से रहते हैं

और न उतने कठोर व्यक्तिवादी हैं। ये लोग प्रायः अपनी कम्पनियों के वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, न कि उनके मालिक। हाल के दशकों में कम्पनियों के प्रबन्ध विभाग के शीर्षस्थ व्यक्तियों का चुनाव अधिकाधिक इस आधार पर किया जाता रहा है कि उन्हें तकनीकी ज्ञान और क्रय-विक्रय का अनुभव कितना है। पहले की तरह उनके वित्तीय अनुभव को उतना महत्त्व नहीं दिया गया। आधुनिक व्यवसाय-अधिकारी व्यवसाय-प्रशासन विद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त होने के कारण दफ्तर और कारखाना, दोनों जगह व्यावहारिक विज्ञान और नई तकनीकों के उपयोग के महत्त्व को समझते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इससे वे दोनों जगह काम की सुचारुता और क्षमता बढ़ा सकते हैं, प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकते हैं और श्रम तथा सामग्री की लागत में वृद्धि को निष्प्रभाव करने का उपाय निकाल सकते हैं। वे शेयर होल्डरों, श्रमिकों और ग्राहकों के प्रति, और सबसे बढ़कर स्वयं कम्पनी के प्रति, अपने उत्तरदायित्व को समझते हैं ताकि कम्पनी एक स्थायी संस्थान के रूप में दीर्घकाल तक कायम रह सके।

कम्पनी के भीतर प्रबन्ध विभाग टीम की भावना और सहयोग से काम करने की उपयोगिता को महसूस करता है और यह भी अनुभव करता है कि कर्मचारी सघों के साथ प्रबन्धकों के सम्बन्ध ऐसे होने चाहिए जो दोनों के लिए परस्पर लाभकारी और हितावह हों। आज के व्यावसायिक प्रबन्धकों की व्यक्तिगत उन्नति उनकी अपनी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि पर निर्भर होती है, इसलिए वे भी यह भली भाँति जानते हैं कि यदि ग्राहकों, प्रतिस्पर्धियों और आम जनता में उनकी कम्पनी की ख्याति होगी तो उससे कम्पनी के माल की बिक्री में और उसे अच्छे कर्मचारियों की प्राप्ति में बहुत योग मिलेगा। आज जल्दी से जल्दी अधिक लाभ उठाना उतना महत्त्वपूर्ण नहीं माना जाता जितना कि ऐसी व्यवस्था करना जिससे कम्पनी का अपने उद्योग में प्रतिष्ठित स्थान बन जाय और वह दीर्घ काल तक लाभ उठाती रह सके।

सहयोग और सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से काम करने

की आवश्यकता की अनुभूति बढ़ जाने से अमेरिकी व्यवसायों में साहस और उद्यम की प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आयी है। इसके विपरीत व्यावसायिक कम्पनियाँ बड़े पैमाने पर उत्पादन करने लग गई हैं। इसका अर्थ यह है कि वे कम मुनाफा लेकर अधिक उत्पादन करने का प्रयत्न करती हैं और राष्ट्र के बाजार में उन्होंने अपना जो क्षेत्र बना लिया है, उसे कायम रखने की, और सम्भव हो तो बढ़ाने की भी कोशिश करती हैं। इसका अर्थ यह है कि वे बड़े पैमाने पर और नये-नये आकर्षक तरीकों से विज्ञापन करती और अपनी विक्री को बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं और साथ ही नई और अधिक परिष्कृत वस्तुओं के उत्पादन की एवं वितरण की नई-नई विधियों का विकास करती हैं। इस प्रकार दूर-दूर तक फैले बाजार, राष्ट्रव्यापी विज्ञापन के साधन, आमदनियों में वृद्धि और उनका लोगो में बढवारा और बड़ी-बड़ी कम्पनियों की स्थापना—इन सबने मिल कर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दी हैं जिनमें प्रबन्ध में निरन्तर सुधार करना और उत्पादन एवं विक्री की विधियों में उन्नति करना आवश्यक है।

प्रबन्धको और संचालको (डायरेक्टरो) की व्यक्तिगत पसन्द या नापसन्द आदि के आधार पर व्यावसायिक पूंजी-निवेश (कैपिटल इन्वेस्टमेंट) विषयक निश्चय किये जाते हैं। यद्यपि बाजार के मूल्य सम्बन्धी सकेतो का आज भी महत्त्व है, फिर भी इनके प्रति व्यावसायिक लोगो की प्रतिक्रियाएँ दीर्घकालिक लाभ की आशाओं पर अधिक और तात्कालिक विक्री की सम्भावनाओं पर कम, अवलम्बित रहती हैं, जब कि पहले यह स्थिति नहीं थी।

हाल के वर्षों में बहुत-से उद्योगों में अनेक प्रकार की फर्मों ने समूची अर्थ-व्यवस्था के विकास की सम्भावनाओं के बारे में बहुत कुछ एक ही जैसी मान्यताएँ अपनायी हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत-सी फर्मों के निवेश सम्बन्धी कार्यक्रम आमतौर पर एक-दूसरे के बहुत अधिक अनुकूल हैं और उनमें तालमेल है। औद्योगिक विस्तार को जारी रखने के बारे में सम्भावनाओं और दृष्टिकोण की इस समानता का एक लाभ निःसन्देह हुआ है और वह यह कि उद्योगों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए व्यवसायों में अधिक पूंजी का निवेश किया गया है और उसके स्तर में और भी अधिक वृद्धि होती जा रही है। इस विस्तार और आधुनिकीकरण ने उत्पादकता में वृद्धि की है और समूची अर्थ-व्यवस्था को ही उन्नत और विकसित किया है।

इस नई किस्म के व्यावसायिक प्रबन्ध की एक विशेषता और भी है और वह यह कि वह परिवर्तमान आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के साथ समझौता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और इस सम्बन्ध में वह व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाता है। प्रबन्धकों में पुराने दकियानूसी और अपरिवर्तनशील कट्टर या विशुद्ध तार्किक सिद्धान्तों के परित्याग के लिए हमेशा तैयार रहने की जो प्रवृत्ति है उसी के कारण वे समूची अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से परिवर्तमान परिस्थितियों के साथ शीघ्रता से समझन कर लेते हैं। प्रबन्धक लोग कारखाने और दफ्तर में नई और अधिक उत्पादक विधियों को विकसित करने और अमल में लाने के लिए तैयार रहते हैं, इसीलिए वे अपने अधिकारी वर्ग के लिए

प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में दिलचस्पी लेते हैं और इंजीनियरी, औद्योगिकी और व्यवसाय-प्रबन्ध सम्बन्धी स्कूल खोलते हैं। किन्तु शिक्षा और प्रशिक्षण से उत्पादकता में वृद्धि तभी होगी, जबकि सिखाने और सीखने को कोई उपयोगी चीज मौजूद हो। इसीलिए उत्पादकता वृद्धि में वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसन्धान का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। इन अनुसन्धानों के बिना अच्छे से अच्छे व्यवसाय प्रबन्धक भी वे सफलताएँ और परिणाम नहीं दिखा सकते थे, जो अब तक उन्होंने दिखाये हैं।

सारांश

अमेरिकी सामाजिक और आर्थिक जीवन में कम्पनियों के एक महत्त्वपूर्ण सस्था के रूप में विकसित होने के फलस्वरूप व्यावसायिक प्रबन्ध की कला भी लगभग उतनी ही आगे बढ़ गई है, जितनी कि कारखाने में औद्योगिक तकनीक विकसित हुई है। कम्पनी प्रबन्धकों के इस नये वर्ग द्वारा अपनाये जाने वाले रुख और तरीकों का महत्त्व अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की सफलता के लिए अधिकाधिक बढ़ता जाएगा।

अनुसन्धान और औद्योगिकी

अमेरिकी दार्शनिक जॉर्ज सेंटायना ने 'आवश्यकता आविष्कार की जननी है' कहावत से भी अधिक गहराई में जाकर कहा था कि प्राचुर्य को आविष्कार का जन्मदाता कहा जाना चाहिए। जो देश या जाति अपनी मौलिक या आर्थिक परिस्थितियों के भारी दबाव के कारण अपनी सीमित प्रतिभा, कल्पना और औजारों को लेकर उनके सहारे जैसे-तैसे जीवन-यापन करती है, वह प्रगति नहीं कर पाती और करती भी है तो अत्यन्त मन्द गति से। यही कारण है कि सम्यता का अधिकतर प्रारम्भिक उत्कर्ष एशिया और अफ्रीका की घन-धान्यपूर्ण हरी-भरी नदी घाटियों में हुआ और वे छोटी-छोटी घुमक्कड़ जनजातियाँ, जिन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उन्हें अगले वक्त का खाना क्या, कहाँ और कब मिलेगा, वे संस्कृति के बिल्कुल आदिम स्तर से आगे नहीं बढ़ सकी। इसमें सन्देह नहीं कि प्राचुर्य ही अमेरिका में भी अनुसन्धान और औद्योगिकी (टैकनोलॉजी) की उन्नति का एक प्रधान कारण और साथ ही प्रधान परिणाम था।

व्यावहारिक और मूल विज्ञान

आज किसी भी आधुनिक देश का बुनियादी या व्यावहारिक विज्ञान की प्रतिभा और उपलब्धियों पर एकाधिकार नहीं है। अमेरिकी लोग मूल विज्ञान के अनुसन्धानों के परिणामों को व्यवहार में लाने और उनसे औद्योगिक क्षेत्र में नई विधियों को अपनाने में विशेष रूप से आगे रहे हैं, भले ही ये आविष्कार या अनुसन्धान अमेरिका में हुए हों या अमेरिका से बाहर। कई वैज्ञानिक खोजें ऐसी हैं, जो हुईं तो अमेरिका से बाहर किन्तु उनका व्यावहारिक उपयोग सबसे पहले अमेरिका में हुआ, क्योंकि

जिन देशों में वे खोजें हुईं, उनके बाजार इतने छोटे और प्रतिस्पर्धाहीन थे कि वे अपने उत्पादन और उत्पादन-विधियों में बार-बार परिवर्तन का खर्च नहीं उठा सकते थे। उदाहरण के लिए मोटर निर्माण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण आविष्कार पश्चिमी यूरोप में हुए, किन्तु जर्मन, ब्रिटिश और फ्रांसीसी उत्पादक, जिनके यहाँ मूलतः ये आविष्कार हुए थे और जिन्होंने उनके औद्योगिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम नमूने तैयार किये थे, अमेरिकी मोटर-निर्माताओं से दस या इससे भी अधिक वर्ष बाद उन्हें अपने कारखानों में प्रयोग में ला सके।

नई-नई विधियों के आविष्कार और प्रयोग की यह प्रवृत्ति ही अमेरिकी उत्पादकता और वैज्ञानिक अनुसन्धान और उसके व्यावहारिक उपयोग के बीच सम्बन्ध की कुजी है। आज इन दोनों के सम्बन्ध का लाभ केवल औद्योगिक या कृषि क्षेत्र में ही नहीं उससे भी अधिक व्यापक क्षेत्र में उठाया जा रहा है। इसकी बदौलत चिकित्सक और दातों के डाक्टर आधुनिक ढंग के नये उपकरणों का, लाट्रियाँ चलाने वाले कपड़े धोने, सुखाने और इस्त्री करने की स्वचालित मशीनों का, और गृहिणियाँ घर की सफाई करने वाली वैक्यूम मशीनों और बर्तन साफ करने वाली बिजली की मशीनों का लाभ उठा रही हैं। यही नहीं और भी बीसियों वर्गों के लोग औद्योगिक क्षेत्र की वैज्ञानिक और औद्योगिकी सम्बन्धी उन्नति का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

इसके अलावा आधुनिक अनुसन्धान और औद्योगिकी की पहुँच उत्पादन की भौतिक प्रक्रियाओं से भी आगे तक है और उनका असर व्यवसायों के संगठन और प्रशासन पर भी पड़ता है। अमेरिकी उद्योगों में बड़े पैमाने पर सामूहिक उत्पादन की नई विधियों के प्रारम्भ होने से पूर्व ही यह अनुभव कर लिया गया था कि जिस तरह नये औजारों और नई मशीनों के उपयोग से उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, वैसे ही उत्पादन की प्रक्रियाओं को कौशलपूर्ण ढंग से संगठित करके भी उसे बढ़ाया जा सकता है। कुछ समय बाद यह भी महसूस किया गया कि यदि श्रमिकों के काम की परिस्थितियाँ अच्छी हों तो उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी

उत्पादन की प्रक्रिया में सघर्ष कम होगा। हाल के वर्षों में प्रदूषण और श्रमिक संगठनों, दोनों के द्वारा किये गए अनुसन्धानात्मक अध्ययनों के फलस्वरूप इन सिद्धान्तों को आम तौर पर स्वीकार कर लिया गया है और उन्हें व्यवहार में लाकर उत्पादकता में वृद्धि भी की जा सकती है।

यद्यपि सामाजिक विज्ञानों का भी उत्पादकता में वृद्धि के लिए बहुत महत्त्व है, तो भी भौतिक विज्ञानों की अपेक्षा उनकी उन्नति अधिक कठिन रही है। इसका एक कारण यह है कि सामाजिक विज्ञानों का स्वरूप ही भौतिक विज्ञानों से भिन्न है—सामाजिक विज्ञानों में एक तो कारण तत्वों की सरया बहुत अधिक होती है, दूसरे उनमें नियन्त्रित ढंग से प्रयोग और परीक्षण करने की गुजायश कम होती है और तीसरे उनमें नैतिक मूल्य सम्बन्धी निर्णयों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन इस कठिनाई का एक कारण यह भी है कि सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में अनुसन्धान के लिए सरकारी या गैर सरकारी क्षेत्रों से पर्याप्त वित्तीय नहायता नहीं मिलती।

वैज्ञानिक और औद्योगिकी सम्बन्धी अनुसन्धानों के परिणामों को आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में प्रयुक्त करना बहुत कुछ विज्ञान की मूल खोजों पर निर्भर है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अधिकतर महान् मूल आविष्कार यूरोप में या यूरोपीय परम्पराओं में प्रशिक्षित वैज्ञानिकों के हाथों हुए हैं।

इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिकी लोगों ने दर्शन और विज्ञान के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण योग नहीं दिया है। जबसे बैजमिन फ्रैंकलिन ने अपने उदाहरण से यह साबित किया कि शुद्ध और प्रयुक्त विज्ञान की प्रतिभा और व्यावहारिक बुद्धि एवं राजनीतिज्ञता का एक ही व्यक्ति में समन्वय सम्भव है, तभी से अमेरिकी लोग भी इन क्षेत्रों में योगदान करते आये हैं। एक और उदाहरण भी लिया जा सकता है—आज की आधुनिक औद्योगिक टेक्नोलॉजी अमेरिकी वैज्ञानिक एली व्हिटने की इस सैद्धान्तिक कल्पना का ही मूर्त रूप है कि मशीनों के पुर्जों में परस्पर परिवर्तन किया जा सकता है। फिर भी पिछले सौ वर्षों में संगठित रूप में बुनियादी

वैज्ञानिक अनुसन्धान अमेरिका में उतना सघन नहीं हुआ, जितना कि यूरोपीय देशों में।

अमेरिका का मूल अनुसन्धान में पीछे रहना यह बताता है कि अमेरिका और यूरोप के मूल और प्रयुक्त वैज्ञानिक अनुसन्धान सम्बन्धी रवियों में अन्तर है। उदाहरण के लिए फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और रूस (जारगाही और कम्युनिस्ट दोनों) की विज्ञान अकादमियों में नियुक्ति, शुद्ध अनुसन्धान में अपना जीवन अर्पण करने वाले नर-नारियों के लिए, सर्वोच्च सम्मान समझी जाती है। इस प्रकार अकादमिशियन बनने की आकांक्षा और ध्येय ने यूरोप की वैज्ञानिक उन्नति को बहुत प्रोत्साहन दिया है। लेकिन अमेरिका में इन विज्ञान अकादमियों की समकक्ष संस्थाओं को यूरोप की इन संस्थाओं के बराबर मान्यता, सहायता और ऊँचा स्थान नहीं मिला है। यूरोप में वैज्ञानिक और अध्यापक को जो प्रतिष्ठा मिलती है वह अमेरिका में प्रायः एक सफल व्यवसाय अधिकारी को, खानकर स्वयं अपने परिश्रम से बने व्यक्ति को, मिलती है।

अमेरिका के वैज्ञानिक उन्नति संघ की परिषद् ने हाल में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि "संयुक्त राज्य में मूल विज्ञान की उन्नति प्रयुक्त (व्यावहारिक) विज्ञान की उन्नति के साथ कदम मिलाकर चलती प्रतीत नहीं होती।" मूल विज्ञान की इस उपेक्षा का जो मुख्य कारण आमतौर पर बताया जाता है, वह यह है कि वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसन्धान के काम में लगे हुए व्यक्तियों और उनके लिए पैसा लगाने वालों, दोनों का मानसिक रुझान व्यावहारिक उपयोग की ओर होता है। दूसरे विश्व युद्ध के दिनों में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने शस्त्रास्त्रों के विकास का काम करने की सरकार की पुकार की ओर ध्यान दिया; युद्ध के बाद उनमें से बहुतने प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने नर-रानी नेत्र छोड़ दी। अधिकतर सृजनात्मक और सफल अनुसन्धानकर्त्ता प्रायः औद्योगिक संस्थानों की प्रयोगशालाओं की ओर आकृष्ट होते जिनमें प्रयुक्त विज्ञानों पर सारा ध्यान केन्द्रित किया जाता है। वे नार या शोधमियों की सहायता 'शुद्ध' वैज्ञानिक अनुसन्धान करने

सस्थाओं की ओर प्राकृष्ट नहीं होते ।

आज संयुक्त राज्य में अनुसन्धान और विकास पर होने वाले सारे खर्च का 10 प्रतिशत से भी कम भाग प्रकृति की बुनियादी प्रक्रियाओं के अनुसन्धान और वैज्ञानिक सिद्धान्तों के निर्धारण और परीक्षण में लगाया जाता है । संयुक्त राज्य में मूल वैज्ञानिक अनुसन्धान में अपेक्षाकृत कम दिलचस्पी और इस प्रयोजन के लिए अपेक्षाकृत कम धन के व्यय पर अमेरिकी वैज्ञानिकों और अमेरिकी सरकार की चिन्ता बराबर बढ़ती रही है ।

ऐसी स्थिति में हाल के वर्षों में रूस ने वैज्ञानिक अनुसन्धान में जो असाधारण उन्नति की है उसने अमेरिकी को बहुत बड़ा आघात पहुँचाया है और उसी के कारण यहाँ शिक्षा और अनुसन्धान की प्रणाली और उसके सम्बन्ध में अमेरिकी लोगों के बुनियादी रुख पर सम्पूर्ण रूप से पुनर्विचार को और भी बल मिला है । यह सम्भव है कि इस पुनर्विचार का असर हमारी शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर पड़े, प्राथमिक, माध्यमिक और व्यावसायिक स्कूल और विश्वविद्यालय आदि सभी उससे प्रभावित हो और मूल अनुसन्धान को और अधिक बल और प्रोत्साहन मिले ।

विज्ञान और औद्योगिकी के विकास में अमेरिकी लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि इस क्षेत्र में अपनी कमजोरी की गम्भीर चुनौती को वे किसी भी तरह दर-गुजर और नजरन्दाज नहीं करेंगे । लेकिन एक खतरा भी है कि इस कमी को दूर करने की जल्दबाजी में कहीं अमेरिकी लोग तकनीकी शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान और गणित को बहुत सकुचित अर्थ में न लेने लगे । इन क्षेत्रों में सृजनात्मक उपलब्धियाँ केवल तकनीक और बारीकियों के अध्ययन पर ही नहीं, बल्कि इन विज्ञानों के सैद्धांतिक और दार्शनिक पक्षों पर भी निर्भर हैं, बल्कि यह बात और भी अधिक महत्वपूर्ण है । और इन सैद्धान्तिक और दार्शनिक पक्षों की जड़ समग्र रूप से संस्कृति के अधिक व्यापक और उर्वरक प्रभावों में गहराई तक खोई रहती है । जहाँ सांस्कृतिक परम्परा समृद्ध और विविधतापूर्ण

तकनीकी उन्नतियों और नवीन वैज्ञानिक सुधारों का परिणाम भी है और कारण भी ।

तालिका 6

संयुक्त राज्य के 11 चुने हुए उद्योगों¹ की प्रयोगशालाएँ और उनमें काम करने वाले कार्यकर्त्ता—1945-1960

	1945	1950	1955	1960 (अनुमान)	प्रतिशत वृद्धि 1945-60 (अनुमान)
प्रयोग- शालाओं की संख्या	1,855	2,414	3,760	5,600	200
वैज्ञानिक और इंजीनियर	50,560	70,182	1,19,641	2,08,500	310
सहायक कार्यकर्त्ता	70,544	87,547	1,41,256	2,10,000	200
प्रयोग- शालाओं के कुल कार्यकर्त्ता	1,21,104	1,57,729	2,60,897	4,18,500	245

उद्योगों, सरकार और शिक्षा संस्थाओं में जैसे-जैसे अधिकाधिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नियुक्तियाँ हुई हैं, वैसे-वैसे अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी कार्यों पर खर्च भी बढ़ता रहा है । यद्यपि शुरू के वर्षों के आकड़ों हाल के वर्षों के आकड़ों की भांति पूर्णतः सही नहीं हैं, तो भी यह अनुमान लगाना अनुचित नहीं होगा कि 1946 से 1953 तक उद्योगों

1. इन उद्योगों में लगभग 85 प्रतिशत वैज्ञानिक कार्यकर्त्ता लगे हुए हैं ।

मे अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी कार्य दुगुने हो गए है। और सन् 1953 के बाद से वे फिर तिगुने हो गए है। सन् 1953 मे अनुसन्धान और विकास पर कुल आनुमानिक खर्च 5 अरब डालर से अधिक था और युद्धोत्तर वर्षों की औसत वार्षिक वृद्धि के दर से सन् 1961 मे उसे 14 या 15 अरब डालर हो जाना चाहिए। दूसरे शब्दों मे संयुक्त राज्य की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 3 प्रतिशत इस समय अनुसन्धान और विकास पर खर्च हो रहा है।

सन् 1959-60 मे अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी सारे खर्च का दो-तिहाई सघीय सरकार ने दिया, हालांकि वास्तविक काम का कुल 20 प्रतिशत ही सघीय विभागों और संस्थाओं द्वारा किया गया। सरकार के अधिकांश अनुसन्धान और विकास के कार्य प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा कराये गए। इस प्रकार मोटे तौर पर सारे अनुसन्धान और विकास कार्य का तीन चौथाई काम प्राइवेट उद्योगों ने किया। लेकिन इस पर हुए खर्च का केवल 50 प्रतिशत ही उन्होंने अपने धन मे से किया, शेष 50 प्रतिशत सघीय सरकार ने दिया।

तालिका 7

अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी व्यय का प्रतिशत वितरण

	वित्तीय साधन		अनुसन्धान—कार्य	
	अनुसन्धान और विकास	बुनियादी अनुसन्धान	अनुसन्धान और विकास	बुनियादी अनुसन्धान
संघीय सरकार	64	56	15	19
उद्योग	33	26	75	30
कालेज और विश्वविद्यालय	2	12	8	44
मुनाफा न कराने वाली अन्य संस्थाएँ	1	6	2	7
	100	100	100	100

सरकार द्वारा या सरकारी पैसे से प्रतिरक्षा सम्बन्धी (सैनिक) वैज्ञानिक अनुसन्धान और विकास का एक बड़ा हिस्सा देर-सवेर गति कालीन असैनिक कार्यों में प्रयुक्त होने लगता है। यही कारण है कि युद्ध काल में हुए वैज्ञानिक अनुसन्धान और विकास कार्यों के फलस्वरूप अब हम संयुक्त राज्य में तथाकथित 'दूसरी औद्योगिक क्रान्ति' (सैकण्ड टैक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन) देख रहे हैं।

औद्योगिक अनुसन्धान में योग देने वाला एक बड़ा कारण द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद निगम कर (कॉर्पोरेट टैक्स) में भारी वृद्धि है। निगम कर का हिसाब लगाते हुए अनुसन्धान और विकास सम्बन्धी खर्चों को आमतौर पर व्यावसायिक व्यय मानकर कर से मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार अधिक साहसी कम्पनियाँ इस प्रकार के कामों पर अपना व्यय बढ़ा देती हैं, जिन पर उन्हें अपने पास से अधिक पैसा न लगाकर टैक्स में से बचायी हुई रकम लगाने की सुविधा मिल जाती है।

अनुसन्धान और विकास पर अमेरिकी उद्योगों द्वारा अधिकाधिक धन का व्यय किया जाना इस बात का प्रमाण है कि वे संयुक्त राज्य की-सी गतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकता-वृद्धि के लिए उसके महत्त्व को अनुभव करने लगे हैं। औद्योगिक तकनीकों के विकास से प्रति मानव घण्टा उत्पादन में भी वृद्धि होती है और साथ ही मजदूरी में भी तदनुसार वृद्धि की जा सकती है। इसके प्रतिलोम की दृष्टि से कहा जाय तो यह भी कह सकते हैं कि जब मजदूरों की मजदूरी की दर बढ़ जाती है तब खर्च को घटाने के लिए ऐसी तकनीकी विधियाँ निकालनी पड़ती हैं जिनसे मानवीय श्रम की बचत की जा सके। आम-तौर पर जिन देशों में मजदूरों की संख्या बहुत बड़ी और मजदूरी की दर अपेक्षाकृत कम होती है, उनमें श्रम की बचत करने के तरीके निकालने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता। किन्तु कुछ मामलों में अन्य कारणों से इन देशों में नई तकनीकों के विकास के लिए प्रयत्न किया जाता है। पुराने तरीकों में सुधार और नये तरीकों का आविष्कार कर पुराने तरीकों से निर्मित वस्तु की अपेक्षा अधिक अच्छी और बेहतर किस्म की

वस्तु तैयार की जा सकती है। उदाहरण के लिए पुराने ढंग के तेल शोधक कारखानों में जो गैसोलिन (विमानों में प्रयुक्त पेट्रोल) तैयार किया जाता था, वह बिल्कुल एक-सा नहीं होता था और बार-बार प्रयोगशालाओं में नमूनों की परीक्षा करके और उसके आधार पर विभिन्न पैमाने वाले गैसोलिनो को मिलाकर सही चीज तैयार की जाती थी, परन्तु नये और स्वचालित तेलशोधक कारखानों में यह कठिनाई नहीं है, उनमें एक-सा गैसोलिन स्वयं तैयार होता जाता है। इस प्रकार संयुक्त राज्य में जो नई औद्योगिक विधियाँ मजदूरी की ऊँची दर के कारण श्रम की बचत के लिए निकाली गई हैं, वे अन्य देशों में मजदूरी की दर अपेक्षाकृत नीची होने पर भी इसलिए अपनायी जाती हैं कि उनसे उत्पादित माल की किस्म अच्छी होती है।

लेकिन यह जरूरी नहीं है कि औद्योगिक तकनीकी विधियों में सुधार मानव के लिए हितकारी ही हो। अठारहवीं और उन्नीसवीं शताब्दियों में जो नई शिल्पिक पद्धतियाँ निकाली गईं उन्होंने दस्तकारी को खत्म कर दिया और अक्सर उनके परिणामस्वरूप मानवीय श्रम की प्रतिष्ठा घटी और हाथ से काम करने वाले शिल्पी सृजनात्मक काम के आनन्द से वंचित हो गए। किन्तु बीसवीं शताब्दी में स्वचालित और स्वनियन्त्रित मशीनों और औद्योगिक विधियों के आविष्कार का यह लाभ हुआ कि कारीगरों को पुरानी परम्परागत विधियों में जो समय और हाथ और दिमाग की ताकत लगानी पड़ती थी, उसमें काफी बचत हुई। इस तरह यान्त्रिकीकरण से, और खासकर हाल में हुए स्वचालित विधियों के क्रमिक विकास से श्रम की प्रतिष्ठा और उसमें सृजन के आनन्द की पुनः स्थापना हुई है, हालांकि यह प्रतिष्ठा और आनन्द औद्योगिक युग से पहले के समाजों में प्रचलित श्रम की प्रतिष्ठा और आनन्द से भिन्न है। आज श्रमिक मशीन का गुलाम नहीं रहा, वह उत्पादन-प्रणाली का अधीक्षक और रक्षक बन गया है।

सारांश

आधुनिक अनुसन्धान गतिशील आर्थिक प्रक्रिया का हृदय है।

इसकी बढ़ती उत्पादन अधिक और उत्कृष्ट किस्म का होता है और लागत में वृद्धि के बावजूद अन्त में वह सस्ता पड़ता है। संयुक्त राज्य में नई औद्योगिक विधियों के विकास और प्रयोग ने अमेरिकी श्रमिक की उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है। इनमें से बहुत-सी नई औद्योगिक विधियाँ अन्य देशों से प्राप्त ज्ञान पर आधारित हैं और कुछ विधियाँ बड़े पैमाने पर विक्री का, जो अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की विशेषताएँ हैं, परिणाम भी हैं और उसका कारण भी। वैज्ञानिक और औद्योगिक तकनीकों के क्षेत्र में होने वाली यह उन्नति, चाहे उसका उद्गम अमेरिका हो या कोई अन्य देश, अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकता को बढ़ाती रहेगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक तकनीकों की यह उन्नति केवल इसी बात पर निर्भर नहीं होगी कि उसके लिए सुप्रशिक्षित वैज्ञानिक और कुशल टैकनीशियन अधिकाधिक संख्या में उपलब्ध होते या नहीं, बल्कि शुद्ध बुनियादी विज्ञान और उसके व्यावहारिक उपयोग के अध्ययन और अनुसन्धान के लिए पर्याप्त धन और साधनों की उपलब्धि भी उसके लिए उतनी ही आवश्यक और महत्वपूर्ण होगी। साथ ही इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि अमेरिकी शिक्षा-प्रणाली के उद्देश्यों पर पुनर्विचार किया जाय और अध्ययन की विषय-वस्तु और अध्यापन की विधियों में सुधार किया जाय।

श्रमिकों का कौशल, प्रबन्ध-व्यवस्था की दक्षता और नई औद्योगिक विधियों का विकास उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के लिए तभी पूर्णतः लाभकारी हो सकते हैं, जब कि आवश्यक सयन्त्र और साधनों के लिए पर्याप्त पूँजी उपलब्ध हो। यदि पूँजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो उससे उत्पादकता में वृद्धि होती है और जब उत्पादकता बढ़ जाती है तो वह उद्योग के भीतर से ही नई पूँजी को जन्म देती है और वह पूँजी फिर उत्पादकता को बढ़ाती है। इस प्रकार पूँजी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि आर्थिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है और इसका प्रतिलोम स्वभावतः यह होगा कि जो देश अपना आर्थिक विकास तेजी से करना चाहते हैं उनके मार्ग में पूँजी की कमी सबसे बड़ी बाधा है। इन देशों के समक्ष यह कठिन समस्या खड़ी हो जाती है कि जो थोड़ा-सा उत्पादन बढ़ता है उसकी आय कैसे बाँटे। उसका कितना अंश आम लोगों की माँग की पूर्ति में, कितना सार्वजनिक (सरकारी) कार्यक्रमों की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति में लगाये और कितना अंश उत्पादक उद्योगों की पूँजी बढ़ाने के लिए।

विदेशी पूँजी का योगदान

संयुक्त राज्य को भी अपने औद्योगिक विकास के प्रारम्भिक दौर में, अन्य अल्पविकसित देशों की भाँति अपनी पूँजी की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए न केवल अपने आन्तरिक वित्तीय साधनों को शक्ति कर डालने के बजाय पूँजी के रूप में निवेश (इन्वेस्ट) करना पड़ा बल्कि अन्य देशों से भी पूँजी को आकृष्ट करना पड़ा। अन्य देशों

भाँति अमेरिका में भी आन्तरिक स्रोतों से उपलब्ध पूँजी अन्य देशों से आयातित पूँजी की अपेक्षा मात्रा से भी अधिक थी और उस पर भरोसा भी अधिक किया जा सकता था। लेकिन प्रथम विश्वयुद्ध तक अमेरिका के विकास में विदेशी पूँजी का, सासकर प्राइवेट पूँजी का, महत्वपूर्ण स्थान था। सन् 1914 में संयुक्त राज्य में लगी विदेशी पूँजी 7 अरब डालर की थी, जिसकी क्रय शक्ति चालू मूल्यों के हिसाब से 35 अरब डालर की थी (देखिये परिशिष्ट तालिका 17)। यही नहीं, प्रथम विश्वयुद्ध से पूर्व अमेरिका के आर्थिक विकास में विदेशी पूँजी का योगदान केवल 7 अरब डालर ही नहीं था, क्योंकि कुछ पूँजी जो इस 7 अरब डालर में शामिल नहीं है, पहले ही अमेरिका ने सम्बद्ध देशों को वापस लौटा दी थी। इसके अतिरिक्त 9 अरब डालर की इस राशि में विदेशी पूँजी-निवेशकों को अमेरिका में अपने पूँजी-निवेश पर हुआ आशिक या पूर्ण नुकसान शामिल नहीं है, हालांकि नुकसान की यह रकम भी अमेरिका में ही लग गई थी और उससे अमेरिका में बहुत-से उत्पादक मयन्त्रों और अन्य साधनों का निर्माण हो गया था। उदाहरण के लिए विदेशी पूँजी से खुली कई रेल कम्पनियाँ अमेरिका में दिवालिया हो गईं, जब कि उनकी रेलें वाकायदा अमेरिका में चलती रही। इस प्रकार दिवाला निकल जाने पर उनकी पूँजी अमेरिका में ही रह गई।

सन् 1914 के बाद संयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था के विकास में प्राइवेट विदेशी पूँजी का योगदान पहले से बहुत कम हो गया। यह समस्या भी बहुत महत्वपूर्ण, नहीं रही कि उद्योगों से होने वाले लाभ को खर्च करने के लिए लोगों में वितरण कर दिया जाय या पूँजी के रूप में पुनः निविष्ट किया जाय। आज संयुक्त राज्य में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, दोनों का स्तर इतना ऊँचा है कि लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के लिए उनकी क्रय-शक्ति बढ़ाई जा सकती है, सरकारी कार्यक्रमों में धन लगाया जा सकता है और प्राइवेट उद्योगों, व्यवसायों और कृषि में भी पूँजी के रूप में उसका निवेश

किया जा सकता है। दर असल, अमेरिका में इस समय कुल उत्पादन इतना अधिक है कि उससे देशवासियों की उपभोग और पूँजी-निवेश की आवश्यकताओं को कोई गम्भीर नुक्सान पहुँचाये बिना सरकार के प्रतिरक्षा और वैदेशिक सहायता के कार्यक्रम को भी काफी ऊँचे स्तर पर रखा जा सकता है।

आन्तरिक पूँजी के स्रोत

हाल के दशकों में संयुक्त राज्य में कुल वचन इतनी रही है कि वह न केवल अपनी बढ़ती हुई आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताएँ पूरी कर सकती थी, बल्कि उससे अन्य देशों को पूँजी का निर्यात भी किया जा सकता था। इन दशकों में पूँजी की कुछ कठिनाई सिर्फ़ तभी पैदा हुई जब सरकार को युद्ध के दिनों में बहुत बड़ी मात्रा में बाजार से ऋण लेना पड़ा या जब हाल के वर्षों में अमेरिका में बहुत बड़ी मात्रा में उद्योग-व्यवसाय और कृषि आदि में पूँजी के निवेश का जबरदस्त दौर आया। किन्तु यह सम्भावना भी ध्यान में रखने योग्य है कि एक ही समय में कुछ कामों के लिए पूँजी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो सकती है और कुछ के लिए वह बहुत दुर्लभ भी हो सकती है। पूँजी के बाजार की स्थिति का बारीकी से अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार की वचनों और निवेशों पर एक नजर डालना जरूरी है।

संयुक्त राज्य में पूँजी निर्माण का वित्तीय स्रोत विभिन्न प्रकार की वचतें हैं—व्यक्तिगत, सन्यागत, कम्पनियों की और सरकारी। अमेरिकी विकास के प्रारम्भिक दौर में उत्पादक निवेश के निम्न अधिकतर पूँजी धनी व्यक्तियों और परिवारों की वचत से प्राप्त होती थी। यद्यपि व्यक्तिगत वचन का आज भी बहुत महत्त्व है, तो भी हाल के दशकों में अन्य किस्मों की वचतें भी तीव्र गति से बढ़ती रही हैं और आज वे कुल वचन के आधे से काफी अधिक हैं।

सन् 1920 और सन् 1950 में प्रारम्भ दशकों के अन्तिम वर्षों की यदि परस्पर तुलना की जाय तो यह परिवर्तन सहज में ही समझा जा

सकता है। यह परिवर्तन आप लोगों की व्यक्तिगत वचतो में विशेष रूप से नज़र आता है। आज आम लोगों के पास नकदी और बैंको में जमा रकम की शक्ल में मौजूद व्यक्तिगत वचत कुल प्राइवेट (गैर सरकारी) वचत के प्रतिगत अनुपात की दृष्टि से चौगुनी हो गई है और वह पूंजी-निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। साथ ही किस्तों पर की गई खरीद और मकान गिरवी रखकर लिये गए ऋणों की अदायगी के लिए भी आम लोग पहले से काफी अधिक रकम चुकाते हैं। पहले यह स्थिति थी कि कोई भी व्यक्ति तब तक मोटर, घरेलू सामान या कपड़ा आदि नहीं खरीद सकता था, जब तक कि उसकी पूरी कीमत चुकाने के लिए उसने पैसा न बचा लिया है। लेकिन आज लोग मामान खरीद पहले लेते हैं और फिर उसकी कीमत किस्तों में आहिस्ता-आहिस्ता चुकाते रहते हैं। इसके विपरीत हम देखते हैं कि पहले आम लोगों की वचत शेयरों और सिक्यूरिटियों में अधिक लगी होती थी, परन्तु आज उसमें कमी हो गई है। पहले इनमें लगी व्यक्तिगत वचत की मात्रा कुल प्राइवेट वचत का 39 प्रतिशत थी, जबकि आज वह सिर्फ 6 प्रतिशत है।

हाल के दशकों में प्राइवेट और सरकारी सत्यागत कार्य-क्रमों की पूंजी-निवेश निधियों में भी बहुत वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए प्राइवेट व्यवसायों के बीमा और श्रमिक कल्याण निधियों से, ट्रेड यूनियनों और मुनाफा न कमाने वाले अन्य संगठनों एवं सरकार के बीमा और पेन्शन कार्यक्रमों के द्वारा निवेश के लिए काफी पूंजी उपलब्ध हो जाती है। इन संस्थागत वचतों से न केवल अमेरिकी परिवारों की बहुत बड़ी सत्या को दुर्घटना, हारी-बीमारी, रिटायरमेंट, मृत्यु आदि की अवस्थाओं में काफी लाभ प्राप्त हो जाते हैं, बल्कि प्रतिवर्ष पूंजी के रूप में निवेश के लिए जो बहुत बड़ी रकम आवश्यक होती है, उसका भी एक बड़ा हिस्सा उपलब्ध हो जाता है। इन सत्याओं के जरिये आम अमेरिकी श्रमिकों और मध्यम-आय वर्ग के लोगों की व्यक्तिगत वचत पूंजी-निवेश के लिए अप्रत्यक्ष रीति से प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, सन् 1960 के अन्त . प्राइवेट पेन्शन योजनाओं की ही करीब 50 अरब डालर की राशि

पूँजी के रूप में विभिन्न स्थानों पर लगी हुई थी—इसका 80 प्रतिशत से अधिक भाग व्यावसायिक कम्पनियों के शेयरों और बांडों के रूप में लगा हुआ था—और उसमें 5 अरब डालर वार्षिक की दर से वृद्धि हो रही थी। इस प्रकार करोड़ों अमेरिकी लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक कम्पनियों के शेयरों के स्वामित्व का लाभ पहुँच रहा है। यह लाभ लाभार्थ (डिविडेंड) और शेयरों की मूल्य वृद्धि के रूप में मिलता है। बहुत-सी ट्रेड यूनियनों ने भी व्यावसायिक कम्पनियों के शेयरों में तथा अन्य विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक उद्यमों में पूँजी लगाई हुई है।

पूँजी-निर्माण के लिए व्यावसायिक कम्पनियों की बचतें तीसरा बड़ा स्रोत है। कुल प्राइवेट बचतों की तुलना में प्रतिशत की दृष्टि से व्यावसायिक कम्पनियों की बचत का अनुपात प्रायः हमेशा एक ही रहा है। व्यवसायों में पूँजी-निवेश और पूँजी के विस्तार के लिए यह स्रोत बहुत महत्वपूर्ण है और इसके महत्व का पता व्यवसायिक कम्पनियों की कुल बचत (मूल्य ह्रास के लिए काटी गई रकमें और अवितरित लाभ) और कुल निविष्ट पूँजी के अनुपात से लग सकता है।

हाल के वर्षों में व्यवसायों में पूँजी-निर्माण में कम्पनियों की अवितरित लाभ की राशि का हिस्सा उतना नहीं रहा, जितना कि उनकी मूल्य ह्रास निधि का। इसका कारण यह है कि 1947-49 के काल के बाद से जब कि अमेरिकी उद्योगों में स्थित पूँजी परिसम्पत्तियों (फिक्सड कैपिटल एसेट) का स्तर बहुत नीचा था, कारखानों के सयन्त्रों और मशीनों आदि में बहुत बड़ी मात्रा में पूँजी लगी है। सन् 1954 के बाद से मूल्य-ह्रास निधियाँ और भी बढ़ी हैं क्योंकि कर का हिसाब लगाने के लिए मूल्य-ह्रास की छूट की सीमा काफी उदारता से बढ़ा दी गई थी। सन् 1960 में अवित्तीय कम्पनियों की कुल बचतें 30.3 अरब डालर की थी, जब कि उस वर्ष उन्होंने लगभग उतनी ही, यानी 30.8 अरब डालर की रकम सयन्त्रों और मशीनों आदि में लगाई। इस प्रकार उद्योगों के विस्तार और उन के आधुनिकीकरण के लिए पूँजी उनके आन्तरिक स्रोतों से ही उपलब्ध हो जाती है।

तालिका ८

प्राइवेट वचतों का विवरण (वार्षिक औसत)

	1926-29		1957-60	
कुल अतिरिक्त वृद्धि	अरब डालर प्रतिशत		अरब डालर प्रतिशत	
व्यक्तिगत वचतें	7 7	65 7	14 0	42 3
नकद और जमा (वचत और ऋण शेयर सहित)	1 0	8 6	12.4	37 6
प्राइवेट सिक्यूरिटियाँ (शेयर और बांड)	4 6	39 3	1 9	5 7
अन्य शुद्ध वचतें ¹	2 1	17 8	—0 3	—1.0
संस्थागत वचतें	1 7	14.6	10 9	33 0
प्राइवेट बीमा और पेन्शन निधियाँ	1 5	12 8	.6	26 0
सरकारी बीमा और पेन्शन निधियाँ	2	1 8	2 3	7 0
कम्पनियों की वचतें ²	2 3	19 7	8 2	24 7
कुल प्राइवेट वचत	11.7	100 0	33 1	100 0

1 इसमें लोगोंके पास मौजूद सरकारी सिक्यूरिटियाँ और अन्य स्थायी परिसम्पत्तियाँ भी शामिल हैं, किन्तु इसमें से उनकी देनदारियाँ और मूल्यहास की रकमें निकाल दी गई हैं।

2 व्यावसायिक कम्पनियों द्वारा सुरक्षित निधि में रखा गया अवितरित मुनाफा।

स्वयं अपने साधनों में वित्त की व्यवस्था करने के लाभ भी हैं और हानियाँ भी। लाभ यह कि उद्योगों के साहसी, प्रतिभाशाली और कल्पनाशील प्रबन्धकों को उससे कार्य की अधिक स्वतन्त्रता रहती है। यदि उद्योग-व्यवसाय के प्रबन्धकों को ऋण देने वाली संस्थाओं और द्रव्य-बाजार को अपने हर काम का व्योरा देना पड़े और इस तरह उन्हें काम की पूरी स्वतन्त्रता न रहे तो उनमें नये विकास-कार्य करने और नई

तालिका 9

कम्पनियों की निधियों¹ के स्रोत और उनके उपयोग (वार्षिक औसत)

	1947-49		1957-60	
	अरब डालर प्रतिशत		अरब डालर प्रतिशत	
स्रोत—कुल योग	22.6	100.0	38.2	100.0
आन्तरिक—योग	16.8	74.3	28.8	75.4
मूल्य-ह्रास	6.2	27.3	20.9	54.7
अवितरित लाभ	10.6	47.0	7.9	20.7
बाह्य—योग	5.8	25.7	9.4	24.6
कुल नई शेयर पूंजी	4.9	21.7	7.9	20.7
अन्य देनदारियों में परिवर्तन	0.9	4.0	1.5	3.9
उपयोग—कुल योग	23.1	100.0	37.5	100.0
कुल कार्यकारी पूंजी	5.4	23.3	6.4	17.2
सयन्त्र और मशीनें आदि	17.4	75.4	26.6	78.8
अन्य परिसम्पत्तियाँ	3	13	1.5	4.0
असंगत (स्रोत उपयोग के कम)	—0.5			

1. इसमें बैंक, बचत और ऋण एसोसियेशनें, बीमा कम्पनियाँ और निवेश कम्पनियाँ शामिल नहीं हैं।

औद्योगिक विधियों को अपनाने की गति बहुत मन्द रहेगी। दूसरी ओर कुछ हानि भी सम्भव है क्योंकि यदि ऋण के रूप में पूँजी देने वाले बाहर के लोगो का कोई नियन्त्रण न रहे तो प्रबन्धको की इस स्वतन्त्रता के फलस्वरूप कुछ अपव्यय भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत-से छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यवसाय अपनी निज की वचतों से अपनी नई पूँजी की आवश्यकताएँ बहुत कम ही पूरी कर सकते हैं। इस हानि के बावजूद अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकता की गति में वृद्धि और विस्तार में कम्पनियों द्वारा अपने लिए स्वयं अपने आन्तरिक स्रोतों से ही पूँजी की व्यवस्था ने भारी योग दिया है।

पूँजी का उपयोग

हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य में व्यक्तिगत वचत का स्तर बहुत ऊँचा रहा है। किन्तु साथ ही लोगो द्वारा वचत की गई राशि के स्वयं अपने ही लिए उपयोग का स्तर भी बहुत ऊँचा रहा है। उदाहरण के लिए सन् 1960 में उपभोक्ताओं पर दुकानों का उधार माल का कर्ज 4 अरब डालर बढ़ गया। इसके अलावा उपभोक्ताओं ने अपने पारिवारिक मकान गिरवी रखकर इस वर्ष 11 अरब डालर का और अतिरिक्त कर्ज लिया। दूसरी ओर सब मिलाकर इस वर्ष उपभोक्ताओं ने अपनी व्यक्तिगत वचतों के रूप में 23 अरब डालर की राशि व्यावसायिक पूँजी-निवेश के लिए (इसमें रिहायशी मकानों का निर्माण भी शामिल है) शेयरों की खरीद की शक्ति में और सघीय और राज्यीय सरकारों और स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को स्कूलों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक निर्माण-कार्यों के लिए उनकी सिक्यूरिटियों की खरीद की शक्ति में दी। फिर भी यदि अमेरिकी उद्योग अपने विस्तार और आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के लिए अधिकतर वित्त व्यवस्था अपनी ही वचत से न कर पाते तो उपलब्ध पूँजी के लिए आपसी प्रतिस्पर्धा अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि की गति को कम कर देती। वचत की रकमों के उपयोग और पूँजी-निवेश की गति को दृष्टि में रखते हुए यह कल्पना सगत नहीं है।

कुल वचतो का एक बड़ा भाग उपभोक्ता स्वयं अपने लिए आवश्यक वस्तुएँ किस्तों पर खरीदने या अपने लिए मकान बनवाने पर खर्च कर देते हैं, यह सही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि वचतो का यह भाग उत्पादकता को बढ़ाने में कोई योग नहीं देता । यदि उपभोक्ताओं को किस्तों पर स्थायी और टिकाऊ सामान खरीदने के लिए देने को यह वचत की रकम न होती तो टिकाऊ उपभोग्य सामग्रियों की बड़े पैमाने पर विक्री का बाजार न रहता । साथ ही यदि वाजिव शर्तों पर मकानों को गिरवी रखकर पर्याप्त कर्ज न मिल सकता तो पिछले वर्ष प्राइवेट घन से बने 13 लाख नये मकान बनकर खड़े न हो पाते और न इमारती सामान और घर की सजावट की सामग्रों के लिए ही एक विशाल बाजार बन पाता । बड़े पैमाने पर वस्तुओं की विक्री होने पर ही बहुत-सी नई तकनीकी उत्पादन विधियों को उद्योगों में अपनाना सम्भव होता है ।

सारांश

शासन

यह बात आम तौर पर स्वीकार की जाती है कि प्राकृतिक साधन, श्रमिकों की दक्षता, प्रबन्ध-कौशल, नई-नई तकनीकी विधियों को अपनाने का प्रयत्न और पूँजी का अपेक्षाकृत प्राचुर्य—ये चीज़ें अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की ऊँची उत्पादकता के लिए अनिवार्य हैं। लेकिन एक बात के सम्बन्ध में लोगों में मतभेद नहीं पाया जाता और वह है शासन की नीतियाँ और कार्यवाहियाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो शासन की उन्नीसवीं सदी की कल्पना से ही चिपके हुए हैं। उनका खयाल है कि सरकार को उत्पादकता में सिर्फ इतना ही योग देना चाहिए कि वह कानून और व्यवस्था को बनाये रखे और शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों और स्वच्छता के क्षेत्रों में आवश्यक सार्वजनिक सेवाएँ उपलब्ध कराती रहे। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे हैं, जो कहते हैं कि उत्पादन के साधनों पर अमुक सीमा तक सरकार का नियन्त्रण रहना चाहिये, बल्कि कुछ लोगों की राय में ये साधन सरकार के स्वामित्व में रहने चाहिए, और कुछ लोगों का मत है कि सरकार को ही उनका संचालन करना चाहिए।

किन्तु संयुक्त राज्य में शासन (सरकार) की कार्य पद्धति विचार-धारा की इन दोनों चरम सीमाओं में से किसी का भी स्पर्श नहीं करती। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था प्रधानतः निजी (गैरसरकारी) उद्योगों द्वारा गठित है, फिर भी सरकार उस पर महज पहरेदारी का ही काम नहीं करती। अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि साहसी, गतिशील और उत्तरदायित्व की भावना से युक्त प्राइवेट उद्यम और रचनात्मक एवं दूरदर्शितापूर्ण सरकारी नीतियों में कोई असंगति नहीं है, बल्कि दोनों एक-दूसरे के साथ खूब निभते हैं। इस प्रणाली के अन्तर्गत आर्थिक प्रक्रिया पर शासन के तानाशाही नियन्त्रण के बिना ही उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है

और उसका स्तर निरन्तर ऊँचा उठता जा रहा है और साथ ही जनता का रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा हो रहा है। यहाँ आर्थिक कल्याण की प्राप्ति अमेरिकी की अपरिहार्य लोकतन्त्रीय स्वतन्त्रता के साथ पूर्णतः सगत रही है। इन मूल्यों में, जिनमें परस्पर विरोध की सम्भावना निहित है, परस्पर समन्वय सिर्फ इस लिए सम्भव हुआ है कि सरकार द्वारा उठाये गए कदम प्राइवेट उद्योग-व्यवसाय और उपभोक्ताओं को काटने के बजाय उनके पूरक रहे हैं।

यहाँ यह भेद स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि शासन के भी तीन स्तर हैं—सघीय, राज्यीय और स्थानीय, और इन तीनों स्तरों के शासन की भी तीन अलग-अलग शाखाएँ हैं—कार्यपालिका, विधायिका और न्याय-पालिका। इस त्रिपक्षीय प्रणाली का जन्म औपनिवेशिक शासन के दिनों में हुआ था। बाद में जब क्रांति के दौरान में और उसके बाद राज्यों के संविधान बनाये गए और सन् 1789 में सघीय संविधान बनाया गया तब उनमें भी उसे पूर्ण रूप में समाविष्ट कर लिया गया। किन्तु इन तीनों स्तरों और इन तीनों शाखाओं के परस्पर सम्बन्ध तब से वैसे ही नहीं चले आ रहे, उनमें बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तन होते रहे हैं। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सघीय सरकार की जिम्मेदारियाँ और उसमें भी राष्ट्रपति की जिम्मेदारियाँ, ऐसी समस्याएँ पैदा होने पर बराबर बढ़ती रही हैं, जो राज्यीय या स्थानीय शासन की क्षमता से बाहर थी और जिनके लिए कार्यपालिका द्वारा पहल की जाने और व्यापक प्रशासनिक कदम उठाये जाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार इस दौरान में, खास कर हाल के दशकों में, राष्ट्रपति और नसद् (कांग्रेस) के सम्बन्धों, सघीय सरकार और राज्यीय एवं स्थानीय सरकारों के सम्बन्धों तथा सरकारी और गैर-सरकारी जिम्मेदारियों के सम्बन्धों में बहुत परिवर्तन हुआ है।

आज सरकार का, अन्य सभी आधुनिक देशों की भाँति, अमेरिका में भी जन-जीवन में बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। वह जनता की अनेक प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती है और उनके बढ़ते में जनता तरह-तरह

के करो के रूप में अपनी आय की एक निश्चित प्रतिशत मात्रा उसे देती है। तालिका 10 में यह बताया गया है कि किस देश में आय का कितने प्रतिशत भाग करो के रूप में सरकार के पास जाता है।

संयुक्त राज्य में सरकार की गति-विधियाँ आर्थिक प्रक्रिया को अनेक विभिन्न रूपों में प्रभावित करती हैं। इनमें से कुछ सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का उद्देश्य कृषि, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन और वित्त के क्षेत्रों में प्राइवेट उद्यमों को सहायता और सुरक्षा प्रदान करना है। उसकी अन्य प्रवृत्तियों में अनेक प्रकार के ऐसे नियमों और प्रतिबन्धों को लागू करना शामिल है, जिनका प्रयोजन श्रमिकों और उपभोक्ताओं के और छोटे किसान, बेरोजगार, विकलांग और बूढ़े आदि

तालिका 10

सन् 1960 में शासन के सभी स्तरों पर¹ विभिन्न देशों में अदा किये गए कुल कर राष्ट्रीय आय के प्रतिशत अनुपात में (प्रारम्भिक अनुमान)

संयुक्त राज्य	26.2
फ्रांस	35.4
आस्ट्रिया	32.8
पश्चिमी जर्मनी	32.6
नार्वे	30.7
नीदरलैंड्स	30.3
इटली	30.0
ब्रिटेन	29.7
डेनमार्क	24.1
बेल्जियम-लक्सम्बर्ग	23.8
पुर्तगाल	17.0

1. इसमें सामाजिक बोमे के रूप में काटी गई राशियाँ भी शामिल हैं।

इसी प्रकार के अन्य दुर्बल और अल्पाधिकारी वर्गों के, अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना है। इनमें से बहुत-सी सरकारी प्रवृत्तियाँ दीर्घ काल से चली आ रही हैं और राजनीतिक प्रशासनों (सरकारों) के बदलते रहने पर भी जारी रही हैं।

प्राकृतिक साधनों का विकास

संयुक्त राज्य के इतिहास में सरकार हमेशा ही कृषि और अन्य प्राकृतिक साधनों के विकास में सक्रिय रही है। संघीय सरकार की सार्वजनिक भूमि नीति ने अमेरिकी कृषि के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण योग दिया। सन् 1862 में जो वासभूमि अधिनियम (होमस्टैड ऐक्ट) बना था, उसने ऐसे हर व्यक्ति को जो किसी एक ही स्थान पर घर बनाकर पाँच वर्ष तक रहा हो और खेती-बाड़ी करता रहा हो, 160 एकड़ भूमि प्रदान की। उसी वर्ष मोरिल अधिनियम भी बना जिसके अन्तर्गत सारे राष्ट्र में कालेजों और कृषि-प्रयोग क्षेत्रों के लिए जमीनें दी गईं। जैसा कि हमने देखा है, सरकार की सहायता से चलने वाली प्रशिक्षण, अनुसन्धान और सूचना-प्रसारण की इन सुविधाओं ने कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसके अलावा, इन्होंने संयुक्त राज्य सरकार के कृषि विभाग की विस्तार-सेवाओं के लिए बुनियाद तैयार की। यह सेवा किसानों को कृषि सम्बन्धी नई-नई विधियों को अपनाने में सहायता देती है। इसके अलावा सरकारी कार्यक्रमों की एक नई शृङ्खला, जिसका सम्बन्ध कृषि-जिन्सों के मूल्यों को स्थिर रखने के उपायों, उत्पादन सम्बन्धी नियन्त्रणों और फालतू जिन्सों को निबटाने के तरीकों से था, दोनों विश्व-युद्धों के मध्यवर्ती वर्षों में प्रारम्भ हुई। ये कार्यक्रम अन्य सरकारी कार्यक्रमों की अपेक्षा अधिक विवाद का विषय थे। इन विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य विश्व के आर्थिक परिवर्तनों, तकनीकी क्षेत्र में हुई उन्नति, मन्दियों और युद्धों के कारण कृषि-उत्पादन की उपलब्धि और माँग में पैदा असन्तुलन को दूर करना था। ये नीतियाँ और कार्यक्रम उपलब्धि और माँग में अधिक सन्तुलन

स्थापित करने एवं कृषि-जिन्सों के मूल्यों और कृषकों की आय को स्थिर रखने में सफल हुए हैं या असफल, इस विषय पर आज तक विवाद चला आ रहा है। कानूनन कृषि-क्षेत्र में कमी कर के फालतू कृषि-उत्पादन को रोकने की नीति ने किसानों को अपनी अवशिष्ट भूमि में ही अधिक उपज करने के लिए प्रोत्साहन दिया और फलतः कुछ हद तक वह कृषि-क्षेत्र में तकनीकी विधियों के विकास और कृषि की उत्पादकता-वृद्धि में सहायक सिद्ध हुई।

अन्य प्राकृतिक साधनों का संरक्षण और विकास भी सरकार की चिन्ता के मुख्य विषय रहे हैं और उसने अनेक प्रकार से उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया है। जहाँ तक संरक्षण का सम्बन्ध है, सरकार की नीतियों और कार्यों ने राष्ट्र की मूल्यवान् वन सम्पदा की रक्षा की है और नये वृक्षारोपण से उसे बढ़ाया है और साथ ही पीने, खेतों को सींचने, उद्योगों में इस्तेमाल करने और अनेक मनोरंजन सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए जलोपलब्धि का विस्तार, रक्षा और शोधन किया है।

अपने बहुदेश्यक जल-कार्यक्रमों के एक अङ्ग के रूप में सरकार ने जल-विद्युत् का इतना विकास किया है कि आज संयुक्त राज्य में उत्पादित आधी से अधिक जल-विद्युत् का स्वामित्व सरकार के हाथ में है। इसी प्रकार सरकार न केवल परमाणु शक्ति के विकास में, बल्कि सौर शक्ति, शिला-तेल (शेल ऑयल) के निष्कर्षण और कोयले के हाइड्रो-जनीकरण सम्बन्धी अनुसन्धानों में भी सक्रिय रही है। पेट्रोलियम उत्पादकों को कर सम्बन्धी बहुत-सी रियायतें दी गई हैं ताकि वे इस आवश्यक ईंधन और रासायनिक कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाएँ। ताँबा, चाँदी, यूरेनियम आदि अनेक धातुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए भी सरकार ने करोड़ों में रियायत, अधिदान (बाउटी), तटकर सम्बन्धी संरक्षण, सामरिक महत्त्व की वस्तुओं के भण्डारण के लिए खरीद आदि उपाय अपनाये हैं। किन्तु सहायता के इन उपायों में से कुछ का आर्थिक दृष्टि से औचित्य सन्दिग्ध प्रतीत होता है।

उद्योगों को प्रोत्साहन

परिवहन के विभिन्न प्रकार के साधनों के विकास और संचालन में सरकार की सहायता ने केवल उत्पादकता में प्रत्यक्ष सहायता ही नहीं दी है, बल्कि अनेक प्राकृतिक साधनों के विकास को प्रोत्साहन भी दिया है। रेलों के प्राग्भ से पूर्व आन्तरिक परिवहन सड़को और नहरों पर अवलम्बित रहता था जिनमें से अधिकतर सघीय और राज्यीय सरकारों के अनुदानों, अनुपूर्तियों (सब्सिडीज) या कर सम्बन्धी रियायतों की सहायता से बनी। बहुत-सी रेलों के निर्माण में भी इसी प्रकार की सहायता दी गई। अकेले सन् 1850 से 1871 तक सघीय और राज्यीय सरकारों ने 18 करोड़ 30 लाख एकड़ भूमि रेल कम्पनियों को मुफ्त प्रदान की और उसी का परिणाम है कि आज संयुक्त राज्य में मुख्य रेलों का विशाल जाल फैला हुआ है। ट्रक और बस परिवहन के उद्योगों को भी, जो अपेक्षाकृत नये हैं, सघीय, राज्यीय और स्थानीय शासनो द्वारा बनाई गई और सभाली जा रही 30 लाख मील लम्बी सड़को से बहुत सहायता मिली है। हाल में ही सघीय सरकार ने एक नया सड़क कार्यक्रम बनाया है जिस में विभिन्न राज्यों से गुजरने वाली 41,000 मील लम्बी ऐसी सीधी सड़कें बनायी जाएँगी, जिन पर एक साथ चार गाड़ियाँ चल सकेंगी और जिन्हें दूसरी सड़कें कहीं नहीं काटेगी। इस कार्यक्रम पर अगले 10 वर्षों में 33 अरब डालर खर्च होगा जिसका 90 प्रतिशत भाग सघीय सरकार देगी।

सन् 1845 से समुद्री जहाजरानी उद्योग को ढाक ले जाने के लिए सरकार से विशेष अनुपूर्ति मिल रही है। हाल में ही प्राइवेट जहाजरानी कम्पनियों को जहाजों के निर्माण और संचालन के लिए करोड़ों में कुछ रियायतें और अनुपूर्तियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त कानून के द्वारा यह अनिवार्य व्यवस्था करके, कि वैदेशिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्य देशों को बेजा जाने वाला 50 प्रतिशत माल अमेरिकी जहाजों में टोया जाएगा, प्राइवेट जहाजरानी को कुछ और भी अप्रत्यक्ष सहायता दी गई है। व्यापारिक हवाई परिवहन उद्योग को भी ढाक ले जाने के

लिए दी जाने वाली अनुपूर्ति, विमान विकास ठेको, सरकारी हवाई अड्डों पर विमानों की देखरेख और स्थलीय सुविधाओं और हवाई यातायात नियन्त्रण प्रणालियों के रूप में सरकारी सहायता दी गई है।

सरकारी नीतियाँ और कार्यक्रम श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और शिक्षा की वृद्धि में अनिवार्य योग देने के साथ-साथ, सरकार के कई समाज-कल्याण कार्यक्रम भी हैं, जो उनकी कार्यकुशलता बनाये रखने में सहायक होते हैं। इसका एक उदाहरण पुनः-प्रशिक्षण कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत उन श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है जिनका कौशल नई स्वचालित मशीनों के अधिकाधिक उपयोग या अन्य कारणों से पुराना पड़ गया है। सरकार द्वारा श्रमिकों को इच्छानुसार ट्रेड यूनियन में गठित करने और सामूहिक सौदेबाजी करने के अधिकार की गारण्टी दी जाने से भी श्रमिकों का उत्साह बढ़ता है। यद्यपि संयुक्त राज्य में सामूहिक सौदेबाजी विशुद्ध रूप से मजदूरों और मालिकों के बीच का मामला है, तो भी यदि सरकार से प्रार्थना की जाय तो वह मध्यस्थता, आपसी सुलह और पंच-निर्णय के लिए सेवाएँ प्रदान करती है।

प्रबन्धकों और व्यापारिक उद्यमों को सरकार द्वारा दी जाने वाली अनेक सेवाएँ अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान करती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अनेक प्रकार की सांख्यिकी और सूचना सम्बन्धी सेवाएँ हैं। इस प्रकार की पथप्रदर्शक सेवाएँ प्रबन्धकों को न केवल बाजारों के दीर्घकालिक विकास का पहले से अनुमान लगाने में सहायता देती हैं, बल्कि उन्हें रोजमर्रा के कामों, प्रशिक्षण, अनुसन्धान और विकास में भी मदद देती हैं। यद्यपि आर्थिक परिस्थितियों और उनकी भावी सम्भावनाओं के मूल्यांकन के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों और सामग्रियों का अब भी अभाव है, उदाहरण के लिए बचत और उपभोक्ताओं के खर्च के बारे में पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो भी सरकारी संस्थाएँ जो कुछ भी जानकारी उद्योग और व्यवसाय को मुफ्त दे रही हैं, वह अमेरिकी व्यवसाय-प्रणाली के सफल संचालन के

लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उद्योग-व्यापार को दी जाने वाली सरकारी सहायता का दूसरा उदाहरण है मानक कार्यालय (ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स) द्वारा दी जाने वाली सहायता जिससे अनेक नये और पुराने उत्पादनों के मानक निर्धारित किये जाते हैं। एक अन्य मोर्चे पर भी सरकार सहायता देती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बन्धों की स्थापना और वृद्धि एवं निर्णय के लिए बाजार तैयार करने में सक्रिय भूमिका अदा करने के साथ-साथ वह अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनियों में भी हिस्सा लेती है, जिससे प्राइवेट अमेरिकी व्यवसायों को विदेशी ग्राहक प्राप्त करने में प्रोत्साहन मिलता है।

पिछले दो दशकों में सरकार ने वैज्ञानिक अनुसन्धान और नई औद्योगिक विधियों के विकास में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो सहायता दी है उसने खास तौर से अमेरिकी उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत बड़ा योग दिया है। जिस नई उद्योग-विद्या (टेक्नोलॉजी) की बदौलत आज अमेरिका में तथाकथित 'दूसरी औद्योगिक क्रान्ति' सम्भव हो रही है, वह इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम और नई वस्तुओं का निर्माण, स्वचालित गणक यन्त्रों और नियन्त्रण उपकरणों का आविष्कार और परमाणु शक्ति आदि क्षेत्रों में प्रतिरक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए सरकार की दिलचस्पी का ही परिणाम है। किन्तु सरकार ने असैनिक किस्म के भी ऐसे अनेक अनुसन्धान कार्यक्रम चलाये हैं या उनके लिए धन दिया है; जिन्होंने प्रकृति में पाये जाने वाले विपुल साधनों के नये या अधिक कौशलपूर्ण उपयोगों की खोजकर प्रमुख उद्योगों में महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएँ पैदा की हैं। यहाँ तक कि जब कोई अनुसन्धान कार्यक्रम विशुद्ध रूप से प्राइवेट उद्योगों द्वारा ही चलाया जाता है, तब भी कर सम्बन्धी अनुकूल व्यवस्थाओं के द्वारा सरकार का प्रोत्साहन उसमें मौजूद रहता ही है।

पूंजी की उपलब्धि में वृद्धि

सरकार की नीतियाँ और कार्यक्रम पूंजी की उपलब्धि को बढ़ाने में भी सहायता देते हैं। प्रारम्भ में सरकार ने कृषि के लिए ऋण की सुविधाएँ

देना शुरू किया था, लेकिन सन् 1930 से प्रारम्भ दशक के मन्दी के वर्षों में प्रायः सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए सरकार ऋण देने लगी।

सन् 1930 के दशक में गृह-निर्माण के लिए धन की सहायता देने का जो कार्यक्रम सरकार ने प्रारम्भ किया था वह अब स्थायी कार्यक्रम बन गया है। यह सरकारी नीति और प्राइवेट व्यवसाय के पारस्परिक सहयोग का एक विशिष्ट उदाहरण है। प्राइवेट ठेकेदार मकान बनाते हैं और उनके लिए धन का प्रवन्ध उन्हें गिरवी रखकर करते हैं। लेकिन गिरवी रखने की शर्तें क्या हों, बीमा और गारण्टी कार्यक्रमों के अन्तर्गत बनाये जाने वाले मकान किस किस के हों और इस प्रकार की वित्तीय व्यवस्था से बनाये जाने वाले मकानों का स्टैंडर्ड क्या हो, इन सब बातों में सरकार का स्पष्ट निर्णायक प्रभाव रहता है। सघीय आवास प्रशासन और भूतपूर्व सैनिक पुनर्वास प्रशासन मामूली-सा शुल्क लेकर प्राइवेट गृह-निर्माण के लिए गारण्टी और बीमा करके सहायता प्रदान करते हैं और कृषि के अलावा शेष आवासगृहों का 40 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा की गई इस गारण्टी और बीमे के आधार पर गैरसरकारी पैसे से बनता है। कृषि ऋण प्रशासन और कृषक आवासगृह प्रशासन लोगों को कृषि-भूमि का स्वामित्व प्राप्त करने, उसे सुधारने, फार्मों में रिहायशी मकान या अन्य इमारतें बनाने और फार्मों को चलाने के लिए ऋण के रूप में सहायता देते हैं।

सरकार के समस्त ऋण कार्यक्रमों के महत्त्व को इस तथ्य से आकांक्षा जा सकता है कि 31 दिसम्बर, 1960 को लोगों से सरकारी ऋणों की वसूली की वक्तव्या रकम 21 अरब 90 करोड़ डालर थी, जो सभी प्रकार के कुल प्राइवेट ऋणों का 4 प्रतिशत थी। इसके अलावा सरकार ने जिन ऋणों का बीमा या गारण्टी की हुई थी उनकी मात्रा भी 70 अरब डालर यानी कुल प्राइवेट ऋणों का 13 प्रतिशत और थी। सघीय जमाखाता बीमा निगम (फेडरल डिपोजिट इन्शुरेन्स कॉर्पोरेशन) आदि कुछ अन्य संगठन स्थापित करके अमेरिका में ऋण व्यवस्था को और भी सुदृढ़ कर दिया गया है। यह निगम 10,000 डालर प्रति खाता तक बैंकों में

जमा रकमों का बीमा करता है ।

पूर्ण रोजगार और आर्थिक अभिवृद्धि की समुन्नति

सन् 1946 में रोजगार अधिनियम पास कर सरकार पर यह जिम्मेदारी डाली गई थी कि वह 'रोजगार, उत्पादन और क्रयशक्ति को उच्चतम स्तर तक' समुन्नत करने की नीति निर्धारित कर क्रियान्वित करे । यद्यपि सरकारें अमेरिका के समूचे इतिहास में अर्थ-व्यवस्था के कुछ खण्डों को समुन्नत करती रही हैं किन्तु इस अधिनियम से आम और समग्र आर्थिक अभिवृद्धि और स्थिरता की नीति अपना कर एक नई जिम्मेदारी सरकार पर डाली गई । लेकिन इस नीति का अर्थ उद्योग-व्यवसाय, श्रमिक वर्ग या उपभोक्ताओं के निश्चयों में किसी तरह का हस्तक्षेप करना नहीं है—यह नीति सरकार के मौजूदा अधिकार के भीतर ही सामान्य वित्तीय और आर्थिक उपायों और अन्य कार्यक्रमों के द्वारा परिचालित की जाती है ।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में सरकार क्या हिस्सा लेती है, इसका सर्वोत्तम अनुमान राष्ट्रीय आर्थिक लेखे या राष्ट्र के आर्थिक वजट से लगाया जा सकता है । इन वजटों का अध्ययन करने से मालूम होगा कि सन् 1929 में जहाँ संघीय, राज्यीय और स्थानीय शासनों के वजटों की कुल राशि, चालू डालर मूल्य के हिसाब से, कुल राष्ट्रीय आय का 10 प्रतिशत थी, वहाँ 1960 में वह बढ़कर 27 प्रतिशत हो गई । इन 27 प्रतिशत में सरकार द्वारा की गई माल की ममस्त खरीद, सरकारी कर्मचारियों को दिये गए वेतन और किमानों, नागरिक सुरक्षा प्राप्त करने के अधिष्ठात्री व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों और सरकारी डॉक्टरों को दी जाने वाली रकमें भी शामिल हैं । सरकारी गारण्टियों या बीमों के द्वारा महंगाई-प्राप्त वेतन-देन—उदाहरणार्थ संघीय आदान प्रदान द्वारा भारत गिन्नी रस जन दिये गए ऋण—अर्थ-व्यवस्था के प्राप्ति वजट में गये हुए हैं । इसलिए यदि उन वेतन-देनों को भी शामिल कर लिया जाए, तो उसका अर्थ यह होगा कि आर्थिक वजट अमेरिकी अर्थ-

तालिका 11

राष्ट्र के 1929, 1960 और 1970 के वज्रट
(राजस्व प्राप्तिओं और राजस्व व्यय का मुख्य-मुख्य क्षेत्रों में प्रतिशत विभाजन)

प्राथमिक वर्ग	1920		1960		1970	
	आय	व्यय	आय	व्यय	आय	व्यय
उपभोक्ता (स्वायत्त आय और उपभोग व्यय)	79.6	75.7	69.8	65.2	68.8	62.9.
व्यापार (अवतरित आय और आन्तरिक निवेश)	11.0	15.5	10.3	14.5	9.9	15.2
शुद्ध विदेशी निवेश	—	0.7	0.3	0.6	0.1	0.7
सरकार (अन्तरण, व्याज और अनुपूर्तियों सहित)	10.7	9.7	27.5	27.2	27.7	27.5
(अन्तरण, व्याज और अनुपूर्तियों को निकाल कर)	1.6	1.6	7.3	7.3	6.5	6.5
सरकार (शुद्ध प्राप्तियों और सामान और सेवाओं की खरीद)	9.1	8.1	20.2	19.9	21.2	21.2
आकड़ों सम्बन्धी अशुद्धि	+0.3	—	—0.6	—0.2	—	—
कुल राष्ट्रीय आय	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

नोट : चालू उल्लेख के हिसाब में आंकड़ों के लिए देखिये परिशिष्ट तालिका 20 ।

व्यवस्था पर सरकार के प्रभाव को उस अंश तक कम प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये लेन-देन उसमें शामिल नहीं है।

सरकारी कार्यवाही के प्रति रवैया

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था गतिशील है और उसके विभिन्न प्रमुख वर्गों के आपसी सम्बन्ध निरन्तर बदलते रहते हैं, इसलिए यह सम्भव है कि किसी समय सरकार अर्थ-व्यवस्था में बहुत कम भाग ले रही हो अथवा बहुत अधिक भाग ले रही हो—और यह भी हो सकता है कि एक ही समय में किसी विशिष्ट क्षेत्र में वह बहुत अधिक काम करने की दोषी हो और दूसरों में बहुत कम काम करने की। इस प्रकार सरकार की किन्हीं विशिष्ट नीतियों और कार्यक्रमों को लेकर मतभेद और विवाद की हमेशा गुंजायश है। लेकिन हितों और विचारों के ये भेद लोकतन्त्र का सार-तत्व है।

यह महत्वपूर्ण बात है कि ये मतभेद आमतौर पर दूर होते रहते हैं और अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की मूल आर्थिक परम्पराएँ इन विवादों की लपेट में नहीं आती। उदाहरण के लिए सयुक्त राज्य के किसी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक दल या वर्ग ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की हिमायत नहीं की। वास्तव में, व्यवसायी वर्ग और श्रमिक वर्ग, दोनों ही राष्ट्रीयकरण के विरोधी रहे हैं। दोनों ही यह अनुभव करते हैं कि राष्ट्रीयकरण से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता नष्ट हो जाएगी और यदि दोनों पक्ष सरकार द्वारा बनाये गए नियमों और विनियमों के अन्तर्गत वेतन, काम के घटे और काम की परिस्थितियों के बारे में परस्पर सौदेबाजी के लिए स्वतन्त्र रहे तो दोनों पक्षों का आर्थिक हित अधिक अच्छी तरह समुन्नत हो सकता है।

सयुक्त राज्य आर्थिक क्षेत्र में स्वतन्त्र उद्यम और सरकारी उत्तरदायित्व के सर्वोत्तम समन्वय के लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। कुछ लोगों का यह ख्याल है कि सरकार कभी-कभी शक्तिशाली आर्थिक हितों के दबाव में आ जाती है और ऐसा लगता है कि उसकी नीतियाँ और कार्य-

क्रम कुछ थोड़े-से सविशेषाधिकार (प्रिविलेज) व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के लिए ही बनाये गए हैं। दूसरी ओर कुछ लोगो का खयाल यह है कि सरकार कभी-कभी अर्थ-व्यवस्था में इतना अधिक उग्र और हस्तक्षेपपूर्ण रख अपनाती है कि निजी उद्यम की स्वतन्त्रता और श्रोजस्विता खतरे में पड़ जाती है। अब ऐसा लगता है कि संयुक्त राज्य एक ऐसी स्थिति में पहुँच रहा है जिस में न तो व्यवसायी, श्रमिक और कृषक वर्ग का और न ही सरकार का मुख्य प्रभाव रह जायेगा। हरेक क्षेत्र शक्तिशाली और गतिशील है और सभी यह महसूस करते हैं कि यदि उनमें से किसी ने भी कोई ऐसा काम करने की चेष्टा की जो आम जन-कल्याण पर बुरा असर डालेगा, तो उसे दबा दिया जाएगा। इस स्थिति का एक महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ है कि इन सभी वर्गों में पारस्परिक विश्वास बढ़ा है और इस विश्वास के फलस्वरूप व्यवसाय प्रबन्धको, श्रमिकों, कृषकों, विभिन्न पेशों के लोगो और सरकारी प्रशासकों का हौसला बढ़ा है और उसने अमेरिकी उत्पादकता में महत्वपूर्ण योग दिया है।

सारांश

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता को बढ़ाने में सरकार के योगदान के विभिन्न पहलुओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि उसके आर्थिक लेन-देन का अधिकतर भाग लोगो के निजी अभिक्रम और चयन का परिणाम है, तो भी संयुक्त राज्य में आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण बन्धन-हीन व्यापार नीति यानी सरकारी हस्तक्षेप से पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं है। सरकार का उत्तरदायित्व—जो आहिस्ता-आहिस्ता अनेक प्रकार के परीक्षण और गलतियाँ करने के बाद एक निश्चित रूप धारण कर सका है—यह है कि वह अर्थ-व्यवस्था के लिए उन साधनो, सेवाओं, प्रोत्साहनो और नियम-विनियमों को प्रस्तुत करे जिनके बिना निजी माली अर्थ-व्यवस्था न तो स्वयं अच्छी तरह चल सकती है और न का आम हित साधन कर सकती है। वास्तव में ऊपर जो उदाहरण दिये गए हैं, उनसे निकलने वाला निष्कर्ष केवल संयुक्त राज्य के लिए

ही नहीं अन्य देशों के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। वह निष्कर्ष यह है कि आर्थिक प्रक्रिया के कुछ पहलुओं में सरकार का सक्रिय और बुद्धिमत्तापूर्ण भाग लेना एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था के लिए, जो बुनियादी तौर पर निजी उद्यम वाली अर्थ-व्यवस्था है, असंगत नहीं है, बल्कि बीसवीं शताब्दी के मध्य में जैसी परिस्थितियाँ हैं, उनमें वह निजी उद्यमों के प्रभाव ढंग से काम करने के लिए अनिवार्य भी है।

मूल्य और संस्थाएँ

अमेरिकी उत्पादकता के उच्च स्तर के प्रमुख कारणों का जो विवरण हमने दिया है उससे यह अब भी स्पष्ट नहीं होता कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था, मात्रा को छोड़कर अन्य बातों में, अन्य पश्चिमी लोकतन्त्रीय देशों की अर्थ-व्यवस्था से क्यों भिन्न है। वह उनसे भिन्न है इससे तो इन्कार किया ही नहीं जा सकता। अन्य देशों से अमेरिका में आने वाले अनेक लोगों का कहना है कि वे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की अनेक विशेषताएँ देखकर चकित रह गए। उसकी गतिशीलता, प्रतिस्पर्धात्मकता, आय का अपेक्षाकृत अधिक समान और न्यायपूर्ण वितरण, उसका लचकीलापन और सूझ-बूझ देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धों और मूल्यों की उस अधिक व्यापक प्रणाली का, जिससे सब मिलाकर अमेरिकी समाज का निर्माण हुआ है, एक अविच्छिन्न अंग है। आर्थिक और आर्थिकेतर तत्वों के अन्तः सम्बन्ध बहुत जटिल हैं। किन्तु इन सम्बन्धों के एक अत्यधिक सरल और आत्मगत दृष्टि से किये गए वर्णन से भी उन अमेरिकी अभिवृत्तियों और परम्पराओं का कुछ संकेत मिल जाएगा, जिनमें अमेरिकी आर्थिक गति-विधियों में अन्तर्हित भावना का पता चल सकता है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता के उच्च स्तर की व्याख्या करने वाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण तत्वों में इन मूल्यों का स्थान है।

अमेरिका में एक नई शुरुआत

ऐतिहासिक दृष्टि से देखे तो अमेरिका की एक मूल अभिवृद्धि वह 'राइनहोल्ड नीवूर' ने 'एक नई शुरुआत' की आशा कहा है। विचार को उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में गोएते ने इन शब्दों में

व्यक्त किया था :

अमेरिका, तुम हो भाग्यशाली
हमारे इस पुराने महाद्वीप से ।
नहीं तुम्हारे पास भग्न दुर्ग
नहीं विदीर्ण असिताश्म स्तम्भ ।
तुम जी सकते हो वर्तमान में,
नहीं बाँध सकते हैं तुमको
आशाहीन अवरोधक द्वन्द्व
या व्यर्थ-सी गुजरी स्मृतियाँ
गये पुराने बीते युग की ।

गोएते ने सिर्फ इस सुस्पष्ट सत्य की ओर ही संकेत नहीं किया था कि जिस समय सर्वप्रथम यूरोपीय उपनिवेशी अमेरिका के तट पर गए थे उस समय अमेरिका एक सर्वथा अक्षत प्रदेश था और इन उपनिवेशियों को अपने आप को वहाँ पहले से ही विद्यमान किन्हीं परम्पराओं और प्रथाओं के अनुकूल नहीं बनाना पड़ा । उसका अभिप्राय यह भी था कि जो लोग एक के बाद एक अमेरिका में बसने के लिए जा रहे हैं, वे अपनी निज की समस्याओं के उन पहलुओं को अपने पीछे ही छोड़कर जा सकते हैं, जिन्हें वे अपने लिए सबसे अधिक अवरोधक समझते हैं ।

राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी० रूजवेल्ट का भी एक अन्य प्रसंग में एक बार कहा गया यह प्रसिद्ध कथन है कि "सभी अमेरिकी आप्रवासी या उनके वंशज हैं ।" कुछ लोग अपनी इच्छा के विरुद्ध आये थे—ये लोग औपनिवेशिक युग के गुलाम और करारबद्ध कर्मचारी थे । किन्तु प्रारम्भिक आगन्तुकों ने जेकर वर्तमान आप्रवासियों तक अधिकतर आदमी स्पेसिया में ही वहाँ आये थे । ये लोग अपनी उन परम्पराओं को, जो अर्द्धदीन से नई थी, अपने पुर्नाने देशों में छोड़कर नये रस्मों, नये रीति-रिवाजों और नई परम्पराओं को विपन्नित करने और अपनाते का मन्त्र जेकर आये थे । अमेरिका ने इन लोगों को अपनी आशाओं और आकांक्षों की पूर्ति के लिए एक नया छन्दर प्रदान किया ।

कुछ लोगो के लिए यह नई शुरुआत मुख्यतः धार्मिक या राजनीतिक थी और कुछ के लिए वह मुख्यतः सामाजिक और आर्थिक शुरुआत थी। लेकिन अधिकतर लोग ऐसे थे जिनके लिए यह शुरुआत इनमे से विभिन्न प्रयोजनो के या कुछ सर्वथा नये प्रयोजनो के मिश्रण के रूप में थी। जो लोग धार्मिक अत्याचारो से बचने की इच्छा से आये थे उनके लिए यहाँ आने का प्रयोजन यह आशा थी कि अन्ततः इस नई वस्ती में धार्मिक पूजा की पूरी स्वतन्त्रता स्थापित होगी। जो लोग स्व-शासन की आकांक्षा लेकर आये थे उन्होने अमेरिकी उपनिवेशो में स्थानीय शासन की और फिर प्रतिनिधि शासन की नई संस्थाओं का विकास किया। और अन्त में, जो लोग आर्थिक स्वतन्त्रता और अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार की इच्छा मन में लेकर आये थे, उनमें ऐसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएँ पैदा हुईं जो बशानुगत सामाजिक और पारिवारिक स्थिति या कानूनी और आर्थिक नियोग्यताओं (डिसेबिलिटी) की सीमाओं का बन्धन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी।

इस प्रकार पिछले 350 वर्षों में जो लोग अमेरिका के तट पर आकर उतरे उनकी प्रधान आकांक्षा यह थी कि वे यहाँ ऐसे नये समाज का निर्माण कर सकेंगे अथवा यहाँ उन्हें ऐसा समाज बना-बनाया मिलेगा जिसमें स्वावलम्बी और जिम्मेदार व्यक्ति स्वतन्त्र जीवन व्यतीत कर सकेगा। यह स्वतन्त्र जीवन पुराने परम्परागत समाजों और उनकी पहले से ही निर्धारित और बड़ी-बड़ी पद-सोपान प्रणाली (हायरार्की) की सीमाओं में जकड़ा हुआ नहीं होगा। यह सही है कि अमेरिका में भी धार्मिक एकरूपता, केन्द्रीकृत अल्पतन्त्रीय शासन प्रणाली (ओलिगार्की), सामन्ती भूमि पट्टेदारी और वाणिज्यकीय व्यावसायिक और औद्योगिक प्रतिबन्ध कायम करने की अनेक कोशिशें की गईं। किन्तु अन्त में धार्मिक विविधता और समानता सार्व मताधिकार और विकेंद्रित स्थानीय शासन, व्यावसायिक उद्यम की स्वतन्त्रता और समुचित सामाजिक संचलता की ही विजय हुई।

प्रारम्भिक अमेरिकी परिस्थितियाँ

इस स्पष्ट और विशिष्ट विकास में इस बात से भी सहायता मिली कि अमेरिका में आने वाले नये लोगों के लिए एक विशाल भूखण्ड खुला पड़ा था जो गैर-आबाद था और जिससे उनके लिए जीवन की नई शुरुआत के लिए भौतिक साधन उपलब्ध थे । यदि धार्मिक एकरूपता, सत्तावादी शासन प्रणाली या अनुचित प्रतिबन्धयुक्त आर्थिक व्यवस्था थोपने की कोई कोशिश की जाती तो जो लोग उससे असन्तुष्ट होते या उसका सफलतापूर्वक प्रतिरोध न कर पाते वे उस प्रदेश को छोड़कर अमेरिकी महाद्वीप के विस्तीर्ण खुले और गैर-आबाद भूखण्ड में किसी और प्रदेश की ओर जाने के लिए तैयार हो जाते ताकि वहाँ फिर जीवन की नई शुरुआत कर सकें । वास्तव में लोगों के फैलने के लिए इतने विशाल भूखण्ड की उपलब्धि और उनके प्रसार की सम्भावनाओं के कारण ही अनेक बार इस प्रकार के प्रतिबन्ध थोपने के प्रयत्न छोड़ देने पड़े ।

लोगों में सिर्फ आबाद फार्मों और कस्बों की सीमा से परे नये गैर-आबाद इलाकों में फैलने का उद्यम ही नहीं था, बल्कि देश के आबाद इलाकों में भी उन्हें हमेशा ऐसी नई-नई दिशाएँ और क्षेत्र मिलते रहते थे जिनमें वे अपने आर्थिक उद्यम का विस्तार कर सकते थे । विस्तार का यह क्षेत्र आज भी विद्यमान है और उपक्रमी और साहसी लोग उसका लाभ उठा सकते हैं । आज भी व्यक्ति अपनी प्रकृति और अनुभव के अनुसार अपने लिए जीवन की नई शुरुआत करने के लिए किसी नये क्षेत्र को ढूँढ़ सकता है ।

किन्तु अतीत में भौगोलिक दृष्टि से विस्तीर्ण गैर-आबाद क्षेत्र में फैलने की सम्भावनाओं ने एक विशिष्ट अमेरिकी चरित्र के विकास को प्रभावित किया । नये आबाद प्रदेशों के लिए आवश्यक जीवन-पद्धति ने कुछ ऐसे चरित्र लक्षणों और सामाजिक अभिवृत्तियों को प्रोत्साहित किया जिन्होंने अमेरिका में 'एक अच्छे समाज' की निश्चित कल्पना लोगों के मन में पैदा की । एक और नये इलाकों के जीवन के खतरो, कठिनाइयों और सकटों का सफलतापूर्वक सामना करने की आवश्यकता ने लोगों में

स्वावलम्बन, सूक्ष्म, व्यावहारिकता और विविध प्रकार के कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा की। दूसरी ओर पारस्परिक सहायता और सामाजिक सहयोग की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिला क्योंकि जमीन को खेती के लिए साफ करना, घर बनाना, परिवहन की सुविधाओं की व्यवस्था करना, और समाज को मानवीय और प्राकृतिक शत्रुओं से बचाना—ये सब काम ऐसे थे जो अकेले किसी एक व्यक्ति या परिवार के बल के नहीं थे। इसके अलावा प्रारम्भिक स्थानीय शासन संस्थाएँ कायम करने और कानून और व्यवस्था की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी आमतौर पर स्वयं वहाँ आबाद अधिवासियों की ही थी। इनसे विकेन्द्रित आधार पर फैसले करने की प्रवृत्ति और लोकतन्त्रीय ढंग के राजनीतिक जीवन को प्रोत्साहन मिला।

लेकिन सिर्फ नये-नये गैर-आबाद सीमावर्ती क्षेत्रों की परिस्थितियों ने ही अमेरिकी लोगों में इन विशिष्ट चरित्रों और सामाजिक अभिवृत्तियों को जन्म नहीं दिया, बल्कि न्यू इंग्लैंड और वर्जीनिया की विशिष्ट 'विचारधाराओं' ने भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान किया। न्यू इंग्लैंड की प्यूरिटनवादी विचारधारा, मैक्स वेबर के शब्दों में, प्रधानतः 'प्रोटेस्टैंट आचारशास्त्र और पूंजीवादी भावना' की उपज थी। जो व्यक्ति कठोर श्रम और मितव्ययिता के गुणों से आर्थिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता था, वह यह समझता था कि वह उन थोड़े-से भाग्यशाली व्यक्तियों में से है जो मुक्ति के लिए चुने गए हैं। यद्यपि इस विचारधारा के धार्मिक पहलू का अठारहवीं शताब्दी के आखिरी चरण में अन्त हो गया, तथापि इसके मूल में जो बुनियादी रवैया थी वह न्यू इंग्लैंड के 'याकीवाद' के रूप में बना रहा। इस याकीवाद की विशेषताएँ थीं स्वावलम्बन, अन्तर्भावनाशीलता, प्रतिस्पर्धात्मक विचक्षणता और उद्यमशीलता।

अमेरिकी चरित्र के निर्माण में वर्जीनिया का योगदान था अमेरिका की परिस्थितियों में यूरोपीय प्रबोध के सिद्धान्तों का समन्वय कर उन्हें अपनाना। थामस जैफर्सन और जेम्स मैडिसन जैसे वर्जीनियाई विचारकों

के चिन्तन और लेखन में यह विचार प्रकट किये जाते थे। इनमें मानवीय तर्क बुद्धि की शक्ति, सामाजिक प्रगति और सुधार की सम्भाव्यताओं और व्यक्ति के जीवन, स्वतन्त्रता और सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न के अधिकारों पर बल दिया जाता था। किन्तु वर्जोनिया के इन दार्शनिकों ने इसी की इस भ्रान्त धारणा को कभी स्वीकार नहीं किया कि हर मनुष्य प्रकृत्या अच्छा है और उसमें पूर्णता को प्राप्त करने की क्षमता है। इसके विपरीत उनके विचार होव्ज और लॉक के इस सिद्धान्त के अधिक निकट थे, और उन्होंने यह चेतावनी भी दी, कि मानवीय आवेदों में विनाश की क्षमता भी है, इसलिए व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और समानता एवं राजनीतिक नृत्ता और सामाजिक व्यवस्था के बीच समुचित सन्तुजन स्थापित किया जाना चाहिए। लेकिन बाद में उन्नीसवीं शताब्दी की समाज की वैभवशालिता और सफलता ने उन धारणाओं को व्यापक बनाया और वृद्धमूल किया कि मानवीय तर्क बुद्धि से कोई भी वस्तु परे नहीं है और व्यक्ति तथा समाज का एक दिन पूर्णता को प्राप्त करना अनिवार्य है। आज के अमेरिकी चरित्र में, जो तत्त्वतः आशावादी और तर्कवादी है, ये विस्मयमय महत्त्वपूर्ण तत्व बन गए हैं।

कुछ अन्य प्रभावों ने भी अमेरिकी समाज को एक निश्चित शक्ति प्रवृत्ति प्रदान करने में सहायता दी। उनमें से एक प्रभावकारी तत्व था साम्प्रदायिक गतिशीलता। यह गतिशीलता अत्यन्त आवेगपूर्ण थी, क्योंकि उनके द्वारा इतनी विभिन्न प्रकार की सन्तुष्टियाँ, धर्मों और जानियों के लोग शासन में सफलतापूर्वक सहयोग नहीं कर सकते थे, जो एक तत्त्वतः गोलगन्धीय समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य था। उनके अनायास सामान्य राजन्य एवं दिशान्ता भौगोलिक क्षेत्र हैं और अन्य देशों की अपेक्षा प्राचीन आशयविभक्त है। उन तत्वों ने भी उसे समार का सचने बना निर्वाण दायित्व एवं बनाने में सहायता की। इन तथा कुछ अन्य तत्वों ने निश्चय अमेरिकी समाज को एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया।

अमेरिका की देशज विशिष्टताओं का प्रभाव

इस प्रकार अमेरिकी समाज में प्रारम्भ से ही कुछ-न-कुछ यह विशेषता रही कि वह अतीत के वजाय वर्तमान और भविष्य की ओर दृष्टि रखता था। उसकी प्रवृत्ति विरासत में पाई हुई प्रथाओं और अमूर्त सिद्धान्तों के वजाय वर्तमान स्थिति के तथ्यों के आचार पर विचार और कर्म करने की थी। उसका यह गहरा विश्वास था कि तर्कपूर्ण विचार और मानवीय कर्म व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं को हल कर सकते हैं। वह समूह और व्यक्ति के हितों में प्रतिस्पर्धा होने पर उनमें समझौता या निभाव करने के लिए उत्सुक रहता था। सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मोटे तौर पर अमेरिकी समाज आगावादी, क्रियात्मक, तर्कवादी, उन्मुक्त मन से हर विषय पर विचार करने वाला और सहकारी भावना से युक्त रहा है। उसने अन्तर्भावना के साथ निष्ठापूर्वक काम करने की प्रवृत्ति, भौतिक कल्याण, तकनीकी कौशल, व्यक्तिगत लचकी-लेपन और सामाजिक एवं भौगोलिक गतिशीलता को हमेशा मूल्यवान समझा है। इन मूल्यों ने अमेरिका की आर्थिक सफलता में योग दिया है और इस सफलता ने इन मूल्यों को समृद्ध बनाया है।

अमेरिकी चरित्र की ये विशेषताएँ हमेशा लाभकारी ही नहीं रही। जहाँ एक ओर इन विशेषताओं के कारण अमेरिकी लोग ऐसी बहुत-सी समस्याओं से, जिन्होंने अन्य देशों के लोगों को परेशान किया, बच सके या उनका समाधान कर सके, वहाँ उन्होंने उनके लिए कुछ परेशानियाँ और कठिनाइयाँ भी पैदा की। उदाहरण के लिए जहाँ अतीत की उत्कण्ठ भावना के अभाव ने अमेरिकी लोगों को घिसे-पिटे विचारों और पुरानी तकनीकी पद्धतियों के बन्धन से मुक्त किया, वहाँ उसने बहुत-से अमेरिकी लोगों में उन लोगों के प्रति ईर्ष्या भी पैदा की जिनके भीतर अपनी एक सुदीर्घ और अविच्छिन्न ऐतिहासिक परम्परा की स्थायी चेतना है। इसी प्रकार जहाँ एक ओर मानवीय तर्क-बुद्धि की शक्तिशालिता और सामाजिक उन्नति की अनिवार्यता के विश्वास ने अमेरिकी विज्ञान और उद्योग विद्या को प्रेरित किया है और अमेरिकी समाज में न्याय और जन-

कल्याण को समुन्नत किया है, वहाँ दूसरी ओर कभी-कभी उसने अमेरिकी लोगों में यह अनुचित और घातक बेफिक्री भी पैदा की है कि अमेरिका विज्ञान और उद्योग-विद्या में दूसरों से आगे है, इसलिए उन्हें किसी विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। उसने अमेरिकी लोगों को आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में देश की आन्तरिक और अन्तर्राष्ट्रीय यथार्थताओं को सही रूप में हृदयगम करने से रोका है और यही कारण है कि कभी-कभी हमने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में कुछ काम निहायत ना-समझी के किये और जरूरत से ज्यादा नैतिकता के चक्कर में पड़े। और आखिरी बात यह कि जहाँ एक ओर अमेरिकी व्यक्तियों और समूहों में परस्पर सहयोग करने और सामुदायिक जीवन में रचनात्मक रूप से भाग लेने की वृत्ति ने विभिन्न संस्कृतियों, जातियों, वफादारियों और दिल-चस्पियों के बावजूद इस बहुविध समाज को एकता के बन्धन में बाँधे रखा वहाँ दूसरी ओर उसका एक नुकसान भी हुआ और वह यह कि व्यक्ति पर समाज के एक स्वीकृत ढाँचे को अंगीकार करने के लिए काफी दबाव पड़ा।

इन अमेरिकी अभिवृत्तियों ने, हालांकि वे बहुत प्रत्यक्ष नहीं हैं और उनके अच्छे-बुरे दोनों पहलू हैं, व्यवसाय और कृषि के प्रबन्ध की प्रणाली को, श्रमिकों की काम के प्रति आत्मार्पण की भावना को और सरकार की नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया है। कुछ अतिशयोक्ति होने पर भी, यह बात कही जा सकती है कि बहुत-से अन्य औद्योगिक देशों में प्रबन्धक लोगों की सबसे पहली भावना यह रहती है कि यथासंभव उत्पादन की पुरानी पद्धति और ढाँचे को ही जारी रखा जाय और उसमें परिवर्तन तभी किया जाय जबकि उससे बहुत अधिक लाभ की असन्दिग्ध आशा हो। इसके विपरीत अमेरिकी प्रबन्धक पुरानी परिचित पद्धतियों और ढाँचों से चिपटे रहने के बजाय उनमें परिवर्तन करना अधिक पसन्द करते हैं। अमेरिका में श्रमिक और किसान भी अन्य देशों के लोगों की अपेक्षा नई तकनीकी विधियों को अपनाने और आवश्यक परिवर्तन करने के लिए अधिक तैयार रहते हैं। इसी तरह

किसी एक सिद्धान्त के प्रति कठमुल्लापन के अभाव और व्यावहारिकता की प्रबल भावना ने सरकार को भी ऐसी नीतियाँ अपनाने के लिए, जो आर्थिक उन्नति के लिए हितकारी हो, और ऐसी नीतियाँ बदलने या त्यागने के लिए, जो अनावश्यक और पुरानी हो गई हो, प्रेरित किया है।

हाल में ही प्रकाशित एक रिपोर्ट में अमेरिकी उत्पादकता के अध्ययन के लिए अन्य देशों से आये कुछ दलों के निष्कर्ष मक्षेप में दिये गए हैं। इस रिपोर्ट में अनेक विदेशी प्रेक्षकों का मत इस प्रकार प्रकट किया गया है। “अमेरिका आने से पूर्व हम लोगों का समाल था कि अमेरिका में उत्पादकता का स्तर ऊँचा होने का कारण मशीनें और यन्त्र हैं। लेकिन अब हमने यह अनुभव किया है कि प्रबन्धक, इंजीनियर और श्रमिक सभी इस दृष्टि से सोचते हैं कि प्रति मानव-घंटा उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से सोचने पर हर व्यक्ति उत्पादन-वृद्धि में अपना सर्वोत्तम योग दे सकता है।”

सम्यक्ता के इतिहास में ऐसे युग शायद ही कभी आये होंगे, और आये भी होंगे तो बहुत कम, जिनमें कि जीवन की परिस्थितियाँ इतनी तेजी से और इतनी अधिक बदली हो, जितनी कि बीसवीं सदी में बदली है। वैज्ञानिक और औद्योगिकी के क्षेत्रों में असाधारण उन्नति, प्रायः सभी देशों में प्रगति की आकांक्षाओं में क्रान्ति, विचारधाराओं और आदर्शवादों के मौजूदा संघर्ष और आधुनिक युद्ध पद्धति की अभूतपूर्व विनाशक क्षमता—इन सब ने मिलकर लोकतन्त्री सरकारों को भी अधिकाधिक शक्ति अपने हाथ में केन्द्रित करने को बाध्य कर दिया है। फिर भी अमेरिकी राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली ने, अपने आधारभूत मूल्यों और सस्थाओं की बदौलत, अपनी निर्णय और कर्म की विकेन्द्रित और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को मूलतः अक्षुण्ण रखते हुए इन परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार अपने आपको ढाल लिया है। यह सही है कि आज बीसवीं शताब्दी में जीवन की परिवर्तमान परिस्थितियों के कारण अमेरिकी लोगों के सामने ऐसे विकल्प बहुत कम रह गए हैं जिनमें से वे अपने लिए किसी अनुकूल

विकल्प को चुन सकते हो। किन्तु फिर भी एक अमेरिकी को, चाहे वह उत्पादक हो या निवेशक (इन्वेस्टर) या उपभोक्ता अपने भाग्य का निर्धारण करने की काफी स्वतन्त्रता है।

सारांश

संयुक्त राज्य के निजके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, और धार्मिक तत्वों ने उसके आर्थिक स्रोतों के विकास और उपयोग को समुन्नत किया है, लोगों में परिवर्तन और नई तकनीकी पद्धतियों को स्वीकार करने की भावना उत्पन्न की है और आर्थिक प्रक्रिया में सरकार को एक विशिष्ट रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया है। ये चीजें अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था को संप्रगुण बनाने वाली 'भावना' के बड़े और अनिवार्य अंग हैं। इस भावना के कारण ही हमारे युग के केन्द्रीकरण और सत्तावाद के प्रबल दवावों के बावजूद अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था अपनी विशिष्ट गतिशीलता, लचकीलेपन और काफी हद तक व्यापक न्याय और समानता को कायम रख सकी है। पिछले अध्यायों में वर्णित अधिक प्रत्यक्ष आर्थिक तत्वों के अलावा अमेरिकी समाज के विशिष्ट मूल्यों और संस्थाओं ने भी अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता के स्तर को ऊँचा उठाने में सहायता दी है। ये मूल्य और संस्थाएँ अब भी मौजूद हैं और उनका स्थायित्व हमारे मन में यह विश्वास पैदा करता है कि आगामी वर्षों में भी उत्पादकता में वृद्धि जारी रहेगी और अगले दशक की आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ रचनात्मक और लोकतन्त्रीय ढंग से हल की जा सकेंगी।

भाग 2

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की समस्याएँ और सम्भावनाएँ

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में अधिकतर उत्पादक—अमिक और प्रवन्धक, दोनों—उद्योगविद्या और प्रवन्ध कला की नवीनतम उन्नत विधियों के उपयोग से सृजनात्मक सफलताएँ प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध है। यद्यपि अमेरिकी लोग इस स्थिति पर गर्व कर सकते हैं तो भी वह सर्वथा निर्दोष नहीं है। अपनी रिपोर्ट के इस भाग में हम इसके असन्तोषकारक होने के कुछ कारणों की ओर संकेत करेंगे और साथ ही यह भी बताएँगे कि उन्हें दूर करने के लिए क्या नीतियाँ अपनाने का प्रस्ताव किया गया है।

अमेरिकी समाज में स्वभावतः बद्धमूल आत्मालोचन और समाज-सुधार की क्षमता को पूरी तरह हृदयगम नहीं कर सके हैं।

अमेरिका के इतिहास में एक के बाद एक सुधार की जो अनेक लहरें आयी हैं, वे किन्हीं अमूर्त-सिद्धान्तों की प्रेरणा का परिणाम नहीं थी, बल्कि वे कुछ खास दुरुपयोगों और वास्तविक त्रुटियों को दूर करने की इच्छा का परिणाम थी, जिनका अमेरिकी समाज के लोकतंत्रीय और व्यक्तिवादी आदर्शों के साथ मेल नहीं था। और फिर ये सुधार हमेशा एक ही स्रोत से उद्भूत नहीं हुए।

सुधार के इन युगों में देश भर में विभिन्न वर्गों, समूहों और राजनीतिक दलों में तरह-तरह के और हमेशा बदलते रहने वाले गठबन्धन हुए और उनके फलस्वरूप सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में बहुत-सी सफलताएँ प्राप्त की गईं। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों में ही नहीं, उनके पूर्ववर्ती राजनीतिक दलों में भी हमेशा दो वर्ग रहे, एक उदार और दूसरा अनुदार। इनके अलावा अन्य दल, जिनमें ये दो वर्ग नहीं थे, अपने कार्यक्रमों के कुछ अंशों में सिर्फ तभी सफलता प्राप्त कर सके जब कि उन्होंने या तो इन दो बड़े राजनीतिक दलों में से किसी एक के साथ गठबन्धन किया या उनमें से किसी में विलीन हो गए। लेकिन अक्सर उनके अस्तित्व ने डेमोक्रेटिक या रिपब्लिकन पार्टियों को सुधार सम्बन्धी कानूनों की वकालत के लिए प्रोत्साहन अवश्य दिया।

इन सुधारों और परिवर्तनों के समर्थकों में विविध प्रकार के लोगों के होने के कारण सुधार के युगों में हुए अधिकतर परिवर्तन विभिन्न विचारों के बीच समझौते द्वारा मध्यमार्ग निकालकर ही किये गए। एक और अमेरिकी लोगों का यह व्यापक विचार है कि हर व्यक्ति को व्यक्तिगत उन्नति के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। उनका मत है कि 'व्यक्ति' की और समाज की स्थितियों को सुधारना सम्भव भी है और उचित भी और सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह जनता को अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए सहायता दे और उसके लिए अवसर प्रदान करे। दूसरी और अमेरिकी लोग व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा के लिए

भी बहुत चिन्तित है, उनका विश्वास है कि सरकार जनता की सहायक है, मालिक नहीं और जो भी सुधार होना हो, वह मुख्यतः स्वयं जनता की इच्छा और प्रयत्न का ही परिणाम होना चाहिए। अभिप्राय यह कि अमेरिकी समाज में सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के बीच जो सृजनात्मक संघर्ष चल रहा है उसीके फलस्वरूप अत्यधिक केन्द्रीकृत सत्तावादी संस्थाओं का सहारा लिये बिना भी अमेरिकी लोग इतने अधिक लाभ प्राप्त कर सकें हैं।

अमेरिका में सबसे पहला बड़ा सुधार-आन्दोलन सन् 1800 से 1840 तक की अवधि में हुआ। दो राष्ट्रपतियों, जैफर्सन और जैकसन ने इस लोकतन्त्रवादी आन्दोलन का नेतृत्व किया, इसलिए उनके नामों पर ही इस आन्दोलन का नाम 'जैफर्सोनियन डेमोक्रेसी' और 'जैकसनियन डेमोक्रेसी' रखा गया। 'जैकसनियन डेमोक्रेसी' कुछ अधिक उग्र सुधारवादी आन्दोलन था। यद्यपि इन दोनों में कुछ अन्तर था, फिर भी उनका कुल सम्मिलित परिणाम यह हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में वास्तविक या सम्भावित समानता की और राजनीतिक प्रक्रिया में अमेरिकी लोगों के अधिकतर वर्गों को हिस्सा देने के उद्देश्यों की उपलब्धि हो सकी। इस आन्दोलन की सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सफलताएँ ये थी : सार्विक मताधिकार, विधायकों और न्यायाधीशों का जनता द्वारा चुनाव, राज्यों और स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के शासनो पर जनता के नियन्त्रण को बढ़ाने के लिए राज्यों के संविधानों में संशोधन, और मारे देश में निःशुल्क शिक्षा का आरम्भ। किसानों और शहरी श्रमिकों ने जैफर्सन और जैकसन के इन लोकतन्त्रवादी आन्दोलनों को समर्थन प्रदान किया था, इसलिए उन्होंने भी कुछ आर्थिक सुधार चाहे। इसके फलस्वरूप किसानों को ये लाभ प्राप्त हुए : सरकार के पास पश्चिम की जो जमीन थी उनके वितरण की नीति अधिक उदार कर दी गई, उन्हें सस्ती व्याज-दर पर ऋण आसानी में मिलने लगा, शुल्क दर में कमी और अन्य ऐसे सरकारी-उपाय अपनाये गए जिनसे अन्तर्राष्ट्रीय और देश के आन्तरिक व्यापार की गर्ने कृषि-उत्पादकों के लिए अधिक अनुकूल होती थी।

श्रमिकों को, खासकर उत्तर-पूर्व के नव-स्थापित कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों को भी काफी लाभ प्राप्त हुआ। उन्हें राज्यीय और स्थानीय शासनों के उन कानूनों को रद्द कराने और न्यायालयों के उन फैसलों को उलटवाने में सफलता मिल गई, जो उन्हें ट्रेड यूनियनों बनाने और हड़ताल करने से रोकते थे।

सन् 1840 से प्रारम्भ दशक के आखिरी वर्षों में दास-प्रथा के प्रश्न को लेकर आन्दोलन छिड़ा और उससे राजनीतिक पार्टियों और उनके कार्यक्रमों का फिर नये सिरे से गठन होने लगा। इस आन्दोलन के फल-स्वरूप राजनीतिक दलों का जो नया पुनर्गठन हुआ वह अपने आप में सुधार का एक बड़ा प्रयत्न था। इसकी नाटकीय घटनाओं ने आने वाले गृह-युद्ध और पुनर्निर्माण युग में देश के सभी वर्गों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में एक बड़ा परिवर्तन किया। ये वर्ष सिर्फ इसीलिए स्मरणीय नहीं हैं कि इनमें दास-प्रथा का अन्त हो गया, बल्कि इनमें रिपब्लिकन दल के पुनर्निर्माण आन्दोलन ने देश के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में नीग्रो लोगों को पूर्ण और समान हिस्सा दिलाने—बल्कि देश के कुछ भागों में एकमात्र उन्हीं को ही हिस्सा दिलाने—का जबरदस्त प्रयत्न किया, हालांकि वह सफल नहीं हुआ। सन् 1875 तक उत्तर में निर्माण-उद्योगों (माल तैयार करने वाले उद्योग) का प्राधान्य हो गया था और पश्चिम में लोगों को रहने और जोतने के लिए मुफ्त वासभूमि देने की नीति और महाद्वीप के आरपार रेलों का नया जाल बिछाने से किसान, पशु पालक और खनक लोग धडाधड फैलने और आबाद होने लगे थे। इसके मुकाबले में संयुक्त राज्य का दक्षिणी भाग बहुत समय तक आर्थिक दृष्टि से गतिहीन रहा और उम गतिहीनता की स्थिति से वह अगली शताब्दी के आरम्भ में कहीं निकल सका। इन घटनाओं ने अनेक पुरानी समस्याओं को पुनर्जीवित कर दिया और नई समस्याएँ खड़ी कर दी और उनसे नये सुधार आन्दोलन के लिए सामग्री तैयार हो गई।

मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सन् 1870 से प्रारम्भ दशक

से लेकर 1930 से प्रारम्भ दशक तक एक के बाद एक जो बहुत-से सुधार आन्दोलन हुए उनमें बहुत-सी बातें समान थी और उन सब की प्रक्रिया एक प्रकार से एक ही सम्मिलित प्रक्रिया थी। सुधार सम्बन्धी इन प्रयत्नों को राजनीतिक आन्दोलन के रूप में संगठित करने की मुख्य प्रेरणा सबसे पहले पश्चिम के किसानों से मिली। बाद में अन्य असन्तुष्ट वर्ग भी उनके साथ आ मिले। शुरू-शुरू के पोपुलिस्ट और प्रोग्रेसिव दल, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दलों के उदार गुट और उनके अधिक उग्र पूर्ववर्ती दल या उनकी शाखाएँ—इन सबका बुनियादी ध्येय एक ही था कि उन अमेरिकी लोगों को अधिक सामाजिक न्याय और आर्थिक कल्याण प्रदान कराया जाय, जो 1930 से प्रारम्भ दशक के 'नई नीति' (न्यू डील) युग में 'विशेषाधिकार-वचित' (अण्डर प्रिविलेज्ड) कहा-लाते थे।

'विशेषाधिकार-वचित' शब्द की व्याख्या हर वर्ग और हर दशक में अलग-अलग की जाती थी। उत्तर और मध्य-पश्चिम के औद्योगिक क्षेत्र में मुख्यतः औद्योगिक श्रमिक ही 'विशेषाधिकार-वचित' कहे जाते थे। प्रारम्भ में सभी श्रमिकों को इनमें गिना जाता था, किन्तु बाद में मुख्यतः बड़े पैमाने पर सामूहिक उत्पादन करने वाले और अन्य असंगठित उद्योगों के मजदूर ही जिनके हितों का प्रतिनिधित्व यूनियनों नहीं करती थी, इन में गिने जाने लगे। कृषि-प्रधान पश्चिम में इस वर्ग में किसान गिने जाते थे, मुख्यतः वे किसान जो अपने पारिवारिक फार्म चलाते थे और यह अनुभव करते थे कि उन्हें अपनी उपज का वाजिव मूल्य नहीं मिलता और इसलिए वे उचित आय से वंचित रहते हैं। दक्षिण में, जो राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय था, प्रारम्भ में असन्तुष्ट वर्ग में छोटे गौरे किसान थे, लेकिन नन् 1930 से प्रारम्भ दशक में स्थिति बदल गई और दक्षिण के नीग्रो लोगों की असन्तोषजनक स्थिति दक्षिणी राज्यों से बाहर ही नहीं, स्वयं दक्षिणी राज्यों में भी चिन्ता का विषय बन गई। पहाड़ी राज्यों में आन्दोलनकर्ता वहाँ के महत्वपूर्ण गान उद्योग थे, जो सस्ती घातुओं के मूल्य बहुत अधिक गिरते ही नष्टावस्था

की सौग करते थे। इसी प्रकार प्रशान्त महासागर के तटवर्ती इलाकों में व्यापारी, किसान और उपभोक्ता, सभी मिलकर यह आन्दोलन करते रहे कि उन्हें परिवहन और बिजली की सुविधाएँ प्रदान की जाएँ।

सुधार आन्दोलन करने वाले आम तौर पर दो तरह के कानून चाहते थे। एक तरह के कानूनों से वे 'विशेषाधिकार-वर्चित' लोगों के कुछ अधिकार सरकार से लागू कराना, या अधिक शक्तिशाली समूहों के अन्यायपूर्ण और अवाञ्छनीय कामों को रोकवाना चाहते थे। इसका एक स्मरणीय उदाहरण सन् 1930 के दशक का श्रम-प्रवन्ध कानून है, जिसने न केवल श्रमिकों के अपने आपको संगठित करने और अपनी पसन्द की ट्रेड यूनियन के द्वारा सौदेबाजी करने के अधिकार को वैध ठहराया, बल्कि इन अधिकारों को लागू करने के लिए एक सरकारी तन्त्र की स्थापना की। सामाजिक क्षेत्र में सुधार के लिए आन्दोलन का उदाहरण वह सघीय कानून है, हालांकि वह अभी आंशिक रूप में ही सफल हुआ है, जिसके अन्तर्गत नीग्रो लोगों और अन्य जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यक वर्गों के साथ सभी प्रकार के भेदभाव का निषेध किया गया है। रेल के किराये-भाड़े की दरों आदि के नियमन और उद्योग-व्यवसायों के बड़े-बड़े एकाधिकार वाले मण्डलों के निर्माण को रोकने के लिए बनाये गए कानून भी सुधार आन्दोलन के उदाहरण हैं।

दूसरी तरह के कानून वे थे जिनका उद्देश्य ऐसे वर्गों के, जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी या जिनकी आर्थिक सौदेबाजी की शक्ति स्वभावतः बहुत कम थी, आय के स्तर को ऊँचा उठाने या उनके कल्याण के लिए सरकारी कार्यक्रम प्रारम्भ कराना था। इस श्रेणी के कानूनों में मजदूरी की दर और काम के घण्टों के बारे में निर्मित कानून, बुढ़ापे और मृत्यु की दशा में श्रमिक और उसके भरण-पोषण के लिए बीमा का कानून, गन्दी बस्तियों के उन्मूलन और अल्प-आय वर्ग के गृह-निर्माण के लिए सघीय सहायता का कानून, और इसी प्रकार खास-खास वर्गों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सघीय, राज्यीय या स्थानीय तारा धन व्यय करने के कानून उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये

जा सकते हैं ।

यह अनवरत आत्मालोचन और उसके फलस्वरूप अमेरिकी समाज में हुए ये सुधार मार्क्सवादियों के इन दोनों कथनों का पूर्णतः खण्डन करते हैं कि स्वतन्त्र उद्यम वाले समाज में 'आम जनता के कण्ठों' में निरन्तर वृद्धि होगी और इस प्रकार के समाज में सरकार केवल 'सत्ता-धारी वर्ग की कार्यकारी परिषद्' से अधिक कुछ नहीं है । औद्योगिक क्षेत्र के मुखियाओं और बड़ी-बड़ी कम्पनियों की राजनीतिक और आर्थिक सत्ता मार्क्सवादी सिद्धान्त में जितनी बड़ी और विशाल समझी जाती है, वास्तव में वह उतनी बड़ी नहीं है । न केवल लोकप्रिय सुधार आन्दोलनों ने, जिनकी जड़े कृषक और श्रमिक वर्ग में बहुत गहरी थी, इस सत्ता को नियन्त्रित किया है, बल्कि एक-दो पीढ़ियों के भीतर स्वयं उद्योगपति ही ऐसी स्थिति में पहुँच गए जब कि उन्होंने अमेरिकी प्रणाली की संस्थात्मक खामियों को अनुभव किया और उन्हें दूर करने में हिस्सा लेने लगे ।

इसमें सन्देह नहीं कि कुछ ऐसे व्यक्ति, और छोटे किन्तु शोर मचाने में तेज, समूह हमेशा रहे जिन्होंने हर सुधार का जोरो से विरोध किया । कुछ सुधारों के उद्देश्यों और तरीकों को लेकर भी विवाद हुए । इन मतभेदों से सिर्फ इतना ही हुआ कि काफी व्यापक रूप से आवश्यक और वाछनीय समझे जाने वाले परिवर्तनों की गति कुछ मन्द हुई, किन्तु वे उन्हें रोक नहीं सके । इस के अलावा अमेरिकी समाज में ऐसा कोई बड़ा वर्ग नहीं था, जो परिवर्तन और सुधार का पूर्णतः और बुनियादी तौर पर विरोधी रहा हो । सत्ता सभी बड़े सामाजिक वर्गों में इस प्रकार बँट गई कि देर-सवेर सभी बढ़ते हुए सामाजिक न्याय और कल्याण में हिस्सेदार होने लगे ।

अमेरिकी समाज के सभी बड़े वर्गों के लिए इस बात की परख का मौका 1930 के दशक की मन्दी के समय आया. कि वे परिवर्तन को वास्तव में स्वीकार करते हैं या नहीं और उनमें व्यावहारिक सुधार की क्षमता है या नहीं । इस मन्दी में बिक्री कम होने और परिसम्पत्ति के आहिस्ता-आहिस्ता खत्म होने से व्यापारियों को लकवा-सा मार

कृषको के हाथ से उनके फार्म और बाजार निकलने लगे; श्रमिकों के सामने अन्तर्होन प्रतीत होने वाली बेरोजगारी का भूत मुंह बाये खड़ा हो गया, घरों के मालिक अपने घरों से वेदखल होने लगे और जिन लोगों ने कीड़ी-कीड़ी कर पैसा जोड़ा था उनकी बैंकों में जमा रकमें और बीमा पालिसियाँ देखते-देखते बैंक और बीमा कम्पनियाँ फेल होने से साफ होने लगी—इन सब आघात पहुँचाने वाली घटनाओं ने लोगों में निराशा, मायूसी और गुस्सा पैदा कर दिया। कुछ समय तक सघीय और राज्यीय सरकारें भी कुछ नहीं कर सकीं। उन्होंने सिर्फ लोगों से अपने ऊपर भरोसा करने के लिए कहा, हालांकि वह बिल्कुल बेकार था, या अपना खर्च घटा दिया अथवा कर बढ़ा दिये, जिससे न चाहते हुए भी वस्तुओं की माँग उलटे और भी कम हो गई। इन सब सकटों के फलस्वरूप कुछ प्रेक्षक यह भविष्यवाणी करने लगे कि संयुक्त राज्य भी जल्दी ही फासिस्ट इटली, नाजी जर्मनी या कम्युनिस्ट रूस के ढग पर तानाशाही देश बन जाएगा। लेकिन अमेरिकी लोगों की एक सर्वथा नगण्य सख्या ही ऐसी थी जो ऐसे क्रान्तिकारी वामपंथी या दक्षिणा पंथी सपने मन में सजो रही थी।

यद्यपि अमेरिकी लोग बहुत निराश और भयभीत हो गए थे तो भी अधिकांश लोगों की दिलचस्पी समूची आर्थिक और सामाजिक प्रणाली के आमूलचूल पुनर्गठन के बजाय ऐसे तात्कालिक कदम उठाने में थी जिनसे मन्दी के कुछ विशिष्ट प्रभाव दूर किये जा सकें। उदाहरण के लिए किसानों ने यह माँग की कि कृषि-जिन्सों की कीमतों को स्थिर रखने के लिए कदम उठाये जाएँ और उन्होंने फसल गिरवी रख कर जो मियादी कर्जें लिये हैं, उनकी मियाद बढ़ा दी जाय। श्रमिकों ने माँग की कि ऐसे नये सरकारी निर्माण कार्य खोले जाएँ जिनसे उन्हें 'रोजगार मिले' और बेरोजगारी बीमा किया जाय एवं बेरोजगारी की दशा में उन्हें राहत दी जाय। जिन लोगों ने अपने मकान बनाने के लिए मकानों पर बन्धक-ऋण लिये थे उन्होंने अपने मकानों को बचाने के लिए गारण्टियाँ चाही और जिन लोगों ने अपना पैसा बचाकर बैंकों में जमा

कराया था, उन्होंने संघीय सरकार से, जमा-खाते का बीमा करने और शेयर-बाजार पर तजर रखने की माँग की।

यह सच है कि सरकार आर्थिक मन्दी के स्वरूप को पूरी तरह समझ नहीं सकी और उसके लिए उन्होंने पुराने घिसे-पिटे उपाय ही अपनाये और अपने पहले के पूर्वग्रह ही कायम रखे जिसका परिणाम यह हुआ कि सन् 1930 से प्रारम्भ दशक के अन्त तक बड़े पैमाने पर देश में बेरोजगारी बनी रही। लेकिन मन्दी के प्रभावों का पूर्णतः अन्त होने में देरी जरूर लग गई तो भी 'नई नीति' के वर्षों में कई ऐसे सामाजिक और आर्थिक सुधारों के आन्दोलन, जो गृह-युद्ध के बाद के वर्षों में बराबर अधूरे चलते आ रहे थे, कामयाब और पूर्ण हो गए।

सन् 1930 के दशक की मन्दी का प्रभाव इतना ज़बर्दस्त था कि लोगो ने ठोस सुधारों की आवश्यकता को बहुत उत्कट रूप में अनुभव किया और इन सुधारों का विरोध बहुत कमजोर हो गया। नतीजा यह हुआ कि पहले जिन सुधारों को असम्भव समझा जाता था, वे बड़ी द्रुत गति से सम्पन्न हो गए। इसके अलावा यदि सन् 1940 और सन् 1950 के दशकों में काफी बड़ी आर्थिक उन्नति न हुई होती तो ये सुधार आन्दोलन सफल न हो पाते। एकदम मन्दी की स्थिति से पुनः आर्थिक अभिवृद्धि के युग के आगमन का परिणाम यह हुआ कि लोगो के वेतनों और आमदनियों में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। यदि आर्थिक अभिवृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि न होती तो वेतनों और आमदनियों में भी इतनी वृद्धि कभी न हो पाती। आमदनियों की वृद्धि का एक परिणाम यह हुआ कि सीमित राष्ट्रीय आय के वितरण के प्रश्न को लेकर जो बहुत-से कटु विवाद उठ सकते थे, उनसे सयुक्त राज्य बच गया।

इस प्रकार अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था एक द्रुत विकास की प्रक्रिया में से गुजरती रही है—और यह विकास कभी-कभी तो इतना द्रुत हुआ है कि उस समय जो समस्याएँ बहुत तात्कालिक और विकट प्रतीत होती थी, वे एकदम स्थिति बदल जाने से निरर्थक हो गईं और उनका स्थान बाद के जमाने की नई समस्याओं ने ले लिया। आर्थिक क्षेत्र की कुछ नीतियाँ

कृषको के हाथ से उनके फार्म और बाजार निकलने लगे; श्रमिकों के सामने अन्तर्होन प्रतीत होने वाली बेरोजगारी का भूत मुंह बाये खड़ा हो गया, घरों के मालिक अपने घरों से वेदखल होने लगे और जिन लोगों ने कौड़ी-कौड़ी कर पैसा जोड़ा था उनकी बैंकों में जमा रकमें और बीमा पालिसियाँ देखते-देखते बैंक और बीमा कम्पनियाँ फेन होने में साफ होने लगी—इन सब आघात पहुँचाने वाली घटनाओं ने लोगों में निराशा, मायूसी और गुस्सा पैदा कर दिया। कुछ समय तक संघीय और राज्यीय सरकारें भी कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने सिर्फ लोगों से अपने ऊपर भरोसा करने के लिए कहा, हालांकि वह विलकुल बेकार था, या अपना खर्च घटा दिया अथवा कर बढ़ा दिये, जिससे न चाहते हुए भी वस्तुओं की माँग उलटे और भी कम हो गई। इन सब संकटों के फलस्वरूप कुछ प्रेक्षक यह भविष्यवाणी करने लगे कि संयुक्त राज्य भी जल्दी ही फासिस्ट इटली, नाजी जर्मनी या कम्युनिस्ट रूस के ढग पर तानाशाही देश बन जाएगा। लेकिन अमेरिकी लोगों की एक सर्वथा नगण्य सत्ता ही ऐसी थी जो ऐसे क्रान्तिकारी वामपक्षी या दक्षिणा पक्षी सपने मन में सजो रही थी।

यद्यपि अमेरिकी लोग बहुत निराश और भयभीत हो गए थे तो भी अधिकांश लोगों की दिलचस्पी समूची आर्थिक और सामाजिक प्रणाली के आमूलचूल पुनर्गठन के बजाय ऐसे तात्कालिक कदम उठाने में थी जिनसे मन्दी के कुछ विशिष्ट प्रभाव दूर किये जा सकें। उदाहरण के लिए किसानों ने यह माँग की कि कृषि-जिन्सों की कीमतों को स्थिर रखने के लिए कदम उठाये जाएँ और उन्होंने फसल गिरवी रख कर जो मियादी कर्जें लिये हैं, उनकी मियाद बढ़ा दी जाय। श्रमिकों ने माँग की कि ऐसे नये सरकारी निर्माण कार्य खोले जाएँ जिनसे उन्हें रोजगार मिले और बेरोजगारी बीमा किया जाय एवं बेरोजगारी की दशा में उन्हें राहत दी जाय। जिन लोगों ने अपने मकान बनाने के लिए मकानों पर बन्धक-ऋण लिये थे उन्होंने अपने मकानों को बचाने के लिए गारण्टियाँ चाही और जिन लोगों ने अपना पैसा बचाकर बैंकों में जमा

कराया था, उन्होंने संघीय सरकार से, जमा-खाते का बीमा करने और शेयर-बाजार पर नजर रखने की माँग की।

यह सच है कि सरकारें आर्थिक मन्दी के स्वरूप को पूरी तरह समझ नहीं सकी और उसके लिए उन्होंने पुराने धिसे-पिटे उपाय ही अपनाये और अपने पहले के पूर्वग्रह ही कायम रखे जिसका परिणाम यह हुआ कि सन् 1930 से प्रारम्भ दशक के अन्त तक बड़े पैमाने पर देश में बेरोजगारी बनी रही। लेकिन मन्दी के प्रभावो का पूर्णतः अन्त होने में देरी जरूर लग गई तो भी 'नई नीति' के वर्षों में कई ऐसे सामाजिक और आर्थिक सुधारों के आन्दोलन, जो गृह-युद्ध के बाद के वर्षों में बराबर अधूरे चलते आ रहे थे, कामयाब और पूर्ण हो गए।

सन् 1930 के दशक की मन्दी का प्रभाव इतना ज़बरदस्त था कि लोगों ने ठोस सुधारों की आवश्यकता को बहुत उत्कट रूप में अनुभव किया और इन सुधारों का विरोध बहुत कमजोर हो गया। नतीजा यह हुआ कि पहले जिन सुधारों को असम्भव समझा जाता था, वे बड़ी द्रुत गति से सम्पन्न हो गए। इसके अलावा यदि सन् 1940 और सन् 1950 के दशकों में काफी बड़ी आर्थिक उन्नति न हुई होती तो ये सुधार आन्दोलन सफल न हो पाते। एकदम मन्दी की स्थिति से पुनः आर्थिक अभिवृद्धि के युग के आगमन का परिणाम यह हुआ कि लोगों के वेतनों और आमदनियों में बहुत बड़ी वृद्धि हुई। यदि आर्थिक अभिवृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि न होती तो वेतनों और आमदनियों में भी इतनी वृद्धि कभी न हो पाती। आमदनियों की वृद्धि का एक परिणाम यह हुआ कि सीमित राष्ट्रीय आय के वितरण के प्रश्न को लेकर जो बहुत-से कटु विवाद उठ सकते थे, उनसे संयुक्त राज्य बच गया।

इस प्रकार अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था एक द्रुत विकास की प्रक्रिया में से गुजरती रही है—और यह विकास कभी-कभी तो इतना द्रुत हुआ है कि उन नमय जो समस्याएँ बहुत तात्कालिक और विकट प्रतीत होती थी, वे एकदम स्थिति बदल जाने से निरर्थक हो गई और उनका स्थान बाद के उगाने की नई समस्याओं ने ले लिया। आर्थिक क्षेत्र की कुछ नीतियाँ

अस्थायी रही, क्योंकि वे मन्दी युद्ध या इसी तरह के स्वल्पकालिक दोरी में अपनाई गई थी, लेकिन कुछ नीतियों का अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पर स्थायी असर पड़ा ।

और परिवर्तन की यह प्रक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है । आर्थिक और सामाजिक क्षितिजों पर नई समस्याएँ उभर रही हैं और उनका सामना करने के लिए नई नीतियाँ अपनानी पड़ेंगी । हम यह दावा नहीं करते कि हमें अपनी मौजूदा और भविष्य में दिखाई पड़ने वाली तमाम कठिनाइयों पर विजय पाने के उपायों की जानकारी है । आज पुरानी धारणाएँ और पुराने समाधान नई समस्याओं में ठीक नहीं अटते और उनके लिए नये दृष्टिकोणों की आवश्यकता है और यही आज के ज़माने की चुनौती है ।

इन समस्याओं के समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आहिस्ता-आहिस्ता अपने मन में भविष्य के वाछनीय सामाजिक और आर्थिक जीवन की एक मूर्ति अंकित करें । सिर्फ यह कह देना कि हर चीज का प्राचुर्य ही हमारा लक्ष्य है, काफी नहीं है । इसके विपरीत यह कहना अधिक स्पष्ट और सार्थक होगा कि हमारा लक्ष्य सभी लोगों की आमदनियों को जीवन-यापन के लिए अनिवार्य न्यूनतम स्तर से काफी ऊँचा उठाना है । इसी तरह यदि हम यह कहें कि हर आदमी को विश्राम के लिए पर्याप्त समय देना और उसे देश के सांस्कृतिक जीवन में रचनात्मक ढंग से भाग लेने के योग्य बनाने के लिए अच्छी व्यापक शिक्षा देना हमारा लक्ष्य है तो वह लक्ष्य हमारी पहुँच के बाहर नहीं होगा ।

ये ऐसी आकाक्षाएँ हैं, जो सर्वत्र पाई जाती हैं । लेकिन इनके अलावा एक और लक्ष्य भी है जो ससार के अन्य भागों की अपेक्षा संयुक्त राज्य में अधिक बार और अधिक बलपूर्वक प्रकट किया गया है । वह लक्ष्य यह है कि हर अमेरिकी के पास इतनी सम्पत्ति हो कि वह आर्थिक सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता अनुभव करे । अमेरिकी इतिहास के प्रारम्भ से ही इस लक्ष्य को लोगों ने सामने रखा है । इस लक्ष्य की अभिव्यक्ति का एक बड़ा साधन सन् 1862 का होमस्टैड ऐक्ट (वासभूमि अधिनियम)

था, जिसके मूल में यह विचार निहित था कि जो भी अमेरिकी चाहे वह अपनी सम्पत्ति अवश्य प्राप्त कर सके जो उसके परिवार की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हो। अमेरिका में व्यक्तिगत सम्पत्ति के स्वामित्व के द्वारा आर्थिक सुरक्षा का आदर्श इतना बढ्दमूल होने का ही यह परिणाम था कि यहाँ सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के कानून बनाने का आन्दोलन यूरोप से बहुत पीछे शुरू हुआ। आज बहुत-से अमेरिकियों का यह विश्वास है कि सामाजिक सुरक्षा के सरकारी कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हैं और उन्हें इतना बढ़ाया जाना चाहिए कि व्यक्ति आपातकालीन परिस्थितियों का सामना कर सके और साथ ही उसकी जीवन-निर्वाह की न्यूनतम आवश्यकताएँ हमेशा पूरी हो सकें। लेकिन साथ ही वे उसे भी एक अत्यधिक वाछनीय लक्ष्य बनाये रखना चाहते हैं कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के पास अपनी निज की सम्पत्ति हो।

आगामी अध्यायो में हम तात्कालिक महत्त्व की समस्याओं और गुरुर-भविष्य की समस्याओं, दोनों पर विचार करेंगे। हमारी तात्कालिक महत्त्व की समस्याएँ ये हैं : आर्थिक वृद्धि की गति को काफी बढ़ाना, जहाँ तक सम्भव हो पूर्ण रोजगार को व्यवस्था करना और कीमती को काफी हद तक स्थिर रखना ; एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकना ; शिक्षा, अनुसन्धान और प्रशिक्षण की प्रणालियों में सुधार कर उन्हें आधुनिक उद्योग शिक्षा और अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के अनुकूल बनाना, पूँजी, मानव और ज्ञान को एक देश से दूसरे देश में प्रवाहित करना ; और जनता को विभिन्न वर्ग की प्रजापति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राथमिक राजस्व-समावेशों का संरक्षण करना और शक्ति और कार्य-मान की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनके नये-नये माधन विचार करना।

अपने-अपने मोर्चों पर अपनी समस्याएँ नज़र नहीं आती या उनमें उनका समाधान करने की क्षमता नहीं है। इनमें से हरेक वर्ग को अपने आत्म-हित के लिए आर्थिक परिवर्तनों की माँग करने का अधिकार है और इसलिए अपनी आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के सामाजिक दृष्टि से उचित और अनुचित उपयोग में भेद करने की भारी जिम्मेदारी उसके ऊपर है। अमेरिकी जनता की ओजस्विता, अमेरिका की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का लचकीलापन और देश का अतीत काल का विकास—ये सभी चीज़ें यह विश्वास पैदा करती हैं कि आर्थिक गति-विधि और आचरण के स्तर को जनता के सामान्य कल्याण के लिए ऊँचा उठाकर इन समस्याओं के प्रभावकारी और स्वीकरणीय हल निकाले जा सकेंगे।

आर्थिक उन्नति में सन्तुलन

उत्पादकता की भांति आर्थिक उन्नति और स्थिरता भी किसी 'प्राकृतिक' नियम से स्वतः उत्पन्न नहीं होती। उत्पादकता में वृद्धि के लिए ज्ञान, श्रम, प्रबन्ध, पूंजी, प्राकृतिक साधन-सम्पदा और समुचित सरकारी नीतियों के सम्मिश्रणों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा उत्पादकता वृद्धि उत्पादित माल की बिक्री के लिए निरन्तर वृद्धि पर भी निर्भर करती है। अगर बहुत तेज आर्थिक उतार-चढ़ाव आये, कीमतों में निरन्तर वृद्धि होती रहे या व्यवसाय के ढाँचे में अपरिवर्तनीयता आ जाय तो उत्पादित माल की बिक्री के लिए बाजारों का विस्तार खतरे में पड़ सकता है। इसलिए, यद्यपि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में विस्तार और उन्नति की बहुत सम्भावनाएँ निहित हैं, तो भी इन तीन सम्भावित खतरों को दृष्टि में रखते हुए यह पहले से ही निश्चित नहीं माना जा सकता कि अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि होगी ही और उसमें स्थिरता भी आयेगी ही। यह बात भी हम निश्चित रूप में नहीं मान सकते कि हमारी विस्तीर्णमान अर्थ-व्यवस्था से हमें स्वतः ही वे वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध हो जाएँगी, जो हमारे अत्यन्त आवश्यक राष्ट्रीय उद्देश्यों और सामान्य कल्याण को समुन्नत करेंगी।

सम्भावित उत्पादन वृद्धि और उसका उपयोग

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में राष्ट्र के उत्पादक साधनों के उपयोग के सम्बन्ध में तीन तरह से निश्चय किये जाते हैं। उपभोक्ता यह फ़ैसला करते हैं कि वे किस किस की वस्तुओं के लिए पैसा खर्च करना चाहेंगे। दूसरे व्यवसायी लोग यह निश्चय करते हैं कि भावी उत्पादन और सेवाओं से लिए सयन्त्र, मशीनरी तथा अन्य पूंजीगत सामग्री में वे कैसे

और कितना धन निवेश करेंगे। और तीसरे मधीय, राज्यीय और स्थानीय शासन अपनी विधि-निर्माण और वजट की प्रक्रियाओं से सार्वजनिक सेवाओं के परिमाण और स्वरूप का निर्णय करते हैं।

ये तीनों व्यवस्थाएँ परस्पर सम्बद्ध हैं, क्योंकि एक तो समस्त उत्पादन, चाहे वह उपभोग के लिए हो, या व्यावसायिक निवेश के लिए, या सरकारी सेवाओं के लिए, किया राष्ट्र की श्रमिक शक्ति द्वारा ही जाता है, और दूसरे, किसी एक उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किये गए उत्पादक साधनों और प्राकृतिक सम्पदा से दूसरी वस्तुएँ तैयार नहीं हो सकती, उदाहरण के लिए उपभोग्य सामग्री तैयार करने वाले साधन निवेश अथवा सरकारी सेवाओं के लिए काम नहीं आ सकते। सरकार स्वतन्त्र उद्यम वाली अर्थ-व्यवस्था में भी अपने सरकारी व्यय कार्यक्रमों, ऋण के उपायों और अन्य नीतियों से राष्ट्र के उत्पादक साधनों के उपयोग पर प्रभाव डाल सकती है। केवल सत्तावादी (तानाशाही) देशों में ही नहीं, लोकतन्त्रीय देशों में भी सरकार के पास ऐसे अधिकार और साधन होते हैं, जिनसे वह इस बात के लिए अर्थ-व्यवस्था को बाधित कर सकती है कि सरकार की वैदेशिक नीति या आन्तरिक आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए जिन वस्तुओं का उत्पादन सर्वप्रथम आवश्यक है, उन्हें वह प्राथमिकता दे। बुनियादी तौर पर ये निश्चय व्यक्तिगत रूप में लोगों द्वारा किये जाते हैं। उपभोक्ता और व्यवसाय प्रबन्धक अपने आर्थिक व्यवहार द्वारा, और नागरिक अपने राजनीतिक चुनाव द्वारा, व्यक्तिगत तौर पर ये निर्णय करते हैं। सन् 1960 में उपभोक्ताओं, व्यवसाय प्रबन्धकों और सरकार, तीनों के द्वारा किये गए इन निश्चयों के फलस्वरूप संयुक्त राज्य में 5 खरब 4 अरब 40 करोड़ डॉलर के सामान और सेवाओं का उत्पादन हुआ। यहाँ उन थोड़े-से महत्वपूर्ण प्रयोजनों का अध्ययन करना दिलचस्प होगा जिनके लिए अमेरिकी जनता ने अपनी साधन-सम्पदा का बंटवारा किया।

राष्ट्र का लगभग एक-तिहाई खर्च खाना, कपड़ा और आश्रय की प्राप्ति के लिए किया गया; और दस प्रतिशत मकानों की सजावट, व्याज

को अदायगी और व्यक्तिगत सेवाओं (हज्जाओं की दूकानों, कानूनी सेवाओं और बीमा आदि) पर व्यय हुआ। उपभोक्ताओं ने मनोरंजन, सिगरेट, शराब और जेवर आदि विलासिता की वस्तुओं पर जो खर्च किया वह शिक्षा और डाक्टरी चिकित्सा (जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाओं और अस्पतालों के निर्माण और संचालन का व्यय शामिल है) पर हुए कुल सम्मिलित व्यय से कुछ ही कम है। पहले लगायी गई रोकों के फलस्वरूप, शिक्षा, मूल अनुसन्धान, डाक्टरी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी देख-भाल और प्राकृतिक साधनों का विकास और संरक्षण आदि महत्वपूर्ण मदों पर उतना व्यय नहीं किया गया, जितना किया जाना चाहिए था और उसमें गम्भीर कमियाँ रह गईं। इन गम्भीर कमियों पर आजकल जो चर्चा चल रही है, उस के फलस्वरूप यह सम्भव है कि भविष्य में उन्हें पहले से अधिक महत्व और प्राथमिकता दी जाय। इससे अनेक सरकारी और गैरसरकारी प्रयोजनों के लिए निर्धारित की जाने वाली राशियों में परिवर्तन हो सकते हैं।

आर्थिक वृद्धि और उपलब्ध धन के विभिन्न मदों में बटवारे के दीर्घकालीन रुझानों को दृष्टि में रखते हुए अगले दशक की सम्भावनाओं की कल्पना करना सम्भव है। यह सम्भव है कि 1970 में न्युक्त्त राज्य की कुल राष्ट्रीय आय, 1960 में प्रचलित मूल्यों के हिसाब में, 8 खरब डालर हो जाय, जब कि 1960 में वह 5 खरब डालर के लगभग थी। परिशिष्ट तालिका 24 में अगले दशक की सम्भावित आर्थिक स्थिति का चित्रण किया गया है। इस तालिका से यह संकेत मिलता है कि सन् 1970 तक सन् 1960 की अपेक्षा 3 खरब डालर की वस्तुएँ और सेवाएँ अधिक उपलब्ध होने लगेगी।

तालिका 12

मुख्य-मुख्य प्रयोजनों के लिए राष्ट्र का व्यय, 1960

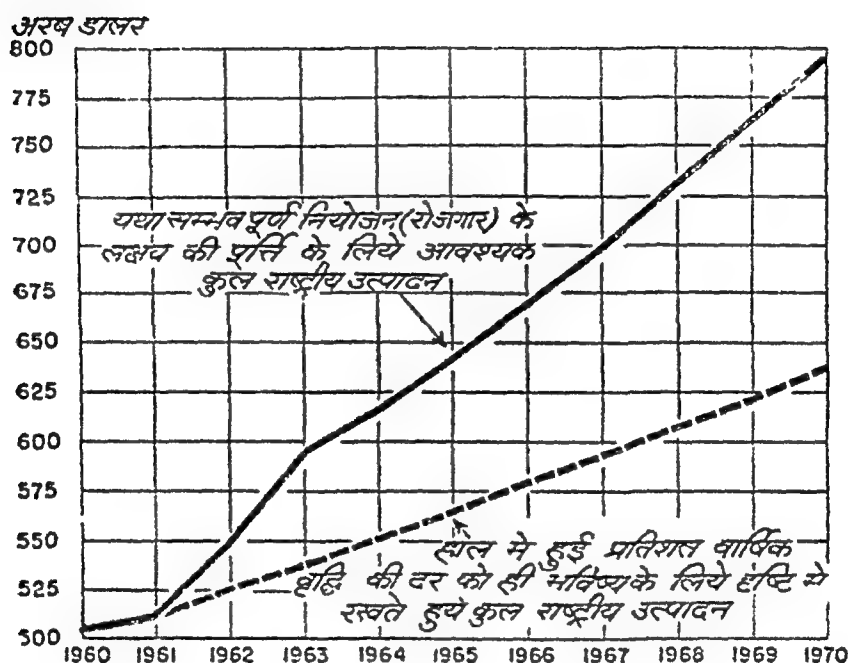
	अरब डालरों में	कुल का प्रतिशत
1 ' उपभोक्ताओं की मूल जरूरतें (खाना, कपड़ा, मकान).....	161.4	32 0
2. उपभोक्ताओं की अन्य जरूरतें (घरेलू वस्तुएँ और व्यक्तिगत व्यवसाय आदि).....	54.5	10 8
3. परिवहन (खरीदे और स्वयं चलाए गए वाहन).....	40 7	8.1
4. उपभोक्ताओं की विलासिता और अर्ध-विलासिता की चीजें.....	41 8	8.3
5 शिक्षा (सरकारी और निजी).....	23 2	4.6
6 अनुसन्धान और विकास.....	13 0	2 6
7. डाक्टरी चिकित्सा और देखभाल....	27 6	5 5
8. निजी धार्मिक और परोपकार के कार्य ...	4 7	0 9
9. निजी पूँजी-निवेश (अनुसन्धान और विकास पर किये गए खर्च शामिल नहीं) ..	72 4	14.3
10. राष्ट्रीय सुरक्षा (अनुसन्धान और विकास के व्यय शामिल नहीं).....	40 4	8.0
11 अन्य सरकारी काम ..	23 4	4 6
12 विदेशों में कुल निवेश....	1 5	0 3
कुल राष्ट्रीय आय ¹	504 4	100 0

1 विस्तृत जानकारी के लिए देखिये परिशिष्ट तालिका 21।

चार्ट 12

कुल राष्ट्रीय उत्पादन, 1960-1970 (संभावित)

(1960 के मूल्यों के हिसाब से)



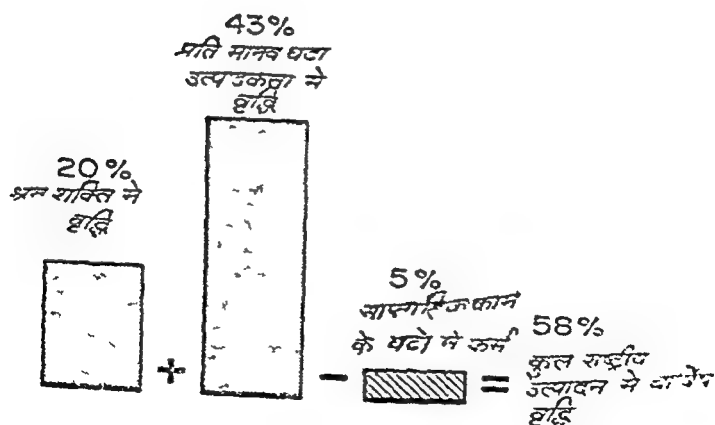
‘यथासम्भव पूर्ण नियोजन’ का अर्थ इतना नियोजन है कि उसमें 4 प्रतिशत से अधिक श्रमिक बेकार न हों।

उसी के हिसाब से काम के घंटों में कम या अधिक कमी होगी। देन की श्रमिक-शक्ति में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि और काम के घंटों में कमी के तर्क नगत् अनुमानों को दृष्टि में रखकर हमने यह हिसाब लगाया है कि सन् 1960 के बाद प्रतिवर्ष नयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्थाओं में 4½ प्रतिशत की वृद्धि होगी और, इस प्रकार देन की आय

सन् 1970 तक सन् 1960 के मूल्यो के अनुसार 8 खरब डालर हो जाएगी, जब कि सन् 1960 मे वह 5 खरब डालर है। लेकिन यदि राष्ट्र की आय (या उत्पादन) पहले की तरह कुल $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक ही बढे तो सन् 1970 मे वह कुल 6 खरब 40 अरब डालर तक ही पहुँच पायेगी अर्थात् 1960 से प्रारम्भ नारे दगक मे कुल 1 खरब 40 अरब डालर की ही वृद्धि होगी। इसका अर्थ यह होगा कि वह समय आने के लिए और भी लम्बी अवधि की जरूरत होगी, जबकि हमारी महत्वपूर्ण जरूरतें उपलब्ध साधनों से पूरी हो सकें।

चार्ट 13

कुल राष्ट्रीय उत्पादन की वृद्धि मे कारक तत्व 1960-1970



लेकिन $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत वार्षिक उत्पादन वृद्धि सम्भव तभी होगी जबकि लोगो मे अतिरिक्त उत्पादन की माँग हो। अगर यह वृद्धि हो जाय ता

सघीय, राज्यीय और स्थानीय शासन करो के रूप में 80 से 90 अरब डालर तक अतिरिक्त आय करो के रूप में खींच लेंगे। इसका अर्थ यह है कि या तो सरकार को अपने व्यय के कार्यक्रमों को काफी बढाना पड़ेगा या करो में कमी करनी पड़ेगी ताकि लोगों को निजी व्यय के लिए अधिक धन उपलब्ध हो और वे उससे उपभोग्य वस्तुएँ खरीद सकें या उसे बचाकर पूँजी-निर्माण में लगा सकें। अधिक सम्भावना यह है कि सरकार ये दोनों उपाय ही थोड़े-थोड़े अपनायेगी। वास्तव में अपने व्यय-कार्यक्रमों में वृद्धि और करो में कमी से प्राइवेट व्यय को प्रोत्साहन देकर सरकार इन दोनों साधनों से वृद्धि की भावी गति को, बल्कि उत्पादन में हुई वृद्धि के बटवारे को भी प्रभावित करती है। यह बड़े महत्त्व की बात है कि लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाओं, विद्वत्तापूर्ण पुस्तकों और कांग्रेस (संसद्) की बहसों के जरिये इस बारे में एक सार्वजनिक वाद-विवाद चल पड़ा है कि देश के सम्भावित साधनों के पूर्ण उपयोग के लिए क्या किया जाय और किन कामों को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाय।

तब यह सवाल उठता है कि सन् 1970 में 3 खरब डालर का जो अतिरिक्त उत्पादन होगा उसका उपयोग किन-किन कामों में किया जा सकता है।

उस समय तक देश की जनसंख्या में 3 करोड़ 30 लाख की वृद्धि हो जाएगी। यदि हम मान लें कि उस समय भी रहन-रहन का स्तर यही रहेगा तब 65 अरब डालर की अतिरिक्त आय इस अतिरिक्त आवादी के उपभोग व्यय में चली जाएगी। कुल उत्पादन में इस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए श्रम-शक्ति और कारखानों के सयन्त्रों और मशीनों आदि में वृद्धि की भी आवश्यकता होगी। इस प्रकार सन् 1970 तक 1960 के स्तर की अपेक्षा प्रतिवर्ष सयन्त्रों, उपकरणों, रिहायशी आवास गृहों, विदेशी निवेश और शिक्षा एवं अन्य-गैर-सरकारी-सेवाओं के लिए 30 से 35 अरब डालर तक की अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी। इसलिए अतिरिक्त आवादी और सयन्त्रों और उत्पादन क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि की आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए 95 से 100 अरब

डालर अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार यह राशि निकाल देने पर भी वस्तुओं और सेवाओं के सरकारी और गैर सरकारी उपयोग के लिए 2 खरब डालर की राशि बच जाएगी।

इस 2 खरब डालर के अतिरिक्त उत्पादन के कुछ वैकल्पिक उपयोग भी सम्भव हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए व्यय की जाने वाली राशि के स्तर को बढ़ाने का ही सवाल है। इनमें तनिष् भी सदेह नहीं कि इस सम्भावित उत्पादन वृद्धि के कारण रहन-सहन के स्तर और पूंजी-निवेश के वाछनीय स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना राष्ट्रीय सुरक्षा के व्यय को बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन यदि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव में कमी हो गई और गस्त्रास्त्रों पर व्यय में कमी की जा सकी तो और भी बहुत-से आवश्यक कामों के लिए धन की जरूरतें ज्यादा पूरी की जा सकेंगी।¹

राष्ट्रीय आयोजन सघ (नेशनल प्लैनिंग एसोसिएशन) की राष्ट्रीय आर्थिक प्रायोजन माला को दृष्टि में रखकर अव्ययन करने से यह मालूम होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, वैज्ञानिक अनुसन्धान, प्राकृतिक साधन नरक्षण (खासकर जलोपलब्धि और उसका उपयोग), स्थलीय और हवाई यातायात और इसी तरह के अन्य कई उपयोगों के लिए अतिरिक्त और अधिक विस्तृत कार्यक्रमों की आवश्यकता है। सन् 1960 के मूल्यों के हिसाब से करीब 69 अरब डालर के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होगी।² यह व्यय करना अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की क्षमता से बाहर नहीं है और यदि सन् 1970 तक राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी खर्चों में कुछ कमी की जा सकी तो वह अनिवार्य भी हो जाएगा। इस प्रकार के खर्च अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के भावी विकास और अभिवृद्धि के लिए अनिवार्य है। इन्हीं क्षेत्रों में ग्रासन खासकर राज्याधीन और स्थानीय शासन, प्रभाव डाल सकता है।

1. परिशिष्ट तालिका 25 में बताया गया है कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा के खर्चों में कमी की जा सके तो किन दूसरे कामों पर कितना-कितना व्यय बढ़ाया जा सकेगा।

2. परिशिष्ट तालिका 26 भी देखिये।

इसमे सन्देह नही कि यदि अगले दशक मे राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी खर्चों मे कमी की जा सके तो रहन-सहन के स्तर को तेज गति से ऊँचा उठाया जा सकेगा । यदि सन् 1970 तक 2 खरब डालर वार्षिक की यह अतिरिक्त अवशिष्ट आय पूरी की पूरी संयुक्त राज्य के श्रमिकों और अन्य वेतन भोगियों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा करने के लिए मिल जाय तो उससे प्रति व्यक्ति वार्षिक आय मे $4\frac{1}{2}$ प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी । लेकिन यह सब हिसाब लगाते हुए इस बात का ध्यान रखना होगा कि उपभोक्ताओं और सरकार की बढ़ती हुई माँगों को पूरा करने के लिए पूँजीगत मामलों और उद्योग-व्यवसाय मे नये निवेश के लिए भी धन की आवश्यकता होगी । इसके अलावा सन् 1970 तक विदेशों में संयुक्त राज्य के निवेश मे जो वृद्धि होगी उसका भी ध्यान रखना होगा ।

उस बात की काफी सम्भावनाएँ हैं कि उत्पादन मे सम्भावित यह वृद्धि किमी एक प्रयोजन के लिए नहीं, बल्कि इन सभी प्रयोजनों के सम्मिश्रण के लिए प्रयुक्त की जाएगी । इसका उपयोग लोगों की मजदूरियों और वेतनों मे वृद्धि और गरीबी के अवशेषों के त्रास के द्वारा जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए किया जाएगा । ऐसा प्रतीत होता है कि इस अतिरिक्त उत्पादन की आय मे से स्वास्थ्य-सेवाएँ, शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुसन्धान, प्राकृतिक साधनों के विकास और संरक्षण, परिवहन, उत्पादन मयन्न और उपकरण और विदेशी निवेश आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की व्यवस्था करने के बाद लोगों के रहन-सहन के स्तर मे $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत प्रति व्यक्ति की वृद्धि सम्भवतः सम्भवतः गती होगी । लेकिन अगर राष्ट्रीय सुरक्षा पर खर्च बढ़ाना पड़ गया, तब लोगों के रहन-सहन के स्तर और सरकार की सुरक्षा में भिन्न मतभेदों में सुधार सम्भवतः स्थिर धीरे-धीरे होगा ।

और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं के मुधार आदि में लगाया जाय । कुछ लोग दूसरी ओर, यह कहते हैं कि वैज्ञानिक और उद्योग-विद्या-सम्बन्धी अनुसन्धानों को, जिनमें अन्तरिक्ष की ग्योज का एक विशाल कार्यक्रम भी शामिल है, सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए । तीसरे वर्ग का कहना है कि अतिरिक्त राष्ट्रीय आय का उपयोग मुख्यतः उत्पादकता को बढ़ाने और उन लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा करने के लिए जिनकी आमदनी मुश्किल से अपने आपको जीवित रखने लायक ही है, किया जाना चाहिए ।

हम इन सब विचारों के विवाद में यहाँ नहीं पड़ना चाहते । महत्त्व की बात यह है कि आज आर्थिक विकास और अतिरिक्त उत्पादन से राष्ट्रीय आय में होने वाली वृद्धि के समुचित दृष्टिकोण के सम्बन्ध में दीर्घकालीन योजना की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है । यह अहसास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके माप ही यह भी समझ लिया जाना चाहिए कि इस सम्बन्ध में आवश्यक नीतियों के निर्धारण और उनके कार्यान्वय की अभी शुरुआत ही है ।

इन सब बातों पर विचार करने से यह भी मालूम होता है कि इस अतिरिक्त उत्पादन के लिए बहुत-से आवश्यक, बल्कि तत्काल आवश्यक, उपयोग हैं । अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे अपने अतिरिक्त उत्पादनों के उपयोग के लिए कोई मौका ही नज़र न आता हो । कुछ लोगों का कहना है कि संयुक्त राज्य की समृद्धि इस बात पर निर्भर है कि शस्त्रास्त्रों पर होने वाला व्यय न केवल जारी रखा जाय बल्कि उसे बढ़ाया भी जाय । लेकिन वास्तविकता यह है कि शस्त्रास्त्रों के उत्पादन पर बहुत ज्यादा राशि खर्च होने से अन्य वांछनीय उद्देश्यों की पूर्ति में बाधा पड़ती है ।

किसी एक किस्म के खर्च में परिवर्तन से, उदाहरण के लिए सैनिक व्यय में एकाएक वृद्धि या कमी से, कुछ कठिनाई तो हो सकती है, लेकिन वह स्थायी नहीं होगी । इस प्रकार की कठिनाई पर बजट और

वित्त सम्बन्धी उचित नीतियों से विजय पायी जा सकती है। आर्थिक विस्तार की आवश्यकता सिर्फ इसीलिए नहीं है कि बढ़ती हुई श्रमिकों की फौज को रोजगार पर लगाये रखना एक वाछनीय उद्देश्य था। वह इसलिए भी आवश्यक है कि वस्तुओं और खाद्य का अतिरिक्त उत्पादन अन्य महत्वपूर्ण और तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है।

आर्थिक उतार-चढ़ाव

कुछ दशक पूर्व यह विचार, कि एक स्वतन्त्र व्यवसाय प्रणाली में गम्भीर और देर तक चलने वाले उतार-चढ़ावों को रोका जा सकता है, वैसा ही अवास्तविक प्रतीत होता था जैसा कि यह विचार कि भूकम्पों को रोकना सम्भव है। बहुत समय तक अर्थशास्त्रियों का यह विचार रहा कि विकासोन्मुख और स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था की जो न्यूनतम कीमत चुकानी अनिवार्य है वह है आर्थिक सुरक्षा। इस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था में इस अरक्षा के विरुद्ध सिर्फ इतनी ही आशा की जा सकती है कि जो लोग समय-समय पर प्राने वाले इन जवर्दस्त उतार-चढ़ावों के शिकार होंगे, उन्हें बेरोजगारी के समय सहायता देकर या बेरोजगारी बीमा करके कुछ संरक्षण दिया जा सकता है।

अर्थशास्त्र के नियमों के अनुसार, उत्पादन आय को पैदा करता है और फिर उस आय के द्वारा उन वस्तुओं की माँग पैदा करता है जो उस उत्पादन के द्वारा उत्पादित हुई होती हैं। इससे यह सिद्धान्त निकलता है कि उत्पादन तभी बढ़ाया जाएगा, जब कि विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच ऐसा सम्बन्ध हो जिससे व्यवसाय का प्रबन्धक अतिरिक्त विक्री से अतिरिक्त मुनाफे की आशा कर सके। यदि आर्थिक गति-विधि में सकुचन आ जाय तो कच्चे माल की कीमतें, मजदूरियाँ और व्याज-दर, तीनों में गिरावट आयेगी। इससे उपभोक्ताओं को गिरी हुई नीची कीमतों पर वस्तुएँ खरीदने का और उत्पादकों को कम मजदूरी पर अधिक मजदूर रखने और अपने उद्योग में अधिक निवेश

करने का प्रलोभन होगा। इसका परिणाम यह होगा कि सकुचन का यह रुझान एकदम उल्टा हो जाएगा।

वास्तव में ये प्रक्रियाएँ आम तौर पर अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों के अनुसार नहीं होती। होता यह है कि जब मजदूरी की दरों में कमी आती है तो, इससे पूर्व कि उससे उत्पादक लोग अधिक मजदूर रखें या उपभोक्ता अधिक माल खरीदें, आम तौर पर उसके फलस्वरूप मजदूरों की संख्या कम हो जाती है और उनकी क्रयशक्ति कम हो जाने से वस्तुओं की विक्री भी घट जाती है। इस प्रकार मजदूरी में कटौती बाजार में खरीद-विक्री को बढ़ाने के बजाय उसे घटा देती है और इस प्रकार अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा करने के बजाय क्षति पहुँचाती है।

कुछ मन्दी की स्थितियाँ ऐसी भी आयी, जब कि व्यवसायियों ने न तो कीमतें कम की और न उत्पादन बढ़ाया, क्योंकि उन्हें यह भरोसा नहीं था कि मूल्यों में कमी ग्राहकों को अधिक खरीद के लिए प्रेरित कर सकेगी। इसी तरह व्याज-दर में कमी से प्रेरित होकर व्यवसायियों ने अपने निवेश में वृद्धि भी नहीं की, क्योंकि उन्हें यह विश्वास नहीं था कि इस निवेश-वृद्धि से होने वाले अतिरिक्त उत्पादन की विक्री हो सकेगी। सन् 1930 से प्रारम्भ दशक के अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि उद्योग-व्यवसाय का विस्तार तभी किया जाता है जब कि विक्रय-मूल्य और लागत का सम्बन्ध उत्पादक के लिए लाभ-जनक हो, किन्तु इस विस्तार के लिए उसे प्रेरणा तब मिलती है जब कि उसे यह लगता है कि उसके उत्पादित माल की विक्री के लिए अधिक बड़ा बाजार उपलब्ध हो सकेगा। मन्दी के वर्षों में उद्योगों का विस्तार न होने का कारण यह था कि उत्पादकों को यह आशा नहीं थी कि अपने उत्पादन के लिए उन्हें अधिक विस्तृत बाजार मिल सकेगा।

व्यवसायी-वर्ग की प्रतिक्रिया कभी तो ऐसी होती है कि थोड़े-बहुत अस्थायी धक्के के बावजूद वह यह आशा करता है कि बाजार

का काफी विस्तार होगा और कभी इसके विपरीत उसकी प्रतिक्रिया यह होती है कि व्यावसायिक क्षेत्र मे आर्थिक गतिरोध आ जाएगा । अशत. यह एक मनोवैज्ञानिक रवैया होता है जो विशुद्ध व्यावसायिक दृष्टियों पर आधारित होता है । उदाहरण के लिए उपभोक्ता कभी-कभी अपने उपभोग के स्तर को गिरने से रोकते ही नहीं है, बल्कि बढ़ा भी देते है, चाहे उन्हें उपभोग्य वस्तुओं की खरीद के लिए बहुत अधिक कर्जदार ही क्यों न हो जाना पड़े । ऐसा तब होता है जब उन्हें लगता है कि उनकी नौकरी बिलकुल सुरक्षित है और उनकी आमदनी बढ़ती जाएगी । दूसरी ओर कभी-कभी यही उपभोक्ता यह महसूस करते है कि उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं है, इसलिए वे कोई नया ऋण लेने मे हिचकिचाते है । अमेरिका मे आर्थिक विकास के लिए जो कदम उठाये जाते है उनका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि अमेरिकी लोगो को अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की भावी समृद्धि का पूरा भरोसा है, हालांकि यही एकमात्र कारण नहीं है । यदि अमेरिका का दीर्घकालिक आर्थिक भविष्य अनुकूल नजर न आता तो व्यवसायी वर्ग नये सयन्त्रो और नई मशीनो पर अरबो डालर खर्च न करता और न ही लोग अपने मकान बनाने और उपभोग्य वस्तुएँ खरीदने के लिए अपनी सम्पत्तियाँ बन्धक रखते ।

व्यवसाय के विस्तार के लिए व्यवसायियों, श्रमिको और उपभोक्ताओं को यह विश्वास होना बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण है कि यदि कोई गम्भीर उतार-चढ़ाव आये भी तो उनका सामना किया जा सकेगा, भले ही उसके लिए सरकार को कोई कार्यवाही करनी पड़े । अन्य देशों की भाँति सयुक्त राज्य मे भी लोग यह मानते है कि आर्थिक अभिवृद्धि के अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा करने और गम्भीर उतार-चढ़ावो को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी सरकार पर है । यह मान्यता 1946 के रोजगार अधिनियम मे निहित है, जिसका दोनो बड़े राजनीतिक दलो ने समर्थन किया था । इन अधिनियम ने सिर्फ सरकार पर नई जिम्मेदारी ही नहीं डाली, बल्कि उसे पूरा करने के लिए प्रशासनिक कदम उठाने और

नियम बनाने के लिए आवश्यक तन्त्र भी स्थापित कर दिया है। रोज-गार अधिनियम बनाने के बाद का अब तक का इतिहास बहुत उत्साह-वर्धक है। यह ठीक है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जो अभावधारण आर्थिक प्रगति हुई है और हाल के वर्षों में मूल्यों में जो अपेक्षाकृत स्थिरता रही है उसका मुख्य कारण सिर्फ यही कानून नहीं है, तो भी इस कानून के अन्तर्गत अपनाई गई सरकारी नीतियों ने इसमें सहायता अवश्य दी है।

अमेरिका के आर्थिक विकास के दौरान में दोनों प्रकार के दौर आये हैं—ऐसे भी जब कि आर्थिक विस्तार और अभिवृद्धि में योग देने वाली ताकतें शक्तिशाली रही और ऐसे भी जब कि वे कमजोर रही। सन् 1930 के दशक में ये ताकतें कमजोर थी, इसलिए सरकारी नीतियों के लिए आर्थिक विस्तार की प्रक्रियाओं को उत्तेजित करना कठिन था। इसके विपरीत 1945 से 1955 तक आर्थिक विस्तार की ताकतें शक्तिशाली थी और बाजार के विस्तार की आशाएँ भी अधिक थी।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद आर्थिक विस्तार की प्रवृत्तियों को बढ़ाने में कुछ अस्थायी कारणों के अलावा चार बड़े और महत्वपूर्ण अभिवर्धक कारणों ने भी योग दिया। इस अवधि में उद्योगविद्या (टैक्नोलॉजी) की उन्नति हुई। आवादी और परिवारों में असाधारण वृद्धि हुई। लोग बड़ी संख्या में शहरों से हटकर उपनगरों में बसने लगे, जिससे नये मकानों, नये बाजारों, सार्वजनिक उपयोग के स्थानों और अन्य सम्बद्ध सार्वजनिक निर्माण कार्यों की आवश्यकता बढ़ी। फिस्तो पर या बन्धक रखकर टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं और मकानों की खरीद के लिए ऋण देने की सुविधाओं में वृद्धि हुई। इन चार बड़े कारणों के अतिरिक्त 1945 से 1947-48 तक की युद्धोत्तर निःशस्त्रीकरण की स्वल्प अवधि के बाद राष्ट्रीय प्रतिरक्षा पर खर्च बढ़ाने और प्रतिरक्षा सम्बन्धी संस्थाओं के विस्तार से भी आर्थिक विस्तार को बहुत प्रोत्साहन मिला। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी जरूरी है कि निजी उद्योग-व्यवसाय का

विस्तार सिर्फ इन्ही वर्षों मे नही हुआ जब कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के खर्च सरकार ने बढ़ा दिये, बल्कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद और 1950 से प्रारम्भ दशक के मध्य मे कोरियाई लड़ाई के बाद सैनिक व्यय में कमी के वर्षों मे भी उसका विस्तार हुआ ।

जब तक आर्थिक विस्तार मे योग देने वाले प्रबल कारण मौजूद हैं तब तक छोटे-मोटे उतार-चढ़ावों का मुकाबला ऋण और वित्त सम्बन्धी समुचित नीतियाँ अपना कर किया जा सकता है । युद्धोत्तर काल के अनुभव ने अनुकूल परिस्थितियों मे इन नीतियों की प्रभाव-कारिता सिद्ध कर दी है ।

लेकिन दीर्घकालिक विस्तार की ये परिस्थितियाँ क्या हमेशा अनु-कूल रहेगी ? आर्थिक उतार-चढ़ाव के बारे मे विचार करते हुए अमेरिकी लोग आम तौर पर यह मानकर चलते हैं कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे आर्थिक विस्तार के अनुकूल परिस्थितियाँ हमेशा विद्यमान हैं, इसलिए सरकार को अपनी नीति सिर्फ कभी-कभी आने वाले छोटे-मोटे स्वल्प-कालिक उतार-चढ़ावों का मुकाबला करने के लिए ही निर्धारित करनी चाहिए । वास्तव मे, सन् 1950 के दशक के मध्य से अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि की गति सन्तोषजनक नही रही है ।

इस तथ्य की दो व्याख्याएँ की जाती हैं । पहली यह कि आर्थिक गिरावटों (रिसेशन) का, खासकर 1958-59 मे, मुकाबला करने के लिए जो नीतियाँ अपनाई गईं, वे अपर्याप्त थी । इनलिए इस गिरावट से जो उद्धार हुआ वह देर तक नही टिका और सन् 1960-61 मे फिर गिरावट का एक झटका आया । यद्यपि ये दोनों गिरावटों में अधिक गम्भीर नही थीं, फिर भी उनके एक के बाद एक शीघ्रता से आने के फलस्वरूप आर्थिक अभिवृद्धि की गति मे कमी तो आई ही । लेकिन यह विचार प्रवृत्ति करने वालों का कहना है कि इन गिरावटों से यह निष्कर्ष नहीं होता कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे अन्तर्निहित विस्तार की ताकत कमतर पड़ गई है, इन मे निष्कर्ष इनका ही माना जाता है कि नजरानों के उतार-चढ़ाव के इन चक्रों का मुकाबला करने के लिए अधिक प्रभाव-कारी नीतियाँ अपनानी चाहिए ।

दूसरी व्याख्या यह की जाती है कि उतार-चढ़ाव के चक्रों का मुकाबला करने के लिए अपनाई जाने वाली नीतियाँ स्वल्पकालिक उतार-चढ़ावों का मुकाबला करने के लिए उपयोगी हो सकती हैं, लेकिन वे आर्थिक वृद्धि के लिए दृढ़ता से किये जाने वाले दीर्घकालिक प्रयत्नों का स्थान नहीं ले सकती। नई-नई औद्योगिक विधियों के विकास से, खास कर स्वचालित यन्त्रों के निर्माण से, प्रति व्यक्ति उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, लेकिन उत्पादकता की यह वृद्धि सारे समाज के लिए हितकर तभी हो सकती है जब कि रोजगार के अवसरों और माँग में भी उसी अनुपात से वृद्धि हो। इसलिए हम आगामी दशकों में नई-नई औद्योगिक विधियों के जिस द्रुत विकास की आशा कर रहे हैं, उससे आर्थिक अभिवृद्धि तो तीव्र गति से अवश्य हो सकेगी, लेकिन साथ ही उसका यह तकाजा भी है कि सरकार की नीतियाँ भी आर्थिक विस्तार को बढ़ाने और कायम रखने वाली हो।

यदि ये नीतियाँ सफल हो जाएँ तो आर्थिक शिथिलताओं का मुकाबला करने और आर्थिक उद्गार को थामे रखने के लिए उठाये जाने वाले स्वल्पकालिक कदमों से लाभ की गुंजायश अधिक होगी। यह निश्चय करने के लिए, कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की अधिक गम्भीर और मुख्य समस्या दीर्घकालिक आर्थिक विकास की है या स्वल्पकालिक उतार-चढ़ावों का मुकाबला करने की, इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे अपने खयाल में सबसे सुरक्षित मान्यता यह होगी कि सरकार को दोनों ही बातों का खयाल रखना चाहिए, उसकी नीतियाँ दीर्घकालिक आर्थिक अभिवृद्धि को समुन्नत करने के साथ-साथ व्यापार में आने वाले स्वल्पकालिक शिथिलता के दौरों का मुकाबला करने वाली भी होनी चाहिए।

दीर्घकालिक अभिवृद्धि की चाहे कोई भी नीतियाँ अपनाई जाएँ, बीच-बीच में व्यावसायिक उतार-चढ़ाव आते ही रहेंगे। इसके बावजूद यह भरोसा करने के कारण है कि, यदि बहुत विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हों तो भी सघीय सरकार व्यवसायी वर्ग और श्रमिक वर्ग के सह-

योग से उन्हे इतना नहीं विगडने देगी कि सन् 1930 के दशक की-सी भयकर मन्दी फिर आ जाय । अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था मे पिछले पच्चीस वर्षों मे मन्दी के भटको को सहन करने वाली कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ कायम हो गई हैं, जो किसी भी मन्दी को भयकरता को कम कर देगी ।

पहले यह स्थिति थी कि हमारी अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों मे यदि मन्दी का रुझान आता था तो वह सारी ही अर्थ-व्यवस्था मे मन्दी ला देता था । जहाँ एक बार व्यवसाय मे खतरे या चिन्ता की जरा-सी स्थिति पैदा हुई कि बैंको मे रुपया जमा कराने वालों मे तहलका मच जाता और वे अपनी रकमों के डूबने के भय से अपना पैसा निकालने के लिए बैंको पर दृष्ट पड़ते । बैंक इन लोगों का रुपया वापस करने के लिए व्यवसायियों को दिये हुए अपने ऋण वापस माँगते और इस तरह कुछ व्यवसायों के लिए आर्थिक कठिनाई पैदा हो जाती । इस प्रकार थोड़े-से लोगों की दिक्कत व्यापक बनकर बहुत-सी फर्मों और उद्योगों के लिए दिक्कत का कारण बन जाती । आज स्थिति बदल गई है । सघीय सरकार ने बैंको मे जमा खातों के बीमे की योजना बनाकर लोगों की जमा रकमों के डूबने का भय दूर कर दिया है । इसी तरह की योजनाएँ गृह ऋण बैंको और पारस्परिक बचत बैंकों आदि के लिए भी बनाई गई हैं ।

पहले मन्दिया उस हालत मे भी फैलती थी, जब कि एक उद्योग मे बेकार हुए व्यक्ति अपनी गरीब मे कमी कर देते और उससे अन्य उद्योगों के तैयार माल की बिक्री कम हो जाती । लेकिन आज उस स्थिति का पूरा नहीं तो आंशिक उलाज अवश्य हो गया है क्योंकि सरकार ने बेरोजगारी बीमा योजना बनाकर बेरोजगारी की हालत मे भी लोगों के लिए एक न्यूनतम आय की व्यवस्था कर दी है ताकि वे अपने लिए खर्च मे कम सीमा की प्रतिबन्धन वस्तुएँ तो खरीद ही सकेंगे हैं । उनके प्रतिष्ठित सामाजिक भुजा लोगों की योजना मे भी फायदा होगा, क्योंकि उनसे पूरा तो सम्पूर्ण पर लोगों को आय का जरिया बना होगा और हमारे इस देश हुआ है जहाँ के लोगों के रिक्त मे जन-सेव

से निवृत्त हो जाना चाहते हैं उन्हें कुछ-न-कुछ रकम मिलती रहेगी ।

पहले आर्थिक उतार-चढ़ावों को अधिक उग्र बनाने वाला एक कारण और भी था । व्यवसाय प्रवन्धक अपने विस्तार कार्यक्रमों में तब तक के लिए कटौती कर देते थे और पूंजीगत व्ययों को तब तक स्वगित रखते थे, जब तक कि उन्हें यह यकीन न हो जाय कि बाजार में उनके माल की माँग फिर बढ़ने लगी है । व्यवसाय प्रवन्धकों के इस रवैये में अब बहुत परिवर्तन हो गया है जैसा कि उनके दीर्घकालिक निवेश कार्यक्रमों से पता चलता है । इन लोगों ने अब विक्री में आने वाले स्वल्पकालिक उतार से घबराकर अपने विस्तार कार्यक्रमों में कटौती करना बन्द कर दिया है । हालांकि व्यवसायियों के रूप में यह परिवर्तन स्पष्ट नज़र आने लगा है तो भी व्यावसायिक निवेश में स्वल्पकालिक उतार-चढ़ावों का पूर्णतः अन्त अभी नहीं हुआ ।

कर-प्रणाली अब भी पहले की भाँति आर्थिक क्षेत्र में स्वतः स्थिरता लाने का काम करती रहती है । यदि मुनाफो और आयदैनियों में कमी आती है तो कर भी कम हो जाते हैं और इस प्रकार कुल आय कम हो जाने पर भी स्वायत्त आय उतनी कम नहीं होती । करो में कमी हो जाने से सरकार के बजट में घाटे की स्थिति पैदा जाएगी और उसके कुछ प्रश्न की पूर्ति वह बाजार से ऋण लेकर करेगी ।

मन्दी के आघातों को सहन करने की इन पहले से बनी-बनाई व्यवस्थाओं से काफी आशावादिता पैदा हुई है और वह सही भी है । लेकिन यह सम्भव है कि एक गम्भीर और देर तक चलने वाली मन्दी को रोकने के लिए ये व्यवस्थाएँ अकेली पर्याप्त न हों । यह आशा करना दुराशा-मात्र होगा कि आर्थिक ढाँचे में परिवर्तन हो जाने से और मन्दी के आघात को कम करने वाली कुछ ऐसी नई व्यवस्थाएँ हो जाने से जो 1929-33 में नहीं थी, अब मन्दी कभी आ ही नहीं सकती । हमारी स्थिति की तुलना एक ऐसे व्यक्ति की स्थिति से की जा सकती है जो एक खिड़की में से फिसलकर नीचे गिरता है, लेकिन एक आगे की ओर बढ़ी हुई सिल उसे आधे रास्ते में ही रोक लेती है । अगर वह

एक ही मजिल नीचे गिरा होगा तो उसे अधिक चोट नहीं लगेगी । लेकिन अगर वह बीसवी मजिल से गिरा हो और दसवी मजिल पर सिल से अटक कर रुका हो तो यह उम्मीद करना कि आधे रास्ते में ही रुक जाने के कारण उसे अधिक चोट नहीं लगेगी, अपने आपको झूठी सान्त्वना देना होगा ।

दूसरे शब्दों में स्थिरीकरण की नीति को केवल उन्हीं व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए जो आघात की कठोरता को कम करने के लिए पहले-से स्वतः बनी हुई है । सरकार को आर्थिक गति-विधि में नीचे की ओर किसी भी गम्भीर झुकाव को एक पूर्ण मन्दी में परिणत होने से रोकने के लिए कार्रवाई करने को हमेशा तैयार रहना चाहिए । सरकार के पास मन्दी का मुकाबला करने के साधन हमेशा रहते ही हैं ।

और सरकार को सिर्फ मन्दी के खतरे के प्रति ही सजग नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्थिरीकरण की जो बनी-बनाई व्यवस्थाएँ आर्थिक शिथिलता के आघात को कम करती हैं, वही इस शिथिलता से ऊपर उभरने की प्रवृत्ति को भी मन्द कर सकती हैं । आर्थिक नीति ऐसी होनी चाहिए कि जब एक बार आर्थिक शिथिलता को रोक दिया जाय, तो वह सट्टे-फाटके से कृत्रिम तेजी को भी न आने दे और जरूरत पड़े तो इस शिथिलता से ऊपर उभरने की प्रवृत्ति को सहारा भी दे ।

अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सबसे अधिक सुलभ उपाय है मुद्रा और ऋण सम्बन्धी नीति । इस नीति में सबसे बड़ी आसानी यह है कि उसे झटपट, और आम तौर पर नया कानून पास किये बिना, अमल में लाया जा सकता है और परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ढाला जा सकता है । आर्थिक अभिवृद्धि को सहारा देने के लिए एक उपयुक्त मुद्रा-नीति अत्यन्त आवश्यक है । वह उचित से अधिक माग को रोकने में भी प्रभावकारी सिद्ध हो सकती है । अन्य परिस्थितियों में उसकी प्रभाविता सीमित होती है । मुद्रा और ऋण सम्बन्धी नीति को सफल बनाने के लिए तह जरूरी है कि कर, ऋण-व्यवस्था और व्यय सम्बन्धी नीतियों में भी उसके अनुसार ही परिवर्तन कर दिये जाएँ ।

यह सही है कि आर्थिक गिरावट के समय लोगो की कर सम्बन्धी देनदारियाँ स्वतः ही कम हो जाएँगी, लेकिन सरकार भी लोगो की क्रय-शक्ति बढ़ाने के लिए करो की दर में कमी कर सकती है। वास्तव में सन् 1930 के दशक और आज के ज़माने में एक महत्वपूर्ण अन्तर है और वह यह कि आज सघीय सरकार के कर बहुत ऊँचे हैं और बहुत व्यापक क्षेत्र में बँटे हुए हैं। इसलिए आज लोगो की क्रय-शक्ति में कमी को रोकने के लिए करो की दर में कमी का उपाय सन् 1930 के दशक की मन्दी के दिनों की अपेक्षा अधिक प्रभावकारी सिद्ध हो सकता है। साथ ही करों में कमी व्यवसायियों को अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहन के साधन के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है। यदि लोगो को यह भरोसा होगा कि उनके उत्पादित माल की बिक्री के लिए फिर से बाज़ार मिल जाएगा और दीर्घकालिक आर्थिक अभिवृद्धि संभव होगी तो ये प्रोत्साहन कारगर सिद्ध होंगे। सन् 1930 के दशक की मन्दी के समय यह भरोसा लोगो को नहीं था।

ऋण-व्यवस्था भी राज्यवित्तीय नीति का एक शक्तिशाली साधन सिद्ध हो सकती है। तेज़ी (व्यापार उत्कर्ष) के दिनों में सरकार जनता से ऋण लेने के लिए अपने बाँड जारी कर सकती है ताकि निजी व्यवसायो द्वारा धन की खींच का मुकाबला कर सके और उसे सीमित भी कर सके। और व्यापार में गिरावट के दिनों में करों से कम धन प्राप्त होने के कारण अपने खर्चों को चलाने के लिए सरकार सघीय रिजर्व बैंक की विस्तारक मुद्रा नीति से सहायता प्राप्त देश की बैंकिंग प्रणाली से वित्त व्यवस्था कर सकती है।

सरकार के व्यय कार्यक्रम भी मन्दी को रोकने वाले साधन हैं। जब गैरसरकारी उद्योग और व्यवसाय खूब बढ़ रहे हों, तब कुछ ऐसे सरकारी निर्माण कार्यों को धीमा या स्थगित किया जा सकता है, जो बहुत महत्वपूर्ण न हों। लेकिन जब मुकाब मन्दी की ओर हो या सचमुच मन्दी आ गई हो तब सरकारी निर्माण कार्यक्रमों की गति तेज़ की जा सकती है। इस नीति को सर्वाधिक प्रभावकारी बनाने के लिए इसका

निर्माण सघीय स्तर पर होना चाहिए और उसमे राज्यीय और स्थानीय शासनो से भी घनिष्ठ सहयोग रखा जाना चाहिए ।

यदि निकट भविष्य मे काफी बडे पैमाने पर नि शस्त्रीकरण सम्भव हो जाय तो एक बडे पैमाने पर स्वल्पकालीन हेरफेर करना पडेगा । सघीय सरकार के खर्च मे इस नि शस्त्रीकरण से जो बचत होगी उसका कुछ लाभ करो मे काफी कमी करके उपभोक्ताओ को दिया जा सकता है । साथ ही सघीय, राज्यीय और स्थानीय शासनो के जिन सैनिकेतर कार्यक्रमो की गति हाल के वर्षो मे घन की कमी से मन्द रही है, उन्हे भी इस बचत से तेज किया जा सकता है । इन कार्यक्रमो मे शिक्षा और स्वास्थ्य, प्राकृतिक साधनो का विकास और सरक्षण, शहरी इलाको का पुनर्निर्माण और स्थलीय और हवाई परिवहन के साधनो का निर्माण शामिल है । बडे पैमाने पर नि शस्त्रीकरण से संयुक्त राज्य के कुछ उद्योगो और क्षेत्रो मे, जिनका सम्बन्ध इस समय सामरिक उत्पादन से हैं, काफी हेरफेर करना होगा । लेकिन इस हेरफेर से जो आर्थिक नुकसान होगा उसके डर से नि.शस्त्रीकरण को टालने की आवश्यकता नही है, क्योकि यदि पहले से ही योजनापूर्वक इस हेरफेर की तैयारी कर ली जाय, तो यह भय नही रहेगा । संयुक्त राज्य की आर्थिक समृद्धि केवल सामरिक आवश्यकता के उत्पादनो पर ही निर्भर नही है ।

नि शस्त्रीकरण के फलस्वरूप जब देश के भीतर आर्थिक विस्तार गिरा हो जाय तो अन्य देशो को, खासकर उन देशो को, जो अभी औद्योगिक विकास की प्रारम्भिक स्थिति मे हैं, पूंजी का निर्यात बढाया जा सकता है । उनसे उन अन्य विकसित देशो की संयुक्त राज्य से माल खरीदने की क्षमता बढेगी और वहाँ के निर्यातकारी उद्योगो मे उत्पादन भी बढावा मिलेगा । सन् 1930 के दशक की मन्दी के समय अनेक देशो ने, जिसमे संयुक्त राज्य भी था, अपने आन्तरिक व्यापारो की रक्षा के लिए आयात पर प्रतिबंध या तरीका प्रस्तावित और अपने निर्यात को बढाने के लिए 'इसरो' की प्रविवर्ती मे अपनी मुद्राओ का घटमूल्यन (devaluation) कर, प्रवृत्ति (वर्जिटीड) देकर और नयी प्रकार के

अन्य साधन अपनाकर बेरोजगारी का 'निर्यात' किया था। इसके परिणाम सभी देशों के लिए बहुत घातक सिद्ध हुए। इस प्रकार की व्यापार-नीतियों से हर देश ने स्वयं हेरफेर करने के बजाय उसे दूसरो पर मढ़ने की कोशिश की, लेकिन आमतौर पर वह उसी के लिए घातक सिद्ध हुई। जल्दी ही सबने यह महसूस कर लिया कि कोई भी देश इस विश्वव्यापी आम आर्थिक मन्दी से अपने आपको प्रभावकारी ढंग से अलग नहीं कर सकता। ऐसी दशा में यदि उद्योग-मम्पन्न देश अपनी बेकार क्षमताओं के कुछ भाग का उपयोग अल्पविकसित देशों के साथ इस ढंग से करे कि दोनों को ही उससे लाभ हो, तो वह अधिक रचना-त्मक होगा।

दीर्घकालिक आर्थिक अभिवृद्धि, व्यावसायिक उतार-चढ़ाव, मन्दी और बेरोजगारी की समस्याएँ अभी तक हल नहीं की जा सकी। एक स्वतन्त्र व्यवसाय वाली अर्थ-व्यवस्था में, जहाँ हर व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से यह निर्णय करता है कि वह कहाँ काम करे, क्या उत्पादन करे, क्या खरीदे-खाये, वहाँ बीच-बीच में आर्थिक उतार-चढ़ाव आयेंगे ही और उनकी वजह से आर्थिक हेरफेर भी करने ही होंगे। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि ये हेरफेर मन्दियों और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी में परिणत हो जाएँ। अमेरिकी जनता यह स्वीकार करती है कि गम्भीर आर्थिक उतार-चढ़ावों का मुकाबला करने और समुचित आर्थिक अभिवृद्धि को सहारा देने के लिए सरकार द्वारा कुछ नीतियों का अपनाया जाना व्यवसाय और श्रम की स्वतन्त्रता के प्रतिकूल नहीं है। अनेक वर्ष पूर्व लोग मन्दियाँ आने पर अपने आपको असहाय अनुभव करते थे और प्रकृति पर छोड़ देते थे, लेकिन अब उन्होंने अपना यह रवैया बिलकुल छोड़ दिया है और प्रकृति का दृढ़ता से मुकाबला करते हैं। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में गम्भीर और लम्बी मन्दियाँ अनिवार्य नहीं हैं। लेकिन यदि गलत नीतियाँ अपनायी जाएँ तो वे जरूर आ सकती हैं। इसलिए हमारे सामने यह चुनौती है कि हम समुचित नीतियाँ विकसित करें और अपनाये।

मूल्य वृद्धि की समस्या

मन्दियों से बचना सन्तुलित आर्थिक अभिवृद्धि को कायम रखने के बृहत्तर कार्य का एक पहलू मात्र है। इसी का दूसरा पहलू मुद्रा-स्फीति है और वह केवल अविच्छिन्न आर्थिक विकास के लिए ही नहीं, बल्कि एक बड़ी जन-संख्या के कल्याण के लिए भी घातक है। सन् 1946 के रोजगार अधिनियम पर कांग्रेस (संसद्) में हुई बहस में यह दलील दी गई थी कि पूर्ण रोजगार के ध्येय की पूर्ति के लिए अपनायी जाने वाली नीतियाँ लागत मूल्यों और विक्रय मूल्यों में बार-बार वृद्धि करती रह सकती हैं।

लेकिन यह बात आमतौर पर स्वीकार की गई कि उत्पादकता वृद्धि के अनुपात में मजदूरियों में वृद्धि करना न केवल मूल्यों के स्थिरीकरण की नीति के प्रतिकूल नहीं होगा, बल्कि वह लोगों की क्रय-शक्ति और उपभोग में आवश्यक वृद्धि करने के लिए वाछनीय भी होगा। लेकिन कुछ व्यक्तियों ने यह भय प्रकट किया कि यदि सभी लोग रोजगार पर लगे होंगे तो श्रमिक उत्पादकता वृद्धि के अनुपात में जितनी मजदूरी बढ़ाना उचित होगा उससे भी अधिक वृद्धि और अन्य लाभों की मांग करेंगे। और यदि ऐसा हुआ तो व्यवसायों के प्रबन्धक यह सोचकर मजदूरियों में वृद्धि कर देंगे कि बाजार की परिस्थितियाँ अनुकूल होने पर कीमते बढ़ाकर मजदूरी के खर्च में हुई इस वृद्धि की पूर्ति की जा सकेगी और सम्भव होगा तो उससे भी अधिक कीमते वसूल की जा सकेंगी। कुछ लोगों ने यह भय प्रकट किया कि बाजार की अनुकूल परिस्थितियाँ देखकर व्यवसायी लोग कीमते बढ़ायेगे और तब श्रमिक लोग महगाई के नाम पर अपनी मजदूरियाँ बढ़वाने की माँग करेंगे और बढ़वा भी लेंगे।

इसलिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि सब लोगों को पूरा रोजगार देने की नीति पर अमल किया जाएगा तो मूल्यों में कुछ न-कुछ वृद्धि निरन्तर होती ही रहेगी। इन अर्थशास्त्रियों के एक

वर्ग का कहना था कि कीमतों में थोड़ी-थोड़ी वृद्धि निरन्तर होती रहना उतना बुरा नहीं जितना कि स्थायी रूप से बेरोजगारी का बना रहना या बीच-बीच में बेरोजगारी के दौर आते रहना। दूसरे वर्ग का कहना था कि मूल्य-स्तर में निरन्तर वृद्धि होती रहने पर व्यावसायिक ढाँचे में कुछ असन्तुलन आना जरूरी है। इसलिए आर्थिक अभिवृद्धि को निरन्तर जारी रखने के लिए कुछ-न-कुछ बेरोजगारी को स्थायी रूप से कायम रखना या बीच-बीच में पैदा करते रहना आवश्यक है, अन्यथा राष्ट्र को निरन्तर मुद्रा-स्फीति के दुष्प्रभाव सहन करने पड़ेंगे।

इस अधिनियम के फलस्वरूप पिछले डेढ़ दशक में रोजगार का स्तर अमेरिका में ऊँचा रहा है, किन्तु फिर भी इन अवधि में इस सवाल का फैसला नहीं हो सका। हम अभी तक कोई ऐसा सुनिश्चित तरीका नहीं निकाल सके जिससे रोजगार के स्तर को ऊँचा रखते हुए मूल्यों में निरन्तर वृद्धि को रोका जा सके। आज कीमतें सन् 1940 से पहले की अपेक्षा दुगुनी हैं, लेकिन यह वृद्धि मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध का और कोरियाई युद्ध के बाद पुनः शास्त्रास्त्र वृद्धि का परिणाम है। सन् 1951 के वसन्त में जो कीमतें थी उनकी अपेक्षा सन् 1961 के वसन्त में 15 प्रतिशत ऊँची कीमतें हैं, लेकिन इस अवधि में रक्षा व्यय के स्तर को देखते हुए यह वृद्धि कुछ अधिक नहीं है। परन्तु 1961 तक उपभोग्य सामग्रियों के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होती रही है, ऐसे समय भी जबकि सरकार का रक्षा व्यय नहीं बढ़ा। इसका अर्थ यह है कि मूल्यों के स्थिरीकरण की समस्या अभी तक हल नहीं हुई। अगर कृषि-जन्य वस्तुओं की कीमतों में कुछ गिरावट न आयी होती तो मूल्यों का सूचकांक और भी ऊँचा होता।

सरकार की राजवित्तीय और ऋण-सम्बन्धी नीतियों ने मूल्य-वृद्धि को सीमित करने में कुछ सहायता दी है। यदि ये नीतियाँ न अपनाई गई होती तो मूल्य और भी बढ़ गए होते। सरकार के बजटों में कुछ अधिशेष यानी उसके खर्च से आय का आधिक्य होता रहा है। सन् 1947 के बाद के 14 वर्षों में से सात में सरकार का तथाकथित नकद

बजट अधिशेष (सरलस) का बजट रहा है। इस वर्ष में सरकार के बजटो मे आय कुल मिलाकर व्यय से लगभग चार अरब डालर अधिक रही। हाल के वर्षों मे सरकार करो मे कमी करने की मांग अक्सर ठुकराती रही है, क्योंकि उसे भय था कि कही इससे मुद्रा-स्फीति (इनफ्लेशन) न हो जाय, हालांकि वह यह भी जानती थी कि कर घटाने से लोगो की चीजो की मांग बढ़ेगी और उससे आर्थिक अभिवृद्धि का स्तर ऊँचा होगा। सरकार की ऋण-नीति ने भी मूल्यो मे वृद्धि को रोकने मे कुछ योग दिया है। खास तौर से ऋण देने पर कुछ रोक लगाकर सरकार ने प्राइवेट रिहायशी मकानो के निर्माण की गति को धीमा किया।

हाल के वर्षों मे इस बात को लेकर खूब बहस चलती रही है कि क्या ऋण-प्रतिबन्ध नीति प्रभावकारी और उचित होगी। ऋणो पर प्रतिबन्ध लगाने और उन्हें सीमित करने की नीति ने अनेक व्यवसायो पर बुरा असर डाला है और जो व्यवसाय बाहरी ऋण पर जितना अधिक निर्भर करता है उस पर उतना ही अधिक असर पड़ा है। लेकिन यह तर्क इस विषय मे निर्णायक नहीं है क्योंकि यदि ऋणो पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय तो स्फीतिजन्य मूल्य वृद्धि ही उसका एक मात्र अनिवार्य विकल्प होगी। मूल्य-वृद्धि की सभी परिस्थितियो मे राजवित्तीय (फिस्कल) और ऋण-प्रतिबन्ध सम्बन्धी नीतियाँ अपनाने के विरोध मे एक दलील और दी जाती है जो अधिक गम्भीर है। वह दलील यह है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी भी हो सकती है, जिनमे इन नीतियो को अपनाने से मूल्य तो कुछ स्थिर हो जाएँगे, लेकिन साथ ही उससे काफी बेरोजगारी भी पैदा होगी। ऐसी दशा मे इलाज बीमारी से भी खराब होगा।

राजवित्तीय और ऋण-प्रतिबन्ध सम्बन्धी उपाय लागत मूल्यो (उत्पादन व्ययो) और वस्तुओ के विक्रय-मूल्यो मे वृद्धि को रोकने के वजाय माँग मे वृद्धि को रोकने मे अधिक कारगर सिद्ध होते है। लागत और कीमतो मे वृद्धि तो व्यवसायो और श्रमिक यूनियनो की शक्ति पर निर्भर है। इसलिए अमेरिकी शासन के भीतर और बाहर, दोनो जगह यह सुझाव दिया गया है कि सरकार कुछ ऐसी नीतियाँ भी निर्धारित करे

जो मुद्रास्फीति की सम्भावनाओं को रोकने में राजवित्तीय और ऋण-प्रतिबन्ध सम्बन्धी नीतियों की पूरक हो सकें। मूल्य-वृद्धि का मुकाबला करने के लिए जो पूरक उपाय सुझाये गए हैं उनमें से कुछ ये हैं। एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकने के लिए अधिक प्रभावकारी नीतियाँ अपनायी जाएँ, आयात-नीतियाँ लचकीली रखी जाएँ, और मूल्य एवं मजदूरी सम्बन्धी राष्ट्रीय नीतियों के दारे में प्रबन्धको और श्रमिकों के बीच एक समझौता हो। ये समस्याएँ हैं जिनका पर्याप्त आर्थिक अभिवृद्धि और समुचित मूल्य-स्थिरता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामना करना जरूरी है।

गतिशीलता और जड़ता

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकता की वृद्धि के लिए जो गत आवश्यक है उनमें से एक शर्त यह भी है कि गतिशीलता का स्तर ऊँचा बना रहे। कुशल प्रबन्धक, श्रमिक और पूंजी तीनों ही ऐसी गतिशील स्थिति में रहे कि जब जहाँ उनकी आवश्यकता हो या उनके लिए अनुकूल अवसर हो तभी वहाँ पहुँच सकें। यह सम्भावना, कि इस गतिशीलता का स्थान कभी जड़ता ले सकती है, एक ऐसी समस्या है जो अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की भावी अभिवृद्धि को खतरे में डाल सकती है। आर्थिक गतिशीलता अनेक प्रकार की हो सकती है—उदाहरण के लिए अमेरिकी लोग देश के एक भौगोलिक इलाके से दूसरे इलाके में, एक कारखाने से दूसरे कारखाने में और एक धन्धे से दूसरे धन्धे में आसानी से जा सकते हैं, साहसी व्यवसायी लोग अपने जमे-जमाये और सुरक्षित व्यवसायों से छुट्टी पाकर नये-नये व्यवसाय प्रारम्भ कर सकते हैं, और पूंजी भी एक व्यवसाय से और एक स्थान से दूसरे व्यवसाय और स्थान में जा सकती है।

भौगोलिक गतिशीलता, जो अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में पिछले सत्तर वर्ष से चली आ रही है, हमेशा वरदान ही सिद्ध नहीं होती। न तो औद्योगिक समृद्धि वाले नगर और न ही औद्योगिक समृद्धि से रहित

नगर अच्छे सामाजिक जीवन के लिए अनुकूल है। जो श्रमिक और उनके परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का सिलसिला अक्सर लगाये रखते हैं, वे न तो अपना निजका घर बना सकते हैं और न समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन में भाग ले सकते हैं। लेकिन आज क्योंकि प्रायः हर कर्मचारो के पास अपनी मोटर गाडी है, इसलिए वह अपना निवासस्थान बदले बिना अपना काम का स्थान बदल सकता है। यदि किसी इलाके में एक उद्योग की हालत खराब हो जाय तो भी यह जरूरी नहीं है कि वहाँ के सामुदायिक जीवन पर उसका असर बुरा ही पड़े, बशर्ते कि उस इलाके में कोई नया उद्योग विकसित हो जाय और वह उपलब्ध जन-शक्ति को खपा ले। यही आम तौर पर होता भी है। लेकिन इसके मुकाबले में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो हमेशा निरन्तर मन्दी के शिकार रहते हैं, उदाहरण के लिए कोयला खानो और इमारती लकड़ी वाले ऐसे क्षेत्र जहाँ से कोयले और लकड़ी का प्रायः सम्पूर्ण दोहन कर लिया गया है। इसमें से कुछ में नये उद्योगों का विकास बहुत अपर्याप्त हुआ है और बेकार मजदूरों के दूसरी जगह जाने की गति भी बहुत मन्द रही है, जिससे सारे राष्ट्र में समृद्धि होने पर भी वहाँ बेरोजगारी काफी अधिक रही है। इस कठिन समस्या को निबटाने के लिए एक नये सघीय क्षेत्र पुनर्विक्रम प्रशासन की स्थापना के साथ कुछ विशेष नीतियाँ प्रारम्भ की गई हैं।

एक ही इलाके में श्रमिकों के एक कारखाने से दूसरे कारखाने में जा सकने के अवसर वाछनीय अवश्य हैं किन्तु उस गतिशीलता की पूरी छूट भी उनके पूर्ण प्रतिबन्ध के नमान ही अवाछनीय होगी। फर्म और उसके श्रमिकों दोनों का लाभ अन्ततः इसी में है कि श्रमिक एक ही जगह टिके रहे और उनके लिए कारखाना बदलने की जरूरत कम से कम हो। श्रमिकों को दरिद्रता (मीनियॉरिटी) का अधिकार प्राप्त है, उनको वार्षिक वेतनों की गारण्टी होती है, नौकरी से अलग करने पर उन्हें मुआवजा देना पड़ता है और दूसरे कई लाभ भी उन्हें देने अनिवार्य होते हैं। इन-लिए आम तौर पर फर्म यह पसन्द करती हैं कि यदि उनकी व्यावसायिक

गति विधि में अस्थायी तौर पर कुछ समय के लिए गिरिलता का दौर आ भी जाय तो भी वे अपने कर्मचारियों को वर्खास्त करने के बजाय काम पर लगाये रखे। लेकिन कारखानों में वेतनभोगी श्रमिकों की सख्या मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ रही है, इससे स्वभावतः श्रमिकों का एक स्थान या एक कारखाने से दूसरे स्थान या कारखाने में जाना भी कम होता जा रहा है।

लेकिन यदि प्रबन्धक और श्रमिक एक ही फर्म से इतने चिपके रहें और दूसरे ऐसे धन्धों की खोज ही न करें, जिनमें उनकी दक्षता और कौशल का अधिक अच्छा उपयोग हो सकता हो, तो उत्पादकता कम हो जाती है। कुछ प्राइवेट फर्मों के पेन्शन सम्बन्धी नियम ऐसे हैं कि यदि उनके प्रबन्धक या कर्मचारी उनके यहाँ से काम छोड़कर कहीं अन्यत्र चले जाएँ तो वे पेन्शन के अधिकार से वंचित हो जाते हैं। इस प्रकार के नियमों का यही नतीजा होता है कि प्रबन्धक और कर्मचारी किसी दूसरी जगह नहीं जा पाते और उनकी उत्पादकता कम हो जाती है। इस खतरे को महसूस कर उसे दूर करने के उपाय सोचे गए हैं। कुछ प्राइवेट पेन्शन योजनाओं में, उदाहरण के लिए कालेजों के अध्यापकों की सेवा निवृत्ति की योजना में, यह व्यवस्था कर दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति एक जगह से काम छोड़कर दूसरी जगह चला जाए तो भी उसका पेन्शन का अधिकार बना रहता है। इसी तरह सरकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत मिलने वाले लाभों से भी व्यक्ति अपना काम बदलने पर वंचित नहीं होता। किन्तु फिर भी इस समय ऐसी अनेक प्राइवेट पेन्शन योजनाएँ हैं जो लोगों को एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाने से अनुचित रूप से रोकती हैं।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में एक और किस्म की गतिशीलता भी है और वह यह कि बहुत-से लोग बाजार की बदलती हुई जरूरतों के मुताबिक एक किस्म के धन्धे को छोड़कर दूसरी किस्म के धन्धे में जाने को तैयार रहते हैं। कुछ अन्य देशों की अपेक्षा अमेरिका में लोगों में यह प्रवृत्ति अधिक है कि वे अपने आपको किसी एक किस्म के धन्धे से

जीवन भर बाधकर नहीं रखते। प्रशिक्षित इंजीनियर व्यवसाय अधिकारी का पद ग्रहण करने के लिए, टेक्नीशियन विश्वविद्यालयों में अध्यापक बनने के लिए और कुशल श्रमिक सुपरवाइजर बनने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अब क्योंकि बहुत-से कार्यों के लिए खास किस्मों की ट्रेनिंग जरूरी हो गई है, इसलिए भविष्य में यह सम्भव है कि लोग अपने उन कामों को बदलने के लिए तैयार न हो जिनकी विशेष ट्रेनिंग वे पहले ले चुके हैं। उद्योग विद्या (टेक्नोलॉजी) की उन्नति के युग का यह अनिवार्य परिणाम है।

स्वचालित यन्त्रों के अधिकाधिक अपनाये जाने से ये प्रवृत्तियाँ और भी बढ़ेंगी। इस बात के प्रमाण अभी से मिलने लग गए हैं कि आधुनिक उद्योग विद्या के फलस्वरूप नई उत्पादन-विधियाँ निकल आने से कुछ किस्म के काम करने वाले लोगों में तो बेकारी बढ़ गई है और कुछ किस्म के काम करने वाले लोग दुर्लभ हो गए हैं। स्वचालित यन्त्रों के उपयोग के प्रारम्भिक दौर में तो यह सम्भव था कि इन मशीनों के उपयोग में जो लोग बेकार हो, वे इन नई मशीनों के निर्माण और रख-रखाव के लिए अधिक आदमियों की माँग के कारण खप जाएँ। लेकिन आगे चलकर यह सम्भव है कि नई तकनीकी विधियों के कारण मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ जाय और जब तक नये उद्योग और नई मेशाएँ काफी विकसित न हो जाएँ और ये मजदूर उनमें काम न करने लगे अथवा काम के घण्टों में कमी न कर दी जाय तब तक वह उग्र रूप धारण किये रहे।

यही कारण है कि यदि श्रमिकों के पूरा काम या उद्योग में स्टेवर दूसरे में जाने की गतिशीलता को बनाये रखा है तो उद्योग विद्या की उन्नति के युग में शिक्षा और प्रशिक्षण में अक्सर जो बहुत महत्व होगा। कुछ व्यावसायिक पेशावियों और कृषिजनों ने श्रमिकों को उन उद्योगों या पुनः प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों में प्रारम्भ भी कर दिये हैं जिनमें स्वचालित यन्त्रों का उपयोग महत्वपूर्ण है। संतीय सरकार भी इन श्रमिकों को, जिनका रोजगार स्वचालित यन्त्रों या अन्य कारणों से

पुराना पड़ गया है, पुनः प्रशिक्षण के कार्यक्रमों में सहायता देती है। इसके अलावा बहुत-से श्रमिक काम के घण्टों में कमी का लाभ उठाकर विशेष प्रशिक्षणों के पाठ्यक्रमों में भाग लेते हैं ताकि उद्योग विद्या में हो रही प्रगति के लिए अपने आप को तैयार कर सकें या अपना धन्धा बदल सकें। भूतपूर्व सैनिकों को मुफ्त शिक्षा की जो सुविधाएँ दी गई हैं उसके फलस्वरूप एक पूरी पीढ़ी के लोग अपनी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति अनुकूल न होने पर भी व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कालेजों के छात्रों और ग्रेजुएटों को भविष्य में विभिन्न पेशों, तकनीकी क्षेत्रों या व्यवसायों में काम के लिए अपने आपको तैयार करने के लिए बहुत-सी छात्रवृत्तियाँ, शिक्षा ऋण या अन्य प्रकार की सहायताएँ भी सरकार या प्राइवेट निधियों से दी जाती हैं।

अन्तिम बात यह कि सन्तुलित आर्थिक अभिवृद्धि के लिए पूँजी की गतिशीलता भी आवश्यक है। जैसा कि हमने देखा है, पूँजी उपलब्ध कराने वाली आधुनिक संस्थाएँ—शेयर बाजार, निवेश निधियाँ, पेन्शन निधियाँ, बीमा कम्पनियाँ, बैंक और अन्य वित्तीय संगठन निवेश-पूँजी के अनेक प्रकार के स्रोत हैं और उनसे पूँजी को सर्वाधिक लाभकारी कामों में लगाने में सहायता मिलती है। फिर भी पूँजी में उतनी गतिशीलता नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। पेन्शन निधियों और निवेश निधियों का धन स्वभावतः सरकारी हुडियों और बाजार के सबसे अच्छे शेयरों में लगता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उपलब्ध पूँजी का सब प्रकार के उद्योगों में समान वितरण नहीं हो पाता।

कम्पनियों के विकास और विस्तार के लिए पूँजी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उनकी अपनी आन्तरिक निधियाँ यानी मूल्य ह्रास निधि और अवितरित लाभ निधियाँ हैं। ये निधियाँ कम्पनी के अपने उपयोग के लिए सुरक्षित रखी जाती हैं। लेकिन बहुत-सी बड़ी कम्पनियाँ ने, जिनके पास ये निधियाँ बहुत बड़ी मात्रा में जमा हो गई हैं, दूसरी फर्मों, जिन्हें पूँजी की आवश्यकता है, अपने में मिला ली है और इस प्रकार उनमें अपनी ये निधियाँ लगाकर उन्होंने पूँजी की गतिशीलता को बढ़ाया है।

इसके अलावा विशेष वित्तीय सुविधाओं को स्थापना कर, विशेष वर्गों और क्षेत्रों को, जैसे कृषकों, छोटे उद्योग चलाने वालों और अनुन्नत इलाकों आदि को, अनुकूल शर्तों पर ऋण देने की व्यवस्था की गई है।

एक गतिशील अर्थ-व्यवस्था में प्रबन्धकों, श्रमिकों और पूँजी में कुछ गतिशीलता कायम रखना अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यदि व्यवसाय संचालकों को यह भरोसा रहे कि सरकार विदेशी और आन्तरिक प्रतिस्पर्धा से उन्हें संरक्षण देगी और इस प्रकार उन्हें हमेशा मुनाफा मिलता रहेगा, यदि मजदूरों को यह भरोसा हो जाए कि वे हमेशा उसी काम पर लगे रह सकेंगे, और यदि पूँजी लगाने वालों को यह यकीन रहे कि उन्हें कभी नुकसान नहीं होगा तो आर्थिक अभिवृद्धि की जीवन-शक्ति नष्ट हो जायगी। इसीलिए कहा जाता है कि पूर्ण सुरक्षा तो सिर्फ कब्र में है। एक गतिशील अर्थ-व्यवस्था में व्यक्ति को एक ओर कम काम करने पर कम और अधिक अच्छा काम करने पर अधिक पुरस्कार देने की व्यवस्था कर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और दूसरी ओर अनुचित कष्टों और ख़तरों से उसकी रक्षा भी की जानी चाहिए।

सारांश

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था अगले दस-पन्द्रह वर्षों में प्राचुर्य के युग में प्रवेश करती है या नहीं, यह आर्थिक और आर्थिकेतर और सरकारी और गैर सरकारी, दोनों क्षेत्रों में किये जाने वाले बहुत से निश्चयों और कार्रवाइयों पर निर्भर है। आर्थिक क्षेत्र में इसके लिए सबसे आवश्यक यह है कि आर्थिक वृद्धि की गति को काफी ऊँचा रखा जाय और मन्दी, मुद्रा-स्फीति और आर्थिक ढाँचे की गतिहीनता को रोका जाय। सन् 1930 के दशक की अपेक्षा आज इन भावात्मक और निपेधात्मक कामों को अधिक अच्छी तरह समझा जा रहा है और साथ ही आज उनके लिए आवश्यक नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाने की योग्यता और इच्छा भी लोगों में पहले से अधिक है। यदि युद्ध को टाला जा सके तो कोई कारण नहीं कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की ये उज्ज्वल और आशा-पूर्ण सम्भावनाएँ निकट भविष्य में अधिकाधिक पूर्ण न हो सकें।

रहन-सहन का स्तर और आय का विभाजन

प्रायः सभी देशों में रहन-सहन के खासे ऊँचे स्तर की जनता की प्रबल और बढ़ती हुई आकांक्षा हमारे जमाने की इतनी महत्त्वपूर्ण घटना बन गई है कि उसे 'बढ़ती हुई आशाओं की क्रान्ति' भी कहा जाता है। वर्तमान शताब्दी से पूर्व मानव समाज यह मानता था कि विधाता ने ही आम जनता के भाग्य में अनिवार्य रूप से गरीबी लिख दी है और जीवन की सुख-सुविधाएँ सिर्फ एक छोटे-से उच्चवर्ग के लिए ही हैं। लेकिन आज ससार भर में भी सभी जगह लोगों ने इस विचार को ठुकरा दिया है। इसके विपरीत उनका यह विश्वास है कि रहन-सहन, स्वास्थ्य और शिक्षा का एक अच्छा स्तर सभी लोगों को उपलब्ध होना चाहिए और वह सम्भव भी है। अनेक देशों में, खासकर संयुक्त राज्य में, इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काफी प्रगति की गई है। फिर भी सभी जगह, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य में भी, गरीबी की समस्या अभी तक विद्यमान है।

अमेरिका में बढ़ती हुई आशाओं की क्रान्ति का उद्देश्य अन्य देशों की अपेक्षा अधिक महत्त्वाकांक्षापूर्ण है। आज, अमेरिकी श्रमिक और कृषक एक ऐसे जीवन-स्तर की आशा करते हैं, जो अधिक सम्पन्न वर्ग के लोगों के जीवन-स्तर से प्रकार में ही नहीं, मात्रा में भी अधिक भिन्न न हो—और उनमें से बहुतों ने काफी हद तक यह जीवन-स्तर प्राप्त भी कर लिया है। इस दृष्टि से अमेरिका द्रुत गति से एक 'मध्य वर्गीय' राष्ट्र बन रहा है। यद्यपि कुछ वर्ग-भेद अभी तक मौजूद है, तो भी न तो वह पहले जैसा स्पष्ट और अपरिवर्तनीय है और न ही अपमानकारक

और न अन्य बहुत-से देशों में अभी तक विद्यमान वर्ग भेद जैसा ।

संयुक्त राज्य में वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए हर आदमी को निम्नतम स्तर पर लाने का तरीका नहीं अपनाया गया, बल्कि यह कोशिश की गई है कि हर आदमी को ही ऊँचा उठाया जाय । अल्प-आय वर्गों की आय अनुपात के लिहाज से दूसरों से अधिक बढ़ी है और दूसरी ओर बहुत अधिक ऊँची आय और समृद्धि की बढ़ती को कम किया गया है । इसका अर्थ यह नहीं समझा जाना चाहिए कि यहाँ 'हर व्यक्ति की समान आय' के सामाजिक सिद्धान्त को अपनाया जा रहा है । यह सिद्धान्त अमेरिका के लोगों को कभी भी बहुत आकृष्ट नहीं कर सका । इसके विपरीत अमेरिकी लोगों ने यह यत्न किया है कि सब लोगों को समान अवसर मिले—खास तौर से शिक्षा और उत्पादक एवं जीवन की आवश्यकता पूर्ति करने वाले धन्य के अवसर ।

द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की जो अभिवृद्धि हुई है उसके फलस्वरूप यहाँ जीवन का स्तर काफी ऊँचा हुआ है । और यदि अमेरिका अपनी निरन्तर सन्तुलित आर्थिक विकास की सम्भावनाओं को भविष्य में भी साकार कर सका तो सन् 1970 तक संयुक्त राज्य में औसत अमेरिकी परिवार का रहन-सहन का स्तर इस समय के स्तर से कम-से-कम एक तिहाई और ऊँचा हो जाएगा । इसके अतिरिक्त यदि अन्तर्राष्ट्रीय तनाव कम हो गया और शस्त्रीकरण का बोझ कुछ सीमित हो गया तो सम्भव है कि अमेरिका उससे भी जल्दी गरीबी का पूर्ण अन्त कर सके । किन्तु संयुक्त राज्य में अवशिष्ट गरीबी को खत्म करने के लिए आवश्यक वृद्धि के साथ-साथ सरकार की नीतियों में भी उचित परिवर्तन होना चाहिए ताकि राष्ट्रीय आय के न्यायपूर्ण और समान विभाजन में और भी सुधार हो । इसके लिए ये नीतियाँ अपनानी होंगी—सघीय, राज्यीय और स्थानीय शासनो की कर-प्रणालियों में परिवर्तन, गरजमन्द लोगों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण; स्वास्थ्य और सामाजिक सहायता कार्यक्रमों में सुधार

हमारे महानगर क्षेत्रों, शिक्षा-प्रणालियों और अन्य सामाजिक समस्याओं में परिवर्तन कर उन्हें आने वाले प्राचुर्य के युग के अनुकूल बनाना ।

गरीबी के अवशेष

यद्यपि ऐसा कोई सर्वमान्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर अभी निर्धारित नहीं हुआ जिससे यह कहा जा सके कि कितनी आय पर्याप्त है और कितनी अपर्याप्त, तो भी संयुक्त राज्य में आज भी ऐसे लोगों की सख्या बहुत बड़ी है जिनकी आय उससे कम है जितनी कि अमेरिकी लोग सन्तोष-जनक रहन-सहन के लिए आवश्यक समझते हैं । यद्यपि न्यूनतम स्तर से कम आय वाले वर्ग के स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयत्न किये गए हैं तो भी अमेरिका के शहरी और देहाती दोनों क्षेत्रों में, अन्तर्राष्ट्रीय जीवन-स्तर की तुलना में नहीं, अमेरिकी जीवन-स्तर की तुलना में, अभी तक गरीबी मौजूद है । सन् 1959 में लगभग 48 लाख, यानी 12 प्रतिशत, गैर-कृषक परिवारों की कुल आमदनी 3,000 डालर से कम थी । इसके अलावा 12 लाख, यानी 27 प्रतिशत, कृषक-परिवारों की कुल आमदनी 2,000 डालर से कम थी । और लगभग 40 लाख व्यक्तियों की भी, जिनका किसी परिवार से सम्बन्ध नहीं था, और जिनकी सख्या इस वर्ग में आने वाले लोगों की सख्या का 38 प्रतिशत थी, आमदनी 2,000 डालर से कम थी ।

लेकिन संयुक्त राज्य में गरीबी की यह अवशिष्ट समस्या अतीत की गरीबी की समस्या से भिन्न है । पिछले दशक तक हाथ का श्रम करने वाले अधिकतर मजदूरों की आमदनी न्यूनतम वांछनीय जीवन-स्तर की दृष्टि से अपर्याप्त थी । परन्तु आज मजदूरी कमाने वाले लोगों की आमदनी न्यूनतम जीवन-स्तर से ऊँची है और जिस परिवार में एक से अधिक व्यक्ति कमाने वाले हैं, उनकी गिनती तो मध्यम-आय वर्ग में भी ऊँची स्थिति में की जाती है । अवशिष्ट गरीबी तो खास-खास परिस्थितियों में पाई जाती है— उदाहरण के लिए छोटी जोतों वाले फार्मों में, हमेशा मन्दी का शिकार रहने वाले इलाकों में, कुछ खास आयु-वर्गों में और ऐसे परिवारों में

जिनके मुखिया कुछ कारणों से पूरे समय या समुचित मजदूरी पर काम नहीं कर सकते ।

यदि 3,000 डालर वार्षिक से कम आमदनी वाले गैर-कृषक परिवारों का बारीकी से अध्ययन किया जाय तो अतीत काल की गरीबी का अन्तर स्पष्ट हो जाएगा । इनमें से आधे से अधिक परिवारों के मुखिया बीमारी, शारीरिक असमर्थता, बुढ़ापा या रोजगार पाने की अयोग्यता या अनिच्छा के कारण बेकार थे । इनमें से लगभग 35 प्रतिशत परिवारों के मुखियाओं की आयु 65 वर्ष या इससे अधिक थी । कुछ परिवारों की मुखिया विधवाएँ या तलाकशुदा अथवा पितृव्य पत्नियाँ थीं, जिन्हें बच्चों का पालन करना था, लेकिन जिनके पास इतना समय, प्रशिक्षण और योग्यता नहीं थी कि वे पूरे समय का रोजगार या पूरी मजदूरी पर काम पा सकें । बहुत-से अल्प-आय वर्ग के शहरी परिवार ऐसे थे जो संयुक्त राज्य के आर्थिक दृष्टि से कम विकसित हिस्सों से (खासकर पुएर्त्तोरिको से) आये थे और जिनके पास सामान्य शहरी धन्धों की योग्यता और कौशल की कमी थी । इसलिए आज शहरी इलाकों में पाई जाने वाली गरीबी का मुख्य कारण विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत अयोग्यताओं या असमर्थताओं के कारण उपर्युक्त काम पाने की कठिनाई है ।

गरीबी के इन अवशिष्ट स्थलों का उन्मूलन करने के लिए केवल देश की आम आर्थिक अभिवृद्धि पर ही भरोसा नहीं किया जा सकता । हमारी कर-प्रणाली और आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रमों से—विशेषतः जीविकोपार्जन की योग्यता को बढ़ाने और भेदभाव को खत्म करने वाले कार्यक्रमों से—एव हमारे सख्यात्मक ढाँचों में जीवन की परिवर्तमान पद्धतियों के अनुसार हेर-फेर से इस गरीबी के उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाये जा सकते हैं ।

कर-प्रणाली

संयुक्त राज्य की आधुनिक आय-कर प्रणाली की एक आधारभूत विशेषता यह है कि पहले जहाँ आय-कर बहुत कम प्रतिशत लोगों पर

लगता था वहाँ अब वह अधिकतर प्राय-भोगियों पर लगता है। सन् 1939 में मोटे तौर पर 7 प्रतिशत श्रमिकों ने सघीय आय-कर के फार्म भरे थे किन्तु सन् 1959 में आय-कर के फार्म भरने वाले श्रमिकों का अनुपात 65 प्रतिशत से अधिक हो गया, क्योंकि एक तो लोगों की आमदनियाँ बढ़ गईं और दूसरे युद्ध-काल में आय-कर के लिए आय की छूट की सीमा कम कर दी गई थी। वास्तव में आय-कर देने लायक आमदनी वाले लोगों की संख्या इनमें भी अधिक है, क्योंकि बहुत-से पति-पत्नी प्राय-कर के संयुक्त फार्म भरते हैं।

व्यक्तिगत सघीय आय-कर का सबसे निचला खण्ड 20 प्रतिशत कर का है, जब कि सबसे ऊँचे खण्ड में व्यक्तिगत आय का 90 प्रतिशत सरकार आय-कर के रूप में ले लेती है। किन्तु आय-कर की यह सबसे ऊँची दर बहुत कम लोगों पर लगती है, इसलिए अमेरिका में औसत कर-भार कम है। इसके अलावा आय के काफी अंश को आय-कर से मुक्त कर दिया जाता है और साथ ही कुछ किस्म की आय पर कर लगाया जाता है (जैसे कि पूंजी-लाभ पर), जिससे कुल आय पर कर का अनुपात कुछ कम हो जाता है। फिर भी यह अनुमान लगाया गया है कि जिन लोगों की वार्षिक आय 4,000 डालर से 5,000 डालर तक है, वे वास्तव में सघीय सरकार को 8 प्रतिशत कर देते हैं, जब कि एक लाख डालर या इससे अधिक आय वाले लोग औसत 40 से 50 प्रतिशत तक आय-कर देते हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों और नगरों ने भी आय-कर लगा रखे हैं, हालांकि उनके कर सघीय सरकार के करों की तुलना में कम प्रगतिशील हैं।

अगर सभी प्रत्यक्षकरों को, चाहे वे सघीय हों या राज्यीय या नगरीय जोड़ा जाय तो 2,000 डालर से कम आय वाले व्यक्तियों और परिवारों पर 25 प्रतिशत, 6,000 डालर से 8,000 डालर तक की आय वालों पर 24 प्रतिशत, और 15,000 डालर से अधिक आय वालों पर 35 प्रतिशत कर-भार पड़ता है। सर्वोच्च आय वर्ग में 50 प्रतिशत से भी

काफी अधिक आय उपर्युक्त सभी प्रकार के सरकारी आय-करों से निकल जाती है। निम्नतम आय-वर्ग के परिवारों द्वारा अदा किये जाने वाले कर मुख्यतः उत्पादन-कर या स्थानीय शासनो द्वारा लगाये गए स्थावर सम्पदा-कर होते हैं जो उपभोग्य वस्तुओं के मूल्यों और मकान-भाड़ों में ही शामिल कर दिये जाते हैं। किन्तु यह याद रखना चाहिए कि निम्नतम आय-वर्ग में आने वाले परिवारों को ही उन सरकारी सहायता एवं व्यय कार्यक्रमों का सबसे अधिक लाभ मिलता है जो खास तौर से गरीबी और असुरक्षा का सामना करने के लिए बनाये जाते हैं।

जैसा कि हमने देखा है, सन् 1920 के दशक के बाद संयुक्त राज्य के सबसे सम्पन्न 5 प्रतिशत लोगों की आमदनी में वृद्धि औसत आमदनी में हुई वृद्धि से कम है। इन लोगों की आमदनी का अधिकतर भाग व्यवसाय से हुए कुल मुनाफों से प्राप्त होता है। ये मुनाफे भी लगभग उतने ही बड़े हैं जितनी कि मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी में वृद्धि हुई है। लेकिन निगम-कर (कार्पोरेशन टैक्स), व्यक्तिगत आय-कर और सम्पदा-कर आदि मिलकर इतने अधिक हो जाते हैं कि इन व्यावसायिक मुनाफों में से इन्हें निकाल देने के बाद सम्पन्नतम वर्ग के अमेरिकी लोगों की आय और दौलत में वृद्धि बहुत सीमित रह जाती है।

संघीय सरकार की कर-प्रणाली में अप्रत्यक्ष करों (उत्पादन-कर और बिक्री-कर) का भाग अन्य देशों की कर-प्रणालियों की तुलना में बहुत कम होता है। किन्तु संयुक्त राज्य में राज्यीय और स्थानीय शासनो की कर-प्रणालियों में अनुपात की दृष्टि से अप्रत्यक्ष करों का महत्त्व बहुत अधिक होता है। इसलिए संयुक्त राज्य की समूची कर-प्रणाली को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए संघीय, राज्यीय और स्थानीय शासनो के बीच वित्तीय सम्बन्धों में परिवर्तन करना अत्यावश्यक होगा।

अमेरिकी कर-प्रणाली का विश्लेषण करने वाले कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि यहाँ उच्च आय-वर्गों में व्यावसायिक मुनाफे और व्यक्तिगत आय पर इतनी अधिक ऊँची दर से कर लगाये जाते हैं कि उनसे व्यवसायों

के प्रवन्ध की लाभकारी व्यवस्था और निवेश तथा कार्य के लिए प्रोत्साहन पर घुरा असर पड़ता है। दूसरी ओर इस के उत्तर में यह कहा जाता है कि पिछले एक दशक में अपेक्षाकृत काफी ऊँचे कर होने पर भी व्यवसायो में निवेश का स्तर ऊँचा ही बना रहा है और काम करने, वन बचाने और उसे व्यवसायो में निवेश करने के प्रोत्साहन में किसी तरह की कमी दृष्टिगोचर नहीं हुई। इतना होने पर भी व्यावसायिक मुनाफो और ऊँची आमदनियों पर कर की दरें अब उतनी ऊँची हो गई हैं कि यदि उनमें और वृद्धि की गई तो उससे राष्ट्रीय आय के समुचित और न्यायपूर्ण विभाजन में सहायता उतनी नहीं मिलेगी जितना कि व्यवसाय-प्रवन्ध और पूँजी-निवेश को धक्का पहुँचेगा।

किन्तु सम्पन्न लोगो पर कर लगाने के तरीको में मुवार के लिए अभी काफी गुजाइश है। उच्चतम आय-वर्ग पर आय-कर की दर इतनी ऊँची है कि सरकार को मजबूरन कुछ विशेष छूटें देनी पड़ी हैं जिनसे 'आय-कर प्रणाली में कटाव' आ गया है। इसलिए अब यह कोशिश की जा रही है कि आय-कर के उच्चतम खण्डों में कमी कर दी जाय, किन्तु साथ ही दूसरी ओर इस ऊँची दर के कारण अब तक जो विशेष छूटे दी जाती थी, उन्हें भी खत्म कर दिया जाय, कर से बचने के रास्ते बन्द कर दिये जाएँ और सम्पदा-कर को अधिक प्रभावकारी बना दिया जाय। इसका परिणाम यह होगा कि ये सम्पन्न वर्ग कर तो लगभग उतना ही देते रहेगे, जितना अब देते हैं, किन्तु उसका ढग अधिक वाछनीय और युक्तियुक्त हो जाएगा।

कुल राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा भाग क्योंकि अल्प और मध्यम आय-वर्गों के लोगो के हिस्से आता है, इसलिए यह कहना सम्भवतः अनुपयुक्त नहीं होगा कि सरकार के विशाल व्यय-कार्यक्रम केवल सम्पन्नतम व्यक्तियों पर लगाये गए करों की आय से ही नहीं चलाये जा सकते। इसे इस तथ्य से स्पष्ट किया जा सकता है कि जो लोग अपनी वार्षिक आय 20,000 डालर या इससे अधिक बताते हैं उनकी कुल आमदनी बिना कर काटे 30 अरब डालर के लगभग होती है, जब कि सधीय,

आर्थिक और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम

आर्थिक अभिवृद्धि से और मध्यम आय-वर्ग और उच्च आय-वर्ग पर लगाये जाने वाले भारी करों से वित्तीय साधनों में जो वृद्धि होती है उस का मुख्य लाभ अल्प आय वाले बहुसंख्यक वर्ग को ही प्राप्त होता है। वास्तव में, आय के पुनर्वितरण की नीतियाँ उच्च आय वर्ग की आमदनियों को घटाने की दृष्टि से उतनी निर्धारित नहीं की जाती, जितनी कि निम्न आय वर्गों की आमदनियों को बढ़ाने की दृष्टि से की जाती है।

हाल का आर्थिक विकास और सरकार के विशेष कार्यक्रम, दोनों ने ही अल्प-आय वर्ग के लोगों की अपनी वास्तविक आमदनी को विभिन्न तरीकों से बढ़ाने की योग्यता में सुधार किया है। उदाहरण के लिए अमेरिका की विस्तीर्णमाण अर्थ-व्यवस्था में स्त्रियों के लिए पूर्ण-कालिक और अर्ध-कालिक रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और स्त्रियों और पुरुषों की मजदूरियों का अन्तर कम हो रहा है। स्त्रियाँ इन अवसरों का लाभ उठा रही हैं। कुल अमेरिकी श्रम शक्ति में चौदह वर्ष या इससे ऊपर की आयु की मजदूर लड़कियों की संख्या 1940 में 26 प्रतिशत थी, किन्तु 1960 में वह 36 प्रतिशत हो गई। काम के समय मजदूर स्त्रियों के बच्चों की देख-भाल की व्यवस्था कर दी जाती है और बहुत-से परिवार घरों में अनेक काम, जो पहले स्त्रियों को हाथों से करने पड़ते थे, अब मशीनों से करने लगे हैं, इसलिए स्त्रियाँ मजदूरी करने के लिए पहले से अधिक अच्छी स्थिति में हो गई हैं।

इसी प्रकार सघीय और राज्यीय सरकारों ने बीमारी, बुढ़ापा, परिवार के पालक की मृत्यु, शारीरिक असमर्थता, बेरोजगारी या अन्य कारणों से 'आर्थिक संकट' में पड़े लोगों की सहायता के लिए कुछ आपात-कालिक और स्थायी कार्यक्रम बनाकर अनेक प्रकार की जिम्मेदारियाँ अपने सिर पर ले रखी हैं। फिर भी अमेरिका में कुछ अन्य औद्योगिक राष्ट्रों की अपेक्षा राष्ट्र की आय का कम प्रतिशत भाग सामाजिक सुरक्षा पर खर्च किया जाता है (देखिये परिशिष्ट तालिका 22)।

केवल बेरोजगारी बीमा और सामाजिक सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत

आने वालों की संख्या ही नहीं बढ़ रही, बल्कि स्वास्थ्य और अस्पताल सेवा की व्यावसायिक बीमा योजनाओं और व्यावसायिक फर्मों, ट्रेड यूनियनों एवं परोपकारी संगठनों द्वारा तेजी से बढ़ाये जा रहे पेंशन और जन-कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत आने वालों की संख्या में भी द्रुत गति से वृद्धि हो रही है।

तालिका 13

सरकारी और गैर-सरकारी बीमा और पेंशन कार्यक्रम (1940-1960)
लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या लाख में

	1939-40	1949-50	1959-60
सरकारी			
बुढ़ापा और मृत्यु बीमा	354	464	750 ¹
बेरोजगारी बीमा	251	348	470 ¹
राज्य कर्मचारी पेंशन (संघीय, राज्यीय और स्थानीय शासन)	20	44	41
रेलवे पेंशन	12	14	9
गैर सरकारी			
पेंशन योजनाएँ	37	86	202
सामूहिक जीवन	अज्ञात	194	421
अस्पताली चिकित्सा	123	766	1279
शल्य क्रिया व्यवस्था	54	542	1169
नियमित चिकित्सा	30	216	826
बड़े इलाज की व्यवस्था	अज्ञात	1	219
आमदनी का जरिया न रहने पर सहायता	अज्ञात	378	432

यद्यपि इन सरकारी और गैर-सरकारी बीमा और पेंशन कार्यक्रमों में भारी वृद्धि हो रही है, तो भी चालू लाभ योजनाओं से सभी व्यक्तियों

१. इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो वर्ष भर में किसी भी समय इन योजनाओं के अन्तर्गत आनेवाले रोजगार में लगे हों।

को जीवन के सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक सकटों से उतना संरक्षण नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। किन्तु यह आशा की जा सकती है कि मजदूरियों, व्यावसायिक निवेशों और सरकारी सेवाओं में वृद्धि के साथ सन्तुलन रखते हुए इन सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों में भी कुछ विस्तार हो सकता है। उत्पादकता में जैसे-जैसे वृद्धि होगी, वैसे-वैसे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पर अनुचित बोझ डाले बिना इन कार्यक्रमों से अधिकाधिक लोगों को अधिकाधिक लाभ पहुँचाया जा सकेगा।

तालिका 14

चिकित्सा और निजी स्वास्थ्य बीमा

वर्ष	कुल व्यय (अरब डालरों में)	प्रति व्यक्ति व्यय (डालरों में)	कुल राष्ट्रीय आय का प्रतिशत अंश
1948	7 ८5	52 68	2 3
1949	7 91	53 02	2 4
1950	8 65	57 50	2 4
1951	9 35	60 59	2 4
1952	10 10	65 84	2 5
1953	10 99	68 91	2 6
1954	11 84	74 45	2 8
1955	12 84	79 09	2 9
1956	14 29	86 42	3 1
1957	15 49	91 99	3 3
1958	16 76	97 77	3 6
1959	18 32	104 93	3 7

जहाँ गरीबी के निरन्तर बने रहने की वजह कोई ऐसे आर्थिक कारण हो, जो व्यक्ति के बस से बाहर हो, वहाँ सरकार उन आर्थिक

परिस्थितियों का इलाज करने के लिए कुछ विशिष्ट कार्यक्रम अपनाती है। उदाहरण के लिए सरकार ऐसे कृषकों को, जो मुश्किल से अपना निर्वाह कर पाते हैं, सहायता देने के लिए अतिरिक्त कृषि-भूमि, बढ़िया बीज और उर्वरक, यान्त्रिक औजार और तकनीकी परामर्श आदि देने के कार्यक्रम अपनाती है या उन्हें दूसरा अश-कालिक या पूर्ण-कालिक काम प्राप्त करने में सहायता देती है। कभी-कभी ऐसे इलाकों में रहने वाले परिवारों के कारण भी, जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, विशेष समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। यही नहीं, कुछ स्थानों पर कारखानों के नई वस्तुओं या उत्पादन-विधियों के आविष्कार से प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और आदि के कारणों से भी श्रमिक आर्थिक संकट में पड़ जाते हैं और उससे कुछ विशिष्ट समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। अतीत में आर्थिक स्थिरता या मंदी वाले इलाकों केवल स्थानीय समस्या समझे जाते थे। सरकार उनकी सिर्फ इतनी ही सहायता कर सकती थी कि जिन श्रमिकों पर इस मंदी का असर पड़ा हो उन्हें बेरोजगारी बीमा या आम सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत ले। इनमें से कुछ इलाकों में व्यवसायियों ने स्वेच्छिक और सहकारी आधार पर अपने आर्थिक साधनों को एकत्र कर अपने मौजूदा बेकार कारखानों को नये कामों में लगाना प्रारम्भ कर दिया है। परन्तु अधिकतर मामलों में ये समस्याएँ केवल स्थानीय प्रयत्नों से ही हल नहीं हो सकती। इसलिए हाल के वर्षों में कांग्रेस ने सघीय सरकार को यह अधिकार दे दिया है कि वह मंदी के शिकार क्षेत्रों को नये उद्योगों को आकृष्ट करने और रोजगार के नये अवसर पैदा करने के लिए सहायता दे।

इसके अतिरिक्त सरकार की कुछ नीतियाँ ऐसी भी हैं जो अमेरिकी जनता की एक बड़ी संख्या को अपनी उपार्जन और उपभोग की क्षमता बढ़ाने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देती हैं। उदाहरण के लिए सरकार सामान्य शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, मनोरंजन, सस्ते मकानों का निर्माण, भूतपूर्व सैनिकों की

सहायता आदि के रूप में अनेक मुफ्त या सस्ती सेवाएँ और सुविधाएँ देती है। जाति, लिंग, धर्म या जन्म-स्थान आदि के कारण किये जाने वाले भेद-भावों को समाप्त करने वाले कानून भी लोगों की कमाई और जीवन-स्तर को बढ़ाने में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देते हैं।

गैर-सरकारी संस्थाओं के परोपकारी कार्य

संघीय, राज्यीय और स्थानीय शासनो द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के अतिरिक्त गैर-सरकारी तौर पर भी बहुत-से ऐसे कार्यक्रम चलते हैं जिनका प्रयोजन लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाना और जीवन के प्रकार को सुधारना है। इन कार्यक्रमों पर सन् 1956 में 75 अरब डालर व्यय किये गए थे और उसके बाद से उनमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। अनेक व्यक्ति, व्यावसायिक कम्पनियाँ, निजी समाजसेवी प्रतिष्ठान और धर्मार्थ-ट्रस्ट धर्म, समाज-कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैज्ञानिक अनुसन्धान और कला आदि के क्षेत्रों में बिना किसी लाभ-प्राप्ति की आकांक्षा के काम करने वाली निजी संस्थाओं को बहुत बड़ी मात्रा में दान या सहायता देते हैं।

गैर-सरकारी तौर पर किये जा रहे परोपकार और समाज सेवा के कामों की विशालता और विविधता अमेरिकी प्रणाली की एक विशिष्टता है। दान देना सिर्फ़ धनी लोगों का ही काम नहीं है, आम तौर पर सभी अमेरिकी परिवार जन-कल्याण, स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में कुछ-न-कुछ योगदान अवश्य करते हैं। करीब 1950 के बाद से यह बात विशेष रूप से देखने में आ रही है कि व्यावसायिक कम्पनियों ने स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं और अस्पतालों को ही नहीं, राष्ट्रव्यापी स्तर पर कार्य करने वाले स्वास्थ्य संगठनों, शिक्षा संस्थाओं, छात्रवृत्ति-कार्यक्रमों, संग्रहालयों और सांस्कृतिक गति-विधियों और प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों की अनुसन्धान संस्थाओं को हमेशा बहुत बड़ी राशियाँ दान में दी हैं।

बहुत-सी ऐसी संस्थाएँ या प्रवृत्तियाँ, जो अन्य देशों में सरकार या

चर्च की वित्तीय सहायता पर निर्भर रहती हैं, संयुक्त राज्य में पूर्णतः या अंशतः व्यक्तियों या व्यावसायिक फर्मों के स्वेच्छिक दान से ही चल जाती हैं। इसके अतिरिक्त सरकार कर की छूट देकर स्वेच्छिक दान की इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन भी देती है। जो लोग स्वीकृत और विश्व सनीय परोपकारी संस्थाओं को दान देते हैं, उन्हें अपनी कुल कर-योग्य आय के 20 प्रतिशत तक भाग पर संधीय आय-कर से छूट मिल जाती है। (इसके अतिरिक्त धार्मिक और कुछ शिक्षा सम्बन्धी प्रवृत्तियों

तालिका 15

संयुक्त राज्य में प्राइवेट दान का विवरण (1956)

	लाख डालरों में	कुल का प्रतिशत
दान के स्रोत		
व्यक्तियों द्वारा दान	51,720	69
व्यावसायिक कम्पनियों द्वारा दान	5,100	7
धर्मार्थ ट्रस्ट	2,370	3
निजी प्रतिष्ठान	6 000	8
पंजी ने उपाध्य आय (प्रतिष्ठानों को छोड़कर)	10,000	13
कुल	75,190	100
दान प्राप्त करने वाले या दान के प्रयोजन		
धार्मिक संस्थाएँ	37,600	50
छात्र-जन-कल्याण संस्थाएँ	17,300	23
शिक्षा	9,770	13
मानव्य समर्थन संस्थाएँ	6,760	9
प्रतिष्ठानों के लिये धर्मन्य	2,260	3
विशेष प्रयोजन	1,500	2
कुल	75,190	100

के लिए दान देने पर 10 प्रतिशत आय और भी कर से मुक्त कर दी जाती है) । व्यावसायिक कम्पनियाँ अपनी कुल आय का 5 प्रतिशत दान में दे सकती हैं और उस राशि को काटने के बाद ही उन पर सघीय कम्पनी-कर लगता है ।

व्यक्तियों और कम्पनियों को दान की राशियों पर आय-कर में जो छूट दी जाती है उसे इस आवार पर उचित बताया जाता है कि इनसे एक तो इस प्रकार के कार्यों का निर्णय करने और उन पर अमल करने में लोग बिना किसी सरकारी दबाव के स्वेच्छ या अपने विवेक से काम लेते हैं और दूसरे स्थानीय लोगों और इलाकों में आत्म-निर्भरता की भावना आती है । इससे काम की स्वतन्त्रता और विविधता बढ़ती है और साथ ही इस बात की सम्भावनाओं में भी वृद्धि होती है कि विज्ञान, शिक्षा और जन-कल्याण सम्बन्धी नये विचारों और नई कल्पनाओं को जनता से सहारा मिलेगा । इस प्रकार प्राइवेट तौर पर किये जाने वाले परोपकार और जन-कल्याण के कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रमों के पूरक बन जाते हैं और संयुक्त राज्य में जीवन के स्तर और जीवन के प्रकार को ऊँचा उठाने में महत्वपूर्ण योग देते हैं ।

जीवन पद्धति में परिवर्तन

पिछले बीस वर्ष से ऊपर के अर्धों में जीवन-स्तर में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है और साथ ही उद्योगों और जन-संख्या में भी जो द्रुत वृद्धि हुई है, उन्होंने मिल कर अमेरिकी लोगों की जीवन-पद्धति में बहुत बड़े परिवर्तन किये हैं । इन परिवर्तनों में से एक यह है कि लोगों के रहने और काम के स्थानों में तबदीली हो गई है, जो किसी भी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं है । कारखाने और घर अब शहरों से हटकर देहातों में जाने लगे हैं । सड़कों में सुधार होने और हर चार अमेरिकी परिवारों में से तीन के पास अपनी निजकी मोटरे होने से अब लोगों के लिए अपने काम के स्थानों के नजदीक रहना जरूरी नहीं है । इसका परिणाम यह हुआ है कि उपनगरों और नजदीकी देहातों में रिहायशी बस्तियाँ ढेर की

ढेर खडी हो गई है और शहरो मे या तो वृद्धि हुई ही नही और हुई भी तो बहुत मामूली । उदाहरण के लिए न्यूयार्क की आवादी बढने के बजाय उलटे घट गई है । सन् 1960 मे उसकी जन-सख्या 1950 की अपेक्षा 1,80,000 कम थी, क्योकि बहुत-से परिवार शहर छोड़कर उप-नगरो मे चले गए थे ।

निवास और काम के ढांचे मे इस परिवर्तन ने जीवन के आराम और काम की परिस्थितियो मे बहुत सुधार किया है । लेकिन इसने बहुत-सी कठिनाइयाँ भी पैदा की है, खास कर बडे शहरो और राजधानी क्षेत्रो के लिए । इसका एक कारण यह है कि आज अमेरिका मे प्राइवेट मोटरो की सख्या मे भारी वृद्धि हो जाने के कारण, नये-नये चौडे राजमार्गों के निर्माण के कार्यक्रमो के बावजूद, सडको पर बहुत भीड होने लगी है और बस-सेवा आदि सामूहिक परिवहन सुविधाओ के आधुनिकीकरण की उपेक्षा हो रही है ।

शहरो मे नागरिक सेवाओ के खर्चे बढ रहे है और उनसे सुविधाओ मे भी वृद्धि हो रही है, फिर भी शहर उनके अनुपात मे अपने साधनो का तेज गति से विकान नही कर पा रहे । अमेरिकी नगरो के सामने अपने कार्यों का पुनर्निर्धारण करने, अपनी पुरानी और अपर्याप्त सडको, गलियो, भवनो और नेवाओ का पुनर्निर्माण और अपनी म्युनिसिपल सस्थाओ और वित्त-व्यवस्था मे सुधार की गम्भीर समस्याएँ पहले से ही विद्यमान है और आगामी वर्षों मे वे और भी गम्भीर हो जाएंगी । उनमे से अन्तिम समस्या खासतौर से महत्त्वपूर्ण है और उनके हल के लिए नागरिक प्रशासन और नागरिक वित्त की नई व्यवस्थाएँ करनी पडेगी और उनकी लपेट मे पुराने नगर और नए विस्तीर्यमाण उपनगर, दोनो आ जाएंगे ।

नगर प्रशासन और स्थानीय राजनीतिक गुट नई उठ रही समस्याओं का पहले से ही अनुमान करने और उनके समाधान के लिए प्रभावकारी उपाय अपनाने मे दृष्ट गमिल रहे है । शानन की ओर ने पर्याप्त पहल न होने के कारण कुछ इलाको में कुछ प्राइवेट वर्गों ने इन समस्याओं

के स्वरूप और आकार का अध्ययन करना और उनके व्यावहारिक हल ढूँढना प्रारम्भ कर दिया है। नगर-पुनर्विक्रम के ये चढते हुए आन्दोलन आम तौर पर व्यवसाय-सचालको, ट्रेड यूनियन नेताओं और खास-खास पेशे में लगे लोगों के सयुक्त सहकारी प्रयास का परिणाम हैं। ये स्कूलों और अन्य सस्थाओं की, जिनके स्वरूप और कार्यों के आकार में बहुत परिवर्तन हो गया है, समस्याओं के समाधान का प्रयत्न करते हैं।

अमेरिकी लोगों की जीवन-विधि में दूसरा महत्त्वपूर्ण आधुनिक परिवर्तन अर्थ-व्यवस्था की उत्पादकता में हुए भारी सुधार और स्वचालित यन्त्रों के अधिकाधिक उपयोग का परिणाम है। अमेरिकी लोगों को अब अपने काम पर उतना समय खर्च नहीं करना पडता, जितना पहले करना पडता था, और इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि जैसे-जैसे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था और उन्नत होती जाएगी उन्हें और भी अधिक अवकाश मिलने लगेगा।

अमेरिका में काम के घंटे घटाकर इस समय औसत 40 घंटे प्रति सप्ताह कर दिये गए हैं और बहुत-से काम ऐसे हैं जिनमें अब शारीरिक श्रम बहुत नहीं करना पडता और अब वे पहले की भाँति बोझ नहीं मालूम होते। इसके परिणामस्वरूप इस समय मोटे तौर पर अमेरिकी लोगों के दिन का विभाजन इस प्रकार है उनका तिहाई दिन काम में, तिहाई दिन खाली अवकाश में और तिहाई दिन सोने में व्यतीत होता है। जिन उद्योगों में काम का समय प्रति सप्ताह 40 घंटे से भी कम है, उनके बहुत-से श्रमिक खाली समय में दूसरी जगह अशकालिक काम करके अपनी आमदनी बढाने का प्रयत्न करते हैं। किन्तु जैसे-जैसे वास्तविक मजदूरी बढती जाएगी, वैसे-वैसे इस तरह अतिरिक्त समय में काम करने की पद्धति कम होती जाएगी। वास्तव में श्रमिकों की उत्पादकता इतनी बढ जाएगी कि दो जगह काम करना अवाच्छनीय हो जाएगा। इस तरह अमेरिकी लोगों का सोने के समय से अतिरिक्त खाली अवकाश का समय बढकर लगभग 40 प्रतिशत हो जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों को हर वर्ष मिलने वाली छुट्टियाँ बढा दी जाएँगी, कम-काम के दिनों में

खाली बैठकर मजदूरी पाते रहने के दिनों में भी वृद्धि हो जाएगी और यही नहीं, शायद सप्ताह में काम के दिन, जो इस समय आमतौर पर पाँच होते हैं, घटाकर चार कर दिये जाएँ। यदि यह सब सम्भव हुआ तो अमेरिकी श्रमिकों का खाली अवकाश का समय और भी बढ़ जाएगा।

समूचे मानवीय इतिहास में यह बात देखने में आयी है कि मानव समाज के एक अल्पसंख्यक और सौभाग्यशाली वर्ग के पास ही इतनी दौलत और इतना खाली वक्त होता है कि वह उसे अपनी इच्छानुसार रचनात्मक काम में लगा सके। मानव सम्यता ने जो बड़े-बड़े उन्नति और प्रगति के काम किये हैं उनमें से बहुतों का श्रेय उन लोगों को है जिन्हें 'खाली निठल्ले रहने वाले' कहा जाता है। इन लोगों ने ही अपने अवकाश के दिनों में कला, विज्ञान और विज्ञानेतर मानवीय विद्याओं में अपनी प्रतिभा का विकास किया। अमेरिका में भी, पश्चिमी जगत् के अन्य देशों की भाँति अधिकतर लोगों का दैनिक जीवन मुख्यतः काम करने और भौतिक अभावों की पूर्ति के लिए संघर्ष करने में व्यतीत होता रहा है। उन्हें जो खाली समय मिलता था उसे वे 'मनोरंजन' में व्यतीत अवश्य करते थे, किन्तु यह समझ कर कि यह मनोरंजन वाद में किये जाने वाले काम के वास्ते मनुष्य को तैयार करने के लिए जरूरी है। इस प्रकार दैनिक जीवन का समूचा आयोजन मूलतः काम और जीवन-संघर्ष के लिए होता था। लेकिन अब इतिहास में यह पहला मौका आया है जबकि समूची जनता के लिए आराम और अवकाश भी एक सम्भावना बन गया है, बल्कि सम्भावना ही नहीं, एक समस्या बन गया है।

कुछ लोगों को इस बात में सन्देह है कि पश्चिमी सम्यता सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से ऐसी स्थिति में पहुँच गई है जहाँ काम के घंटों में काफी कमी करके अवकाश के घंटों में वृद्धि की जा सकेगी इन लोगों का कहना है कि काम के दिनों में मनुष्य के क्रिया-कलाप का निर्धारण मुख्यतः उनके सामने उपस्थित काम से होता है। और खाली अवकाश के दिनों में भी उसके क्रिया-कलाप कुछ हद तक उसके परिवार और समुदाय की आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों पर निर्भर होते हैं। किन्तु

काम के समय आदमी को अपने क्रिया-कलाप के लिए चुनाव की उतनी स्वतन्त्रता नहीं होती, जितनी अवकाश के समय होती है। और निर्णय करने की हर स्वतन्त्रता में यह सम्भावना रहती है कि कहीं उसका दुरुपयोग न किया जाय।

अतीत में जब कभी काम के घटो को घटाने की कोशिश की गई, किसी-न-किसी ने यह चिन्ता अवश्य प्रकट की कि लोगों को अधिक अवकाश मिलने का अर्थ यह है कि वे मदिरालयों, नाचघरों या जुआखानों में अथवा पारिवारिक झगड़ों में अधिक समय व्यतीत करने लगेंगे। किन्तु वास्तव में ये चिन्ताएँ निराधार मिद्ध हुई हैं। इसका एक आशिक कारण यह है कि बहुत-से श्रमिकों ने खाली समय में हमारे अशकालिक काम ले लिये। लेकिन इसमें भी अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि काम के दिनों या घटों में कमी उम समय हुई है जिन समय श्रमिकों की आमदनियाँ बढ़ रही थी और उनके रहन-सहन का ढग बदल रहा था। उदाहरण के लिए आमदनियाँ बढ़ने से लोग भाड़े के मकानों के बजाय अपने निजके मकान बनाकर रहने लगे और उससे उन्होंने अपने खाली समय का उपयोग बागवानी या घर की सजावट और सुधार आदि अधिक आनन्ददायक और रचनात्मक कामों में करना पसन्द किया।

अमेरिका में युद्धोत्तर काल के प्रारम्भिक वर्षों में 'अपना काम आप करो' की जो लहर चली वह सिर्फ उपभोग्य वस्तुओं की कमी का, या उमके बाद सेवाओं के महंगी हो जाने का परिणाम नहीं थी, बल्कि वह बड़ी सख्या में लोगों के अपने मकान बना लेने और उनके अवकाश के समय में वृद्धि का अनिवार्य परिणाम थी। थोरस्टाइन वैब्लन ने जिसे 'मानव की कर्म-कौशल वृत्ति' अर्थात् अपने हाथों के रचनात्मक कार्य से आत्माभिव्यक्ति को आकाक्षा कहा है, उसकी बड़े पैमाने पर तृप्ति का भी यह एक प्रयत्न था। इसके अलावा खाली अवकाश के समय के और बहुत-से शौकों और दस्तकारी के क्रिया-कलापों और खेल-कूद एवं घर से बाहर मनोरंजन की प्रवृत्तियों में भी भारी

वृद्धि हुई है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण विशाल राष्ट्रीय और राज्यीय मनोरजन उद्यानों में मिल सकता है, जहाँ आनन्द-विहार के लिए कैम्प लगाने वाले, मछली पकड़कर दिल बहलाने वाले और प्रकृति-प्रेमियों की भारी भीड़ रहती है। इन क्रिया-कलापों में वृद्धि के कारण ही मनोरजन और खेल के सामानों की बिक्री बहुत बढ़ गई है।

कुछ अमेरिकी लोग इस बात से चिन्तित हैं, और उनकी यह चिन्ता अकारण भी नहीं है, कि खाली समय के अधिक बौद्धिक उपयोगों का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। उनका खयाल है कि संगीत का रसास्वादन और उसकी रचना, नाटक, पुस्तकों का अध्ययन और प्रणयन, और अन्य कलाओं, मानवीय विद्याओं एवं विज्ञानों का समुचित विकास नहीं हो सकेगा। उनकी राय में सिनेमा आदि सामूहिक मनोरजन के साधनों और रेडियो, टेलीविजन आदि संचार साधनों के दर्शकों और श्रोताओं की संख्या में जिस तेजी से वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए सांस्कृतिक मनोरजनों का रूढ़ अधिकाधिक व्यावसायिक होता जाएगा और वे इस दृष्टि से दिये जाएँगे कि निम्नतम रुचि और प्रतिभा वाले लोगों का मनोरजन कर सकें और इस प्रकार उनका स्तर गिर जाएगा। सिनेमा फ़िल्मों, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रमों, सस्ती लोकप्रिय पत्रिकाओं और समाचारपत्रों में उन्हें इस सांस्कृतिक अवगति के आसार अभी से नजर भी आने लगे हैं। वे यह चेतावनी भी देते हैं कि सामूहिक और विशाल पैमाने पर विज्ञापन के कुछ तरीके भी ऐसे हैं जिनसे लोगों की रुचियों में यह पतन आ सकता है।

लेकिन इस बात के उत्साहवर्धक लक्ष्य भी सारे देश में दिखाई दे रहे हैं कि अधिकाधिक अमेरिकी लोग सांस्कृतिक विकास के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं। उदाहरण के लिए रेडियो और टेलीविजन के जरिये संगीत, नृत्य और नाटक ऐसे लोगों तक भी पहुँच गए हैं जिन्होंने 'शास्त्रीय' संगीत, नृत्य और नाटकों का कभी रसास्वादन नहीं किया था, बल्कि हमेशा उनका मजाक उड़ाया था। साहित्य, कला, इतिहास, विज्ञान और मार्वाजनिक मामलों से सम्बद्ध कार्यक्रम भी आम तौर पर

अधिकाधिक अमेरिकी लोगो की रुचियो को परिष्कृत और प्रभावित कर रहे है। देश-भर मे शहरो और कस्बो मे प्राइवेट लोगो द्वारा चलाये जा रहे वाद्य-वृन्दो और संगीत-मण्डलियो की सरया अधिकाधिक बढ रही है और उन्हें अधिकाधिक लोकप्रियता भी प्राप्त हो रही है। इससे लोगो मे संगीत का शौक बढन से वाद्य यन्त्रो और अच्छे संगीत के रिकार्डों की विक्री मे वृद्धि हो रही है। अधिकाधिक गहरो मे पेशेवर नाटक मण्डलियाँ और रगमच और शौकिया कलाकारो के नाटक दल बढ रहे हैं। अमेरिकी लोगो की गहुत बडी सख्या चित्रकारा और मूर्ति-कला की शौकीन है और साप्ताहिक अवकाश और अन्य छुट्टी के दिनो मे संग्रहालय और चित्र-दीर्घाएँ दर्शको से भरी रहती हैं। उत्कृष्ट उपन्यासो और विद्वत्तापूर्ण पुस्तको के सस्ते सस्करणो की भारी विक्री, जो अब भी निरन्तर बढ रही है, पिछले दशक की एक बडी सांस्कृतिक घटना है। जो भी व्यक्ति सयुक्त राज्य मे लोक-संस्कृति की वास्तव मे जाँच-पडताल करने की चेष्टा करेगा, वह यह देखेगा कि यह संस्कृति बहुत प्राणवान् और विविधतापूर्ण है, भले ही वह उच्चतम कोटि की न हो।

तो भी अमेरिकी लोगो के सामने अगले कुछ दशको की जो बृहत्तम चुनौतियाँ विद्यमान है, उन मे से एक शिक्षा की प्रणाली मे सुधार करने की भी है, जिससे न सिर्फ अच्छे वैज्ञानिक, टेक्नीशियन और कुशल श्रमिक तैयार हो, बल्कि प्राचुर्य और बाहुल्य का जो नया जमाना आ रहा है, उसमे सांस्कृतिक विकास और मनोरजन के रचनात्मक किया-कलापो के निरन्तर बढते हुए अवसरो मे भाग लेने की व्यक्ति की क्षमताओ मे भी वृद्धि हो सके।

सारांश

ग्राम जीवन-स्तर मे सुधार और अल्प-आय वर्ग के परिवारो के स्तर को ऊँचा उठाने की आवश्यकता सयुक्त राज्य मे केवल सामाजिक उद्देश्य के रूप मे ही स्वीकार नहीं की गई है, बल्कि वह आर्थिक आवश्यकता भी है। कारण, अमेरिकी उद्योगो का अस्तित्व बड़े पैमाने पर वस्तुओ

की विक्री पर निर्भर है। केवल उच्च आय-वर्ग के लोगो का उपभोग का स्तर ऊँचा होना, चाहे वह सामाजिक दृष्टि से कितना ही वाछनीय हो, अमेरिका के उद्योगो के बढ़ते हुए उत्पादन की विक्री की आवश्यकता पूरी करने के लिए काफी नहीं है।

कभी-कभी यह कहा जाता है कि उत्पादकता-वृद्धि को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए और जन-कल्याण की अभिवृद्धि उसके मुकाबले में गौण वस्तु है। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये दोनों एक-दूसरे का विकल्प नहीं हैं, बल्कि पूरक हैं। एक स्वस्थ लोकतन्त्र में उत्पादकता को बढ़ाने के लिए श्रमिकों के कल्याण और सुख-सुविधाओं में वृद्धि करना आवश्यक है, और उससे उत्पादकता बढ़ जाने पर सभी की सुख-समृद्धि बढ़ती है। गडबडी तब पैदा होती है, जबकि दोनों को पूरक न मानकर एक के मुकाबले में दूसरे पर अधिक बल दिया जाता है। यही कारण है कि व्यवसायियों, ट्रेड यूनियनों, कृषकों और सरकारी अधिकारियों का सामाजिक दृष्टि से उत्तरदायित्वपूर्ण और परस्पर सहकारी रवैया उत्पादकता और जन-कल्याण दोनों में वृद्धि के बीच सन्तुलित सम्बन्ध कायम रखने के लिए अत्यावश्यक है। यदि ऐसा नहीं होगा तो आर्थिक अभिवृद्धि मन्द हो जायेगी और जीविन-स्तर को ऊँचा उठाने के लिए निरन्तर की जा रही माँग को एक नियत और स्थिर राष्ट्रीय आय के पुनर्वितरण से ही पूरी करने का प्रयत्न किया जाएगा, जो अधिकतर निष्फल ही रहेगा। उसका अन्तिम परिणाम सामाजिक तनाव में वृद्धि और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की और अधिक क्षति होगी।

संयुक्त राज्य ने उत्पादकता और रहन-सहन का स्तर, दोनों में काफी वृद्धि के लक्ष्य एक साथ प्राप्त किये हैं। यदि उचित सन्तुलन कायम रखा गया और आर्थिक अभिवृद्धि जारी रही तो यह भरोसा किया जा सकता है कि अगले दस वर्षों में, और शायद इससे भी कम समय में, कम आय के कारण होने वाली गरीबी अमेरिकी समाज के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं रह जाएगी।

संयुक्त राज्य के उद्योगों में आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण

बड़ी और छोटी कम्पनियाँ और उनके प्रबन्धक अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में उत्पादकता की वृद्धि में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, उसकी चर्चा हमने प्रथम भाग में की थी। किन्तु हमने इस प्रश्न को बिना उत्तर दिये ही छोड़ दिया था कि क्या बड़ी कम्पनियों को नई औद्योगिक विधियों और प्रबन्ध विधियों से होने वाले लाभों की खातिर अमेरिका के लोकतन्त्र और स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा के आदर्शों का बलिदान कर दिया गया है। यह प्रश्न नया नहीं है। अमेरिकी इतिहास के दौरान में अनेक बार यह प्रश्न पूछा जाता रहा है और विभिन्न प्रकार के कानूनों में उसका उत्तर खोजने की चेष्टा की जाती रही है।

आज कुछ अमेरिकी लोगो का खयाल है कि लोकतन्त्र की रक्षा के लिए राजनीतिक और आर्थिक फैसले करने का काम विकेन्द्रित रहना जरूरी है और इस विकेन्द्रीकरण के साथ आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण का किसी भी तरह मेल नहीं बैठता। हैमिल्टन के सत्ता और सम्पत्ति पर राष्ट्र के स्वामित्व के सिद्धान्त और जैफर्सन के व्यक्ति की स्वतन्त्रता और आत्म-उत्तरदायित्व के सिद्धान्त में प्रत्यक्षतः जो विरोध नजर आता है उसे आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण का प्रश्न जितने स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है उतने स्पष्ट रूप में कोई दूसरा प्रश्न प्रस्तुत नहीं करता। किन्तु हमारा विश्वास है कि इन दोनों सिद्धान्तों में, जो अशत परस्पर-विरोधी हैं एक व्यावहारिक समन्वय अब होने लगा है।

केन्द्रीकरण की मात्रा

बड़ी कम्पनियाँ अमेरिकी उद्योग क्षेत्र पर वास्तव में किस हद तक

छायी हुई है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आर्थिक केन्द्रीकरण को नापने के अनेक तरीके निकाले गए हैं।

बड़ी कम्पनियों के अपेक्षाकृत प्राधान्य और महत्त्व को नापने के लिए अमेरिका की सौ सबसे बड़ी-निर्माता कम्पनियों के बारे में आँकड़े संचित किये गए हैं। सन् 1947 में देश की 100 सबसे बड़ी निर्माता कम्पनियों का उत्पादन समूचे निर्माण-उद्योग के कुल उत्पादन का 23 प्रतिशत था। सन् 1954 में वही बढ़कर 30 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ गया।¹

इसका दूसरा पैमाना 'केन्द्रीकरण के अनुपात' को चित्रित करता है। यदि किसी विशिष्ट उद्योग की चार सबसे बड़ी कम्पनियाँ उस उद्योग के कुल पोत-लदान (शिपमेंट) का 50 प्रतिशत या इससे अधिक पोत-लदान करती हों तो यह कहा जाता है कि उस उद्योग में केन्द्रीकरण का अनुपात बहुत ऊँचा है। मध्यम दर्जे के केन्द्रीकरण वाले उद्योग वे माने जाते हैं जिनमें यह अनुपात 20 से 50 प्रतिशत तक होता है और कम केन्द्रीकरण वाले उद्योगों में उनकी गिनती की जाती है जिनमें यह अनुपात 20 प्रतिशत से कम होता है।² उदाहरण के लिए मोटर गाड़ी उद्योग एक ऐसा उद्योग है जिसमें केन्द्रीकरण बहुत अधिक है, क्योंकि इस उद्योग की चार सबसे बड़ी कम्पनियाँ संयुक्त राज्य में कुल मोटर गाड़ियों के (जिनमें कार, बस, लारी, ट्रक और उनके पुर्जे भी शामिल हैं) पोत-लदान का 75 प्रतिशत पोत-लदान करती हैं। सन् 1947 और 1954 के बीच अधिक केन्द्रीकरण वाले उद्योगों का पोत-लदान का भाग कुल पोत-लदान के 25.7 प्रतिशत से बढ़कर 26.9 प्रतिशत हो गया। यह वृद्धि यद्यपि बिल्कुल मामूली है तो भी वृद्धि तो है ही।

यद्यपि बड़ी कम्पनियों के महत्त्व और अधिक केन्द्रीकरण वाले

1. सन् 1947 और 1954 के लिए कुल उत्पादन के आँकड़े और सन् 1960 के लिए कुल विक्री के आँकड़े लिये गए हैं।

2. देखिये परिशिष्ट तालिका 27।

उद्योगों के अनुपात में हाल के वर्षों में कुछ वृद्धि हुई है तो भी अधिक केन्द्रीकरण वाले उद्योगों की संख्या में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। इस विरोधाभास का कारण यह है कि आम तौर पर उन्हीं उद्योगों का तीव्र गति से विकास हुआ है जिनमें बड़ी कम्पनियों का प्राधान्य और केन्द्रीकरण का अनुपात ऊँचा था और जिन उद्योगों में बड़ी कम्पनियाँ अधिक नहीं थी और केन्द्रीकरण का अनुपात भी ऊँचा नहीं था, उनका विकास उतनी तीव्र गति से नहीं हुआ।

इस प्रकार इस प्रश्न का निर्णय, कि क्या हाल के वर्षों में केन्द्रीकरण में थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है या वह स्थिर रहा है, अतः इस बात पर निर्भर है कि इसके लिए पैमाना कौन-सा अपनाया जाता है। जो भी हो, यह निश्चित है कि यह वृद्धि बहुत अधिक नहीं हुई।

अमेरिकी उद्योगों में बड़ी कम्पनियों का अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व होने पर भी, अधिकतर श्रमिक आज भी अधिक केन्द्रीकरण वाले उद्योगों में काम करते हैं। सन् 1954 में कम केन्द्रीकरण वाले उद्योगों में 63 लाख कर्मचारी काम करते थे। यह संख्या मोटे तौर पर निर्माण-उद्योगों के कुल कर्मचारियों की संख्या का 40 प्रतिशत थी। इसी प्रकार मध्यम केन्द्रीकरण वाले उद्योगों में 57 लाख कर्मचारी थे, जो कि निर्माण-उद्योगों की कुल कर्मचारी संख्या का 36 प्रतिशत थे। अधिक केन्द्रीकरण वाले उद्योगों में कर्मचारियों की संख्या और निर्माण-उद्योगों की कुल संख्या के मुकाबले में उसका अनुपात दोनों क्रमशः 39 लाख और 24 प्रतिशत थे। इस प्रकार यह जाहिर है कि निर्माण-उद्योगों के तीन-चौथाई कर्मचारी कम या मध्यम केन्द्रीकरण वाले उद्योगों में काम करते हैं। कपड़ा, सिले-सिलाये वस्त्र, लकड़ी, नकदी का सामान और छपाई आदि उद्योगों में कोई खास केन्द्रीकरण नहीं है। कुछ सेवा-उद्योगों में भी छोटी इकाइयों का ही बाहुल्य है। उदाहरण के लिए, इस देश के मुख्य राष्ट्रीय मार्गों के साथ-साथ 41,000 मोटल (ऐसे होटल, जहाँ पर्यटक अपनी मोटरों के साथ ठहर सकते हैं)

स्थापित है। पाँच लाख से अधिक सस्थान, यानी कुल सेवा-सस्थानों के आधे से अधिक, ऐसे व्यक्तियों द्वारा चलाये जाते हैं, जो स्वयं मालिक भी हैं और कर्मचारी भी। इस तरह अमेरिका में, ऐसे लोगों के लिए, जो अपने मालिक खुद बनना चाहते हैं, बहुत अवसर हैं।

ये आँकड़े इस अतिरजनापूर्ण धारणा का खण्डन करते हैं कि अमेरिकी उद्योगों पर कुछ बड़ी कम्पनियाँ छाई हुई हैं। फिर भी इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अधिकतर गतिशील उद्योगों में बड़ी कम्पनियों का बहुत महत्व है और इन थोड़ी-सी बड़ी कम्पनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा बहुसंख्यक छोटी कम्पनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा से भिन्न किस्म की है। यह स्थिति वास्तव में चिन्ता जनक है।

केन्द्रीकरण के सम्बन्ध में चिन्ता के कारण

निजी उद्योग की प्राधारभूत विचारधारा यह है कि एक बन्धनहीन और प्रतिस्पर्धात्मक अर्थ-व्यवस्था में किसी भी उद्योग में कोई खास कम्पनी इस उद्योग के अन्य कारखानों पर छायेगी नहीं। यदि किसी कम्पनी में मुनाफे की गुजाइश इतनी अधिक है कि उसका और विस्तार किया जा सकता है तो इस बात की सम्भावना है कि उस क्षेत्र में उसके कुछ प्रतिस्पर्धी खड़े हो जाएँ। इसके प्रलावा हर कम्पनी का विस्तार एक निश्चित सीमा तक ही हो सकता है। उससे अधिक विस्तार होने पर उसकी कार्यकुशलता कम हो जाएगी और उत्पादन-व्यय बढ़ जायगा। इस प्रकार यह समझा जाता है कि स्वतन्त्र और प्रतिस्पर्धा-युक्त अर्थ-व्यवस्था विकेन्द्रित आर्थिक सत्ता वाली प्रणाली है।

कुछ यूरोपीय देशों में कम्पनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा की उग्रता को कम करने के लिए कुछ विशिष्ट उद्योगों की उत्पादक कम्पनियों ने कीमतें न गिरने देने के लिए आपस में सत्र (कार्टल) बनाकर समझौते कर लिये हैं। किन्तु सयुक्त राज्य में कम्पनी-गुटों के निर्माण को रोकने वाले कानून बनाकर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को सीमित करने

वाली इस प्रवृत्ति को प्रतिबन्धित कर दिया गया है। यहाँ सिर्फ उन्हीं उद्योगों में इस प्रकार आपसी समझौते से बने हुए कम्पनी-गुट हैं, जिनमें इसके लिए विशेष रूप में कानून द्वारा अनुमति दी गई है। कम्पनी-गुटों के समझौते अमेरिकी लोगों की साहम, उद्यम और गतिशीलता की भावना के भी प्रतिकूल हैं। वे यह नहीं चाहते कि उनके विस्तार और प्रसार के संसर्ग में किसी भी प्रकार की बाधा आये, चाहे वह स्वयं ही खड़ी की गई हो। उनकी यह प्रतिक्रिया सन् 1930 के दशक में मन्दी के प्रभाव से उबरने के लिए किये गए प्रारम्भिक प्रयत्नों के समय स्पष्ट दीख पड़ी थी। उस समय कुछ उद्योगों में इन कम्पनी-मण्डलों (कार्टलों) जैसी 'सांकेतिक क्लूट प्राधिकारों' (कोड अथॉरिटीज) व्यवस्था स्थापित करने का प्रयत्न किया गया था, किन्तु उसका बहुत विरोध किया गया। इसीलिए जब उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के उत्पादक कम्पनियों के संघ निर्माण के प्रयत्न को अवैध ठहरा दिया तो आम तौर पर व्यावसायिक वर्ग के भीतर और बाहर इसका स्वागत किया गया।

लेकिन अमेरिका में उत्पादक कम्पनियों के संघ न होने का अर्थ यह नहीं है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में प्रर्थशास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार पूर्ण प्रतिस्पर्धा विद्यमान है। इसके विपरीत कुछ अत्यधिक महत्वपूर्ण उद्योगों में थोड़ी-सी बड़ी कम्पनियों का ही बाजार पर प्रभुत्व है और इन उद्योगों में नये आने वाले उद्यमी उत्पादकों को इन पुरानी और जमी हुई विशाल कम्पनियों को चुनौती देने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

यह प्रश्न किया जा सकता है कि यदि ये विशाल कम्पनियाँ प्रतिस्पर्धा के संघर्ष में सफल हैं और उत्पादकता को बढ़ाने में इतना महत्वपूर्ण योग देती हैं तो उनको लेकर चिन्ता करने की क्या बात है। इस प्रश्न के उत्तर में इन कम्पनियों से चिन्ता के पाँच मुख्य कारण बताये हैं

1. यद्यपि यह सही है कि जब तक किसी उद्योग में परस्पर प्रति-

स्पर्धा करने वाली बहुत-सी कम्पनियाँ विद्यमान हैं, तब तक वास्तविक अर्थों में उस उद्योग में 'एकाधिकार' जैसी चीज नहीं है, तथापि थोड़ी-सी कम्पनियों की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा बहुतों की आपसी प्रतिस्पर्धा से भिन्न चीज है। ऐसे उद्योगों में, जिनमें प्रमुख फर्म थोड़ी-सी है, उत्पादित वस्तुओं के जो मूल्य चलते हैं, और जिन्हें 'सुव्यवस्थित' मूल्य कहा जाता है, वे सैकड़ों प्रतिस्पर्धियों की प्रतिस्पर्धा से बाजार में स्वतः बनने वाले मूल्यों से भिन्न होते हैं। इसलिए स्वभावतः ऐसे उद्योगों में इस बात की संभावना रहती है कि वे मूल्यों को साधारणतः औद्योगिक प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप बनने वाले स्तर से ऊँचे स्तर पर रखा सके और मौका पड़ने पर उन्हें उससे और भी ऊँचा उठाया जा सके।

2. किसी उद्योग में कुछ सौ बड़ी कम्पनियों का पूंजी-निवेश उस उद्योग के कुल निजी निवेश का एक बहुत भाग होता है। इस निवेश को भी 'सुव्यवस्थित' निवेश कहा जा सकता है। यह निवेश बड़ी कम्पनियों के प्रबन्धकों की भावी व्यवसाय सम्बन्धी आशाओं के अनुरूप किया जाता है और इसीलिए आर्थिक गति-विधि के वास्तविक स्तर को निर्धारित करने में उसका बहुत हाथ रहता है।

3 यदि कम्पनियाँ बहुत बड़ी हों तो हजारों प्रबन्ध अधिकारी, इंजिनियर, वैज्ञानिक और अन्य कर्मचारी तथा हजारों तथाकथित 'स्वतन्त्र' विक्रेता और लाखों या करोड़ों उपभोक्ता एक ही कम्पनी पर आश्रित हो जाते हैं। इससे कर्मचारियों के लिए अपने रोजगार के वास्ते फर्म का चुनाव करने, व्यापारी के लिए बिक्री के वास्ते वस्तुओं को चुनने और उपभोक्ता के लिए खरीद के वास्ते वस्तुओं को पसन्द करने की गुंजायश बहुत कम रह जाती है।

4. यह सम्भव है कि बड़ी फर्में छोटी फर्मों के, चाहे वे उत्पादन में अधिक कुशल ही क्यों न हों, बाजार में उतरने में बाधा पैदा कर सकें। बड़ी फर्में अपनी आर्थिक सम्पन्नता का अनेक प्रकार से उपयोग कर सकती हैं। वे अपने माल के विज्ञापन पर इतनी विशाल रकम खर्च कर सकती हैं कि वे छोटी फर्मों की पहुँच से बाहर हों। वे कुछ समय तक 'मूल्य

सम्बन्धी युद्ध' भी चला कर छोटी फर्मों को बाजार से निकालने की कोशिश कर सकती है। वे विक्रेताओं के साथ इस आशय के समझौते कर सकती हैं कि वे सिर्फ उन्हीं का माल बेचें। इसी तरह के दूसरे कार्य भी वे कर सकती हैं जो छोटी फर्मों की धमती से बाहर हों। इसके अलावा बड़ी फर्मों पेटेंटों के मामले में भी आपस में समझौता कर लेती हैं, जिससे वे आपस में तो एक दूसरे के पेटेंट का उपयोग कर लेती हैं, परन्तु नई फर्मों को उसका उपयोग नहीं करने देती। लेकिन कम्पनी-गुटों के निर्माण के विरुद्ध बनाये गए कानूनों ने आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग की इन सम्भावनाओं को कुछ हद तक सीमित अवश्य कर दिया गया है, परन्तु उसका पूर्णतः अन्त नहीं हुआ।

5 आर्थिक सत्ता के कुछ थोड़े-से लोगो में केन्द्रित होने का परिणाम यह भी हो सकता है कि वे लोग अनुचित रूप से राजनीतिक दबाव डालें।

विशालता और एकाधिकार

आर्थिक सत्ता के भी, अन्य सत्ताओं की भाँति उपयोग और दुरुपयोग, दोनों सम्भव हैं। स्वभावतः सर्वोत्तम नीति यह होगी कि आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग को तो रोका जाय, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाय कि अर्थ-व्यवस्था बड़ी कम्पनियों की उपयोगिता, कार्य-कुशलता और ऊँची उत्पादकता के लाभों से वंचित न हो। लेकिन आम तौर पर आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग को रोकने की कोशिश करते समय विशाल फर्मों की समस्याओं और एकाधिकार की समस्याओं, दोनों को एक समझ लिया जाता है। यह ठीक है कि इन दोनों की समस्याओं में परस्पर सम्बन्ध है, तो भी वे एक नहीं हैं। आम परम्परागत विचारधारा में यह समझा जाता है कि यदि बहुत-से उत्पादक एक ही बाजार में अपना माल बेचें और हर एक-दूसरे से सस्ता माल बेचने के लिए कीमत इतनी कम कर दें कि वह सारा उत्पादन, जिससे लाभ होने की सम्भावना हो, बाजार में खप जाय तो किसी फर्म का एकाधिकार नहीं रहता। हमने ऊपर

कहाया है कि अनेक उद्योगों में, और खुदरा व्यापार में भी, इस तरह की ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा न केवल हाल के दशकों में कायम रही है, बल्कि और भी बढ़ी है। लेकिन कुछ उद्योगों में प्रतिस्पर्धा का रूप बदला है। उनमें मूल्यों की प्रतिस्पर्धा ने वस्तुओं की किस्म, डिज़ाइन और उधार की शर्तों की प्रतिस्पर्धा का रूप धारण किया है।

इसके अलावा एक और किस्म की प्रतिस्पर्धा भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। उदाहरण के लिए रेल परिवहन को सड़क परिवहन और विमान परिवहन से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है और रेल परिवहन उद्योग में आर्थिक केन्द्रीकरण बहुत अधिक मात्रा में होने पर भी यह प्रतिस्पर्धा काफी ज़बरदस्त है। इसी तरह विजली के पारेपण (ट्रान्समिशन) के लिए तार और अन्य सामग्रियाँ सप्लाई करने में तावा और एल्युमीनियम उद्योगों में प्रतिस्पर्धा चल रही है। इसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा का सामना इस्पात उद्योग को एल्युमीनियम और अन्य हल्की धातुओं के उद्योगों से करना पड़ रहा है और एक-न-एक दिन उसे इनी का सामना विकिरण द्वारा सञ्चालित बनाये गए प्लास्टिक के उद्योग से भी करना पड़ेगा। इसी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला तेल और गैस उद्योगों को भी परमाणु शक्ति से करना पड़ेगा। छोटे खुदरा दुकानदारों, भण्डार-शृङ्खलाओं, सहकारी दुकानों और डाक में ऑर्डर लेकर माल सप्लाय करने वाली बड़ी दुकानों में भी ऐसी तरह की प्रतिस्पर्धा चल रही है। इन तरह की प्रतिस्पर्धा नई तकनीकी विधियों का आदिष्णार कर या प्रदन्त सम्पत्ती नई तकनीकी को अपनाकर बहुत प्रभावकारी ढंग में चलाई जा सकती है।

महत्त्व लम्बे अर्से के बाद ही नजर आता है। यह सही है कि कोई-कोई समय ऐसा भी हो सकता है जबकि कुछ उद्योग, जैसे कि इस्पात या रासायनिक सामान के उद्योग, काफी व्यापक शृङ्खला में वस्तुओं की कीमतों को निर्धारित करने में बड़ा असर डाल सकते हों। खामकर, ऐसे उद्योगों में, जिनके उत्पादनों की माँग अधिक घटती-बढ़ती नहीं है, यह सम्भव है कि कुछ कम्पनियाँ अपने मुनाफे बढ़ा सकें या कम से कम उनमें कमी न होने देने के लिए अपनी कीमतें उस स्तर से ऊँची रखें, जो विशुद्ध प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से आवश्यक है। किन्तु इन उद्योगों में कीमतें अन्ततः इतने ऊँचे स्तर पर नहीं रखी जाएँगी, कि उपभोक्ता लोग ऐसी दूसरी वस्तुओं की खोज करने लगे जिनसे उनकी जगह काम चल सके। इन उद्योगों में उत्पादनों की कीमतें न तो इतनी गिरने दी जाती हैं कि उनसे उन पर आने वाली लागत ही न निकल सके और न उन्हें इतना ऊँचा जाने दिया जाता है कि लोग उनकी जगह काम दे सकने वाली दूसरी चीजें निकालने के लिए प्रयत्न करें। लेकिन इन दोनों सीमाओं के मध्य में रहने पर भी मूल्यों का निर्धारण बाजार की प्रतिस्पर्धा में नहीं होता, बल्कि इन उद्योगों के संचालक ही ये मूल्य निर्धारित करते हैं। अर्थशास्त्री लोग इन्हीं मूल्यों को 'संचालकों द्वारा निर्धारित मूल्य' कहते हैं।

आर्थिक दृष्टि से निर्धारित मूल्य-सीमाओं के भीतर वास्तविक मूल्य निर्धारित करते समय समझदार और उत्तरदायित्व का ज्ञान रखने वाले व्यवसायियों को और भी अनेक बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जनमत, कम्पनी गुटों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की सम्भावना, सामूहिक सौदेबाजी और बाजार की दीर्घकालिक सम्भावनाओं आदि पर मूल्य नीति का प्रभाव। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस अर्थ-व्यवस्था में बड़ी कम्पनियों का बहुत महत्त्व है, उसकी आर्थिक नीति सम्बन्धी समस्याएँ उस अर्थ-व्यवस्था की समस्याओं से बिल्कुल भिन्न होंगी, जिसका मुख्य लक्ष्य प्राइवेट उद्योगों के एकाधिकारों को खत्म करना और प्रतिस्पर्धा को बनाये रखना होता है। इस भेद पर और आर्थिक नीति

के लिए उसके महत्त्व पर विचार करने से पूर्व संयुक्त राज्य के कम्पनी-गुट विरोधी (एंटी-ट्रस्ट) कानून के क्रमिक विकास पर एक नजर डालना उपयोगी होगी।

कम्पनी-गुट विरोधी कानून

सन् 1787 में जैफर्सन ने अमेरिकी लोगों से अनुरोध किया था कि वे अपने संविधान में एक एकाधिकार-विरोधी व्यवस्था का समावेश कर लें। कम्पनी-गुट विरोधी सघीय कानून बनने से काफी पहले ही अनेक राज्यों ने कम्पनियों के गुटों और एकाधिकार की प्रवृत्ति के विरुद्ध कानून बना डाले थे। लेकिन ये कानून मुख्यतः आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण के विरुद्ध जनता के भय को अभिव्यक्त ही करते थे, एकाधिकार की प्रवृत्ति को रोकते नहीं थे। सन् 1890 में कांग्रेस (संसद) द्वारा कम्पनी-गुट विरोधी शेरमान कानून पास किये जाने के बाद ही पहले पहल सघीय सरकार ने एकाधिकार की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए आवश्यक अधिकार अपने हाथ में लेने प्रारम्भ किये। बाद में सन् 1914 में क्लेटन के कम्पनी-गुट-विरोधी कानून और सन् 1950 के विलय-विरोधी कानून से सरकार के इन अधिकारों को परिवर्तित परिस्थितियों और समस्याओं के अनुकूल बनाया गया।

सन् 1890 और 1914 के कम्पनी-गुट विरोधी कानूनों का प्रयोजन मुख्यतः व्यापार-निरोधक कार्रवाइयों को, अर्थात् बड़ी कम्पनियों की उन व्यक्तिगत या सामूहिक कार्रवाइयों को रोकना था, जिनसे वे किसी उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बहुत कम कर सकती थी, किसी खास उत्पादन के लिए बाजार पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकती थी या लागत बढ़ने पर भी अपने उत्पादन का मूल्य बढ़ा सकती थी। प्रारम्भ में अदालतों ने सन् 1890 के कानून को हदता से लागू नहीं किया। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी की समाप्ति पर उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों के फलस्वरूप इस कानून को अधिक कठोरता से चलाया जाने लगा और सन् 1914 के कानून से उसका और भी विस्तार हुआ। उसके

वाद से कम्पनी-गुट-विरोधी कानूनों का और भी दृढ़ता से पालन कराया जाने लगा, खासकर ऐसे मामलों में जहाँ कोई उत्पादक कम्पनी अपने प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने या अन्य तरीकों से बाजार पर हावी होने की कोशिश करती। कभी-कभी तो सरकार ने किसी उत्पादक कम्पनी के खिलाफ एकाधिकार की कार्रवाइयों और मूल्यों को मनमाने स्तर पर रखने के प्रयत्नों के सुवृत्त मिलने से पहले ही कार्रवाई कर दी।

कुछ हद तक कम्पनी-गुट-विरोधी कानून की व्याख्या इस प्रकार की जाने लगी, मानो वे केवल व्यापारिक प्रवृत्तियों का निरोध करने वाली मौजूदा कार्रवाइयों को रोकने के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी सम्भावनाओं को रोकने के लिए भी बनाये गए हों। यह सम्भावना तब समझी जाती थी जब कि कोई कम्पनी दूसरी कम्पनियों का अपने साथ विलय करके अपने आकार को अपने उद्योग या बाजार की तुलना में अधिक बड़ा बना लेती थी। कम्पनी-गुट-विरोधी कानून का प्रयोजन इस प्रकार के विलयों को रोकना भी है, इस बात की पुष्टि सन् 1950 के विलय-विरोधी कानून से हो जाती है। इस कानून ने कम्पनियों के इस तरह के विलय को रोकने की कार्रवाई को और भी सुदृढ़ बनाया। यह कानून द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कम्पनियों के विलय की घटनाएँ बड़े पैमाने पर होने के कारण बनाया गया। हाल के वर्षों के इन व्यावसायिक विलयों ने नई समस्याएँ खड़ी कर दी हैं और कम्पनी-गुट-विरोधी नीति के उद्देश्यों और इस नीति पर अमल के बारे में कुछ पुराने विवाद खड़े कर दिये हैं।

कुछ उद्योग ऐसे हैं, जिन्हें आर्थिक या सुरक्षा सम्बन्धी कारणों से प्राइवेट उत्पादकों की अनियन्त्रित प्रतिस्पर्धा के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। ये उद्योग हैं सार्वजनिक उपयोग के उद्योग, जैसे रेल, सड़क और जल परिवहन, बिजली और गैस, टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेडियो और टेली-विजन। यद्यपि अन्य अनेक देशों में इन सब या अधिकांश उद्योगों पर सरकार का एकाधिकार है तो भी संयुक्त राज्य में इनमें से अधिकांश उद्योग प्राइवेट लोगों के हाथों में हैं, परन्तु सरकार उन पर नज़र रखती

है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कुछ म्युनिसिपैलिटियों द्वारा संचालित नागरिक परिवहन सर्विसे, सघीय सरकार द्वारा संचालित डाक-सेवा और सरकार द्वारा चलाये जा रहे बिजली के उत्पादन और वितरण के कुछ कारखाने, जो आमतौर पर सरकार की बहुद्देश्यक नदी-परियोजनाओं के अंग हैं।

प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा चलाये जाने वाले जनोपयोगी सेवा-उद्योगों के सघीय और राज्यीय सरकारों द्वारा नियमन का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा को कम करना है क्योंकि वह इन उद्योगों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इसका दूसरा उद्देश्य उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में ये सेवाएँ उपलब्ध कराना है। सरकार द्वारा इन उद्योगों को अपने स्वामित्व और नियन्त्रण में लिये जाने के बजाय इन्हें प्राइवेट व्यवसायियों के हाथों में रखते हुए इन पर अपनी नजर रखने के लाभ और हानियाँ दोनों हैं। एक ओर बहुत-से अमेरिकी यह समझते हैं कि बड़े-बड़े सरकारी उद्योगों से बचना एक लाभ है। दूसरी ओर सरकार के ऊपरी निरीक्षण और नियमन की आवश्यकता में एक नुकसान भी है और वह यह कि अनेक प्राइवेट हित अक्सर नियामक सरकारी संगठनों के निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन नियमन के समर्थकों का कहना है कि कुछ मामलों में नियामक संगठन परिवहन, संचार और बिजली आदि के क्षेत्रों में न केवल एक ही काम के एक से अधिक कम्पनियों द्वारा किये जाने और इस प्रकार श्रम और धन के अपव्यय को रोकते हैं, बल्कि पहले से जमी हुई कम्पनियों को हानिकर प्रतिस्पर्धा से भी बचाते हैं। जो भी हो, नियामक सरकारी संगठनों के कामों में यदि इस किस्म की कुछ त्रुटियाँ हों तो उनकी कांग्रेस में और जनता में आलोचना हो सकती है और इस आलोचना के फलस्वरूप उनमें सुधार भी संभव है। जनोपयोगी सेवा उद्योगों के संचालन की विभिन्न पद्धतियों के गुण-दोष चाहे कुछ भी हो, अधिकतर अमेरिकी लोगो का यह खयाल है कि इस प्रकार के जनोपयोगी सेवा उद्योगों के राष्ट्रीयकरण अथवा प्राइवेट कम्पनियों द्वारा अनियन्त्रित और मनमाने तौर पर संचालन के बजाय

अच्छा है कि ये उद्योग रहे प्राइवेट व्यवसायियों के हाथों में, किन्तु इन पर सरकार का निरीक्षण और नियमन रहे ।

बड़ी कम्पनियों का गठन और कार्य

इस समय सरकार के कम्पनी-गुट-विरोधी रुख और व्यावसायिक गति-विधि के सरकार द्वारा नियमन की अन्तर्निहित विचारधारा पर नये सिरे से पुनर्विचार किया जा रहा है । इसका मुख्य कारण यह है कि बड़ी कम्पनियों द्वारा चलाये जाने वाले व्यवसायों और व्यावसायिक प्रबन्ध के स्वरूप में हाल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं ।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में बड़ी कम्पनियाँ जो रचनात्मक भूमिका अदा करती हैं, उसके महत्व को अब अधिकाधिक स्वीकार किया जाने लगा है । यही कारण है कि अब यह माँग पहले की भाँति उग नहीं रही कि कम्पनी-गुट-विरोधी कानूनों का उपयोग कम्पनियों के आकार को नियन्त्रित करने और उन्हें बहुत बड़ी कम्पनियों का रुख धारण न करने देने के लिए किया जाय । अमेरिकी जनता ने, यहाँ तक कि ट्रेड यूनियनों ने भी, यह स्वीकार कर लिया है कि बड़ी कम्पनियाँ इस देश में रहेगी ही लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि इससे कम्पनियों के बड़े-बड़े गुटों के निर्माण को रोकने वाला कानून कम महत्वपूर्ण हो जायेगा ।

कम्पनियों के आकार के सग्रन्ध में जनमत में हाल में जो भारी परिवर्तन हुआ है उसके अनेक कारण हैं । लोग अब यह महसूस करने लगे हैं कि बहुत-सी कम्पनियों में जैसी उग्र प्रतिस्पर्धा होगी वैसी ही कम कम्पनियों में भी हो सकती है । दूसरी बात यह कि लोग अब यह भी जान गए हैं कि अब प्रतिस्पर्धा एक ही उद्योग की अनेक कम्पनियों में नहीं होती, बल्कि अलग-अलग उद्योगों में भी होती है । साथ ही लोगों की यह आशंका भी बहुत-कुछ कम हो गई है कि यदि एक ही या कुछ ही कम्पनियाँ बहुत बड़ी होंगी तो वे अपने उत्पादन की मनमानी कीमतें रखकर उपभोक्ता का शोषण कर सकेंगी । कारण, लोग अब यह अनुभव करते हैं कि यदि कम्पनी बड़ी होगी तो वह बड़े पैमाने पर

अधिकाधिक लोगों के लिए उत्पादन करेगी और क्योंकि उसके कारखाने भी बड़े होंगे, इसलिए वे कम मुनाफा लेकर भी उत्पादन कर सकेंगे। अब लोगों में यह आशंका भी नहीं रही कि कम्पनियों के मालिक या प्रबन्धक अपने क्षेत्र में एकाधिकार के फलस्वरूप भारी मुनाफे कमा कर विशाल व्यक्तिगत सम्पत्तियाँ बना लेंगे। इसके विपरीत यह देखा गया है कि बड़ी-बड़ी कम्पनियों के निर्माण के साथ ही साथ अमेरिका के सभी सामाजिक वर्गों के लोगों में आय और सम्पत्ति का पहले से अधिक न्यायपूर्ण वितरण होने लगा है। यह धारणा कि उत्पादन के केन्द्रीकरण से सम्पत्ति भी कुछ थोड़े-से लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जाएगी, इस तथ्य के कारण अब निर्मूल सिद्ध हो गई है कि कम्पनियों का, खासकर बड़ी कम्पनियों का, स्वामित्व कुछ थोड़े-से लोगों के हाथों में न होकर बहुत बड़ी संख्या में विद्यमान शेयर होल्डरों (हिस्सेदारों) के हाथों में होता है। इसके अलावा एक और बड़ी-बड़ी कम्पनियों का आपेक्षिक महत्त्व बढ़ रहा है और दूसरी ओर धनी लोगों की कुल व्यक्तिगत स्वायत्त आय का प्रतिशत अनुपात निरन्तर कम होता जा रहा है।

तौर पर बड़ी कम्पनियो मे छोटी कम्पनियो से भी अधिक है, क्योकि बड़ी कम्पनियो के पास इस के लिए वित्तीय साधन अधिक होते हैं और सामूहिक बीमा कराने मे उन्हें खर्च कम पडता है ।

बड़ी कम्पनियो के सम्बन्ध मे हुए इस रख-परिवर्तन के फलस्वरूप न्यायालयो के निर्णयो मे भी कम्पनी-गुट-विरोधी कानूनो की कुछ भिन्न व्याख्याएँ की गई और खयाल हे कि इस सम्बन्ध मे शायद और भी परिवर्तन हो ।

कम्पनी-गुट-विरोधी कार्रवाइयो की आवश्यकता है या नही, इसका फैसला दो कसौटियो के आधार पर किया जाता है—पहली यह कि कम्पनो का ढाँचा कैसा है और दूसरी यह कि वह काम किम ढग से करती है । ढाँचा विषयक कसौटी मे यह देखा जाता है कि कम्पनी कितनी बडी है, उसमे किन्ही अन्य कम्पनियो का विलय तो नही हुआ या अन्य कम्पनियो के साथ उसके कोई गठबन्धन तो नही है । कम्पनियो के ढाँचे और आकार की कसौटी के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई यह मानकर की जाती है कि जो कम्पनियाँ बहुत बडी हैं और जिनका बाजार मे विकने वाले माल मे बहुत बडा हिस्सा है, वे सम्भवत बाजार पर अपना एकाधिकार स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है । इस प्रकार केवल कम्पनियो के ढाँचे और आकार की कसौटी पर ही निर्भर करने से उन कम्पनियो के साथ व्यर्थ ही अन्याय होता है, जिन्होने अपने उत्पादन की किस्म अच्छी होने के कारण या अपने उत्तम संगठन की बदौलत अपनी आर्थिक सत्ता का निर्माण किया है । इस प्रवृत्ति का नतीजा यह हुआ है कि वास्तव मे ही एकाधिकार की चेष्टा करने वाली कम्पनियो के साथ-साथ ऐसी कम्पनियाँ भी कम्पनी गुट विरोधी कानून का शिकार हो जाती है जो ऐसी चेष्टा नही करती, किन्तु फिर भी बहुत बडी होती है ।

इसके विपरीत अब हाल मे यह तर्क दिया जाने लगा है कि कोई भी कम्पनी तब तक सिर्फ इसीलिए बुरी नही हो सकती कि वह बहुत बडी है, जब तक कि वह अपनी आर्थिक सत्ता का दुरुपयोग न करे ।

यह तर्क देने वाले कम्पनी के काम के ढंग की कसौटी पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि कसौटी यह होनी चाहिए कि कम्पनी अपनी आर्थिक सत्ता का वास्तव में रचनात्मक उपयोग कर रही है या हानिकारक उपयोग। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कम्पनी के काम के ढंग की कसौटी पर भविष्य में और भी अधिक बल दिया जाएगा, हालांकि उससे न्यायिक निर्णय में कुछ कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। एक कठिनाई यह है कि अभी तक ऐसी कोई निश्चित कसौटी नहीं निकाली गई जिससे यह कहा जा सके कि आर्थिक सत्ता का उपयोग रचनात्मक ढंग से किया जाता है या हानिकारक ढंग से। जब ऐसी कसौटी निर्धारित कर ली जाएगी तब केवल ढाँचे की कसौटी का, यानी इस धारणा का कि कम्पनी का बड़ा होना ही हानिकारक है, महत्व स्वयं धीरे-धीरे कम हो जाएगा।

लेकिन कम्पनी के ढाँचे की कसौटी के सम्बन्ध में रुख में जो थोड़ा परिवर्तन हुआ है, उसका अर्थ यह नहीं है कि न्यायालय इस कसौटी को अब महत्वहीन समझने लग गये हैं। अभी हाल में ही ड्यू पॉण्ट कम्पनी को न्यायालय ने आदेश दिया था कि वह अपने जनरल मोटर्स के शेयर बेच दे। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए ड्यू पॉण्ट पर यह आरोप नहीं लगाया कि उनसे जनरल मोटर्स के शेयर खरीद कर उस पर अनुचित प्रभाव डाला है, परन्तु उसने यह आशका अवश्य प्रकट की कि वह ऐसा कर सकती है। उस प्रकार उनसे यह निर्णय करने हुए कम्पनी के काम के वास्तविक ढंग की नहीं, बल्कि उसके ढाँचे की कसौटी पर ही मामले को परखा। फिर भी इन बातों काफ़ी आभा है कि काम के ढंग की कसौटी पर, अर्थात् आर्थिक सत्ता के वास्तविक उपयोग पर, ही भविष्य में अधिक बल दिया जाएगा। कम्पनियों के काम के ढंग के सम्बन्ध में यह कसौटी, कि क्या वान मार्जनिंग हिन में है और क्या नहीं, अब धीरे-धीरे बन भी रही है।

कम्पनियों के सम्बन्ध में इसीलिए आती है कि मुनाफा क्या नहीं और मुनाफा कमाने का अर्थ क्या है कि उनका मान अधिक अच्छे तरीके

से तैयार किया और बेचा जाता है। लेकिन केवल उत्पादन और विक्री का कौशल ही, एकमात्र ऐसी कसौटी नहीं है जिनसे कि कम्पनियों के मुनाफो और उनके काम के ढग के बारे में निर्णय किया जाता है, या किया जाना चाहिए। कम्पनियों के प्रबन्धक अब यह बात अधिकाधिक महसूस करने लगे हैं कि मुनाफा कमाने के लिए कर्मचारियों और जनता, दोनों के साथ अच्छे सम्बन्ध होने चाहिए। और अच्छे जन-सम्पर्क के लिए यह जरूरी हो जाता है कि कम्पनियाँ समूची अर्थ-व्यवस्था पर अपने कार्यकलाप के प्रभाव को देखें। इसमें सन्देह नहीं कि जिन सरकारी सगठनों के हाथ में कम्पनी-गुट-विरोधी कानूनों को लागू करने का भार है, वे जहाँ-कहीं इन कानूनों का उल्लंघन होते देखेंगे वही आवश्यक कार्रवाई करेंगे, किन्तु साथ ही कम्पनियों द्वारा आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए यह बात भी उतनी ही महत्वपूर्ण है कि कम्पनियाँ जो कुछ करती हैं, वह सबकी नजर में रहे। उदाहरण के लिए यदि मूल्य-नीति की सरकार और कांग्रेस द्वारा जाँच की जाती रहे तो वह अदालतों के जरिये कम्पनी-गुट-विरोधी कानून को लागू कराने की कार्रवाई की अपेक्षा अधिक कारगर हो सकती है। वास्तव में कुछ अन्य देशों में, जहाँ उद्योग सरकार के हाथों में है, राष्ट्रीयीकृत उद्योगों पर उतनी कड़ी नजर नहीं रखी जाती, जितनी कि अमेरिका में बड़े प्राइवेट उद्योगों पर रखी जाती है।

सम्भवतः आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण योग कम्पनियों की नये ढग की प्रबन्ध-व्यवस्था का है, जिसकी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब व्यावसायिक प्रबन्ध ऐसे लोगों के हाथ में आ गया है जो उसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य के रूप में अपनाते हैं, और आधुनिक ढग की कम्पनियों को एक ऐसी वस्तु के रूप में समझा जाता है जिसका एक अपना जीवन और अस्तित्व है, इसलिए पुराने जमाने के उद्योग-संचालकों में जनता की उपेक्षा करने की जो वृत्ति थी, वह अब नये प्रबन्धकों में नहीं पाई जाती। आज कम्पनियों और उनके प्रबन्धकों पर इस बात के लिए बहुत दबाव पड़ रहा है कि

वे अपने व्यवसाय को समाज के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से चलाये। लेकिन स्वयं आधुनिक कम्पनियाँ भी एक सत्ता के रूप में ऐसे दबाव पैदा करती हैं जो इन रचनात्मक प्रवृत्तियों के प्रभाव को कुछ हद तक नष्ट कर देते हैं, जैसा कि हाल में बिजली का सम्मान बनाने वाली कुछ बड़ी कम्पनियों की परस्पर मिलकर बोली लगाने की साजिश के समय देखने में आया। इस साजिश के अनेक कारणों में से एक यह था कि कम्पनियों के अधिकारियों पर, जो अपनी स्थिति बनाये रखने और भविष्य में और ऊँचे पदों पर तरक्की के लिए चिन्तित थे, मालिकों का ऊपर से यह दबाव पड़ा कि वे अपनी कम्पनियों के माल की बिक्री और मुनाफों को बढ़ाएँ, या कम से कम उन्हें गिरने न दें, इसी में उनकी सफलता है।

इसका अर्थ यह है कि यद्यपि बड़ी कम्पनियों द्वारा अपनी आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रभाव काम कर रहे हैं तो भी एकाधिकार के दुरुपयोग के लिए अवसर और प्रेरणाएँ मौजूद अवश्य हैं। ये अवसर और प्रेरणाएँ बड़ी कम्पनियों को इसलिए मिलती हैं क्योंकि वे अपने ऊपर किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा का अवाछनीय और परेशान करने वाला दबाव नहीं पड़ने देना चाहती, वे अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करना चाहती हैं, या उनमें मानवीय प्रकृति और समाज की और भी कमजोरियाँ होती हैं। यद्यपि सरकार यह स्वीकार करती है कि बड़ी कम्पनियों का रख अब रचनात्मक है और अधिकतर कम्पनियों के प्रबन्धकों का रवैया भी अधिकाधिक उत्तरदायित्वपूर्ण होता जा रहा है तो भी इस बात की जरूरत है कि सरकार कम्पनियों के काम के ढंग पर नज़र रखे और जहाँ भी उसे आर्थिक सत्ता का दुरुपयोग होता नज़र आये वही हस्तक्षेप करे।

आज शायद ही कोई अमेरिकी ऐसी कम्पनी-गुट-विरोधी नीति का समर्थक हो, जो बड़ी कम्पनियों को सिर्फ इसलिए टुकड़े-टुकड़े कर दे कि उनसे आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग की सम्भावना है। इसके विलोम के तौर पर यह भी कहा जा सकता है कि शायद ही कोई ऐसा अमेरिकी

नागरिक हो जो ऐसी कम्पनी-गुट विरोधी नीति को खत्म करने का ममयंक हो जिससे आर्थिक शक्ति के वास्तविक दुरुपयोग को टोका जा सकता है। अमेरिकी लोगो की एक बहुत बड़ी मस्या, जिसमे व्यवसाय जगत् के नेता भी है, इस तथ्य को स्वीकार करती है कि एक लोकतन्त्रीय देश में सत्ता और अधिकार के साथ जवाबदेही भी होनी जरूरी है। आधुनिक युग की बड़ी कम्पनियों में व्यक्तिगत तौर पर शेयर होल्डरो का सीधा नियन्त्रण अक्सर कमजोर और प्रभावहीन होता है। यह सही है कि कोई भी व्यक्ति किसी ऐसी कम्पनी के शेयरो में पैसा नहीं लगायेगा जिसके बारे में उसे यह यकीन न हो कि उसके प्रबन्धक कौशल और उत्तरदायित्व के साथ काम करते हैं जिससे उसके शेयरो की कीमत बढ़ेगी और उसे मुनाफा भी सन्तोषजनक मिलेगा। लेकिन फिर भी, अगर सरकार की कम्पनी-गुट-विरोधी नीतियाँ न होती और कम्पनियों के काम की सार्वजनिक जाँच की व्यवस्था न होती तो यह सम्भव था कि प्रबन्धक लोग अपनी कम्पनियों की आर्थिक सत्ता का दुरुपयोग करते और उन्हें किसी के आगे जवाब भी न देना पड़ता। इस प्रकार इस व्यवस्था से कम्पनियाँ अपनी आर्थिक सत्ता के अच्छे या बुरे उपयोग के बारे में अमेरिकी जनता के सम्मुख उत्तरदायी हो जाती है।

लघु उद्योग नीतियाँ

कम्पनी-गुट-विरोधी नीति तत्त्वतः एक निपेधात्मक (नेगेटिव) नीति है जिसका उद्देश्य आर्थिक शक्ति के दुरुपयोग को रोकना है। इसके विपरीत लघु और मध्यम उद्योगो की समस्यायो का मुकाबला करने के लिए ठोस भावात्मक (पोजिटिव) उपाय और नीतियाँ होनी चाहिए। लेकिन ये नीतियाँ और उपाय मुख्यतः स्वयं व्यवसायी लोगो की ही जम्मेदारी है। सरकारी कार्यक्रम तो उन फर्मों को, जिन्हे प्रतिस्पर्धा के कारण कठिनाइयो का सामना करना पड़ रहा है, आवश्यक पहल करने और कदम उठाने के लिए केवल सहायता ही दे सकते हैं और वह उचित भी है।

छोटे और मध्यम व्यवसायों के जीवित रहने की समस्या अनेक कारणों से पैदा होती है। ये कारण अलग-अलग या परस्पर मिलकर एक फर्म की अपने उद्योग में प्रतिस्पर्धा में टिकने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। इनमें से कुछ कारण बड़ी फर्मों को अधिक लाभ-पूर्ण स्थिति का परिणाम होते हैं। लेकिन अनेक छोटी फर्मों की कठिनाइयों के ऐसे कारण भी होते हैं, जिनका बड़ी कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा की शक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं होता। इनमें से सबसे अधिक बड़ा और प्रभावशाली कारण सम्भवतः यह है कि बहुत-सी फर्में, बल्कि उनके कर्मचारी भी, नई औद्योगिक विधियों को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते, जिससे उनके उत्पादन और उत्पादन-विधियाँ दोनों, बड़ी कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा के बिना भी, पुराने हो जाते हैं। विदेशों से आयातित माल की प्रतिस्पर्धा उतना बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि विदेशों में मजदूरी की दर सस्ती होने और उसके फलस्वरूप विदेशी उत्पादन की लागत कम होने के कारण उनकी प्रतिस्पर्धा में न टिक सकने की जिस असमर्थता की अक्सर दुहाई दी जाती है, उसका वास्तविक कारण यह होता है कि ये असमर्थ अमेरिकी फर्में अपनी उत्पादकता के स्तर को ऊँचा उठाने, अपने पुराने ढंग के उत्पादन की किस्म सुधारने या अपने बिक्री और वितरण के दकियानूसी तरीकों में परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं होती।

इसलिए यह जाहिर है कि जहाँ तक इन फर्मों के पुरानी लोक से न हटने के कारण उनकी प्रतिस्पर्धा की स्थिति के बिगड़ने का ताल्लुक है, सरकार उनकी इस समस्या के हल में कोई सहायता नहीं दे सकती। ऐसे मामलों में सरकार उन्हें ऋण, अनुपूर्तियाँ, संरक्षणात्मक तट-कर या अन्य रूपों में जो सहायता देती है, उससे केवल रोग के बाहरी लक्षण का ही इलाज होता है, रोग के मूल कारण का नहीं और उसका नतीजा यह होता है कि जिन कठिनाइयों को दूर करने की नीयत से यह सहायता दी जाती है, वे हमेशा के लिए जड़ जमाकर बैठ जाती हैं। ऐसे मामलों में केवल इन फर्मों को नये तरीक़े अपनाने की सलाह देकर ही वास्तव में

सहायता पहुँचायी जा सकती है। इसके मुकाबले में बहुत-सी दूसरी छोटी फर्में ऐसी भी हैं जो आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, पर उनके पास उनके लिए पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं हैं और न वे काम करने के लिए पूर्णतः स्वतन्त्र ही हैं। ऐसी फर्मों को सरकार वित्तीय और तकनीकी विधियों के प्रशिक्षण की सहायता दे सकती है ताकि वे जो कदम उठाना चाहती हैं उसे प्रभावकारी बनाने के लिए जिन वस्तुओं की कमी है, उनकी पूर्ति हो सके।

सरकार की नीतियाँ आम तौर पर भी छोटी फर्मों को कुछ ऐसी कठिनाइयों पर विजय पाने में सहायता दे सकती हैं जो बड़ी फर्मों की प्रतिस्पर्धा के कारण उन्हें भेलनी पड़ती हैं। इन फर्मों की सबसे बड़ी कठिनाई वित्तीय है। इसलिए ऐसी फर्मों को, जिनके कुछ उन्नति कर सकने की सम्भावनाएँ हैं, अनुकूल शर्तों पर ऋण देने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाये गए हैं। इन कार्यक्रमों के परिणाम बहुत प्रोत्साहनजनक सिद्ध हुए हैं। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि छोटी फर्मों को वित्तीय सहायता देने की मौजूदा विधियाँ सर्वोत्तम हैं। हो सकता है कि कृषि-फार्मों को वित्तीय सहायता देने के लिए अर्ध-सरकारी सगठनों की जो शृंखला स्थापित की गई है, वैसी ही शृंखला छोटी फर्मों को सहायता देने के लिए भी आवश्यक हो। ऐसी वित्तीय संस्थाएँ स्थापित करने के लिए सन् 1958 में एक कानून पास किया गया था, और उसके अन्तर्गत बहुत-सी ऐसी संस्थाएँ काम भी कर रही हैं।

जहाँ तक कि कुछ अन्य कठिनाइयों का ताल्लुक है, छोटी फर्में उन पर विजय पाने के लिए स्वयं ही अपने तौर-तरीकों में कुछ हेरफेर कर रही हैं। उदाहरण के लिए छोटी फर्में बड़ी फर्मों की भाँति बड़े पैमाने पर अनुसन्धान और विकास के कार्य करने हाथ में नहीं ले सकती। इसलिए ऐसी परामर्शदात्री फर्में स्थापित की जा रही हैं जो छोटी फर्मों को तकनीकी विधियों को विकसित करने के मामले में सलाह-मशविरा देती हैं। इसी तरह कुछ राज्य सरकारों ने और व्यवसायियों के कुछ स्वैच्छिक सगठनों ने भी छोटी फर्मों की तकनीकी सहायता के लिए कार्यक्रम

बनाये हैं ।

छोटी फर्मों ने अपने आकार के छोटेपन के कारण पैदा होने वाली कठिनाइयों पर विजय पाने के लिए एक और तरीका भी अपनाया है और वह यह है कि एक से अधिक छोटी फर्में परस्पर मिल जाती हैं । लेकिन छोटी फर्मों का यह पारस्परिक विलय पिछले दस वर्षों में हुए बड़ी फर्मों के विलयों से भिन्न किस्म का है । इस विलय में अलग-अलग फर्मों की पृथक् सत्ता पूर्णतः नष्ट नहीं होती, बल्कि वे अपनी काम की स्वतन्त्रता को काफी हद तक बनाये रखती हैं । इन विलयों के परिणाम-स्वरूप बनी अनेक बड़ी फर्मों को अधिक अनुकूल और वाजिब शर्तों पर अधिक पूंजी जुटाने में सफलता मिली है । इससे उनके संयुक्त व्यवसाय को और भी अनेक प्रकार से नया बल प्राप्त हुआ है ।

सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि कई अहम क्षेत्रों में छोटी फर्मों ने बड़ी और विशाल फर्मों से भी अपने आपको अधिक सफल सिद्ध किया है । अतीत में छोटी फर्में अपने लिए बेहतर अवसरों की खोज करके अपने अस्तित्व को कायम रख सकी हैं । भविष्य में भी छोटी और मध्यम कम्पनियाँ मुख्यतः अपनी व्यक्तिगत निपुणता और जागरूकता के बल पर ही जीवित रह सकेंगी । सरकारी सहायता उनके इन गुणों का स्थान नहीं ले सकती । वह केवल इन गुणों को सहारा ही दे सकती है ।

सारांश

यह स्पष्ट है कि अमेरिका एक ओर तो उन नीतियों में परिवर्तन कर रहा है जिनका उद्देश्य आर्थिक सत्ता के दुरुपयोग को रोकना था और दूसरी ओर वह छोटे उद्योगों को सहायता देने के लिए नये उपाय भी अपना रहा है । इस प्रकार वह धीरे-धीरे एक तरफ निरन्तर आर्थिक विकास और दूसरी तरफ स्वतन्त्रता और किसी कार्य के लिए उपक्रम करने की प्रवृत्ति की रक्षा, दोनों में समन्वय कर रहा है । इस प्रक्रिया में 'एकाधिकारवादी पूंजीवाद' की पुरानी धारणाएँ तीव्र गति से समाप्त हो रही हैं, क्योंकि पिछले बीस वर्षों में बड़ी कम्पनियों के स्वरूप और

प्रभाव में और छोटी कम्पनियों की प्रतिस्पर्धा की स्थिति में बहुत दूरगामी परिवर्तन हो गए हैं। लेकिन इस परिस्थिति के फलस्वरूप जो नये हल और नई नीतियाँ अपनायी जा ऐंगी, उनके बारे में अभी से कोई विस्तृत पेशीनगोई नहीं की जा सकती। लेकिन यह जरूरी है कि व्यावसायिक व्यवहार के उन तरीकों का और अधिक स्पष्टीकरण किया जाय, जो शेयरहोल्डरो, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ उपलब्ध साधनों के अधिक प्रभावकारी उपयोग और आर्थिक उन्नति और स्थिरता में भी योग दे सकें। व्यावसायिक व्यवहार के ऐसे नियमों को अधिक अच्छे और पूर्ण रूप में विकसित और निर्धारित करना आर्थिक शक्ति को आर्थिक अभिवृद्धि के साधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है।

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत में संयुक्त राज्य अमेरिका का स्थान

संयुक्त राज्य का अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक जगत को परिस्थितियों और रुझानों पर ससार के सभी देशों से अधिक प्रभाव है। वह कच्चे माल और तैयार वस्तुओं का ससार का सबसे बड़ा निर्यातक और आयातक है। अनेक देशों के लिए वह सबसे बड़ा बाजार और सामान की उपलब्धि का सबसे बड़ा स्रोत है। कुछ देशों का तो आधे से अधिक निर्यात अमेरिका को होता है और वही उनको अधिकतर माल सप्लाई करता है। किसी भी अन्य देश की अपेक्षा अमेरिका के व्यवसायी ही विदेशों में अपनी पूंजी सबसे अधिक लगाते हैं। इसी तरह अन्य देशों के लोग भी अपने देश के बाद दूसरे नम्बर पर अमेरिका में ही अपनी सबसे अधिक पूंजी लगाते हैं। अमेरिकी सरकार ही अन्य देशों को सीधी या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिये सबसे अधिक सहायता देती है, ताकि वे आर्थिक और सामाजिक उन्नति कर सकें या कम्युनिस्ट आक्रमण और आन्तरिक षड्यन्त्र से रक्षा के लिए अपनी सैनिक शक्ति मजबूत कर सकें। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और अन्य देशों के मुद्रा कोषों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्रा अमेरिकी डालर ही है।

किन्तु अमेरिका के दृष्टिकोण से शेष ससार के साथ उसका वैसा सम्बन्ध नहीं है, जैसा उसका अमेरिका के साथ है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था शेष ससार की अर्थ-व्यवस्था पर उतनी निर्भर नहीं रही, जितनी कि शेष ससार की अर्थ-व्यवस्था उसकी अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर रही है। उदाहरण के लिए, यद्यपि सन् 1960 में अमेरिका का निर्यात और आयात विश्व के कुल निर्यात और आयात का क्रमशः 17½ प्रतिशत और 13½ प्रतिशत था तो भी संयुक्त राज्य की कुल राष्ट्रीय आय का वह क्रमशः

6 प्रतिशत और 5 प्रतिशत ही था। इसी तरह सन् 1960 में अमेरिका ने अन्य देशों में दीर्घकालिक निवेश के लिए 4 अरब डालर से अधिक राशि, जो ससार के सभी देशों के विदेशी पूंजी-निवेश के आधे से अधिक थी, लगायी थी। लेकिन उस वर्ष अमेरिकी लोगों ने अपने देश में जितनी कुल प्राइवेट पूंजी लगायी थी, उसकी तुलना में वह कुल 5½ प्रतिशत ही थी।

संयुक्त राज्य और शेष संसार की आर्थिक दृष्टि से एक-दूसरे पर निर्भरता में जो असमानता है वह उन्नीसवीं शताब्दी में और उसके बाद काफी हद तक प्रथम विश्व युद्ध तक ब्रिटेन और शेष ससार की पारस्परिक आर्थिक निर्भरता की असमानता से बिलकुल उलटी है। उस जमाने में ब्रिटेन विश्व के आर्थिक जगत् का नेता था। ब्रिटेन में सामान और सेवाओं का जितना उत्पादन और उपभोग होता था, उसमें उसके विदेशी व्यापार का हिस्सा अधिक होता था और ब्रिटेन जो वचत या पूंजी निर्माण करता उसमें भी विदेशी निवेश ही महत्वपूर्ण भाग अदा करता था। विश्व का करीब-करीब सारा व्यापार ही ब्रिटेन की मुद्रा पाँड स्टर्लिंग के आधार पर होता था और उन्नीसवीं शताब्दी का स्वर्ण-मान मुख्यतः बैंक ऑफ इंग्लैंड, लन्दन के द्रव्य बाजार और ससार भर में फैले ब्रिटिश बैंकों, बीमा कम्पनियों और जहाजरानी की फर्मों के जरिये से स्वतः चलता रहता था। इस प्रकार एक तरह से यह कहा जा सकता है कि उन्नीसवीं शताब्दी की स्वतन्त्र-व्यापार वाली विश्व की अखण्ड आर्थिक प्रणाली इतनी निर्बाध और बेरोकटोक गति से इसलिए चलती थी कि ब्रिटेन आर्थिक दृष्टि से शेष ससार पर जितना अधिक निर्भर करता था, उतना शेष ससार उसपर निर्भर नहीं था।

यद्यपि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली द्वितीय विश्वयुद्ध के तत्काल बाद के वर्षों की अपेक्षा काफी अच्छी है, क्योंकि हाल के वर्षों में उसमें सुधार हुआ है तो भी बहुत-सी गम्भीर समस्याएँ अभी तक मौजूद हैं। इन समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक नेतृत्व और साधन उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संयुक्त राज्य पर है,

क्योंकि गैर-कम्युनिस्ट संसार में वही सबसे बड़ा, सबसे सम्पन्न और सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र है। मोटे तौर पर इस समय अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक अणाली के सम्मुख तीन बड़ी कठिनाइयाँ हैं :

- ❶ अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का विस्तार उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए और न उसके लाभ उतने मिल रहे हैं जितने मिलने चाहिए क्योंकि (1) तटकर और अन्य बाधाओं के कारण सामान और सेवाएँ एक देश से दूसरे देश में निर्वाह रूप में नहीं जा पाती; (2) कच्चे माल के विश्व व्यापार में वृद्धि धीमी गति से हो रही है और उसमें स्थिरता नहीं है, और (3) मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।
- ❷ एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अल्पविकसित देशों को न तो अपने निर्यात व्यापार से और न ही प्राइवेट विदेशी निवेश से उतना धन प्राप्त हो रहा है जितना उन्हें अपनी बढ़ती हुई आवादी और लोगों की उपभोग की बढ़ती हुई आवाजों के अनुरूप अपनी आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिए जरूरी है।
- ❸ सोवियत संघ और साम्यवादी चीन की साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षाओं के कारण अनेक विकसित और विकसितोन्मुख देशों की अर्थ-व्यवस्था पर भारी बोझ पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें साम्यवादी देशों के बाह्य आक्रमण और अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद के आन्तरिक पड़घनों से अपनी रक्षा के लिए बहुत खर्च करना पड़ता है।

लेकिन अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था और दोष अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के परस्पर सम्बन्धों में जो सममानता है उसकी वजह से संयुक्त राज्य इन सम्बन्धों में अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के हल के लिए एक सीमा तक ही नेतृत्व और मार्गदर्शन प्रदान कर सकता है या उनके लिए तैयार हो सकता है। इन सम्बन्धों में हम अमेरिकी दृष्टिकोण से इन समस्याओं को प्रस्तुत करने और पर ध्यान देने कि संयुक्त राज्य ने अपने अन्य नागरिकों और मित्र देशों के साथ मित्रवत हल के लिए क्या मुख्य नीतियाँ

और कार्यक्रम अपनाये। यहाँ हम स्वभावतः अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों के आर्थिक पहलू पर ही जोर दे रहे हैं तो भी यह बात नहीं भुलाई जानी चाहिए कि इन कठिनाइयों का समूचे मानव-समाज के भविष्य के लिए गम्भीर राजनीतिक और सामरिक महत्त्व भी है।

संयुक्त राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप

संयुक्त राज्य और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के पारस्परिक सम्बन्धों की असमानता का मूल कारण अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का विशिष्ट स्वरूप है, जिसकी चर्चा हम पिछले अध्यायों में कर चुके हैं। यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि संयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था राष्ट्रीय नहीं, बल्कि महाद्वीपीय अर्थ-व्यवस्था है। उसके प्राकृतिक साधनों का विस्तार और विविधता, उसकी आवादी की विपुलता, बहुविधता और उत्पादकता, उसके उपभोग का ऊँचा स्तर और वित्तीय साधनों की प्रचुरता, और उसमें सामान, धन और जन-शक्ति के आन्तरिक आवागमन की अपेक्षाकृत स्वतन्त्रता—इन सबको देखने से यह कहा जा सकता है कि संयुक्त राज्य अपने आप में एक महाद्वीप है। इस दृष्टि से केवल सोवियत संघ ही उसकी कुछ बराबरी कर सकता है, लेकिन वह भी बहुत अधिक नहीं। यहाँ तक कि यूरोपीय साप्ताहिक बाजार भी, चाहे उसमें ब्रिटेन और कुछ अन्य छोटे नजदीकी देश भी मिला जाएँ, उतनी मात्रा में आत्मनिर्भरता और आन्तरिक क्रय-शक्ति प्राप्त नहीं कर सका जितनी कि अमेरिका ने प्राप्त कर ली है, हालांकि यह सम्भव है कि कुछ समय बाद वह अपनी जनता को वे लाभ अधिकाधिक मात्रा में प्रदान कर सके जो संयुक्त राज्य ने अपनी अर्थ-व्यवस्था की विशालता, समृद्धि और गतिशीलता से प्राप्त किये हैं।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के महाद्वीपीय अर्थ-व्यवस्था होने का एक परिणाम यह है कि संयुक्तराज्य कच्चे, आधे-तैयार और तैयार सभी प्रकार के माल का सबसे बड़ा आयातक भी है और सबसे बड़ा निर्यातक भी, और उसकी यह स्थिति सारे ससार में अनूठी है। वैसे आम तौर

पर औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप यह होता है कि वे भारी मात्रा में निर्यात तैयार माल का करते हैं और आयात कच्चे माल का। दूसरी ओर अल्पविकसित देशों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप इससे उलटा होता है—उनका अधिकतर निर्यात कच्चे माल का और आयात तैयार माल का होता है।

बीसवीं शताब्दी से पूर्व अमेरिका मुख्यतः कृषि-जिन्से और औद्योगिक कच्चा माल निर्यात करता था और कारखानों में निर्मित वस्तुएँ आयात करता था। लेकिन जब अमेरिका का औद्योगिक उत्पादन बढ़कर उसके कृषि जिन्सों और कच्चे माल के उत्पादन से काफी आगे निकल गया तब भी वह कृषि-जिन्सों का और काफी हद तक औद्योगिक कच्चे माल का भी बड़ा निर्यातक बना रहा। संयुक्त राज्य में कृषि की उत्पादन क्षमता बहुत ऊँची होने के कारण यहाँ कृषि-जिन्सों की उपज देश की अपनी जरूरतों से ज्यादा होती है, इसलिए अमेरिका अनाज, मॉस, अन्य खाद्य-पदार्थ, पशुओं का चारा, रुई और तम्बाकू आदि अपनी फालतू वस्तुएँ संसार के अन्य देशों को सप्लाई करता है। यह ठीक है कि अमेरिकी उद्योग स्वयं कुछ प्रायातित धातुओं और खनिज पदार्थों पर काफी हद तक निर्भर हैं तो भी अमेरिका कुछ औद्योगिक कच्चा माल और ईंधन काफी बड़ी मात्रा में अन्य देशों को निर्यात करता है। जब भी ऐसा मौका आया कि डालर क्षेत्र से बाहर के देश विद्युत् की इन कच्ची और आधी-तैयार वस्तुओं की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने में असफल रहे तभी संयुक्त राज्य ने इन वस्तुओं का निर्यात काफी तेज गति से और काफी अधिक मात्रा में बढ़ा दिया। लेकिन साथ ही साथ निर्यात और तैयार वस्तुओं का निर्यात इन वस्तुओं के निर्यात से भी अधिक रहा है और वह अब भी बढ़ रहा है।

विश्व-व्यापार में अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की यह दोनों प्रकार की भूमिका संसार के विभिन्न भागों को भेजे जाने वाले और उनसे मगाये जाने वाले उसके माल का अध्ययन करके भली भाँति समझी जा सकती है। कम विकसित देशों की तुलना में संयुक्त राज्य एक उन्नत औद्योगिक

देश है, और उनसे मुख्यतः कच्चा औद्योगिक माल आयात करता है और उसके बदले में उन्हें मुख्यतः कारखानों में तैयार माल भेजता है।

चार्ट 14

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति, 1959

स्वाधुर्धन और कारखानों में निर्मित
कच्चा माल माल



आयात

निर्यात

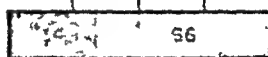
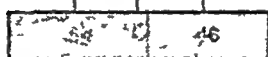
प्रतिशत

प्रतिशत

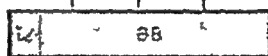
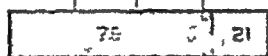
0 25 50 75 100

0 25 50 75 100

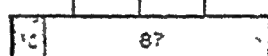
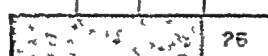
सं. अमेरिका
United States



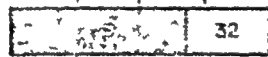
जापान
Japan



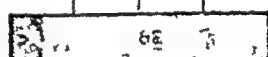
ब्रिटेन
United Kingdom



फ्रांस
France



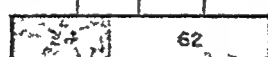
पश्चिमी जर्मनी
West Germany



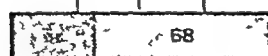
मिस्र
(सं. अ. गणराज्य)
Egypt (U.A.R.)



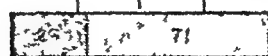
अर्जेण्टाईना
Argentina



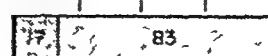
इंडोनेशिया
Indonesia



ऑस्ट्रेलिया
Australia



ईराक
Iraq



अ. इसमें अनेक अर्ध-निर्मित वस्तुएँ भी शामिल हैं।

लेकिन औद्योगिक दृष्टि से समृद्ध देशों के साथ उसके व्यापार का स्वरूप इससे उलटा है, हालांकि यों, सब मिलाकर देखा जाय तो, ये देश उसके कारखानों में निर्मित माल के सबसे बड़े आयातक हैं।

परन्तु यदि कुल समुच्चय की दृष्टि से देखा जाय तो आयात और निर्यात अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के लिए अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है। उष्ण कटिबन्ध की कुछ चीजों, जैसे कॉफी, कोको, प्राकृतिक रबर, सख्त रेशा, केला, सख्त लकड़ी की कुछ किस्मों और कुछ तिलहनो का संयुक्त राज्य में उत्पादन आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं होगा। इसी तरह अलौह धातुएँ और खनिज—जैसे मैंगनीज, क्रोम, निकल, ताँबा, बॉक्साइट, टीन और होरे—संयुक्त राज्य में पैदा नहीं होते या उचित मात्रा पर उनका यहाँ उत्पादन नहीं किया जा सकता। इसलिए इन वस्तुओं को इस्तेमाल करने वाले अमेरिकी उद्योग इनके आयात पर निर्भर करते हैं। दूसरी ओर कुछ अमेरिकी उद्योग ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ निर्यात-बाजार पर निर्भर हैं, जैसे सिनेमा फ़िल्में, कुछ किस्मों की औद्योगिक और कृषि मशीनरी और कुछ अन्य जिनसे।

यद्यपि पिछले दस वर्षों में अमेरिका के कुल निर्यात का 60 प्रतिशत भाग कारखानों में तैयार माल का था, तो भी तैयार माल के निर्यात की गति में वृद्धि सबसे धीमी थी। दस वर्षों में उसमें केवल 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अमेरिका से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में सबसे अन्तिम स्थान आधे-तैयार कच्चे माल का और आधे-तैयार निर्मित माल का है, परन्तु इन्हीं के निर्यात में इन दस वर्षों में बसे अधिक, यानी 150 प्रतिशत, वृद्धि हुई। कच्चे माल का स्थान मात्रा और वृद्धि की गति दोनों के लिहाज से इन दोनों के बीच में है। इसके निर्यात में 1950 के दशक में 20 प्रतिशत वृद्धि हुई। विदेशी व्यापार के खाते में दूसरी तरफ कच्चे माल और आधी-तैयार निर्मित वस्तुओं के आयात में इस दशक में लगभग उमी गति से वृद्धि हुई जिस गति से संयुक्त राज्य की कुल राष्ट्रीय आय में, लेकिन कारखानों में तैयार निर्मित माल के आयात में लगभग 150 प्रतिशत वृद्धि हो गई।

व्यापार की समस्याएँ और नीतियाँ

शेष ससार के साथ सयुक्त राज्य के व्यापार का जो ढाँचा है उसमें कुछ समस्याएँ स्वभावतः अन्तर्निहित हैं और हाल के वर्षों में वे बहुत महत्वपूर्ण हो गई हैं। किन्तु अमेरिका के विदेशी व्यापार का एक बड़ा भाग ऐसा भी है, जिसके सामने विदेश में व्यापार करने में आम तौर पर होने वाले सामान्य व्यावसायिक खतरों के अलावा कोई बड़े खतरे नहीं हैं, इसलिए अमेरिकी आयात और निर्यात के सम्मुख उपस्थित कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए हमारा अभिप्राय उनका अतिरजनापूर्ण वर्णन करना नहीं है। मात्रा की दृष्टि से देखें तो अमेरिकी विदेशी-व्यापार का समस्याग्रस्त अंश उसके कुल विदेशी व्यापार का बहुत छोटा अंश है। फिर भी तीन कारणों से वह बहुत महत्वपूर्ण है। पहला यह कि समस्या और कठिनाई से ग्रस्त इस व्यापार का सम्बन्ध, खासकर आयात के मामले में, ऐसे व्यावसायिक हितों से है, जो खूब संगठित हैं, हल्ला-गुल्ला कर सकते हैं और राजनीतिक दृष्टि से प्रभावशाली हैं। दूसरा यह कि अमेरिका के आयात और निर्यात के तुलनात्मक स्तरों में एक छोटा-सा परिवर्तन भी सयुक्त राज्य के अदायगी सन्तुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तीसरा कारण यह है कि बहुत-से देशों के लिए सयुक्त राज्य के साथ व्यापार इतना महत्वपूर्ण है कि वे अमेरिका को उसके उन कामों से जाँचते हैं, जो वह अपनी आयात और निर्यात की-समस्याओं को हल करने के लिए करता है। अन्य देशों का यह रुख सयुक्त राज्य की परराष्ट्र नीति की प्रभावकारिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में पुराना सिद्धान्त यह है कि जो राष्ट्र जिन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक सुविधा और लाभ की स्थिति में है, यदि वह उनका उत्पादन कर सके और उन्हें विदेशों में बिना किसी बाधा के बेच सके तो उससे विश्व व्यापार प्रणाली के सभी सदस्य देशों को लाभ होता है। इस सिद्धान्त की मान्यता यह है कि यदि आयात और निर्यात पर तट-कर

आदि की बाधाएँ अपेक्षाकृत मामूली होंगी, तब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभों की इस विश्व व्यापार प्रणाली में भाग लेने वाले देशों में देर-सवेर समुचित वितरण हो जायेगा, बशर्ते कि हर देश की

चार्ट 15

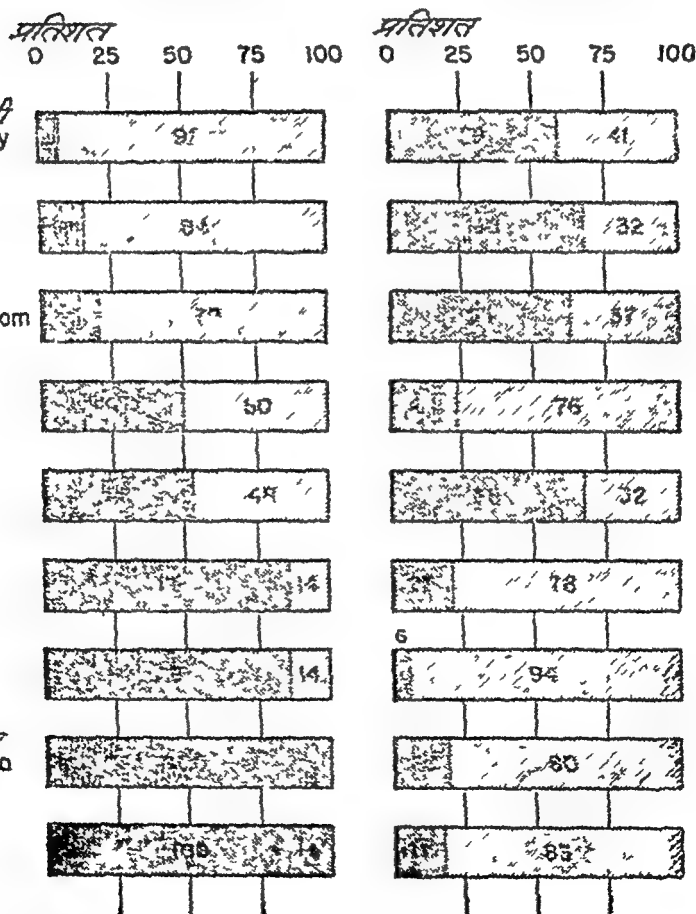
कुछ चुने हुए देशों के साथ संयुक्त राज्य का विदेशी व्यापार, 1959

खाद्य ईंधन और कारखाने से निर्मित
कच्चा माल माल



सं.रा. को निर्यात

सं.रा. से आयात



1. इसमें बहुत-सी अद्व. निर्मित वस्तुएँ भी शामिल हैं।

विशिष्टता उन वस्तुओं का उत्पादन हो, जिनका वह दूसरों से सस्ता और अच्छा उत्पादन या निर्माण कर सकता है।

किन्तु फिर भी, उन्नीसवीं शताब्दी के थोड़े-से समय को छोड़कर, शेष सारे समय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के अधिकतर सदस्य देश अपनी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्थाओं के ढाँचे या परिस्थितियों में अनवरत परिवर्तन करने के लिए, जो कभी-कभी बहुत उग्र होते हैं, अनिच्छुक रहे हैं, हालांकि ये परिवर्तन इस सिद्धान्त के अनुसार अनिवार्य होते हैं कि जो देश किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन के लिए दूसरे देशों से अधिक लाभजनक स्थिति में है, वही उसका उत्पादन करे और उसे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेरोकटोक बेच सके। यहाँ तक कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भी संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस आदि नये औद्योगिक राष्ट्रों ने अपने 'शिशु उद्योगों' को ब्रिटेन के पहले से जमे हुए और उन्नत उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देना जरूरी समझा। दूसरी ओर जब इन नये औद्योगिक राष्ट्रों ने, कुछ तो तटकर आदि संरक्षणों के द्वारा और कुछ अन्य उपायों से, अपने आपको औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत बना लिया तब उल्टा ब्रिटेन ही स्वतन्त्र व्यापार के सिद्धान्त को छोड़ने के लिए मजबूर हो गया ताकि वह संयुक्त राज्य, जर्मनी और जापान के नये और अधिक कुशल उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से अपने कुछ पुराने ढर्रे के उद्योगों को बचा सके।

दोनों विश्व-युद्धों के बीच की अवधि में, खासकर सन् 1930 के दशक की भारी मंदी के बाद, प्रायः सभी प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रों ने अपने गिरते हुए आन्तरिक बाजारों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए अपने आयात सम्बन्धी प्रतिबन्ध बढ़ा दिये। इस प्रकार अपेक्षाकृत अधिक लाभजनक स्थिति वाली वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और निर्वाह व्यापार के पुराने सिद्धान्त को मानते हुए भी प्रायः सभी देशों ने अपने औद्योगीकरण को बढ़ाने के लिए, या अपने पुराने और अकुशल उद्योगों को अन्य देशों के नये और कुशल उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए अथवा मंदी के दिनों में अपने आन्तरिक उत्पादन की आयात के

दुष्प्रभावों से रक्षा करने के लिए आयात पर पाबन्दियाँ लगा दी ।

संयुक्त राज्य ने अपने समूचे इतिहास में हमेशा इनमें से किसी एक या एकाधिक उद्देश्यों के लिए आयात पर प्रतिबन्ध लगाये रखा है । सन् 1860 के बाद, सिर्फ दो मौकों को छोड़कर, हमेशा ही संयुक्त राज्य अपने तटकर की दरों में समय-समय पर वृद्धि करता रहा है और सन् 1930 के स्मूट-हॉले टैरिफ ऐक्ट के समय तो ये दरें अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई । लेकिन उसके बाद सन् 1934 से यह रुझान उल्टा हो गया । राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी० रूजवेल्ट द्वारा प्रारम्भ किये गए पारस्परिक व्यापार समझौता कार्यक्रम के अन्तर्गत अमेरिका ने अन्य देशों के साथ समझौते करके अपने अनेक तटकरों को या तो विलकुल खत्म कर दिया या उनमें काफी कमी कर दी और इन समझौतों के फलस्वरूप अन्य देशों ने भी अमेरिका की खास खास चीजों पर अपने आयात-कर कम कर दिये । कांग्रेस समय-समय पर पारस्परिक व्यापार समझौतों अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार देती रही है कि वे अन्य देशों से अमेरिकी माल पर तटकर सम्बन्धी रियायतें प्राप्त करें और उसके बदले में उन्हें भी रियायतें दें ।

किन्तु 1940 के दशक के बाद राष्ट्रपति को दिये गए इस अधिकार की प्रभावकारिता कुछ कम हो गई, क्योंकि उपर्युक्त कानून में दो संशोधन कर दिये गए, जिनसे ऐसे अमेरिकी निर्माता, जो यह महसूस करते हैं कि उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से नुकसान हो रहा है या हो सकता है, तटकर में प्रस्तावित कमी को रोक सकते हैं या पहले कम किये गए तटकरों को फिर बढ़ा सकते हैं । इसके अलावा कांग्रेस ने वस्त्र, सीसा, जस्त, चीनी आदि कुछ वस्तुओं के आयात के लिए कोटे भी बाँधे, क्योंकि यह महसूस किया गया कि तटकर बढ़ाने से भी इन वस्तुओं में विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला नहीं किया जा सका, या राष्ट्रीय रक्षा अथवा अन्य कारणों से ऐसा करना आवश्यक है ।

बहुत-से अमेरिकी उद्योगों में, खासकर बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले उद्योगों में—जैसे कि टिकाऊ उपभोग्य वस्तुओं के उद्योग—अमेरिकी

निर्माताओं को यह डर नहीं है कि अमेरिका के आन्तरिक बाजार में विदेशी निर्माता उनका मुकाबला कर सकेंगे। और ये उद्योग विदेशी बाजारों में भी अपना माल अधिक बेच सकते हैं, क्योंकि अन्य देश माल मगाने के मामले में डालर क्षेत्र से भेदभाव न करते। लेकिन दूसरी ओर कुछ उद्योग ऐसे भी हैं, जिनमें अमेरिका के आन्तरिक बाजार में विदेशी निर्माताओं की तरफ से काफी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा है। इनमें बहुत-से उद्योग वे हैं जिनमें श्रम की बहुत जरूरत पड़ती है, या जो अपेक्षाकृत छोटे पैमाने पर उत्पादन करते हैं या ऐसे खास और जटिल किस्म के उपकरण तैयार करते हैं जो बड़े पैमाने पर तैयार नहीं किये जा सकते। उदाहरण के लिए अनेक प्रकार के कपड़े, घड़ियाँ, चीनी मिट्टी का सामान, कुछ रासायनिक पदार्थ और कुछ खास किस्मों के बिजली के या दूसरे भारी सामान, जिनके लिए इंजीनियरी और श्रम दोनों की बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है, इनमें शामिल किये जा सकते हैं। इन और इनके जैसी अन्य वस्तुओं के अमेरिकी निर्माताओं ने तटकर में वृद्धि, कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध, सरकारी खरीद में तरजीह आदि उपायों से देश के आन्तरिक बाजार विदेशी निर्माताओं की वास्तविक या सम्भावित प्रतिस्पर्धा से संरक्षण या तो प्राप्त कर लिया या उसके लिए उद्योग कर रहे हैं।

अमेरिकी आयात प्रतिबन्धों में भविष्य में कमी होगी या नहीं, यह अभी अनेक कारणों से अनिश्चित है। अन्य बड़े औद्योगिक राष्ट्रों की तुलना में अमेरिका में इस समय ये प्रतिबन्ध कम हैं। अमेरिकी तटकरों में जो भी कमियाँ आसानी से या बिना किसी विवाद के की जा सकती थी, वे सभी पारस्परिक व्यापार समझौता कार्यक्रम के अन्तर्गत की जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त जिन मामलों में तटकर की दरें कम नहीं की गईं, उनमें भी तटकरों का प्रभाव प्रायः खत्म हो गया है क्योंकि या तो उन वस्तुओं के मूल्यों में दीर्घकाल के लिए कमी कर दी गई है या लोगों की रुचियाँ बदल जाने से उनका आयात ही नगण्य रह गया है। इसलिए यदि आयात-करों में भविष्य में और कमियाँ की गईं तो उनसे अमेरिका

के आन्तरिक बाजार में विदेशी प्रतिस्पर्धा के बढ़ने की ही अधिक सम्भावना है। संयुक्त राज्य में इस प्रतिस्पर्धा में वृद्धि को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से स्वीकार तभी किया जाएगा जब कि (क) इस प्रतिस्पर्धा से प्रभावित होने वाले उद्योगों के मालिक और मजदूर, दोनों स्वेच्छा से या सरकारी सहायता से आवश्यक हेरफेर और परिवर्तन करने को तैयार हों और उसके लिए समर्थ भी हों; और (ख) विदेशी बाजारों में अमेरिकी निर्यात को बढ़ाने के लिए भी उतने ही अवसर मिलें और संयुक्त राज्य के निर्यातक उसका लाभ उठाने के लिए तैयार और समर्थ हों।

अमेरिकी उत्पादक अपने देश के आन्तरिक बाजार में विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ने पर आवश्यक परिवर्तन अनेक प्रकार से कर सकते हैं। अनेक उद्योगों में यह सम्भव है कि उत्पादकता में वृद्धि अथवा उत्पादित माल की किस्म में सुधार कर लिया जाय, जिससे कि तटकर में कमी कर देने पर भी वे मूल्य या किस्म के लिहाज से विदेशी माल का मुकाबला कर सकें। लेकिन अतीत में यह देखा गया है कि कुछ अमेरिकी उद्योग या कारखाने विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित होने पर इन परिवर्तनों के लिए तैयार नजर नहीं आये। और कुछ उद्योग ऐसे हैं जिनमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिक अनुसंधान, पूंजी या प्रबन्ध-कौशल अथवा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होगी जिसके बिना ये उद्योग इस दिशा में प्रगति नहीं कर सकते।

कुछ उद्योग ऐसे भी हैं जिनमें विदेशी उत्पादक उत्पादन के लिए इतनी अधिक लाभजनक स्थिति में हैं, कि अमेरिकी उत्पादकों का उत्पादकता में यथासम्भव वृद्धि करने पर भी उनकी प्रतिस्पर्धा में टिकना सम्भव नहीं है। यह बात उन देशों के आयात के बारे में खास तौर से सही है जिनमें मजदूरी की दर और कच्चे माल का मूल्य बहुत कम है। ऐसी वस्तुओं के मामले में यदि अपेक्षाकृत लाभजनक स्थिति के सिद्धान्त को पूरे तौर पर लागू करना हो तो यह जरूरी होगा कि अमेरिका अपनी पूंजी और अपने श्रमिकों को और किस्मों के उत्पादन में लगाये और इन

वस्तुओं की अपनी माँग को पूरा करने के लिए पूर्णतः आयात पर ही निर्भर रहे। और पिछले तीस वर्षों में काफी अधिक किस्मों की वस्तुओं के बारे में यह दुःखद परिवर्तन करना भी पड़ा है। यह बात सहज में समझ में आने वाली है कि इन वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए उत्पादकों और श्रमिकों ने स्वभावतः अपने देर से चले आ रहे कामों को बन्द या कम करने का प्रतिरोध किया। जिन इलाकों में आयात की प्रतिस्पर्धा से भिन्न अन्य उद्योगों में भी शिथिलता या ह्रास आ रहा था, वहाँ यह प्रतिरोध और भी उग्र हुआ। इसलिए इन ह्रासोन्मुख, अवरुद्ध उद्योगों और शिथिलता तथा मन्दी के शिकार इलाकों में ही तटकरों में प्रस्तावित कमी को रोकवाने या पहले हुई कमियों को रद्द करवाने के लिए सबसे अधिक आन्दोलन हुए और वे सफल भी हुए। यही नहीं, इन उद्योगों और इलाकों ने नये कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगवाने और सरकारी खरीद में तरजीह या अन्य प्रकार के संरक्षण और सहायताएँ प्राप्त करने में भी सफलता प्राप्त की।

हाल के वर्षों में उद्योगों, कम्पनियों, श्रमिकों और मन्दी के शिकार इलाकों को आयात की प्रतिस्पर्धा के कारण दोनों प्रकार के परिवर्तन करने के लिए सहायता देने के अनेक प्रस्ताव किये गए। जहाँ व्यावहारिक और सम्भव प्रतीत हुआ उन्हें अपनी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सहायता देने का प्रस्ताव रखा गया और साथ ही जहाँ उचित हुआ, उन्हें अपनी पूँजी और श्रमिकों को दूसरी किस्मों के उत्पादनो या दूसरे इलाकों में लगाने के लिए भी प्रोत्साहन और मदद देने के सुझाव दिये गए। लेकिन इस प्रकार के परिवर्तन करने के लिए सहायता देने के अनेक प्रस्ताव पिछले दस वर्षों में कांग्रेस में पेश किये जाने पर भी उनमें से पास कोई नहीं हुआ। फिर भी विदेशी प्रतिस्पर्धा से प्रभावित कुछ उद्योगों और इलाकों ने इस तरह के परिवर्तन के लिए सघीय, राज्याय और स्थानीय शासनों द्वारा मन्दी-ग्रस्त इलाकों की सहायतार्थ प्रारम्भ किये गए कार्यक्रमों के अन्तर्गत, जिनका अध्याय 9 में उल्लेख किया जा चुका है, सहायता प्राप्त की। अमेरिकी आयात प्रतिबन्धों में भविष्य में

कोई और कमी की जाती है या नहीं, राजनीतिक दृष्टि से इसकी सम्भावना इस बात पर बहुत कुछ निर्भर है कि क्या आयात की प्रतिस्पर्धा के बढ़ने से प्रभावित होने वाले उद्योगों, उत्पादकों और इलाकों को उपर्युक्त परिवर्तन करने के लिए सहायता देने के प्रभावकारी कार्यक्रम अपनाये जाते हैं। यह बात इसलिए भी है, कि जितना भी संरक्षण इन उद्योगों के ऊपर से हटाया जा सकता था, करीब-करीब वह सब पहले ही हटाया जा चुका है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी निर्यात के लिए अवसर और गुंजाइश को बढ़ाना भी एक कठिन कार्य हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के एकदम बाद के पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के वर्षों में यूरोप और जापान को अमेरिका से किये जाने वाले निर्यात के कम होने का यह कारण उतना नहीं था कि वहाँ इस निर्यात की कीमत अच्छी वसूल नहीं हो सकेगी या वहाँ अमेरिकी माल पर तटकर अधिक है, जितना कि यह कारण था कि इन देशों के पास अपनी जनता का पेट भरने या अपनी युद्धध्वस्त अर्थ-व्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका से खाद्य, ईंधन और पूंजीगत सामग्री मगाने के लिए मूल्य की अदायगी के साधन पर्याप्त नहीं हैं। इसी तरह लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के अल्प-विकसित देश भी निःसन्देह अमेरिका से कहीं अधिक माल आयात करते यदि उनके पास उसका मूल्य चुकाने के लिए पर्याप्त डॉलर होते। लेकिन यूरोप के पुनरुद्धार का कार्यक्रम 1950 के दशक के मध्य में समाप्त हो जाने और 1957 में हुए स्वेज संकट के भी खत्म हो जाने के बाद विश्व के बाजार में अमेरिकी निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में काफी परिवर्तन होता रहा है।

यूरोप के उद्योग न केवल द्वितीय विश्वयुद्ध के दुष्प्रभावों से मुक्त हो गए हैं, बल्कि उन्होंने उत्पादकता, उत्पादन और सांख्यिक उद्यम के नये ऊँचे स्तर प्राप्त कर लिये हैं। इसका एक कारण यह है कि मार्शल योजना के अन्तर्गत अमेरिका ने जो रकम अपनायी और जो ढंग अपनायी उनसे यूरोप के देशों ने अनेक सवक लिये। इसका दूसरा कारण यूरो-

पीय साभा बाजार का निर्माण और प्रगति है। इस बाजार के निर्माण से सदस्य देशों में आर्थिक उन्नति के अवसर बढे और उनमें निर्माताओं का परस्पर प्रतिस्पर्धा का उत्साह भी बढा। इसका तीसरा कारण यह था कि यूरोपीय देशों की सरकारों ने अपने निर्यात को बढाने के लिए विशेष प्रयत्न किये और कार्यक्रम बनाये और साथ ही 1949 के मुद्रा-सुधारों के परिणामस्वरूप अमेरिकी डालर के साथ अपनी मुद्राओं की विनिमय दर घटा दी।

आज यह स्थिति है कि यूरोपीय देशों के, खासकर यूरोपीय साभा बाजार के सदस्य देशों के, निर्माता यूरोप के भीतर भी और बाहर भी अपने उत्पादनों के लिए नये-नये बाजार खोजने में जोरों से लगे हैं। यूरोप और जापान के निर्माता और निर्यातक मूल्य, उत्पादन की विधि, ग्राहकों की जरूरतों और रुचियों की सन्तुष्टि, मशीनों की मरम्मत और फालतू पुर्जों की सप्लाई, ऋण की व्यवस्था, जहाजी परिवहन और बीमे का खर्च और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के अन्य पहलुओं की दृष्टि से न केवल अमेरिकी निर्माताओं और निर्यातकों का सफलतापूर्वक मुकाबला कर रहे हैं, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने उन्हें प्रतिस्पर्धा में पछाड भी दिया है।

यूरोपीय देशों और जापान में फिर से निर्यात की क्षमता पैदा हो जाना एक स्वागतयोग्य घटना है। ये देश अपने आर्थिक स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिए विदेशी व्यापार पर सयुक्त राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक निर्भर हैं। यदि इन देशों को अपनी जनता के रहन-सहन को सन्तोषजनक बनाना हो, समार के अल्पविकसित भागों की सहायता के काम में हिस्सा बटाना हो और कम्युनिस्टों के आक्रमण और आन्तरिक षडयन्त्र से अपनी रक्षा करनी हो तो उनकी अर्थ-व्यवस्थाओं को निरन्तर उन्नत करते रहना और उनके विदेशी व्यापार को बढाना जरूरी है। इसलिए इन देशों की आर्थिक उन्नति स्वयं अमेरिका के भी हित में है और उनकी प्रतिस्पर्धा की शक्ति अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को सीधा लाभ भी पहुँचा सकती है, क्योंकि उससे अमेरिकी उत्पादन कर्त्ताओं को भी

इस प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए प्रेरणा मिलेगी ।

लेकिन इसके बावजूद यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राज्य को भी विश्व के निर्यात-व्यापार में होने वाली भावी वृद्धि में हिस्सा मिले। संयुक्त राज्य की लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के आर्थिक और सामाजिक विकास में सहायता देने की क्षमता और सत्कार के विभिन्न भागों में अपने साथी और भिन्न देशों की रक्षा में मदद देने की सामर्थ्य अन्ततः इस बात पर ही नीची निर्भर है कि वह अपने विदेशी व्यापार को अनुचित रीति में समुचित रख सके। सन् 1957 तक अमेरिका का निर्यात उसके आयात में इतना अधिक अवश्य होता था कि वह संयुक्त राज्य की सरकार के वैदेशिक सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत अन्य देशों को दी जाने वाली रकमों को और अन्य देशों में नयी अमेरिकी पूंजी गैर-इस पर शक्त और अमेरिका को प्रेषित लाभ के अन्तर को समुचित कर सके। लेकिन उसके बाद अमेरिका के विदेशी व्यापार में काफी समुन्नत हो गया, जिसके परिणामों का हम आगे चलकर इन्तरेण्ड करेंगे। फिर भी यहाँ काफ़ी समय तक इस बात की आवश्यकता होती कि अमेरिका वैदेशिक सहायता पर काफ़ी धन खर्च करे और अमेरिका को आवश्यक अपनी विदेशों में लगती रहे। यदि अमेरिका के निर्यात में वृद्धि नहीं होती, तो संयुक्त राज्य की आर्थिक स्थिति और देश के लिए सहायता देने में इस आवश्यकता कार्यक्रमों को जारी रखने की क्षमता भी काफी कम हो जायेगी।

[illegible]

— 4 —

कता यूरोप और जापान के श्रम-प्रधान उद्योगों की अपेक्षा कई गुना अधिक थी और इसलिए मजदूरी की मस्ती दर के कारण कम लागत आने के इन देशों के लाभ को बराबर करके भी अमेरिकी उद्योगों का माल उनसे सस्ता पड़ता था। यह ठीक है कि पिछले दस वर्षों में यूरोप में मजदूरी की दरों में वृद्धि हो रही है और जापान में यह वृद्धि उससे भी अधिक है, लेकिन साथ ही यह भी सही है कि ये देश नये सयन्त्र और मशीनें लगाने और अधिक अच्छे कुशल प्रबन्ध-विधियों और अधिक अच्छे वितरण के तरीकों को अपनाने पर उससे भी अधिक खर्च कर रहे हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अमेरिका और इन देशों के उद्योगों की उत्पादकता का अन्तर आहिस्ता-आहिस्ता कम हो रहा है और कुछ मामलों में वह पूर्णतः समाप्त हो गया है। यदि यूरोपीय देश उद्योगों में नई पूँजी के निवेश को इसी तरह बढ़ाते रहे, जैसा कि सम्भव प्रतीत होता है, तो अमेरिका और यूरोप की मजदूरी की दरों का अन्तर, हालांकि वह अब कम हो रहा है, अमेरिकी उद्योगों के लिए और भी अधिक गम्भीर समस्या पैदा करेगा और उनके लिए निर्यात बाजार में अपनी निर्मित वस्तुओं की कीमतें नीची रखना मुश्किल हो जाएगा।

इस असंगति का दूसरा कारण यह है कि कुछ अमेरिकी कम्पनियों का रुख अपने निर्यात व्यापार के प्रति बहुत उत्साहपूर्ण नहीं है। अमेरिका की अधिकतर निर्माता कम्पनियों का निर्यात उनकी कुल बिक्री का बहुत ही थोड़ा हिस्सा होता है। इसलिए वे अपने उत्पादन को देश के भीतर बेचने वाले विभाग को अधिकाधिक कार्यकुशल बनाने की ओर जितना ध्यान देती हैं, उतना अपने निर्यात-व्यापार विभाग की ओर नहीं देती। ये कम्पनियाँ अपने आन्तरिक बिक्री विभाग के उच्च अधिकारियों को बिक्री बढ़ाने के लिए जितनी स्वतन्त्रता देती हैं उतनी अपने निर्यात विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्यात बढ़ाने के लिए नहीं देती। इसके अलावा अमेरिकी लोग अपने देश की आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से जितने

परिचित हैं उतने अन्य देशों की परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं, इसलिए वे यह जानते हैं कि अमेरिकी खरीदार क्या खरीदना चाहता है, लेकिन अन्य देशों का खरीदार क्या खरीदना चाहता है, इस की उन्हें पूरी जानकारी नहीं है।

बहुत-सी अमेरिकी कम्पनियों में यह भी प्रवृत्ति देखी गई है कि वे माल का अन्य देशों में निर्यात करने के बजाय उसका उत्पादन ही अन्य देशों में करती हैं। इसके दो कारण हैं, एक यह कि इससे निर्यात बाजार में उन्हें प्रतिस्पर्धा कम करनी पड़ती है और दूसरा यह कि उन्हें यूरोप और जापान में अपनी पूंजी का निवेश करने के लिए नये और अधिक आकर्षक अवसर उपलब्ध हैं। कुछ मामलों में तो अमेरिकी कम्पनियों ने यूरोप में अपने ही कारखाने खड़े कर लिये हैं और कुछ मामलों में यूरोप में पहले से ही मौजूद कम्पनियों के साथ उन्होंने साझेदारी कर ली है या उनके साथ लाइसेंस सम्बन्धी समझौते कर लिये हैं। इससे इन कम्पनियों को दो लाभ होते हैं। एक तो वे यूरोपीय साभा बाजार और उससे सम्बद्ध देशों की तटकर सम्बन्धी दीवारों के भीतर ही व्यापार कर सकती हैं और अमेरिका से माल निर्यात करने पर तटकर की ऊँची दीवार को पार करने की जो कठिनाई होती है, वह उन्हें नहीं उठानी पड़ती, और दूसरे, वे यूरोप में मजदूरी की सस्ती दर के कारण कम खर्च में माल तैयार करके वहाँ से आसानी से सप्ताह के अन्य भागों को निर्यात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत-सी अमेरिकी कम्पनियाँ उन अल्प विकसित देशों में भी, जिन्हें पहले वे अपना माल अमेरिका में निर्यात करती थी, अब अपनी निर्माण शाखाएँ या अधीनस्थ सहायक कम्पनियाँ खोलने लग गई हैं। ये अमेरिकी कम्पनियाँ अपने देश में मशीनरी आदि के पुर्जों और हिस्से या अर्ध-निर्मित वस्तुएँ भेजती हैं और इन निर्माणशाखाओं या अधीनस्थ सहायक कम्पनियों में उन्हें जोड़कर पूरा मशीन तैयार की जाती है या निर्मित वस्तु को अन्तिम रूप में जोड़कर या सुधारकर तैयार किया जाता है और फिर वे सब चीज़ें उन देशों में बेची जाती हैं। यही कारण है कि

पिछले दस वर्षों में पुर्जों, हिस्सों और अद्वंनिर्मित वस्तुओं का निर्यात काफी बढ़ा है।

और अन्त में यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि बहुत-से देश अमेरिका में निर्मित माल के साथ भेदभाव करते हैं। कुछ मामलों में अमेरिकी माल के आयात को रोकने के लिए तटकर की ऊँची दीवारें खड़ी कर दी जाती हैं और कुछ में अमेरिकी माल के आयात के लिए कोटे बाँध दिये जाते हैं या विदेशी मुद्रा सम्बन्धी पाबन्धियाँ लगा दी जाती हैं। हाल के वर्षों में यूरोपीय देशों और जापान की आर्थिक स्थिति सुधरने और मुद्राओं की परिवर्तनीयता (एक मुद्रा का दूसरी में परिवर्तन) में काफी सुधार होने के कारण और कुछ हद तक व्यापार-समझौता कार्यक्रम के अन्तर्गत हुए आपसी समझौते से तटकरों में कमी की वजह से अमेरिकी माल के साथ यह भेदभाव काफी कम हो गया है। किन्तु अब भी पर्याप्त भेदभाव मौजूद है। अल्पविक्रमि देशों में यह भेदभाव विदेशी मुद्रा की कमी के कारण और उनके नव-स्थापित शिशु उद्योगों को संरक्षण देने के लिए किया जाता है। पश्चिमी यूरोप के देशों में यह भेदभाव दो कारणों से हो रहा है। एक तो उन देशों के उद्योगों को संरक्षण देने के लिए और दूसरे इसलिए कि साम्राज्य बाजार के सदस्य देशों के पारस्परिक व्यापार पर आन्तरिक सीमा शुल्क कम हो रहे हैं और बाहरी देशों से उनके आयात पर सीमा-शुल्क बढ़ाया जा रहा है।

इन तथा कुछ अन्य कारणों का सम्मिलित परिणाम यह हुआ है कि हाल के वर्षों में अमेरिका से पूर्ण-निर्मित माल के निर्यात में वृद्धि की गति धीमी रही है। इनमें से कुछ कारण तो जीवन के ऐसे तथ्य हैं जिनके सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सकता और वे वांछनीय भी हैं। और दूसरे कारण ऐसे हैं जिन्हें, यदि अमेरिकी व्यावसायिक फर्में चाहे और उनमें उसके लिए पर्याप्त शक्ति हो तो, वे निवारण कर सकती हैं। यदि अमेरिकी फर्में अपने आन्तरिक बाजार में प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर सकती हैं तो इसमें सन्देह का कोई कारण नहीं कि उनमें से बहुत-सी

फर्मों विदेशों में बढ़ रही प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने के लिए भी देर-सवेर आवश्यक कदम उठा सकेगी। अमेरिकी फर्मों में निःसन्देह इतनी योग्यता है कि वे अपने निर्यात विभागों के कर्मचारियों और उनकी कार्यपद्धति में सुधार कर सकें और अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अधिक समझदारी और सूझ-बूझ से काम ले सकें। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उन्नति की गति को बढ़ाने के लिए उसकी औद्योगिक उत्पादकता को बढ़ाना भी जरूरी होगा। सयुक्त राज्य में उद्योगों के प्रबन्धक और श्रमिक दोनों ही अगर अपनी जिम्मेदारी को कुछ थोड़ा-सा और महसूस करें तो वे अपनी लागत को इतनी कम कर सकते हैं कि विश्व के बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों का मुकाबला कर सकें।

इसके अतिरिक्त अमेरिकी सरकार ने भी हाल में अमेरिका के निर्मित माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को सुधारना प्रारम्भ कर दिया है। अब तक सरकार निर्यात को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी सीधी सहायता यह देती थी कि वह अन्य देशों को दी जाने वाली अनुदान या ऋण की सहायता के साथ उससे अमेरिकी वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित मात्रा की खरीद की शर्त लगा देती थी। पर अभी कुछ समय से कांग्रेस वाणिज्य विभाग के लिए निर्यात को प्रोत्साहन देने, विदेशी बाजारों में अमेरिकी माल का प्रचार करने और अन्य तरीकों से अमेरिकी निर्यातकों को मदद देने के लिए काफी राशियाँ स्वीकार कर रही हैं। कुछ ऐसे प्रस्तावों पर भी विचार किया जा रहा है जिनसे अमेरिकी निर्यातक सरकार की मदद से विदेशी खरीदारों को उधार माल बेच सकेंगे और सरकार उस उधार की वसूली की गारण्टी करेगी। इस तरह अब सयुक्त राज्य की सरकार भी अपने निर्यातकों को इस प्रकार की सहायताएँ देने लगी है जो यूरोपीय देशों और जापान की सरकारें अपने निर्यातकों को वर्षों से देती आ रही हैं।

यद्यपि अमेरिका के कारखानों में निर्मित माल के निर्यात को

प्रोत्साहन देने की समस्या अपेक्षाकृत नई है, परन्तु सयुक्त राज्य के कृषि-उत्पादनो की समस्या सरकार और प्राइवेट उत्पादको को काफी समय से परेशान करती रही है। सयुक्त राज्य में अनाज, गन्ना, पशुओं का चारा, कपास, तम्बाकू, ताजा फल और अन्य कृषि उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में पैदा होते हैं कि देश के ऊँचे जीवन-स्तर को देखते हुए भी वे उसकी अपनी आन्तरिक माँग से काफी अधिक हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अन्य देश इन फालतू उत्पादनो को खरीदने के लिए या तो तैयार नहीं हैं, या उनमें इसके लिए सामर्थ्य नहीं है। पश्चिमी यूरोप में कृषि को काफी समय से अत्यधिक सरक्षण दिया जाता रहा है और यूरोपीय देश बाहर से कृषि-जिन्से सिर्फ उतनी ही मगाते हैं जितनी कि उनकी कमी को पूरी करने के लिए जरूरी है। इससे कुछ मात्रा में वे अन्य देशों से व्यापारिक तरजीह के समझौते के अन्तर्गत लेते हैं और फिर भी अगर कुछ कमी रह जाय तो उनकी पूर्ति के लिए वे अमेरिका से कृषि-जिन्से खरीदने हैं। ममार के अल्प विकसित भाग में, खासकर दक्षिणी एशिया और लैटिन अमेरिका में, अन्न की उपज वहाँ की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। इसलिए उन्हें अनाज आयात करने की बहुत जरूरत पड़ती है ताकि अपनी जनता के अन्न के उपभोग के स्तर को शरीर-धारण के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से ऊँचा उठा सके। कहीं-कहीं तो अन्न की उपज जीवन-यात्रा चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर से भी नीचे रहती है, इसलिए वहाँ अन्न के उपभोग को न्यूनतम स्तर तक पहुँचाने के लिए भी अन्न का आयात आवश्यक हो जाता है। लेकिन इस आवश्यकता के बावजूद ये देश खाद्य पदार्थों का आयात नहीं कर पाते, क्योंकि एक तो उनके पास उसके लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं होती और दूसरे गरीबी के कारण उनकी जनता की क्रय-शक्ति भी इतनी नहीं होती कि वह अन्न खरीद सके।

इसलिए सयुक्त राज्य सरकार बहुत-से अल्प विकसित देशों को मुद्रा के रूप में, उन्हीं की स्थानीय मुद्रा में कीमत लेकर अपनी फालतू

कृषि-जिन्से देती रही है ताकि वे अपनी खाद्यान्न की कमी पूरी कर सकें। हाल में इस कार्यक्रम को 'शान्ति के लिए अन्न कार्यक्रम' के नाम से पुनर्गठित किया गया है और इस कार्यक्रम ने बहुत-से देशों को अपने आहार के स्तर को ऊँचा उठाने में सहायता दी है। लेकिन इन देशों को बहुत बड़ी मात्रा में अमेरिकी कृषि-जिन्से भेजने से अन्य देशों को व्यापारिक आधार पर किये जाने वाले कृषि-जिन्सों के निर्यात में कभी-कभी रुकावट पड़ती रही है और इन देशों में अमेरिका के पास वहाँ की स्थानीय मुद्रा इतनी बड़ी मात्रा में जमा हो गई है कि उसका समुचित उपयोग एक गम्भीर समस्या बन गया है और यह भी आशंका हो गई है कि कहीं इसका प्रभाव मुद्रा-स्फीति को पैदा करने वाला न हो। लेकिन मौजूदा शताब्दी के शेष वर्षों में ससार की आबादी में भारी वृद्धि का जो अनुमान लगाया जा रहा है, उसे देखते हुए अमेरिकी कृषि की असाधारण उत्पादकता मानव समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान सिद्ध हो सकती है। सिर्फ इस समस्या का हल करना आवश्यक है कि इन फालतू अमेरिकी कृषि उत्पादनों का वितरण कैसे किया जाय, यानी जिन लोगों को इन जिन्सों के आयात की बहुत अधिक आवश्यकता है, उनमें उसे खरीदने के लिए जरूरी क्रय-शक्ति कैसे पैदा की जाय। 'शान्ति के लिए अन्न' कार्यक्रम इसी दिशा में एक कदम है, लेकिन आने वाले वर्षों में इस दिशा में इससे भी अधिक प्रगति करनी पड़ेगी।

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आगामी दशक में अमेरिका शेष ससार में अपना निर्यात किस हद तक बढ़ा सकता है, यह कुछ हद तक प्राइवेट व्यवसायियों के क्रिया-कलाप पर और कुछ हद तक उन कार्यक्रमों और नीतियों पर, जिन्हे संयुक्त राज्य की सरकार अमल में लाना चाहेगी या ला सकेगी, निर्भर है। यदि अमेरिकी माल का खासकर कारखानों में निर्मित माल का, निर्यात विश्व के बाजारों की वृद्धि के अनुकूल उचित मात्रा में बढ़ाना है तो अमेरिकी सरकार को अन्य देशों की सरकारों को यह समझाने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करना होगा कि उन्हें डालरो से खरीदे जाने वाले माल के साथ अवशिष्ट

भेदभाव भी खत्म कर देना चाहिए यदि यह सम्भव न हो तो उसे कम अवश्य कर देना चाहिए । देश के भीतर भी, और अन्य देशों के साथ मिलकर भी, ऐसे नये उपाय करने की आवश्यकता है जिनसे कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में होने वाली नई वृद्धि के लाभों में अमेरिका भी समुचित हिस्सा बटा सके और इस व्यापार वृद्धि के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सके ।

प्राइवेट विदेशी निवेश

सन् 1914 से पूर्व ब्रिटिश लोग विदेशों में अपनी पूँजी का जितने बड़े पैमाने पर निवेश करते थे, उतने बड़े पैमाने पर विदेशों में निवेश करने की न तो संयुक्त राज्य के प्राइवेट निवेशकों को कभी आवश्यकता अनुभव हुई और न उनका उस ओर कभी झुकाव ही हुआ । उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश अर्थ-व्यवस्था एक ऐसे स्तर पर पहुँच चुकी थी कि उसका अपना खाद्य और कच्चे माल का आन्तरिक उत्पादन उसकी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकता था । इसलिए ब्रिटिश व्यवसायियों को अपने उद्योगों की ओर फिर अन्य देशों के उद्योगों की भी जरूरतें पूरी करने के लिए विदेशों में इन वस्तुओं की उपलब्धि का विकास करने के लिए पूँजी का निवेश करना पड़ा । इस विदेशी पूँजी-निवेश से लोगों को देश के भीतर पूँजी-निवेश से होने वाले मुनाफे से भी कहीं अधिक मुनाफा कमाने का अवसर नज़र आया । इसका नतीजा यह हुआ कि लन्दन के द्रव्य बाज़ार के रास्ते से न केवल अंग्रेज निवेशकों का, बल्कि अन्य यूरोपीय देशों के धनी लोगों का, पैसा भी विदेशों में निवेश के लिए जाने लगा । उन्नीसवीं शताब्दी में ससार में अपेक्षाकृत अधिक शान्ति थी और ब्रिटेन की विश्वव्यापी नौ सेना इस शान्ति की रक्षा के लिए सर्वत्र विद्यमान थी; इसलिए विदेशों में धन का निवेश करना देश के भीतर निवेश करने से अधिक खतरनाक नहीं समझा जाता था ।

आज अमेरिकी निवेशकों को अपने देश के भीतर ही काफी लाभदायक कामों में अपना धन लगाने के अवसर उपलब्ध हैं और अमेरिकी अर्थ-

व्यवस्था की जरूरतें पूरी करने के लिए विदेशों में कच्चे माल के रूप में काम आने वाली जिन सामग्रियों के स्रोतों को विकसित करने की आवश्यकता है, वे अपेक्षाकृत कम हैं। इनमें कुछ खनिज पदार्थ, कुछ धातुएँ और कुछ कृषि-उत्पादन शामिल हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के भीतर लगाई गई पूंजी विदेशों में लगाई गई पूंजी की अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहती है। युद्ध, क्रान्ति और उग्र राष्ट्रवाद के खतरे और सामान और धन के एक देश से दूसरे देश में जाने पर लगी मौजूदा पाबन्दियाँ प्राइवेट निवेशकों को अपना धन दूसरे देशों में लगाने के लिए निरुत्साहित करती हैं। यद्यपि आज भी अमेरिका का प्राइवेट विदेशी पूंजी-निवेश किसी भी अन्य देश के विदेशी पूंजी-निवेश से बड़ा है तो भी ऐसे देशों की, जो अपने आर्थिक विकास के लिए हाथ-पाँव मार रहे और भारी संघर्ष कर रहे हैं, विदेशी पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिहाज से वह बहुत कम है।

अमेरिका के विदेशी निवेश का सबसे अधिक भाग कनाडा और लैटिन अमेरिका में लगा हुआ है, खासकर उनके पेट्रोलियम और निर्माण उद्योगों में। एक ही जगह यह केन्द्रीकरण इस बात को स्पष्ट सूचित करता है कि इस समय अमेरिकी निवेशकों को विदेशी निवेश के लिए व्यापक प्रोत्साहन नहीं मिल रहा और पश्चिमी गोलार्द्ध में धन का निवेश करना अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित है। अन्यत्र भी अमेरिकी निवेशकों का पूंजी-निवेश मुख्यतः मध्यपूर्व के तेल उद्योग में और पश्चिमी यूरोप के निर्माण में ही केन्द्रित है। सँक्रा बाजार की प्रगति के बाद तो पश्चिमी यूरोप के निर्माण उद्योगों में अमेरिकी पूंजी का निवेश और भी अधिक देखने में आया है।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य सरकार ने अनेक उपायों से अमेरिकी निवेशकों को विदेशों में पूंजी-निवेश करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। उसने इसके लिए लोगों को कर सम्बन्धी विशेष लाभ दिये, उन्हें उनकी पूंजी और लाभ को डॉलर में परिवर्तन करने की गारंटी की और विदेशों में पूंजी लगाने की संभावनाओं और लाभों के बारे में जान-

कारी दी। इसके अलावा सरकार ने अन्य देशों के साथ निवेश-सन्धियाँ भी की, जिनके अन्तर्गत हर देश एक-दूसरे को यह वचन देता है कि वह दूसरे के निवेशक के साथ समान वर्ताव करेगा, उसकी कमाई पर दोहरा कर नहीं लगायेगा और सम्पत्ति की ज़ल्ती या राष्ट्रीयकरण की दशा में पर्याप्त मुआवजा देगा। किन्तु फिर भी इन सन्धियों की संख्या बहुत थोड़ी है।

तालिका 16

विदेशों में सीधी लगी कुल अमेरिकी पूंजी—1960 तक

उद्योग	कनाडा	लैटिन अमेरिका (अरब डालरों में)	पश्चिमी यूरोप	अन्य	कुल	उद्योग की दृष्टि से प्रतिशत
पेट्रोलियम	27	33	17	3.3	10.9	33
खनन और प्रद्रावरण						
उद्योग	13	13	1	3	30	9
निर्माण उद्योग	4.8	1.6	3.8	10	11.2	34
व्यापार	6	.8	7	3	24	8
सार्वजनिक उपयोग की सेवाएँ	6	12	1	7	2.5	8
विविध	1.1	1.1	.3	.2	2.7	8
कुल	11.2	9.2	6.6	5.7	32.7	100
क्षेत्र की दृष्टि से प्रतिशत	34	28	20	18	100	

अन्य देश युद्ध के बाद के प्रारम्भिक काल की अपेक्षा अब प्राइवेट विदेशी निवेशकों के लिए अपने यहाँ अधिक अनुकूल वातावरण पैदा कर रहे हैं। यह बात बहुत-से ऐसे नव-स्वतन्त्र देशों के बारे में खास तौर से 1.5 करोड़ डालर से कम।

सही है जो औपनिवेशिक शासन के अन्तर्गत प्राप्त किये गए दुर्भाग्यपूर्ण अनुभवों और कट्टर राष्ट्रवादी और समाजवादी रुझान के कारण शुरू में प्राइवेट विदेशी निवेशकों को शका की दृष्टि से देखते थे। इस मैत्रीपूर्ण रुख का एक कारण यह है कि उन्हें अपने विकास के लिए पूँजी की बहुत ज्यादा जरूरत है और इसके लिए उन्हें न आन्तरिक स्रोतों से, न अन्य सरकारों से और न ही अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से उसकी पर्याप्त उपलब्धि हो रही है। दूसरा कारण यह है कि बहुत-से अल्प-विकसित देश यह अनुभव करने लगे हैं कि उत्तरदायित्वपूर्ण अमेरिकी लोगों द्वारा किया गया पूँजी-निवेश न केवल आवश्यक पूँजी और तकनीकी एवं प्रबन्ध विषयक ज्ञान की प्राप्ति का कुशल और अच्छा साधन है, बल्कि उसके कार्यों से जनता के एक बड़े भाग के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि हो सकती है। हाल के वर्षों में अमेरिकी कम्पनियों ने अन्य देशों में स्थानीय उद्योगों के विकास को प्रोत्साहित करने, स्थानीय व्यक्तियों को तकनीकी और प्रबन्ध सम्बन्धी प्रशिक्षण देने और उन्हें उच्च पदों पर नियुक्त करने और अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने में जो योग दिया है, उसने अनेक देशों में लोगों के मन से यह भय दूर करने में महत्वपूर्ण सहायता दी है कि अमेरिकी लोग उनका 'शोषण' करेंगे या वे उन पर फिर 'साम्राज्यवाद' को लादना चाहते हैं।

यद्यपि अन्य देशों का रुख अमेरिकी पूँजी को स्वीकार करने के लिए पहले से अधिक अनुकूल है और अमेरिकी सरकार भी अपने प्राइवेट निवेशकों को विदेशों में पूँजी लगाने के लिए प्रोत्साहन दे रही है, तो भी विदेशों में निवेशित प्राइवेट पूँजी वह भूमिका अदा नहीं करेगी, जो उसने उन्नीसवीं शताब्दी में की थी। न केवल प्राइवेट पूँजी का अन्य देशों को निर्यात बहुत कम पैमाने पर हो रहा है, बल्कि प्राइवेट पूँजी आम तौर पर कुछ ऐसे कामों में भी नहीं लग रही जो आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में प्राइवेट विदेशी पूँजी बुनियादी परिवहन सुविधाओं, सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं एवं

स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में लगती थी, परन्तु आज कुछ देशों के मामलों में इस बात की बहुत कम संभावना है कि विदेशी पूँजी इन कामों में लगे। लेकिन कृषि, खनिज उद्योगों, निर्माण-उद्योगों और वितरण व्यवसायों में प्राइवेट विदेशी पूँजी के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए इन सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त मात्रा में विकसित होना जरूरी है।

बीसवीं शताब्दी के मध्य में अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी के प्रवाह को जो काम पूरे करने है, प्राइवेट अमेरिकी विदेशी निवेश, उनका एक अंश ही पूरा कर सकता है। आर्थिक विकास के लिए पूँजी के एक देश से दूसरे देश में प्रवाह को कैसे पर्याप्त उन्नत किया जाय, यह समस्या, संयुक्त राज्य और पूँजी का आयात करने वाले देश, दोनों के लिए अगले दशक की महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक होगी।

वैदेशिक सहायता कार्यक्रम और नीतियाँ

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य की सरकार ने अन्य देशों को लगभग 80 अरब डालर की सहायता दी है ताकि वे अपनी युद्ध-ध्वस्त अर्थ-व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करने, अपनी राष्ट्रीय रक्षा-व्यवस्थाओं को सुधारने और अपनी आर्थिक वृद्धि की गति को तेज करने के लिए जरूरी वस्तुएँ और सेवाएँ खरीद सकें। सरकारी ऋण और अनुदान इसलिए जरूरी थे, क्योंकि वस्तुओं का सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान और पूँजी का सामान्य प्रवाह अनेक देशों को उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं करा सकता था। इसके अलावा, अमेरिकी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सभ की विविध संस्थाओं, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक और अमेरिकी राज्यों का सभ आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी अन्तर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए 5 अरब डालर की राशि दी।

अमेरिकी लोग अपने साथी और मित्र देशों को इतनी बड़ी मात्रा आर्थिक सहायता देने के लिए अनेक कारणों से इच्छुक और उद्यत

रहे हैं। सबसे अधिक स्पष्ट कारण यह है कि अमेरिका जिन देशों को अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण समझता है उनकी अर्थ-व्यवस्थाओं को अस्त-व्यस्त होने से बचाना चाहता है और यह भी चाहता है कि कम्युनिस्ट उन्हें आक्रमण करके जीत न सकें या आन्तरिक पड़यन्त्र से उनमें कम्युनिज्म स्थापित न करा सकें। इस स्वार्थ भावना के साथ यह मानवीय भावना भी मिली रहती है कि ससार में कहीं भी प्राकृतिक या मनुष्य-कृत विपत्तियों में गस्त लोगों की सहायता की जाय और अमेरिका की सम्पत्ति और दक्षता में अल्पविकसित देशों को भी साझेदार बनाया जाय।

जिन यूरोपीय देशों को युद्ध के तत्काल बाद के वर्षों से काफी दूरी अमेरिकी सहायता मिली, उन्होंने 1950 के दशक के शुरू में ही काफी हद तक अपने आपकी आर्थिक दृष्टि से खड़ा कर लिया और आन्तरिक राजनीतिक स्थिरता भी प्राप्त कर ली। लेकिन पश्चिमी यूरोप में उन्नीसवीं शताब्दी की यह धारणा अब समाप्त हो गई है या धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है कि किसी भी राष्ट्र के सफल अस्तित्व के लिए औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्रों में समृद्धता, सैनिक प्रभुत्व, औपनिवेशिक शासन और धार्मिक वर्गों का राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से कमजोर रहना आवश्यक है। द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से वे देश एक नई युनिटाद पर अपने राजनीतिक और आर्थिक जीवन का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। यूरोप में उनके देश परस्पर मिलकर राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अपने साथ बना रहे हैं और अपनी प्रभुशक्तियों में दूसरे देशों को भी शामिल थे रहे हैं और जो देश उन नई व्यवस्थाओं में शामिल हो रहे हैं उनकी सुरक्षा, उत्पादन और मान-मान के स्तर में वृद्धि हो रही है। यूरोप में इस तरह की और भी कई चीजें घटित बनाने में सक्षमता मिलेगी जानती, जो अभी से नहीं जाना जा सकता। सिन्धु इनके परिणाम का अर्थ है कि यूरोप के अर्थ-राजनीतिक समानों के अर्थ-राजनीतिक के लिए निर्धारित होगा। जो कारण है कि संयुक्त राज्य ने इन वर्ग-वर्गों में सारी शक्ति-धर्मों को है और उन्हें अपने वर्गों में प्रोत्साहित भी किया है।

एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक गैर-कम्युनिस्ट देशों का पश्चिमी यूरोपीय देशों से भी कहीं अधिक काया-पलट हो रहा है। पश्चिम के व्यापार और विचारों के संपर्क से ये देश अपने सदियों पुराने सामाजिक और आर्थिक ढाँचे से बाहर निकल आये हैं और अपनी पुरानी जीवन-पद्धति में फिर से लौट जाने के लिए तैयार नहीं हैं। इनमें से कुछ देशों ने अभी हाल में ही स्वाधीनता प्राप्त की है, फिर भी ये सभी देश अपनी आर्थिक अभिवृद्धि की गति तेज करना चाहते हैं ताकि अपनी जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठा सकें। लेकिन अधिकतर अल्प-विकसित देशों से तब तक न तो उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है और न ही जीवन-स्तर को ऊँचा उठाया जा सकता है, जब तक कि उनकी मौजूदा आर्थिक प्रणाली और उनके परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों और सामाजिक संस्थाओं में दूरगामी परिवर्तन न किये जाएँ। किन्तु इस प्रकार के विकासात्मक परिवर्तन न तो आसान हैं और न जल्दी किये जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, इनमें से कई देशों के लिए सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया दो महत्वपूर्ण कारणों से बहुत पेचीदा हो गई है। पहला यह कि सोवियत संघ और कम्युनिस्ट चीन हर सम्भव उपाय से उन पर अपने प्रभुत्व का विस्तार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरा यह कि पश्चिमी चिकित्सा विज्ञान और आर्थिक टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप इन देशों की जनसंख्या में बहुत तेज रफ्तार से वृद्धि हो रही है। अभिप्राय यह है कि इन देशों की प्राकृतिक और अन्य साधन-सम्पदाओं के विकास और उपयोग में इतनी तीव्रता से वृद्धि की जानी चाहिए कि कम्युनिस्ट इन देशों को आक्रमण या आन्तरिक षडयन्त्रों से जीत न सकें और साथ ही उत्पादन उनकी आबादी की वृद्धि से आगे निकल जाय।

इस प्रक्रिया में लगे गैर-कम्युनिस्ट देशों की आबादी सप्ताह की कुल आबादी के आधे के लगभग है और उनके पास पृथ्वी की अछूती प्राकृतिक सम्पदाओं का, जिनका दोहन अभी तक नहीं किया गया, सबसे बड़ा भंडार है। इतने बड़े पैमाने पर होने वाले परिवर्तनों का परिणाम सिर्फ

इन देशों की जनता के लिए ही नहीं, सयुक्त राज्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। अमेरिका की इस प्रक्रिया में सिर्फ इसीलिए दिलचस्पी नहीं है कि भविष्य में वह इनसे कच्चे माल के आयात की आवश्यकता पूरी कर सकेगा। इन देशों के भविष्य में उसकी दिलचस्पी का और भी अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि आज इन देशों और औद्योगिक दृष्टि से काफी उन्नत और अग्रणी देशों की उत्पादकता और रहन-सहन के स्तर में जो भारी अन्तर है, वह इस प्रक्रिया से कम हो जाएगा और अमेरिका इसे बहुत आवश्यक समझता है। यदि दुनिया के कुछ थोड़े-से देश धन-धान्य और सम्पदा से भरपूर हो और बहुसंख्यक देश गरीबी और भारी जनसंख्या की समस्याओं के साथ जूझ रहे हो और उनके बीच की यह खाई बराबर अधिकाधिक चौड़ी होती जाय तो ऐसी दुनिया में कोई भी नई राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती।

इसीलिए यूरोपीय राष्ट्रों और अल्पविकसित देशों में जो कायाकल्प चल रहे हैं, उनमें सयुक्त राज्य की गहरी दिलचस्पी है। आशा है कि ये कायापलट पश्चिमी समाज के, खासकर सयुक्त राज्य के लोकतन्त्र के अस्तित्व और प्रगति के लिए खतरा सिद्ध नहीं होंगे। इसका अर्थ यह नहीं है कि अन्य देश अमेरिकी समाज के विशिष्ट मूल्यों और संस्थाओं को अपना लेंगे। अमेरिकी लोगों के लिए दूसरों को यह आदेश देना कि वे किस प्रकार की आर्थिक और सामाजिक प्रणालियाँ अपनायें, न तो व्यावहारिक दृष्टि से सम्भव है और न नैतिक दृष्टि से उचित ही। बल्कि आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि इन नये उभरते समाजों के रख और उनकी नव-विकसित संस्थाएँ इस प्रकार की हो कि अमेरिकी समाज से सर्वथा भिन्न होते हुए भी अमेरिकी लोगों का उनके साथ शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व सम्भव हो और वे परस्पर व्यापार कर एक-दूसरे को लाभ पहुँचा सकें और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं के हल के लिए आपस में सहयोग कर सकें।

ससार-भर के देशों में इस समय जो नये रख और नई संस्थाएँ

विकसित हो रही है वे उनकी जनता द्वारा अपनी राजनीतिक और आर्थिक सामर्थ्य और सांस्कृतिक सम्भावनाओं की सीमाओं के भीतर रहते हुए स्वयं निर्धारित की जानी चाहिए। इन बातों को दृष्टि में रख कर यदि तोला जाय तो परिमाण की दृष्टि से अमेरिका की वैदेशिक आर्थिक गति-विधि का महत्त्व बहुत सीमित है। फिर भी दो दृष्टियों से उसकी बहुत अधिक अहमियत भी है।

पहली यह कि अमेरिका की वैदेशिक आर्थिक गति-विधि इन देशों के वित्तीय और तकनीकी साधनों को बढ़ाती है, जो मात्रा में स्वल्प होने पर भी उनके आर्थिक विकास कार्यक्रमों की सफलता या असफलता पर निर्णायक प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरी यह कि ये वैदेशिक आर्थिक गति-विधियाँ अमेरिका में तथा अन्य देशों में अमेरिकी और अन्य लोगों के लिए ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करती हैं जिनमें वे परस्पर मिलकर रचनात्मक ढंग से वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में रह सकते हैं और यह बात दोनों के लिए बहुत अर्थयुक्त और महत्त्वपूर्ण है। विभिन्न जातियों और ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों वाले लोगों का दैनन्दिन और व्यावहारिक जीवन में अनवरत रूप से साथ रहना एक ऐसा सर्वोत्तम और सम्भवतः एकमात्र उपाय है जिससे पारस्परिक विश्वास और एक-दूसरे को समझने के और एक-दूसरे के ज्ञान को अपनाने के मौके मिलते हैं और सांस्कृतिक बाधाओं की परवाह किये बिना एक-दूसरे की तकनीकों को स्वेच्छा से सीखने के अवसर उपलब्ध होते हैं। इस तरीके से, अमेरिकी लोग शासन और अर्थ-व्यवस्था दोनों में कार्यरत लोकतन्त्र की एक मिसाल पेश कर सकते हैं।

इन देशों का आर्थिक विकास और सामाजिक कायाकल्प आसानी से नहीं किया जा सकता और न शीघ्रता से पूरा किया जा सकता है। इसलिए यह सम्भव है कि इस प्रक्रिया में अमेरिका काफी समय तक दिलचस्पी और हिस्सा लेता रहे। जरूरत इस बात की है कि संयुक्त राज्य की वैदेशिक आर्थिक गति-विधि को अमेरिका की परराष्ट्र नीति । एक अविच्छिन्न और अविभाज्य अंग समझा जाय और यह माना

जाय कि उसका उद्देश्य केवल तात्कालिक खतरों को रोकना ही नहीं, बल्कि कुछ दीर्घकालिक ठोस लक्ष्यों का प्राप्त करना है।

विकास की समस्याओं और भावी सम्भावनाओं को अधिक अच्छी तरह हृदयंगम किये जाने के कारण ही सन् 1961 में संयुक्त राज्य के वैदेशिक सहायता कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। उसके लक्ष्यों, उपायों और प्रशासन में परिवर्तन किये गए। अमेरिका यह स्वीकार करता है कि आर्थिक अभिवृद्धि और सामाजिक परिवर्तन, दोनों विकास की समूची प्रक्रिया के अनिवार्य हिस्से हैं, इसलिए उसके वैदेशिक सहायता कार्यक्रम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को कृषि-सुधार करने, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को ऊँचा उठाने, शहरी और देहाती में अच्छी आवास-व्यवस्था करने, कर-प्रणाली को अधिक न्यायपूर्ण और प्रगतिशील बनाने, मजदूरों और मालिकों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने और अन्य सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। सहायता प्राप्त करने वाले देशों के लिए अब दोनों दृष्टियों से कार्यक्रम बनाये जाते हैं—एक ओर उनके दीर्घकालिक उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं और दूसरी ओर स्वल्पकालिक कार्यक्रमों को अच्छी तरह चलाने के लिए धन का समुचित विभाजन किया जाता है। मार्शल-योजना की भाँति अब भी कार्यक्रम निर्माण की यह पद्धति पुनः एक बुनियादी पद्धति के रूप में अपना ली गई है। वैदेशिक सहायता सम्बन्धी विभिन्न कार्यों को विभिन्न संगठनों के द्वारा चलाने की नीति को हाल में बदल देने के कारण एक नई अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट) स्थापित की गई है जिसमें इन सब विभिन्न संगठनों के कार्यों का समावेश कर दिया गया है। अब यह एजेंसी ही परराष्ट्र विभाग की देखरेख में वैदेशिक विकास सहायता का सारा काम करती है। कांग्रेस ने इस नये संगठन को यह अधिकार दे दिया है कि वह इन देशों के विकास कार्यक्रमों के लक्ष्यों की पूर्ति को आसान बनाने के लिए दीर्घ-कालिक सहायता के वायदे कर सकता है।

यदि कांग्रेस इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त

राशि मजूर करने को तैयार हो और अमेरिकी जनता भी इस कार्यक्रम को समग्र रूप से अपना समर्थन प्रदान करती रहे तो ये परिवर्तन आगामी वर्षों में अमेरिकी वैदेशिक सहायता के कार्य-कलापों को काफी हद तक प्रभावकारी बना देंगे । लेकिन यह कार्य बहुत विशाल है और अमेरिका इसमें जो योग दे रहा है वही अकेला इसे सफल बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है । पश्चिमी यूरोप के देश, जापान और अन्य राष्ट्र भी आर्थिक और सामाजिक विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कुछ इलाकों में काफी बड़े पैमाने पर सहायता दे रहे हैं । विकसित देशों के इन प्रयत्नों को काफी बढ़ाना और समन्वित करना होगा, तभी अगले दस वर्षों में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को दी गई कुल सहायता वास्तव में कुछ प्रभावकारी रूप धारण कर सकेगी ।

सयुक्त राज्य का अदायगी सन्तुलन और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की सभी वैदेशिक गति-विधियों—व्यापार, पूंजी-निवेश और सहायता—के लिए अमेरिका और अन्य देशों के बीच मुद्रा का अनेक प्रकार का आदान-प्रदान होता है । मुद्रा के इस सारे आदान-प्रदान को संक्षेप में अदायगी सन्तुलन के व्योरे में दिखाया गया है । इसमें शेष ससार के साथ अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का सम्बन्ध एक नजर में देखा जा सकता है । वह इस सम्बन्ध में आने वाले उतार-चढ़ावों को देखने के लिए एक थर्मामीटर का भी काम दे सकता है । इससे यह पता चल सकता है कि कैसे समय-समय पर अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था और शेष ससार की अर्थ-व्यवस्था के बीच अदायगी के प्रवाह में कभी तो बहुत-बड़ा नफा हुआ और कभी घाटा ।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद से आम तौर पर अमेरिका के व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं के वैदेशिक व्यापार में सन्तुलन अमेरिका के पक्ष में ही रहा, अर्थात् उसने अन्य देशों को ये वस्तुएँ और सेवाएँ दी अधिक और उनसे ली कम । इसी तरह सन् 1940 में अमेरिका द्वारा अन्य देशों

में प्राइवेट पूंजी का निवेश पुनः प्रारम्भ किये जाने के बाद से आम तौर पर अमेरिकी निवेश के लिए विदेशों में सरकारी पूंजी अधिक गई पर उम्र पर होने वाली आय अमेरिका में कम आयी।¹ यही स्थिति विदेशों में गई प्राइवेट अमेरिकी पूंजी के बारे में भी है। हालांकि उसकी मात्रा कम है पर अब वह धीरे-धीरे बढ़ रही है (देखिए परिशिष्ट तालिका 17 और 18)। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने अपने सभी प्रकार के सरकारी वैदेशिक सहायता कार्यक्रमों और अन्तर्राष्ट्रीय नगठनों के कार्यों में समय-समय पर दिये गए आर्थिक योगदान की शक्ति में काफी बड़ी रकमों की विदेशों को अदायगी की।

1940 के दशक में संयुक्त राज्य का अदायगी सन्तुलन उसके अपने पक्ष में था, क्योंकि अन्य देशों का अमेरिकी माल का आयात अमेरिका को किये गए उनके निर्यात के मूल्य से और अमेरिकी सहायता के रूप में प्राप्त रकमों में अधिक था। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक देशों को अमेरिका के साथ अपना लेन-देन का हिस्सा निवटाने के लिए अपने स्वर्ण और डॉलर के सुरक्षित कोष की सहायता लेनी पड़ी, जिससे उनका अर्थ-तन्त्र मोला संयुक्त राज्य के स्वर्ण कोष में आ गया। मई 1949 में संयुक्त राज्य का स्वर्ण कोष बढ़कर 24 अरब डॉलर का हो गया। मार्शल-योजना के दिनों में और मई 1950 में अन्य विकसित देशों को अमेरिका द्वारा आर्थिक सहायता प्रारम्भ की जाने पर अमेरिका के भुगतान सन्तुलन में कुछ मामूली-सा घाटा उत्पन्न हुआ और अमेरिकी लेन-देन की उसकी मात्रा में बढ़ गई। इसका परिणाम यह हुआ कि बहुत-से यूरोपीय देश अमेरिका से लेना और डॉलर खरीद कर अपना स्वर्ण एवं

तालिका 17

संयुक्त राज्य का अदायगी सन्तुलन, 1956-1960 (लाख डालरों में)

	कैलेंडर वर्ष			
	1956	1957	1958	1959 ¹ 1960
क. अमेरिकी सरकार के लेनदेन,				
1. सैनिक कार्यक्रम	-26560	-26540	-29730	-26530 -25180
2. आर्थिक सहायता कार्यक्रम	-5350	-8660	-8950	-7060 -8470
3. व्याज और मूल की वसूली	+6730	+8640	+8510	+13590 +9510
4. अमेरिकी सरकार के अन्य लेन देन	-5260	-5520	-4770	-7890 -7070
	-30420	-32080	-34940	-27890 -31210
ख. प्राइवेट अमेरिकी लेनदेन	+22420	+36130	+9260	-14040 +20050
1 व्यापार				

वसूली	+6730	+8640	+8510	
4. अमेरिकी सरकार के अन्य, लेन देन	—5260	—5520	—4770	—7890
	—30420	—32080	—34940	—27890
ग. प्राइवेट अमेरिकी लेन देन 1. व्यापार	+22420	+36130	+9260	—14040
				+20050

2. प्राइवेट पूंजी और

आय

—5730 —4990 —2290 +4010 —6100

3. अन्य सब प्राइवेट

अमेरिकी लेन देन

—7680 —5570 —10840 —13650 —15320

+9010 +25670 —3870 —23680 —1370

ग. अमेरिकी सरकार की

सिख्योरिटियो को छोड़कर

अन्य रूपों से अमेरिका में

लगी विवेकी पूंजी

+5300 +3610 +240 +5480 +3270

घ. भूल-बूक

+6430 +7480 +3800 +7830 +9050

ड. कुल घाटा (+अधिशेष)

—9680 +4680 —34770 —38260 —38360

1. इसमें 1959 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि में अमेरिका द्वारा दी गई 13750 लाख डालर की राशि शामिल नहीं है।

से काफी मात्रा में सोना बाहर जाने लगा है।

तालिका 17 में सन् 1956 से 1960 तक के वर्षों में अमेरिका के अदायगी सन्तुलन की स्थिति संक्षेप में दिखायी गई है। (इन पाँच वर्षों की अदायगियों का विस्तृत व्यौरा परिशिष्ट तालिका 19 में देखा जा सकता है)।

ये दोनों तालिकाएँ इस ढंग से बनाई गई हैं कि उनमें व्यापार और सामान्य प्राइवेट आर्थिक गति-विधि के फलस्वरूप होने वाली अदायगियों को संयुक्त राज्य सरकार के आर्थिक क्रियाकलापों और कार्यक्रमों के फलस्वरूप की जाने वाली अदायगियों से अलग करके दिखाया गया है। इस तरीके से यह हिसाब आसानी से लगाया जा सकता है कि हाल के वर्षों में विभिन्न किस्मों के सरकारी और गैर-सरकारी लेन-देन में अमेरिका को कितना बड़ा घाटा रहा है। यह कथन, कि अमेरिका के अदायगी सन्तुलन में घाटा पूर्णतः या मुख्यतः वैदेशिक सहायता कार्यक्रमों का परिणाम है, विवाद का विषय है, क्योंकि वैदेशिक सहायता से अन्य देशों में अमेरिकी धन जाता है, बल्कि उससे अमेरिका के व्यापारिक निर्यात में भी वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त सन् 1960 में आर्थिक सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत घाटा, जैसा कि तालिका 17 में दिखाया गया है, अदायगी सन्तुलन के कुल घाटे के एक चौथाई से भी कम है।

हाल के वर्षों में अमेरिका से सोने की जो निकासी हुई है, उसके बावजूद, संयुक्त राज्य के सुरक्षित मुद्रा कोष इतने बड़े हैं कि 1950 के दशक के प्रारम्भ में अमेरिका के अदायगी सन्तुलन में जो छोटा-सा घाटा हम देखते हैं, वैसे घाटे चिन्ता का कारण नहीं है। लेकिन 1958 से 1960 तक लगातार जो भारी घाटा दिखायी देता है, वैसे घाटा अवश्य चिन्ता का कारण है और केवल संयुक्त राज्य के लिए ही नहीं, उसके साथी और मित्र देशों के लिए भी, खास तौर से इसलिए कि बुनियादी कठिनाइयों के प्रभाव अक्सर अस्थायी सट्टेबाजी की गति-विधियों से बढ़ जाते हैं।

केवल अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के देश की आन्तरिक स्थिति के पहलू

से देखा जाय तो लगातार इतनी बड़ी मात्रा में घाटा होना इस बात का संकेत है कि आन्तरिक आर्थिक परिस्थितियों और वैदेशिक आर्थिक परिस्थितियों के बीच सन्तुलन और समन्वय बिगड़ गया है। इस प्रकार का असन्तुलन आम तौर पर इसलिए होता है कि देश का लागत और मूल्यों का आन्तरिक स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर से मेल नहीं खाता। इन दोनों स्तरों में मेल के अभाव का कारण या तो स्वल्पकालिक व्यापारिक उतार-चढ़ाव का चक्र होता है या व्यावसायिक ढाँचे में होने वाले दीर्घकालिक परिवर्तन या दोनों। इनमें से जो भी कारण हो, उसको दृष्टि में रखकर समय-समय पर आने वाले इन व्यापारिक चक्रों को रोकने की कार्रवाई करके, या उत्पादकता में वृद्धि कर और अर्थ-व्यवस्था के ढाँचे में परिवर्तन कर, या राष्ट्रीय मुद्रा की विनिमय-दर में परिवर्तन कर या इसी प्रकार के अन्य कदम उठाकर तालमेल के इस अभाव का इलाज किया जा सकता है। इसके लिए कब, ठीक कौन-सा कदम उठाया जाय, इसका चुनाव इस बात को दृष्टि में रखकर किया जा सकता है कि कब कौन-सी बात आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से सम्भव और व्यवहार्य है।

लेकिन कोई भी देश, खासकर अमेरिका, अदायगी सन्तुलन में लगातार घाटा बना रहने पर केवल आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से ही चिन्तित नहीं होगा। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली और उसमें संयुक्त राज्य के डालर की विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए संयुक्त राज्य इस प्रकार के असन्तुलन को रोकने के लिए जो भी कार्रवाई करेगा उसकी एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया अग्रज्य होगी। यही कारण है कि संयुक्त राज्य एक सीमा तक ही ये कार्रवाइयाँ कर सकता है और वह भी कुछ खास किस्म की ही। इसमें जो समस्याएँ उलझी हुई हैं उनको समझने के लिए वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की मुख्य-मुख्य विशेषताओं पर संक्षेप में विचार करना जरूरी है।

प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों के मध्यमवर्ती काल से अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में जो मुद्रा-प्रणाली रही है उसे स्वर्ण या विनिमय प्रणाली अथवा मुख्य मुद्राओं वाली प्रणाली (की करैन्सी सिस्टम) कहा जा सकता

है। इसका अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें सब देश अपनी अदा-यगी सन्तुलन के आखिरी वचत या घाटे के लेन-देन का निवटारा या तो सोना ले-दे कर या ऐसी मुद्राएँ ले-देकर करते हैं जिनकी सारे संसार में माँग होती है और जिन पर सरकारों और व्यापारियों दोनों को भरोसा होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से संयुक्त राज्य का डालर, और कुछ हद तक पौंड स्टर्लिंग मुख्य मुद्राएँ रही हैं। दूसरे देश एक-दूसरे के साथ या संयुक्त राज्य और ब्रिटेन के साथ अपने अन्तर्राष्ट्रीय हिसाब-किताब को निवटाने के लिए इन मुद्राओं का इस्तेमाल करते हैं और अपने सुरक्षित मुद्रा-कोषों का कुछ भाग अपने केन्द्रीय बैंकों में या न्यूयार्क और लन्दन के बैंकों में इन मुद्राओं की शक्ल में जमा रखते हैं। इसी प्रकार संसार-भर के प्राइवेट बैंकर और व्यापारी फर्मों भी, खास कर वे जो अन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन करते हैं, या तो इन मुद्राओं की अपनी अव-शिष्ट और अप्रयुक्त रकमों को बैंकों में जमा कर देते हैं या न्यूयार्क और लन्दन में छोटी मियाद की सरकारी हुण्डियों में लगा देते हैं।

मुख्य मुद्राओं वाली यह प्रणाली उन्नीसवीं शताब्दी की स्वर्ण-मान प्रणाली का परिणाम है। स्वर्ण-मान प्रणाली उन्नीसवीं शताब्दी के बाद भी काफी समय तक जारी रही, हालांकि वह कुछ कमजोर पड़ गई थी। लेकिन सन् 1931 में जब ब्रिटेन ने पौंड स्टर्लिंग की सोने में स्वतः परिवर्तनीयता का परित्याग कर दिया तो वह प्रणाली खत्म हो गई। स्वर्ण-मान प्रणाली के अन्तर्गत सभी अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी सन्तुलनों का निवटारा, सिद्धान्ततः, सोने में किया जाता था और किसी भी देश के सुरक्षित मुद्रा कोष में उसके सुरक्षित सोने की मात्रा ही गिनी जाती थी। लेकिन व्यवहार में सब अदायगी सन्तुलनों का निवटारा मुद्राओं में, विशेषतः पौंड स्टर्लिंग में किया जाता था, क्योंकि वह इच्छानुसार और निर्बाध रूप से सोने में परिवर्तित किया जा सकता था।

दोनों विश्व युद्धों के मध्यवर्ती काल में स्वर्ण-मान प्रणाली में संशोधन दो कारणों से किया गया। पहला यह कि विश्व के व्यापार में इतनी अधिक वृद्धि हो गई थी कि स्वर्ण-मान प्रणाली उसकी

आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती थी। अभिप्राय यह कि दोनों युद्धों के मध्यवर्ती काल में विश्व का व्यापार तो बहुत अधिक बढ़ गया किन्तु सोने की उपलब्धि इतनी नहीं हुई कि उससे अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी संतुलन को निबटाया जा सके।

इसका दूसरा कारण और भी अधिक बुनियादी था। स्वर्ण-मान जब तक जारी रहा, तब तक सब देशों को अपने अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी संतुलन के निबटारे के लिए सोना देना पड़ता था। इसका असर यह होता था कि उनपर स्वतः एक लगाम लगी रहती थी जिससे उन्हें अपनी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्थाओं को अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के अनुकूल रखना पड़ता था ताकि अन्य देशों के साथ उनके लेन-देन में असंतुलन न हो। वे अपनी आन्तरिक आर्थिक नीतियाँ मनमाने तौर पर निर्धारित नहीं कर सकते थे। जिस देश के अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी संतुलन में बहुत घाटा रहता था, उसे उसकी पूर्ति के लिए सोना देना पड़ता था। इससे उस की मुद्रा की पुश्त पर सोना कम हो जाता और फलस्वरूप वह पर्याप्त मुद्रा जारी नहीं कर सकता था। मुद्रा के अभाव में व्याज-दरें बढ़ जातीं, आन्तरिक व्यापार कम हो जाता और कीमतें और रोजगार में भी कमी आ जाती। लेकिन आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था की दृष्टि से ये सब बातें चाहे जितनी अप्रिय हों, उनसे वैदेशिक अदायगी का असंतुलन अवश्य ठीक हो जाता, क्योंकि अन्य देशों की मुद्रा (व्याज की दर अधिक होने के कारण) उसमें खिच आती, (कीमतें कम होने से) निर्यात बढ़ जाता और (आन्तरिक माँग कम हो जाने से) आयात घट जाता।

यह ठीक है कि उन्नीसवीं शताब्दी में जो स्वर्ण-मान प्रणाली प्रचलित थी उससे विदेशी व्यापार और लेन-देन के असंतुलन का स्वतः इलाज हो जाता था किन्तु उसके लिए समृद्ध देश को कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती थी। उसकी आन्तरिक आर्थिक गति-विधि कम हो जाती थी और उससे बेरोजगारी बढ़ जाती थी। इसलिए बीसवीं शताब्दी के शुरू के दशकों में ससार के अनेक बड़े लोकतन्त्रीय राष्ट्रों ने इस प्रणाली को राजनीतिक दृष्टि से अस्वीकार कर दिया। एक देश के बाद दूसरे

देश में एक ओर पूर्ण वयस्क मताधिकार प्रणाली प्रचलित हो रही थी और दूसरी ओर साथ ही यह विचार भी दृढ़ता से जड़ें जमाता जा रहा था कि जनता की आर्थिक सुरक्षा और सामान्य कल्याण का स्तर काफी ऊँचा उठाया जाना चाहिए। इसके अलावा सन् 1914 के बाद दो विश्व युद्धों और उनके मध्यवर्ती काल में आई भारी मन्दी ने सब देशों की सरकारों पर इस बात की जिम्मेदारी बढ़ा दी कि वे अपने वित्तीय साधनों को संगठित करें और खास-खास राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए उनका बंटवारा करें। इस प्रकार राष्ट्रीय सरकारों के लिए धीरे-धीरे यह असम्भव हो गया कि वे अपने आपको अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की ताकतों के प्रभाव और स्वर्ण-मान के कठोर नियन्त्रण की कैद में रखते हुए अपने देश के रोजगार के स्तर, राष्ट्रीय आय के वितरण और रहन-सहन के स्तर को एक सीमा के भीतर ही बनाये रखें। इसलिए सबसे पहला बड़ा परिवर्तन इस मान्यता को अपना कर लिया गया कि केवल सोना-चाँदी आदि कोई ठोस वस्तु ही किसी देश की मुद्रा का आधार नहीं होनी चाहिए। परिणाम यह हुआ कि एक के बाद एक अधिकाधिक देश अपनी मुद्रा को प्रत्येक आधार (फिड्यूशियरी बेसिस) पर प्रचलित करने लगे। इसका अभिप्राय यह कि मुद्रा जारी करने के लिए सोना या चाँदी को उसकी पुष्ट पर रखना जरूरी न मान कर सरकारें अन्य रूपों में अपनी साख (प्रत्यय) के आधार पर मुद्रा का प्रचलन करने लग गईं। इससे वे मुद्रा और उधार के परिमाण, व्याज की दर और सरकार के व्यय के स्तर पर अधिक नियन्त्रण करने की स्थिति में आ गईं। इसका नतीजा यह हुआ कि आन्तरिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्वर्ण-मान प्रणाली के कठोर प्रतिबन्धों के बजाय सामाजिक दृष्टि से अधिक स्वीकरणीय तरीके अपनाना सम्भव हो गया।

दोनों विश्व युद्धों के मध्यवर्ती काल में मुख्य मुद्राओं के द्वारा विनियम की जो प्रणाली अपनाई गई वह वास्तव में आन्तरिक क्षेत्र में अपनाई गई प्रत्येक मुद्रा प्रणाली (फिड्यूशियरी मॉनोटेरी मैकेनिज्म) का ही अन्तर्राष्ट्रीय रूप थी। इससे अन्तर्राष्ट्रीय अंदायगी सन्तुलनों के

निवटारे के लिए मोने का सहारा लेने के बजाय, जिसकी उपलब्धि पर्याप्त नहीं थी, डालर और पीड स्टर्लिंग के द्वारा उनका निवटारा करने की अधिक सरल और सुविधाजनक व्यवस्था मिल गई, राष्ट्रों के सुरक्षित मुद्रा कोषों में केवल सोना रखने के बजाय डालर और पीड स्टर्लिंग जमा करने की आसानी हो गई और राष्ट्र के अन्तर्राष्ट्रीय हिसाब-किताब के असन्तुलन को दूर करने के लिए अधिक लचीली विधियाँ उपलब्ध हो गईं। लेकिन उन दो देशों (ब्रिटेन और संयुक्त राज्य) के लिए कुछ समस्याएँ भी उठ खड़ी हुईं, जिनकी मुद्राओं का सहारा इसके लिए लिया जाने लगा।

ऐसे भीके बहुत कम रह गए जब कि इन दोनों मुख्य मुद्राओं की उपलब्धि और माँग में उचित सन्तुलन रहता हो। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि प्रायः सभी देशों की डालर की माँग बहुत बढ़ गई और यह माँग इतनी बढ़ी कि ये देश न अपने वैदेशिक व्यापार में हुई कमाई से, न अपने निजके सुरक्षित मुद्रा कोष से और न सरकारों या गैर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से ऋण लेकर उनकी पूर्ति कर सकते थे। ऐसी स्थिति में संयुक्त राज्य सरकार के वैदेशिक महायन्त्रा अनुदानों और ऋणों ने इन देशों की, खासकर पश्चिमी यूरोप के देशों की, जाकर की उस कमी को दूर करने और उनके आयात के स्तर को बनाये रखने में काफी सहायता दी।

लन्दन के सोने के बाजार में उसका भाव 35 डालर प्रति औंस के अधिकृत भाव से (जिस पर संयुक्त राज्य का कोप विभाग अन्य देशों की सरकारों के माँग करने पर चाहे जितने डालरों के बदले में सोना दे देता है) ऊँचा चला जाता है। उदाहरण के लिए अक्टूबर, 1960 में जब संयुक्त राज्य के अदायगी सन्तुलन में बहुत बड़ा घाटा हो गया तो डालर का मन्दी का सट्टा होने लगा और व्यापारियों और बैंकों को अपने पास जमा डालरों की भारी मात्रा की सुरक्षा के बारे में आशकाएँ होने लगी जिससे उनमें डालरों को सोने में बदलवाने की खलबली मच गई और बाजार में सोने का भाव 40 डालर प्रति औंस तक पहुँच गया। इस खलबली के कारण यूरोप के अनेक केन्द्रीय बैंक संयुक्त राज्य के कोप विभाग से अपने डालरों को सोने में बदलवा कर अपने डालर कोप कम करने लगे। इससे संयुक्त राज्य से बहुत-सा सोना बाहर चला गया।

पीड स्टर्लिंग को, जो दूसरे दर्जे की मुख्य मुद्रा है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी कठिनाइयों का अनेक बार सामना करना पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन के अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी सन्तुलन में बार-बार घाटा आता रहा। ऐसे मौकों पर अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, अन्य देशों की सरकारों और उनके केन्द्रीय बैंकों को बैंक ऑफ इंग्लैंड को सफटकालीन सहायता देनी पड़ी ताकि वह स्टर्लिंग को अन्य मुद्राओं में परिणत करने के लिए की जाने वाली माँगों को पूरा कर सके।

इस प्रकार युद्धोत्तर काल का अनुभव यह रहा है कि ये मुख्य मुद्राएँ कभी तो बेहद कम हो गईं और कभी बहुत ज्यादा, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के निर्विघ्न चलने में काफी बाधा आई। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि, जिसकी सर्वप्रथम कल्पना 1944 में ब्रिटेन बुड्स सम्मेलन में की गई थी, इस मुख्य-मुद्रा प्रणाली की खामियों को दूर करने का साधन मानी जाती है। इस निधि के अन्य कामों में से एक काम यह है कि वह उन देशों को डालर दे, जिनके पास अपनी अन्तर्राष्ट्रीय देनदारियों को पूरा करने के लिए उसकी पर्याप्त मात्रा नहीं है। वह कुछ खास परिस्थितियों में सोना भी उन देशों को दे सकती

है। यदि ब्रिटेन और संयुक्त राज्य पर स्टर्लिंग और डॉलर को सोने या अन्य मुद्राओं में परिवर्तित करने की माँग का इतना अधिक दबाव पड़े कि वे कठिनाई में पड़ जाएँ तो यह निधि उनकी भी सहायता कर सकती है। लेकिन 1959-60 में संयुक्त राज्य से बहुत बड़ी मात्रा में और काफी अधिक समय तक सोना बाहर जाने पर भी संयुक्त राज्य सरकार ने उससे कोई सहायता नहीं माँगी। इसके मुकाबले में ब्रिटेन ने युद्धोत्तर काल के स्टर्लिंग पर बार-बार सिकट आने पर निधि से काफी सहायता ली। निधि इन कार्यों को पूरी तरह से निभा सके, इसके लिए हाल के वर्षों में अनेक बार उसके मुद्रा कोष में वृद्धि करनी पड़ी। अभी हाल में 1961 में भी उस निधि के मुद्रा कोष को बढ़ाने की जरूरत पड़ी, जब कि डॉलर और स्टर्लिंग पर सटोरियों का दबाव पड़ने के कारण मुख्य मुद्राओं वाले देशों की सहायता के लिए पूरक ऋणों की व्यवस्था की गई।

यद्यपि अधिकतर राष्ट्रों की सरकारें और उनके केन्द्रीय और प्राइवेट बैंक मौजूदा मुख्य-मुद्रा प्रणाली को पसन्द करते हैं तो भी पिछले कुछ वर्षों में इस प्रणाली की दो प्रकार की आलोचनाएँ की जाती रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बैंक व्यवसायियों के अधिक अनुदार वर्ग का कहना है कि इस प्रणाली के परिणामस्वरूप राष्ट्रों को अपने वैदेशिक अदायगी सन्तुलन को ठीक करने के लिए अपनी राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों में परिवर्तन की बहुत अधिक छूट मिल जाती है। दरअसल, यह वर्ग चाहता है कि स्वर्णमान प्रणाली फिर से लागू कर दी जाय ताकि उससे सब देश स्वतः नियन्त्रण में रहें और जब भी किसी देश को काफी समय तक और काफी बड़े अदायगी असन्तुलन का सामना करना पड़े तो वह मजबूरन अपनी अर्थ-व्यवस्था को संकुचित कर दे।

मुख्य-मुद्रा प्रणाली की आलोचना करने वाले दूसरे वर्ग का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि से पूरक सहायता मिलने पर भी अदायगी के लिए नकदी की समस्याएँ अन्ततः अनिवार्य हैं। इस वर्ग का कथन है कि सोने का उत्पादन विश्व के व्यापार की तुलना में मन्द गति से

बढ़ा है और आगे भी मन्द गति से ही बढ़ेगा। इसलिए मुख्य मुद्राओं को और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा दी जाने वाली पूरक सहायता को अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी सन्तुलन में अधिकाधिक हिस्सा लेना पड़ेगा और इन दोनों में से कोई भी वह सहायता पर्याप्त रूप में नहीं दे सकता, जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की जरूरतों को पूरा कर सके। इसके अलावा इन आलोचकों को यह भय भी है कि इन मुद्राओं पर शायद बहुत गम्भीर सकट आये और उन पर से लोगों का विश्वास उठने की और भी अधिक गम्भीर घटनाएँ घटे। उस दशा में इन दोनों देशों के सुरक्षित मुद्रा कोषों पर इतना दबाव पड़ सकता है कि वह सभाले न सभले।

इसके साथ ही यह सम्भावना भी है कि यदि इन दोनों देशों के सामने डालर और स्टर्लिंग पर लोगों का विश्वास बनाये रखने की सभावना बहुत गम्भीर रूप धारण करके आये तो उनके लिए अपनी आन्तरिक अर्थ-व्यवस्थाओं को सुधारने के बहुत कम उपाय रह जाएँ और उन्हीं थोड़े-से उपायों में से कुछ को उन्हें चुनना पड़े और उसका परिणाम उनके लिए अच्छा न हो। ब्रिटेन के बारे में यह बात सही सिद्ध भी हो चुकी है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उसकी आर्थिक अभिवृद्धि की मन्द गति का कारण कुछ अंश तक यह था कि उसे समय-समय पर आन्तरिक पूँजी-निवेश को सीमित करना पड़ा और उपभोक्ताओं की माँग पर भी अकुश लगाना पड़ा ताकि स्टर्लिंग में लोगों का विश्वास बनाये रखने के लिए वह अपने निर्यात को बढ़ा और आयात को घटा सके। दोनों विश्व युद्धों के मध्यवर्ती काल में भी ब्रिटिश लोग स्टर्लिंग को एक मुख्य मुद्रा बनाये रखने के लिए काफी बड़ी बेरोजगारी और जीवन-स्तर की अभिवृद्धि के अभाव के रूप में उसकी कीमत चुकाने को तैयार थे। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद वे इसके लिए राजी नहीं हुए और उन्होंने अपने जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की, कोशिश की जिसका नतीजा यह हुआ कि बीच-बीच में स्टर्लिंग मुद्रा कमजोर होती रही। जहाँ तक अमेरिकी लोगों का

सम्बन्ध है, अगर उन्हें डालर को एक मुख्य मुद्रा बनाये रखने के लिए अपनी अर्थ-व्यवस्था और अपने जीवन-स्तर की अभिवृद्धि को रोकना पड़े तो वे उसके लिए ब्रिटिश लोगो से भी कम राजी होंगे। लेकिन अगर उसका अर्थ देश के भीतर मुद्रा-संकोच और बेरोजगारी मे वृद्धि हो तो वे उसके लिए और भी कम राजी होंगे, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार मे डालर की साख को बचाने के लिए इन उपायो से भी अधिक महत्वपूर्ण और सामाजिक दृष्टि से स्वीकरणीय उपाय मौजूद है (उदाहरण के लिए, उत्पादकता मे और निर्यात उद्योगो की कार्यकुशलता मे वृद्धि)।

इसलिए मुख्य-मुद्रा-प्रणाली के बजाय किसी अन्य ऐसी प्रणाली को अपनाने के लिए, जिसमे ये खतरे और नुकसान कम हो या बिलकुल न हो, अनेक सुझाव दिये गए हैं। इनमे सबसे अधिक प्रसिद्ध येल विश्व-विद्यालय के प्रोफेसर राबर्ट ट्रिफिन का यह सुझाव है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षित मुद्रा प्रणाली स्थापित की जाये। छोटे तौर पर श्री ट्रिफिन का सुझाव यह है कि एक नई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा जारी की जाय और अन्तर्राष्ट्रीय अदायगियों के साधन के रूप मे डालर और स्टर्लिंग की जगह उसका उपयोग किया जाय और साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय अदायगी के लिए सब राष्ट्र डालर या स्वर्ण के सुरक्षित कोष बनाने के बजाय इस अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के सुरक्षित कोष बनाये। यह नई मुद्रा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा, और सम्भव हो तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि (इन्टरनेशनल मॉनीटरी फण्ड) द्वारा संचालित की जाय। यह सम्भव है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के परिचालन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि को एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्रीय बैंक मे परिणत कर दिया जाय, और उसे यह अधिकार दे दिया जाय कि जब जैसी आवश्यकता हो, वह इस अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की सप्लाई बढ़ा या घटा सके। दूसरी सम्भावना यह व्यक्त की जाती है कि जो भी नई व्यवस्था हो वहाँ सब देशो पर स्वतः कुछ ऐसा दबाव डाल सके कि उन्हें एक उचित सीमा तक अपनी वैदेशिक अदायगियों को सन्तुलित रखना होगा और मुद्रा-स्फीति के सम्भावित प्रभावो को

सीमित करना होगा। यह स्वतः पडने वाला दबाव कुछ वैसा ही होगा, जैसा कि स्वर्णमान से पडता था।

यूरोपीय साभा बाजार के देश एक यूरोपीय सुरक्षित मुद्रा कोष प्रणाली स्थापित करने का विचार कर भी रहे थे। उनका उद्देश्य इस प्रणाली को अन्ततः इस यूरोपीय बाजार की एक सर्वमान्य मुद्रा बनाना था। यदि ऐसी प्रणाली स्थापित हो जाय और ब्रिटेन भी उसका सदस्य बन जाय तो मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली की अनेक खामियाँ इससे दूर हो जाएँगी। साथ ही इससे सयुक्त राज्य को भी इस यूरोपीय प्रणाली में शामिल होने और इस प्रकार उसे अटलांटिक के उस पार तक विस्तृत करने को प्रोत्साहन मिलेगा। इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि यह यूरोपीय मुद्रा प्रणाली और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि दोनों का विलय हो जाय और यूरोप की इस नई अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा को ट्रिफिन के प्रस्ताव के अनुसार मारे विश्व की अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में मान्यता मिल जाय।

मौजूदा मुख्य-मुद्रा प्रणाली की कठिनाइयों को चाहे किसी भी उपाय से दूर किया जाय, उसका परिणाम यह होगा कि सयुक्त राज्य की अदायगी सन्तुलन की स्थिति पर दबाव कम हो जायेगा। लेकिन इससे सयुक्त राज्य अपनी विदेशी अदायगियों को उचित रूप से सन्तुलित रखने की जिम्मेदारी से पूर्णतः मुक्त नहीं होगा, हालांकि इस सन्तुलन को कायम रखने की कार्यवाहियों के लिए उसे अधिक समय लगेगा और साथ ही उसके लिए सम्भावित कार्यवाहियों में से चुनाव की गुंजायश भी अधिक रहेगी। उदाहरण के लिए, यह मुमकिन है कि वह अपनी मुद्रा को सीमित करने या आयात में कमी करने के उपायों को आजमाने के बजाय उत्पादकता और निर्यात को बढ़ाने के उपायों का सहारा ले, जिनमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है। उपयुक्त परिस्थितियों में वह डालर की विनिमय दर में परिवर्तन करने के प्रश्न पर भी विचार कर सकती है। हालांकि फिलहाल उसकी कोई सम्भावना नहीं है, क्योंकि अन्य देशों के पास काफी डालर जमा हो गए हैं और सयुक्त

राज्य पर यह नैतिक जिम्मेदारी है, और व्यावहारिक दृष्टि से भी यह सही है, कि वह अन्य देशों की सरकारों या लोगों के पास जमा इन डालरों के मूल्य को कायम रखे। संयुक्त राज्य की सरकार के लिए हर हालत में ऐसी नीतियों या कार्यक्रमों को अपनाना जरूरी होगा जिनसे लोकतन्त्रीय मूल्यों की रक्षा करते हुए वह अपने निर्यात को इतने ऊँच स्तर पर रख सकें कि विश्व की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति के कारण अपनाये जाने वाले वैदेशिक कार्यक्रम सन्तुलित रहे।

संयुक्त राज्य की विदेश नीति और अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

संयुक्त राज्य के सामने अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में आने वाली कठिनाइयों का जो विवरण हमने अभी प्रस्तुत किया है, वह यह सूचित करता है कि विश्व की ऐसी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था कायम करने के लिए, जो सभी स्वतन्त्र देशों की रक्षा और प्रगति के अनुकूल हो बहुत कुछ करना अभी बाकी है। इस कार्य में अमेरिकी लोगों की एक विशेष जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके पास ताकत है, दौलत है और साथ ही काम करने की स्वतन्त्रता भी अधिक है। इस कार्य का आर्थिक पहलू यह है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के साथ अधिक एकीकरण कर दिया जाय ताकि संयुक्त राज्य अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और पूँजी-निवेश को ऊँचे स्तर पर रख सके। यह काम सन् 1914 से पहले के जमाने को पुनः लाने की कोशिश करके नहीं किया जा सकता। यह काम केवल ऐसे साधनों से ही किया जा सकता है जो वर्तमान वास्तविकताओं और भविष्य की आवश्यकताओं को स्वीकार करे और ससार-भर में बदल रहे मूल्यों और आशाओं को काफी ध्यान में रखे।

द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व अमेरिका ने पृथक्ता, अर्थात् अपने आपको शेष संसार की उलझनों से अलग रखने, की जो नीति अपना रखी थी, उससे तुलना करके जब हम देखते हैं तो मालूम होता है कि उसने अपनी वैदेशिक नीति को बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की नई परिस्थितियों के

साथ बहुत तेज गति से और काफी दूर तक ढाल लिया है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या इन परिवर्तनों से युग की आवश्यकताओं की पर्याप्त पूर्ति हो जाती है। अमेरिका के लोगो में अब भी राष्ट्रीयता और प्रभु-सत्ता की पुरानी परम्परागत धारणाओं के नुकते-निगाह से सोचने की प्रवृत्ति है। यद्यपि वे यह स्वीकार करते हैं कि अन्य देशों का अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, साझेदारी और पारस्परिक प्रभु-सत्ता के आशिक त्याग के नये दृष्टिकोणों से सोचना उनके अपने लिए सगत हो सकता है, लेकिन, जहाँ तक अमेरिकी लोगो की जिम्मेदारियों और आवश्यकताओं का ताल्लुक है, वे इन नई सृजनात्मक धारणाओं को उनके साथ पूर्णतः जोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। अमेरिकी लोगो में एक प्रवृत्ति यह भी है कि जब अन्तर्राष्ट्रीय कठिनाइयों के हल में देरी होती है तो वे अवीर हो जाते हैं। वे आमतौर पर यह समझ ही नहीं पाते कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में कहीं अधिक कठिन होता है, खासकर तब जब कि कोई देश केवल लोकतंत्रीय उपायो और पद्धतियों को ही अपनाने के लिए कृत-संकल्प हो। इसके अलावा अमेरिकी लोग आम तौर पर यह समझने की गलती भी कर देते हैं कि सोवियत रूस और चीन के कम्युनिस्टों की साम्राज्यवादी महत्त्वाकांक्षाएँ ही विश्व की आधुनिक समस्याओं का एकमात्र कारण है। यह ठीक है कि रूस और कम्युनिस्ट चीन के आक्रमण और आन्तरिक षडयन्त्रों का खतरा बहुत बड़ा है और वह निरन्तर बढ़ भी रहा है, लेकिन अगर किसी चमत्कार से इस खतरे का किसी तरह अन्त हो जाय तो भी ससार में कठिन और गहरी जड़ो वाली अन्तर्राष्ट्रीय समस्याएँ बाकी रह जाएँगी, भले ही उनका हल करने के लिए उतनी त्वरित गति से प्रयत्न न किया जाय। वास्तव में कम्युनिज्म का खतरा बहुत हद तक विश्व की आबादी, आशाओं और क्षमताओं में हुए अधिक बुनियादी परिवर्तनों का परिणाम है, उनका कारण नहीं है। ये परिवर्तन और रुझान कम्युनिज्म के पन-पने के लिए अवसर पैदा करते हैं और इन अवसरों के फलस्वरूप पनप कर कम्युनिज्म इन समस्याओं को और भी गम्भीर बना देता है।

अमेरिकी लोग मौजूदा आर्थिक प्रणाली के स्वरूप को, और इन खेतों के खिलाफ चौकसी और इन समस्याओं के हल के लिए आवश्यक कार्रवाइयों को, पहले से अधिक अच्छी तरह समझने लगे हैं। और जैसे-जैसे उनकी यह अनुभूति और समझ-बूझ बढ़ती जायेगी, वैसे-वैसे आवश्यक नीतियों को अपनाने और उन्हें अधिक सक्षमता और जोश के साथ क्रियान्वित करने की उनकी इच्छा और योग्यता भी बढ़ती जाएगी। किन्तु ये परिवर्तन चाहे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों न हों, केवल उन्हीं के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आगामी वर्षों में अमेरिका की वैदेशिक नीतियाँ भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगी। संयुक्त राज्य के लोगों को यह भी महसूस करना चाहिए कि अपने वैदेशिक व्यापार और पूँजी-निवेश से, अपनी वैदेशिक सहायता के विस्तार से और अपनी अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा की स्थिति में सुधार से उन्हें भी अन्ततः लाभ पहुँचेगा। यह लाभ जिस हद तक मौजूद है और जिस हद तक अमेरिकी लोग उसके महत्व को समझेंगे, सम्भवतः उसी हद तक वे अपनी अर्थ-व्यवस्था का अपने साथी और मित्र देशों की अर्थ-व्यवस्था के साथ एकीकरण करने का प्रयत्न करेंगे।

वास्तव में अमेरिका की वैदेशिक नीति के ठीक ढंग से विकसित होने में एक बड़ी कठिनाई यह रही है कि उसने अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के ठीक ढंग से चलने की उतनी चिन्ता नहीं की जितनी कि अमेरिकी समाज के कुछ मुख्य गुटों के तात्कालिक और प्रत्यक्ष स्वार्थों की पूर्ति की चिन्ता की। जैसा कि हमने ऊपर देखा है, इस कठिनाई का एक कारण अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के साथ एकतरफा सम्बन्ध था। अमेरिका को अन्य देशों के साथ व्यापार करने या उनमें पूँजी लगा कर कमाई करने की उतनी जरूरत नहीं है, जितनी कि शेष संसार को अमेरिका के साथ व्यापार करने और उससे अपने यहाँ पूँजी लगवाने की है। कुछ हद तक इसका कारण संयुक्त राज्य और उसके साथी मित्र देशों के राजनीतिक और सामरिक सम्बन्ध भी है। प्रथम विश्व के बाद शेष संसार की शान्ति और तानाशाही देशों के आक्रमण

आन्तरिक पडयन्त्रों से उसकी रक्षा मुरयत सयुक्त राज्य की आर्थिक और सैनिक शक्ति पर निर्भर रही है। लेकिन सयुक्त राज्य की अपनी शान्ति और सुरक्षा अपने साथी और मित्र देशों की आर्थिक और सैनिक शक्ति पर उतनी निर्भर नहीं रही।

सयुक्त राज्य की वैदेशिक नीतियों में जिन परिवर्तनों की आवश्यकता है, वे अपने आप में चाहे कितने ही कठिन हों, आगामी वर्षों में जैसे-जैसे अमेरिकी लोगों को यह महसूस होता जाएगा कि उनकी अपनी सफलता के लिए वे आवश्यक हैं, वैसे-वैसे उन्हें क्रियान्वित करना अधिकाधिक आसान होता जाएगा। आज भी सयुक्त राज्य राजनीतिक और आर्थिक दृष्टियों से शेष ससार पर पहले की अपेक्षा अधिक निर्भर है, और 1960 के दशक में उसकी यह निर्भरता और भी बढ़ती जाएगी। एक ओर अमेरिका के प्राकृतिक साधन-सम्पदा के स्रोत क्रमशः क्षीण होते जा रहे हैं, अमेरिकी लोगों का रहन-सहन का स्तर ऊँचा होता जा रहा है, और अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की उत्पादन क्षमता और उत्पादकता में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है, और दूसरी ओर यूरोपीय साम्राज्य और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय गुट अधिकाधिक तरक्की करते जा रहे हैं—इन दोनों बातों को देखते हुए अमेरिकी जनता विदेशी व्यापार और विदेशों में पूँजी-निवेश के महत्त्व को अधिकाधिक महसूस करने लगेगी। कम्युनिस्ट देशों की शक्ति में वृद्धि और एशिया और अफ्रीका के गैर-कम्युनिस्ट देशों की स्वतन्त्र रूप से काम करने की आजादी और क्षमता का परिणाम यह होगा कि सयुक्त राज्य पश्चिमी यूरोप और लैटिन अमेरिका के अपने साथी और मित्र देशों पर राजनीतिक और सामरिक दृष्टि से अधिक निर्भर हो जाएगा। इन बुनियादी रुझानों के कारण सयुक्त राज्य की जनता और सरकार के लिए उन नीतियों और कार्यक्रमों को अपनाना, जो एक बेहतर राजनीतिक और आर्थिक विश्व प्रणाली के निर्माण में अधिक प्रभावकारी ढंग से योग दे सकते हैं, उतना कठिन नहीं रहेगा।

सयुक्त राज्य को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण के इतने कठिन सभावित परिणामों का सामना इससे पहले कभी नहीं करता पड़ा जितने

कठिन परिणामों का सामना आज करना पड़ रहा है। उसने अपनी निज की समस्याओं के हल के लिए नहीं, बल्कि अधिकतर अपने साथी और मित्र देशों की समस्याओं के हल के लिए ही उनके साथ प्रभावकारी सहयोग किया है। लेकिन यह बात अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में अमेरिका का अपना भी बहुत हित है। संयुक्त राज्य की व्यापारिक बाधाओं को कम करने, संयुक्त राज्य के निर्यात को बढ़ाने और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-व्यवस्था को सुधारने में जो कठिनाइयाँ हैं, उन्हें अमेरिका अकेला दूर नहीं कर सकता। जैसे-जैसे अमेरिका की जनता और कांग्रेस इस बात को अधिक महसूस करने लगेगे वैसे-वैसे संयुक्त राज्य उन सस्थात्मक व्यवसायों में, जिनका प्रयोजन अटलांटिक राष्ट्रों को अपनी सर्वसामान्य समस्याओं के हल और सर्वसामान्य बाह्य खतरों से रक्षा के लिए परस्पर घनिष्ठता से सगठित करना है, हिस्सा लेने के लिए अधिक तैयार और सक्षम होता जाएगा। इसी तरह संयुक्त राज्य उन अधिक व्यापक किन्तु अपेक्षाकृत शिथिल सगठनों में भी शामिल हो सकता है, जो सभी विकसित और विकासोन्मुख देशों की सर्वसामान्य कठिनाइयों के हल के लिए बनाये जाएँगे। इन आशापूर्ण और रचनात्मक रुझानों से अन्ततः संयुक्त राज्य अपने उन उत्तरदायित्वों को, अधिक प्रेरणाप्रद और ओजस्वी ढंग से पूरा कर सकेगा, जो एक नये और बेहतर संसार को बनाने के लिए जरूरी है— एक ऐसे संसार को, जिसमें सभी लोग एक दिन अधिक सुनिश्चित और सुरक्षित स्वतन्त्रता और अधिकाधिक सुख और क्षेम का उपभोग कर सकेंगे।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था : स्वरूप और भविष्य

हमने अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की अनेक पहेलियों से ममीका की है। हमने उसकी असाधारण नफ़ेलताओं की ओर संकेत किया है और नाय ही उसकी खामियों और अनमुलभी समस्याओं की भी चर्चा की है। शायद उसकी सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि संजग आलोचना ने, जो लोकतन्त्र में खूब फलती-फूलती है, अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की खामियों और समस्याओं के अध्ययन और उनके रचनात्मक समाधानों और सुधार की अनवरत खोज को प्रोत्साहन दिया है।

अमेरिका की आज की आर्थिक और सामाजिक प्रणाली में अनेक परिवर्तन हुए हैं। उसका आज का रूप 25 या 50 वर्ष पहले के रूप से बहुत भिन्न है। किन्तु उसका वर्तमान उन देशों की भांति, जिनमें सामाजिक क्रान्तियाँ हुई, अतीत से विलकुल विच्छिन्न नहीं हुआ। संयुक्त राज्य में अतीत से विरासत में मिली संस्थाओं को नये कामों के अनुकूल ढाल लिया गया है। यहाँ जो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था उभर रही है उससे वे लोग चक्कर में पड़ जाते हैं जो पूँजीवाद या समाजवाद जैसे पुराने परम्परागत नामों से उसकी व्याख्या करना चाहते हैं। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था बन्धन-हीन पूँजीवाद अथवा समाजवाद के 'विशुद्ध' नियमों के अनुसार नहीं चलती। फिर भी वह इन दोनों में से किसी भी व्यवस्था से अधिक प्रभावकारी रूप में चल रही है।

इन अन्तिम पृष्ठों में हम अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था के स्वरूप को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने का यत्न करेंगे। एक तरह से यह एक असम्भव कार्य है, क्योंकि अमेरिकी प्रणाली की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है

कि यह कोई स्थिर और जड़ वस्तु नहीं है, बल्कि एक सजीव और चेतन वस्तु है, जो बहुत-सी, और कुछ अंश तक परस्पर-विरोधी, प्रेरणाओं से प्रभावित होती रहती है। किन्तु अतीत में उसकी जो प्रधान विशेषताएँ रही हैं, उन पर दृष्टिपात करके इस बात का कुछ अन्दाज लगाया जा सकता है कि भविष्य में अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के किस दिशा में जाने की सम्भावना है।

अमेरिकी व्यक्तिवाद और जासन का कर्तव्य

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था का सबसे बुनियादी तथ्य शायद यह है कि दूकानों और कारखानों, दफ्तरों और प्रयोगशालाओं, घरों और फार्मों में काम करने वाले लोग यह महसूस करते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर वे अमेरिकी प्रणाली के अविच्छिन्न अंग हैं। न व्यवसाय प्रबन्धक, न कर्मचारी और न ही सरकारी अधिकारी इस प्रणाली के एकमात्र प्रेरक या सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग समझे जाते हैं। हरेक का अपना-अपना अलग काम है और वह उसे पूरा करता है। उसके काम को दूसरा कोई पूरा नहीं कर सकता और न वह काम उस पर ऊपर की किसी अधिकारी सत्ता द्वारा उसपर थोपा जाता है। बल्कि वह स्वयं उभरता और शक्ति अख्तियार करता है, उसकी आलोचना हो सकती है और उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है।

अमेरिकी लोग अपना काम-धन्दा करते हुए या अपना दैनिक जीवन व्यतीत करते हुए अपने और अपने परिवार के सुख के लिए प्रयत्न करते हैं। किन्तु उन्हें यह विश्वास है कि अपनी उन्नति के लिए उद्योग करते हुए वे अपने समाज के सर्वसामान्य हित और ध्येय को भी पूरा करते हैं। कभी-कभी हरेक का अपना हित अलग-अलग होने के कारण उनमें परस्पर-विरोध भी होता है, परन्तु वह 'वर्ग-सघर्ष' जैसी किसी चीज में परिणत नहीं होता। इसके विपरीत ये विरोध या सघर्ष न्यूनाधिक प्रभावकारी ढंग से या तो आपसी वार्ता द्वारा, जैसा कि मजदूर सम्बन्धों में होता है, प्रत्यक्ष रीति से निबट जाते हैं या राष्ट्र के

जीवन के द्वारा अग्रत्यक्ष रीति से हल हो जाते हैं। यह इसलिए सम्भव है क्योंकि अमेरिकी प्रणाली ऐसे गहरे बन्वनों पर आधारित है जिन्होंने परस्पर-विरोधी हितों और आकांक्षाओं को आपस में बाँध रखा है। यद्यपि इन बन्वनों को बिनकुल स्पष्ट करना आसान नहीं है तो भी अमेरिकी लोकतन्त्र का सार यही है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की जिस विशिष्टता को नमनना और हृदयगम करना सबसे कठिन है, वह यह है कि उसमें जहाँ एक ओर व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उपक्रम की रक्षा की जाती है, वहाँ नगठनात्मक प्रबन्ध भी ऊँचे दर्जे का है। ऊपर ने देखने पर जिन उद्देश्यों और अभिवृत्तियों में बुनियादी तौर पर विरोध नज़र आता है, वही अमेरिकी जीवन-पद्धति में परस्पर नमन्वित हो जाती हैं। यद्यपि पिछले नौ वर्षों में औद्योगिक विकास खूब हुआ है और बड़े-बड़े नगर बन गए हैं तब भी पुराने युग की साहसिकता और नये-नये क्षेत्रों की खोज के लिए आगे बढ़ने की वृत्ति कुछ-न-कुछ आज भी बाकी है। यह वृत्ति व्यक्ति में स्वावलम्बन की भावना पैदा करती है और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर सहकारी प्रयत्न में शामिल होने के लिए भी उसे तैयार करती है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में आज भी इन दोनों वृत्तियों का रचनात्मक स्थान है। बड़े से बड़े कारखाने में भी श्रमिक कर्मचारी केवल एक सख्या मात्र नहीं होता, मि० स्मिथ या मि० जोन्स के रूप में और बहुत सम्भव है विल या वाँव के आत्मीयतापूर्ण नामों के रूप में उसकी एक पृष्ठ-व्यक्तिगत सत्ता बनी रहती है। यह मात्र एक शिष्टाचार नहीं है। बल्कि यह व्यक्ति के प्रति एक स्थायी सम्मान या समादर को प्रकट करता है, और कुछ हद तक व्यक्ति का यह सम्मान ही अमेरिकी श्रमिकों की उत्पादकता के ऊँचे स्तर का कारण है।

अब तक हमने जो कुछ विवेचन किया है, उसमें इस बात पर बल दिया है कि अमेरिकी प्रणाली में कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान किन्हीं कट्टर सिद्धान्तों से नहीं बल्कि पराक्षर और गलतियों से प्राप्त अनुभव से सम्बद्ध तथ्यों और वास्तविक विकल्पों की दृष्टि में रख

कर किया जाता है। इसका एक उदाहरण सरकारी और प्राइवेट उत्तर-दायित्वों के बीच की विभाजिक रेखा का लचकीलापन है। जो विदेशी आगन्तुक अमेरिका के स्वतन्त्र व्यवसाय और उद्यम की सफलताओं को देखकर चकित रह जाते हैं, वे अक्सर इस बात पर भी बहुत आश्चर्य करते हैं कि यहाँ सरकार भी कृषि, आवास, सामाजिक सुरक्षा या आर्थिक व्यवस्था के विकास और स्थिरीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। अमेरिकी लोगों में इस बात को लेकर बहुत विवाद चलता रहता है कि सरकार का असली काम क्या है, किन्तु इस बुनियादी सिद्धान्त पर मतभेद आपको शायद ही नजर आयेगा कि एक स्वतन्त्र उद्यम प्रणाली में व्यक्ति पर यथासम्भव अधिकतम भरोसा किया जाना चाहिए, परन्तु सामान्य जन-कल्याण की खातिर जब और जहाँ आवश्यक हो, सरकार को भी प्रभावकारी कार्रवाई करनी चाहिए।

कुछ देशों में 'राज्य' को जनता से और राष्ट्रीय समाज की अन्य सस्थाओं से पृथक् और ऊँचा समझा जाता है। वह एक ऐसी ऊँची सत्ता माना जाता है, जिसके अपने अलग हित और उद्देश्य हैं जिन्हें और सब हितों और उद्देश्यों से पहले स्थान दिया जाता है। इन देशों में सरकार इस सर्वोपरि राज्य का दृश्यमान पार्थिव रूप होती है और इसलिए वह राज्य की सत्ता और विशेषाधिकारों का उपभोग करती है और जनता उसकी आज्ञाओं का पालन करती है। परन्तु अमेरिकी जीवन ऐसी धारणाओं और मनोवृत्तियों से बिल्कुल मुक्त है। अमेरिकी लोग केवल 'सरकार' की ही बात सोचते और करते हैं, वे 'राज्य' की बात नहीं सोचते या करते। और 'सरकार' को वे उस महिमा-मण्डित रूप में नहीं देखते, जिस रूप में कुछ देशों में 'राज्य' को देखा जाता है। यहाँ सरकार केवल समाज की एक सस्था मात्र है। इसके अलावा उसे आमतौर पर जनता का सेवक समझा जाता है। कानून और परम्परा ने उसकी सत्ता और विशेषाधिकार सीमित कर दिये हैं और उसकी नीतियाँ और क्रियाकलाप स्वयं सरकार के स्वतन्त्र समझे जाने वाले हितों से नहीं, बल्कि बहुत हद तक विभिन्न समूहों के परस्पर-प्रतिस्पर्धी हितों से

जीवन के द्वारा अप्रत्यक्ष रीति से हल हो जाते हैं। यह इसलिए सम्भव है क्योंकि अमेरिकी प्रणाली ऐसे गहरे बन्धनों पर आधारित है जिन्होंने परस्पर-विरोधो हितो और आकांक्षाओं को आपस में बाँध रखा है। यद्यपि इन बन्धनों को विलकुल स्पष्ट करना आसान नहीं है तो भी अमेरिकी लोकतन्त्र का सार यही है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की जिस विशिष्टता को सम्भन्ना और हृदयगम करना सबसे कठिन है, वह यह है कि उसमें जहाँ एक ओर व्यक्ति की स्वतन्त्रता और उपक्रम की रक्षा की जाती है, वहाँ नगठनात्मक प्रबन्ध भी ऊँचे दर्जे का है। ऊपर से देखने पर जिन उद्देश्यों और अभिवृत्तियों में बुनियादी तौर पर विरोध नजर आता है, वही अमेरिकी जीवन-पद्धति में परस्पर समन्वित हो जाती है। यद्यपि पिछले सौ वर्षों में औद्योगिक विकास खूब हुआ है और बड़े-बड़े नगर बस गए हैं तब भी पुराने युग की नाहसिकता और नये-नये क्षेत्रों की खोज के लिए आगे बढ़ने की वृत्ति कुछ-न-कुछ आज भी बाकी है। यह वृत्ति व्यक्ति में स्वावलम्बन की भावना पैदा करती है और साथ ही आवश्यकता पडने पर सहकारी प्रयत्न में शामिल होने के लिए भी उसे तैयार करती है। अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में आज भी इन दोनों वृत्तियों का रचनात्मक स्थान है। बड़े से बड़े कारखाने में भी श्रमिक कर्मचारी केवल एक सख्या मात्र नहीं होता, मि० स्मिथ या मि० जोन्स के रूप में और बहुत सम्भव है विल या बॉव के आत्मीयतापूर्ण नामों के रूप में उसकी एक पृथक् व्यक्तिगत सत्ता बनी रहती है। यह मात्र एक शिष्टाचार नहीं है। बल्कि यह व्यक्ति के प्रति एक स्थायी सम्मान या समादर को प्रकट करता है, और कुछ हद तक व्यक्ति का यह सम्मान ही अमेरिकी श्रमिकों की उत्पादकता के ऊँचे स्तर का कारण है।

अब तक हमने जो कुछ विवेचन किया है, उसमें इस बात पर बल दिया है कि अमेरिकी प्रणाली में कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान किन्हीं कट्टर सिद्धान्तों से नहीं बल्कि पराक्षण और गलतियों से प्राप्त अनुभव से सम्बद्ध तथ्यों और वास्तविक विकल्पों को दृष्टि में रख

कर किया जाता है। इसका एक उदाहरण सरकारी और प्राइवेट उत्तर-दायित्वों के बीच की विभाजिक रेखा का नचकीलापन है। जो विदेशी आगन्तुक अमेरिका के स्वतन्त्र व्यवसाय और उद्यम की सफलताओं को देखकर चकित रह जाते हैं, वे अक्सर इस बात पर भी बहुत आश्चर्य करते हैं कि यहाँ सरकार भी कृषि, आवास, सामाजिक सुरक्षा या आर्थिक व्यवस्था के विकास और स्थिरीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा करती है। अमेरिकी लोगो में इस बात को लेकर बहुत विवाद चलता रहता है कि सरकार का असली काम क्या है, किन्तु इस बुनियादी सिद्धान्त पर मतभेद आपको शायद ही नजर आयेगा कि एक स्वतन्त्र उद्यम प्रणाली में व्यक्ति पर यथासम्भव अधिकतम भरोसा किया जाना चाहिए, परन्तु सामान्य जन-कल्याण की खातिर जब और जहाँ आवश्यक हो, सरकार को भी प्रभावकारी कार्रवाई करनी चाहिए।

कुछ देशों में 'राज्य' को जनता से और राष्ट्रीय समाज की अन्य सस्थाओं से पृथक् और ऊँचा समझा जाता है। वह एक ऐसी ऊँची सत्ता माना जाता है, जिसके अपने अलग हित और उद्देश्य हैं जिन्हें और सब हितों और उद्देश्यों से पहले स्थान दिया जाता है। इन देशों में सरकार इस सर्वोपरि राज्य का दृश्यमान पार्थिव रूप होती है और इसलिए वह राज्य की सत्ता और विशेषाधिकारों का उपभोग करती है और जनता उसकी आज्ञाओं का पालन करती है। परन्तु अमेरिकी जीवन ऐसी धारणाओं और मनोवृत्तियों से त्रिलकुल मुक्त है। अमेरिकी लोग केवल 'सरकार' की ही बात सोचते और करते हैं, वे 'राज्य' की बात नहीं सोचते या करते। और 'सरकार' को वे उस महिमा-मण्डित रूप में नहीं देखते, जिस रूप में कुछ देशों में 'राज्य' को देखा जाता है। यहाँ सरकार केवल समाज की एक सस्था मात्र है। इसके अलावा उसे आमतौर पर जनता का सेवक समझा जाता है। कानून और परम्परा ने उसकी सत्ता और विशेषाधिकार सीमित कर दिये हैं और उसकी नीतियाँ और क्रियाकलाप स्वयं सरकार के स्वतन्त्र समझे जाने वाले हितों से नहीं, बल्कि बहुत हद तक विभिन्न समूहों के परस्पर-प्रतिस्पर्धी हितों से

निर्धारित और निर्दिष्ट होते हैं।

सरकार देश की आर्थिक प्रक्रिया में जो हिस्सा लेती है, उसे घटाने या बढ़ाने के लिए आम तौर पर कानून की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ यह है कि यह घटा-वटी विधायक और प्रशासक प्रक्रियाओं के आपसी नियन्त्रणों और सन्तुलनों का ही परिणाम नहीं होती, बल्कि वह बाद में न्यायपालिका की परीक्षा की कसौटी पर भी खरी उतरनी चाहिए। इसके अलावा सभी नागरिकों को सरकारी नीतियों और कार्यक्रमों का समर्थन या विरोध करने का अधिकार है। इसलिए विशिष्ट हितों वाले अनेक समूहों ने अपने सदस्यों की ओर से विधायिका अथवा कार्यपालिका को प्रभावित करने के लिए अपने सगठन बना रखे हैं। ये सगठन कहीं अपनी आर्थिक शक्ति का दुरुपयोग न करें, इसलिए कांग्रेस ने इस प्रकार विधायकों या प्रशासकों को प्रभावित करने वाले सगठनों के क्रियाकलापों को नियन्त्रित करने के लिए भी कानून बनाये हैं। फिर भी ये तथा कुछ अन्य साविधानिक और सगठनात्मक व्यवस्थाएँ ऐसी हैं जिनके द्वारा अमेरिकी लोकतन्त्र सरकार और प्राइवेट व्यक्तियों के निश्चयों को युक्ति-युक्त और सन्तोषजनक रूप में सन्तुलित करता है।

संयुक्त राज्य की संघीय और राज्यीय सरकारों के संविधानों में निरपवाद रूप से यह आधारभूत विश्वास निहित है कि आर्थिक क्रिया-कलाप व्यक्ति का अधिकार है और सरकार केवल एक सीमा तक ही उसे सार्वजनिक हित में नियन्त्रित कर सकती है। यह सच है कि आर्थिक क्षेत्र में सरकार के अधिकारों और कार्यों का पिछले वर्षों में, खास कर बीसवीं शताब्दी की अभूतपूर्व परिस्थितियों के फलस्वरूप, काफी विस्तार हुआ है, तथापि उसका कार्य अब भी गौण और सहायक कार्य मात्र है। आर्थिक क्षेत्र में मुख्य भूमिका अब भी विकेंद्रित प्राइवेट उद्यम के ही हाथ में है। अमेरिकी लोगों में इस स्थिति में किसी तरह का बुनियादी परिवर्तन करने का भी कोई विचार नहीं है।

इसमें सन्देह नहीं कि अमेरिकी लोग, चाहे वे प्रबन्धक हों, या कृषक, या श्रमिक या उपभोक्ता, अपना निश्चय स्वयं करना पसन्द करते

हैं। किन्तु वे यह भी स्वीकार करते हैं कि एक जटिल आधुनिक समाज कुछ नियमों के बिना नहीं चल सकता। उदाहरण के लिए, मोटर चलाने वाले लोग इस बात पर नाराजगी जाहिर करेंगे कि कोई उन्हें यह बताये कि वे कब और कहाँ मोटर चलाये, परन्तु इस थोड़ी-बहुत नाराजगी के बावजूद वे यातायात सम्बन्धी नियमों का पालन करते हैं, जिसके बिना यातायात में विलकुल ही अराजकता पैदा हो जायेगी। इस बात पर खासा विवाद हो सकता है कि यातायात को तीव्र गति से चलाने के लिए नियन्त्रक रोशनियाँ कम की जानी चाहिएँ या बढ़ाई जानी चाहिएँ, लेकिन इस सिद्धान्त पर कोई विवाद या मतभेद नहीं होगा कि सरकार द्वारा यातायात के नियन्त्रण के लिए लगाई गई रोशनियाँ उपयोगी हैं और ड्राइवरो के स्वावलम्बन और आत्म-उत्तरदायित्व के साथ असंगत नहीं है। लोगों के प्राइवेट क्रियाकलापों के बहुत-से अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर सरकार के नियन्त्रण और निर्देशन के बारे में भी यही बात है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में आयोजन का स्थान

संयुक्त राज्य के बारे में गलतफहमी का एक कारण यह भी है कि यहाँ आयोजन के सम्बन्ध में बहुत चर्चा होती है, हालांकि मजा यह है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को 'आयोजित अर्थ-व्यवस्था' से सर्वथा उल्टी व्यवस्था माना जाता है। आम तौर पर 'आयोजित अर्थ-व्यवस्था' का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था माना जाता है जिसमें उत्पादन, निवेश और उपभोग सम्बन्धी सभी बड़े निश्चय किसी एक केन्द्रीय सत्ता द्वारा किये जाये। यह समझा जाता है कि एक केन्द्रीय सत्ता कुछ वर्षों की अवधि के लिए एक आर्थिक योजना बनाये और उत्पादन और वितरण के प्रबन्धक, जो राज्य के अधिकारी हो, उस योजना पर अमल करे। योजना का पूर्णतः पालन न करने पर ये अधिकारी कठोर दंड के भागी समझे जाते हैं। लेकिन वास्तव में यह बात अमेरिकी प्रणाली से विलकुल उल्टी है।

परन्तु अमेरिका में एक सरकारी केन्द्रीय योजना नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में आयोजन के लिए कोई स्थान है ही नहीं। हमने इस तथ्य के महत्त्व पर काफी बल दिया है कि आज व्यवसायी लोग केवल स्वल्पकालिका उतार-चढ़ावों को दृष्टि में रखकर ही अपने निवेश सम्बन्धी निश्चय नहीं करते, बल्कि वे दीर्घकालिक संभावनाओं को नजर में रखकर दूरदृष्टि से ये निश्चय करते हैं। व्यवसायी लोग एक नियत अवधि में अधिकतम लाभ की प्राप्ति आदि अपने उद्देश्यों को तब तक पूरा नहीं कर सकते, जब तक कि वे अपने उत्पादनों की भावी विक्री आदि का पहले से ही अनुमान न लगायें। किसी एक वर्ग के उत्पादनों की विक्री की भावी सम्भावनाओं का अनुमान सारी अर्थ-व्यवस्था की भावी अभिवृद्धि के प्रसंग में ही लगाया जा सकता है। यही बात कृषकों के निश्चयों के बारे में भी लागू होती है। इसी तरह श्रमिक नेता अपना मजदूरी और वेतन सम्बन्धी नर्घर्ष तब तक नहीं चला सकते और सरकार भी कृषि, जल और विद्युत् के विकास की सम्भावनाओं का अनुमान और सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक स्थिरीकरण या राष्ट्रीय रक्षा कार्यक्रमों का निर्माण तब तक नहीं कर सकती जब तक कि हर क्षेत्र समूची अर्थ-व्यवस्था की सम्भावित अभिवृद्धि और आवश्यकताओं को नजर में रखकर आयोजन न करे।

यह अवश्य सम्भव है कि व्यवसायियों, श्रमिक यूनियनों, कृषक सगठनों और सरकार की राय भावी आर्थिक अभिवृद्धि की गति, स्वचालित या अन्य तकनीकी विधियों के परिणाम और उपभोग की तुलना में पूंजी-निर्माण की सही सम्भावनाओं आदि के बारे में एक न हो। इन मतभेदों को लेकर बहस हो सकती है और कुछ हद तक देश में विवाद भी छिड़ सकते हैं, जो लोकतन्त्र की जान है। लेकिन इस बात पर किसी का मतभेद नहीं है कि चाहे व्यवसायी वर्ग हो, चाहे श्रमिक वर्ग, या कृषि जीवी वर्ग या सरकार, सभी को अपने निश्चय भविष्य को दृष्टि में रख कर योजनापूर्वक करने चाहिए। इस बारे में भी दो रायें नहीं हैं कि इन सभी वर्गों की योजनाएँ एक-दूसरे के साथ यथासम्भव

समन्वित होनी चाहिए और यह काम सरकार का है कि वह अपनी आर्थिक और वित्तीय नीतियों से आर्थिक अभिवृद्धि को सन्तुलित रखते हुए यह समन्वय करे।

योजनावद्ध विकास सिर्फ केन्द्र-नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्थाओं की ही विशेषता नहीं है। वह उन अर्थ-व्यवस्थाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए भी अनिवार्य है, जिनका आधार लोकतन्त्रीय स्थापना है, जिनमें व्यवसाय और श्रम, दोनों स्वतन्त्र और बन्धनहीन हैं। लेकिन केन्द्र-नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था और स्वतन्त्र अर्थ-व्यवस्था, दोनों के आयोजन के तरीके विलकुल जुदा-जुदा हैं। केन्द्र-नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था योजना का एक निश्चित खाका तैयार कर लिया जाता है और उत्पादन अधिकारी उसमें दिये गए आदेशों से रचमात्र भी इधर-उधर नहीं हो सकते। दूसरी ओर लोकतन्त्रीय अर्थ-व्यवस्था में आयोजन इस ढंग से होता है कि हर कृषक, व्यवसायी, श्रमिक नेता या सरकारी अधिकारी सरकार द्वारा अथवा किसी प्रामाणिक प्राइवेट अनुसंधान संगठन द्वारा निर्दिष्ट एक समग्र अर्थ-व्यवस्था के व्यापक ढाँचे के भीतर अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करता है और उनके लिए वह उत्तरदायी होता है। इसके अलावा इन प्राइवेट निश्चय-कर्त्ताओं का आयोजन जिनता अच्छा होगा, केन्द्रीय आयोजन की आवश्यकता उतनी ही कम होगी।

यदि प्रशासन के भीतर और बाहर, दोनों जगह आर्थिक अभिवृद्धि की भावी सम्भावनाओं के बारे में आम तौर पर मोटी योजनाएँ बना ली जाएँ तो विकेन्द्रित आयोजन में बहुत सहायता मिल सकती है। ये मोटी आम योजनाएँ विभिन्न वर्गों के निश्चयकर्त्ताओं के लिए पथ-प्रदर्शन का काम दे सकती हैं। किन्तु वे अपने लिए कौन-सी योजना को चुने यह फैसला करना स्वयं उन्हीं का काम है। सरकारी और गैर-सरकारी विभिन्न वर्गों की योजनाओं में समन्वय और एकीकरण इसीलिए हो पाता है क्योंकि वे आर्थिक विकास की भावी सम्भावनाओं की एक ही व्यापक और आम योजना को लक्ष्य में रखकर बनाई जाती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आर्थिक अभिवृद्धि की ठीक-ठीक

क्या गति होनी चाहिए, इसके बारे में सब की राय एक ही हो। किन्तु कुछ समय से आहिस्ता-आहिस्ता मोटे तौर पर यह बात सभी लोग स्वीकार करने लगे है कि आर्थिक अभिवृद्धि के क्या स्तर होने चाहिए और उनके मुताबिक ही सब के उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाते हैं और सब लोग काम करते हैं।

स्वतन्त्र व्यवसाय वाली अर्थ-व्यवस्था में आयोजन के लिए अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों पर यहाँ हमें विस्तार से चर्चा नहीं करनी है। हम यहाँ सिर्फ इसी बात पर बल देना चाहते हैं कि यद्यपि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में केन्द्रित आयोजन नहीं होता तो भी इसमें आयोजन होता काफी मात्रा में है और वह भी सरकारी और गैर-सरकारी दोनों प्रकार का। वास्तव में अमेरिकी प्रणाली की स्वतन्त्रता और कुशलता के लिए यह आयोजन अनिवार्य है। राष्ट्रीय आयोजन एसोसियेशन (नेशनल प्लानिंग एसोसियेशन) का एक मुख्य काम सरकारी सगठनों और विभिन्न गैर-सरकारी वर्गों और सगठनों द्वारा किये जाने वाले लोकतन्त्रीय आयोजन में सहायता करना है।

सन् 1930 के दशक की मन्दी और सन् 1960 के दशक की अभिवृद्धि

सम्भव है, पाठक के मन में एक प्रश्न घुमडता और उसे अशान्त करता हो। उसे यह यकीन हो सकता है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था आज बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन साथ ही उसके मन में यह प्रश्न भी उठ सकता है कि तब अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था ने 1930 के दशक में वैसी ही अभिवृद्धि क्यों नहीं दिखाई जैसी उसमें आज दीख रही है। उस दशक की मन्दी के दिनों में कुछ अर्थशास्त्री यह व्याख्या करने का प्रयत्न करते थे कि अमेरिकी समाज की परिस्थितियों में आर्थिक क्षेत्र में जडता क्यों आनी स्वाभाविक थी। वही अर्थशास्त्री आज यह सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं कि क्यों निरन्तर समृद्धि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की एक स्वाभाविक विशेषता बन गई है। ऐसी हालत में इस

बात का क्या भरोसा है कि अमेरिका फिर से आर्थिक जड़ता और मन्दी के जमाने में नहीं लौट जायेगा ?

यह नाजुक प्रश्न अवश्य उठाया जाना चाहिए । यह मानकर सन्तोष कर लेने से अधिक खतरनाक बात और कोई नहीं हो सकती कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था अब मन्दियों की सम्भावना से बिलकुल मुक्त हो गई है । यह जरूर सही है कि 1930 और 1960 के दशकों में कुछ निर्णायक अन्तर है । सन् 1930 के दशक में सरकारी कार्रवाई बेतरतीब थी, जिसमें आर्थिक सुधारों और आर्थिक पुनरुद्धार के अनेक उपाय मिले-जुले थे और लोग, खासकर व्यवसायी लोग, उन्हें सन्देह की नजर से देखते थे । परन्तु आज अर्थ-व्यवस्था के भीतर ही कुछ ऐसे नियन्त्रण और ऐसी रोकें हैं, जो उसके ढाँचे का अंग बन गई हैं और जो सम्भावित मन्दियों के प्रभाव को कम करती हैं । शासन—कार्य-पालिका और विधायिका दोनों—आज इस ढंग से सगठित हैं कि ज्योंही आवश्यकता पड़ती है, वह तुरन्त कार्रवाई करता है । सब से अधिक महत्वपूर्ण एक तीसरा तत्व है और वह यह है कि मुख्य गैर-सरकारी वर्ग और आम जनता, दोनों ही सरकार द्वारा किये जाने वाले मन्दी-विरोधक कार्यों का समर्थन करने के लिए तैयार हैं और उनसे इसकी आशा की जाती है । यह स्वीकार कर लेने के बाद कि मन्दी आने पर अथवा आर्थिक अभिवृद्धि की गति के धीमी पड़ने पर आवश्यक निरोधक कदम उठाना सरकार की जिम्मेदारी है, सभी लोग उन आवश्यक सरकारी कार्रवाइयों को बिना आपत्ति के स्वीकार कर लेंगे, चाहे वे कुछ वर्गों को तात्कालिक या काल्पनिक हितों के विरुद्ध हो जाती प्रतीत होती हो । इन कारणों से आर्थिक भविष्य में लोगों का विश्वास कहीं अधिक बढ़ गया है और उससे प्राइवेट व्यवसायी लोग आर्थिक विस्तार को जारी रखने या पुन प्रारम्भ करने के लिए पहले से अधिक अच्छे अवसर पा सकते हैं ।

इस तरह, जहाँ 1930 के दशक में आर्थिक मन्दी और जड़ता का भय बुरी तरह हावी हो गया था, वहाँ 1960 के दशक को लोग आर्थिक

प्राचुर्य के एक नये युग की देहरी नमस्ने है। श्री रजवेल्ट ने दूसरी बार राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा था कि राष्ट्र का तिहाई हिस्सा ऐसा है जिसके पास 'रहने की अच्छे मकान नहीं, पहनने की अच्छा कपड़ा नहीं और खाने की पर्याप्त पौष्टिक आहार नहीं।' उसी तिहाई भाग की इन आर्थिक अपर्याप्तताओं और अपूर्णताओं को दूर करने के लिए वर्तमान शताब्दी के मध्य तक संयुक्त राज्य ने काफी प्रगति कर ली है। आज गरीबी और आर्थिक अभाव की समस्याओं पर वीरे-वीरे विजय पाई जा रही है। जो लोग हारकर मैदान नहीं छोड़ते उन्हें कुछ समय भले ही लग जाय, परन्तु अन्ततः आर्थिक अतिवृद्धि और उसके उपायों में सुधार से उनकी समस्या का हल जरूर निकल आयेगा। अगर युद्ध की सम्भावनाओं को किसी तरह रोका जा सके तो इस बात की काफी सम्भावना है कि संयुक्त राज्य अगले एक या दो दशकों में सभी के लिए प्रचुर भौतिक सम्पदा के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा।

अगर यह मान ले कि अमेरिका अपनी भावी भावनाओं की चुनौती का सामना कर सकता है तो सन् 1970 तक औसत अमेरिकी परिवार के रहन-सहन का स्तर आज के स्तर से 30 प्रतिशत ऊँचा हो जाएगा और देश की उत्पादकता में जो वृद्धि होगी उससे उत्पादन में 60 प्रतिशत वृद्धि की गुंजायश रहेगी। तब अमेरिकी लोग अपने प्राकृतिक संपत्तियों की रक्षा और विकास की आवश्यक सामाजिक सुविधाएँ उपलब्ध करने की और शिक्षा, स्वास्थ्य और बूढ़ों की देखभाल की अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को पूरा कर सकेंगे।

लेकिन आर्थिक अभावों से उत्पन्न गरीबी और मानवीय कष्टों के उन्मूलन का अर्थ यह नहीं होगा कि अमेरिकी समाज की सब बड़ी समस्याएँ हल हो जायेंगी। बल्कि वास्तविकता इसके विपरीत होगी। पूर्व अध्यापकों में हमने केवल अमेरिका की सफलताओं और उपलब्धियों का ही वर्णन नहीं किया है, बल्कि यह भी बताया है कि सन्तुलित आर्थिक विकास को कायम रखने, आर्थिक सत्ता के अत्यधिक

केन्द्रीकरण को रोकने और अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की अन्य तात्कालिक किन्तु अधिक परिचित समस्याओं का समाधान करने के प्रयत्नों में क्या कमियाँ हैं। इन लक्ष्यों के बारे में अब अधिकाधिक मतैक्य होता जा रहा है और जैसे-तैसे आर्थिक व्यवहार के वाछनीय स्तरों में सुधार होता जाएगा, वैसे-वैसे इन समस्याओं को निबटाने की विधियों और और तकनीकों में भी सुधार होता जायेगा। हमने हाल में ही पैदा हुई समस्याओं की भी चर्चा की है, जो अभी-अभी स्पष्ट रूप में सामने आने लगी हैं और जिनका समाधान अधिकाधिक आवश्यक हो रहा है। आने वाले वर्षों में इन समस्याओं पर अनेक कठिन निश्चय करने पड़ेगे और आवश्यक कदम उठाने होंगे। उदाहरण के लिए आबादी में हो रही वृद्धि, उद्योगों के विस्तार और संयुक्त राज्य में गरीबी पर विजय पाने के लिए निरन्तर किये जा रहे प्रयत्नों के संभावित परिणामों को दृष्टि में रखकर बड़े नगरों और महानगर क्षेत्रों, शिक्षा प्रणाली और अन्य सामाजिक संस्थाओं को उनके अनुकूल ढालने की समस्याएँ ऐसी हैं जिन्हें हमें हल करना होगा, किन्तु इन समस्याओं को अभी तक पूरे तौर पर हृदयगम भी नहीं किया जा रहा। पश्चिमी राष्ट्रों को अधिक संगठित करने, अल्पविकसित देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास को उन्नत करने एवं कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अधिक पर्याप्त साधन उपलब्ध करने और अधिक रचनात्मक अमेरिकी नेतृत्व प्रदान करने के लिए अभी बहुत कुछ काम बाकी है। लोगों को प्रशिक्षण देने और सभी प्रकार के वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसन्धान की सुविधाएँ प्रदान करने की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को भी पूरा करना होगा। अन्तरिक्ष का अनुसन्धान मानव-जाति के लिए जिन भावी सम्भाव्यताओं का द्वार खोल रहा है, चाहे वे भलाई के लिए हों या बुराई के लिए, उनका भी यह तकाजा होगा कि अमेरिका उनके लिए अधिकाधिक साधनों और वैज्ञानिक दक्षता की व्यवस्था करे।

भावी जीवन-विधि

यद्यपि अमेरिका के सामने इस प्रकार की बहुत-सी गम्भीर समस्याएँ हैं तो भी उसके सामने कुछ अन्य जटिलतर और चकरा देने वाली समस्याएँ भी हैं, जो गरीबी के उन्मूलन की दिशा में की जा रही प्रगति का परिणाम हैं। इन समस्याओं का सम्बन्ध भौतिक सामग्रियों के मात्रा-त्मक प्राचुर्य के युग में जीवन के गुणात्मक स्वरूप के साथ है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि इन समस्याओं का सम्बन्ध केवल आर्थिक कठिनाइयों के साथ ही नहीं है, बल्कि प्रचुर भौतिक सामग्रियों से सम्पन्न समाज में पैदा होने वाले सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और नैतिक प्रश्नों से भी है। जीवन पद्धति किस ढंग की हो, इसकी विविध समस्याओं में से एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि व्यक्ति अपने अवकाश के खाली समय को किस ढंग से बिताये और सब लोगों को एक निश्चित और बँधी-बँधायी पद्धति को अपनाने के लिए समाज पर आज जो दबाव पड़ रहे हैं उनका मुकाबला करते हुए व्यक्ति के सृजनात्मक व्यक्तित्व की रक्षा कैसे की जाय।

उत्पादकता में हो रही निरन्तर वृद्धि और स्वचालित यन्त्रों के उपयोग के परिणामस्वरूप अमेरिकी लोग काम के घण्टों और शारीरिक श्रम में कमी करके भी अधिकाधिक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर सकेंगे। अभी हाल के वर्षों की स्थिति का अध्ययन करने पर इस बात के काफी प्रमाण मिल सकते हैं कि यदि अमेरिकी लोगों के पास धन और समय पर्याप्त हो तो वे अपने खाली समय में ऐसे काम करना पसन्द करेंगे जो उन्हें रुचिकर होंगे। अवकाश काल की इन प्रवृत्तियों की कुछ दिशाओं की हमने चर्चा की है, और इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि अनेक प्रकार की सांस्कृतिक, मनोरंजनकारी और हस्त-शिल्पिक प्रवृत्तियों में बहुत अधिक और उत्साहवर्धक प्रगति हुई है। लेकिन भविष्य में अमेरिकी लोगों को कुछ नई किस्म की रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना होगा ताकि उन्हें अपने खाली समय को व्यतीत करने के

लिए स्वेच्छा और आजादी से अपने मन-पसन्द क्रियाकलापों को चुनने का जो अधिकाधिक अवसर मिलेगा, उसका वे उपयोग कर सकें। इस-लिए आज अमेरिकी समाज के सामने, खासकर अमेरिकी शिक्षा-पद्धति के सामने यह चुनौती है कि वह अमेरिकी लोगों की रुचियों को नये ढंग में ढाले ताकि भविष्य में उन्हें जो पहले से भी अधिक खाली समय मिलेगा उसे वे समाज को नुक्सान पहुँचाने वाली प्रवृत्तियों के बजाय अपने मन को सन्तुष्ट करने वाली और साथ ही समाज को लाभ पहुँचाने वाली प्रवृत्तियों में लगा सकें।

आज के जमाने में एक ओर औद्योगिक देशों की अर्थ-व्यवस्थाएँ बहुत जटिल और परस्पर-निर्भर हैं और दूसरी ओर आबादियों में वृद्धि, जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के प्रयत्न और अन्तर्राष्ट्रीय तनाव उन पर और भी अधिक दबाव डाल रहे हैं। फलतः यह खतरा पैदा हो गया है कि कहीं ये मिलकर समाज को एक बँधी-बँधाई लीक पर चलने और सब व्यक्तियों को एक जैसा जीवन अपनाने के लिए मजबूर न करे। इसीलिए सरकारी संगठनों, व्यावसायिक कम्पनियों, ट्रेड यूनियनों को ही नहीं, विश्वविद्यालयों और अन्य प्राइवेट संस्थाओं को भी मजबूरन अपने आकार का विस्तार करना पड़ा है, अपने कार्यों को बढ़ाना और अपनी कार्य-विधियों को युक्तियुक्त आधार पर स्थापित करना पड़ा है, ताकि वे बीसवीं सदी के मध्यकाल की कठोर और परिवर्तमान परिस्थितियों का मुकाबला कर सकें।

इस नये रुझान के परिणामस्वरूप आज एक नये किस्म के मानव का उदय हुआ है जिसे विलियम ह्यूइट ने 'संगठन मानव' का नाम दिया है। इस 'संगठन मानव' की सफलता अपने से ऊपर के अधिका-रियों और अपने सहकर्मियों को इस बात का विश्वास दिखाने की उसकी योग्यता पर निर्भर है कि वह किन्हीं नये और सर्वथा अपरम्परागत विचारों का प्रचार कर या अपने आचरण को पूर्णतः वैयक्तिक रूप देकर संगठन के निर्विघ्न कार्यसंचालन में बाधा नहीं डालेगा। इसके अलावा अमेरिकी लोगों की बहुत बड़ी संख्या आज उपनगरों में रह रही

है और उसका जीवन-स्तर निम्नवर्गीय होने के बजाय मध्यवर्गीय है और साथ ही इन लोगों पर अपने स्थानीय समाज की जीवन-पद्धति का अनुसरण करने के लिए बहुत दबाव भी पड़ रहा है, जिससे वैयक्तिकता और सृजनात्मकता के लिए गुंजाइश और भी कम होती जा रही है। इसलिए भौतिक समृद्धि और प्राचुर्य का जो नया जमाना आ रहा है उसमें एक मुख्य काम ऐसी नई जीवन-विधियों का विकास करना होगा जिनसे लोग अपनी वैयक्तिकता का परित्याग किये बिना सामाजिक जीवन व्यतीत कर सकें और अपने व्यक्तिगत ध्येयों को भी प्राप्त कर सकें।

किन्तु अमेरिकी समाज की कुछ ऐसी विशिष्टताएँ भी हैं जो समाज की बँधी लीक के अधिकाधिक परिपालन और सारे समाज को एकाकार बना डालने की प्रवृत्तियों को उदासीन करती रहती है। संयुक्त राज्य में प्रायः हर व्यक्ति का सम्बन्ध ऐसे अनेक समुदायों और सगठनों से रहता है जिनका आपस में कोई सम्बन्ध नहीं होता। कारखाना, दफ्तर, ट्रेड यूनियन, गिरजाघर, राजनीतिक दल, सामाजिक क्लब और पड़ोस की सांस्कृतिक एवं खेल एसोसियेशने—इन सभी का अपने सदस्यों की वफादारी पर दावा होता है और सभी में यह होड़ चलती है कि लोग उनमें अधिकाधिक भाग लें। एक तरह से देखा जाय तो इन संस्थाओं और सगठनों में भाग लेना अपने आप में एक बँधी परिपार्टी का पालन करना है, क्योंकि सामाजिक जीवन में अधिकाधिक सक्रिय भाग लेने की वांछनीयता की मौजूदा धारणा आज की एक बँधी परिपार्टी ही है। किन्तु साथ ही व्यक्ति का किसी एक मन पसन्द धार्मिक सम्प्रदाय, राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन या पेशा-वर्ग से सोद्देश्य सम्बन्ध रहने के कारण उसमें उसके प्रति आस्था और गहरी निष्ठा पैदा हो जाती है जिसका नतीजा यह होता है कि वह कम मन पसन्द एवं वांछनीय और अधिक सर्व-सामान्य एवं व्यापक जीवन-पद्धति के पालन का प्रतिरोध करने लगता है। इस प्रकार की परस्पर-प्रतिस्पर्धा निष्ठाएँ और वका-दारियाँ भी रवैयों और रुचियों में विविधता पैदा करती हैं और इस

प्रकार अत्यधिक साम्य और एकरूपता लाने की प्रवृत्ति का प्रतिरोध करती है ।

साम्य और एकरूपता की प्रवृत्तियों से अमेरिका को चिन्तित होने का कारण यह है कि उसकी आस्था परम्परा से ही व्यक्तिवाद के आदर्श के प्रति रही है । अमेरिकी समाज में व्यक्तिगत सृजनात्मकता का भविष्य क्या होता है, यह इस बात पर निर्भर है कि लोग उसके विनाश के खतरो को कितनी उत्कटता से अनुभव करते हें, अमेरिकी लोगों में खुले मन से हर चीज पर विचार करने और प्रयोग करने की प्रवृत्ति कितनी है, व्यावसायिक कम्पनियों, ट्रेड यूनियनों और अन्य बड़े संगठनों में अपने सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना कितनी है, सरकार को किस हद तक जनता की मालिक के बजाय सेवक समझा जाता है और अन्य बहुत-सी सस्थाओं और मूल्यों का किस ढंग से विकास होता है । जब तक अमेरिकी समाज की ये विशेषताएँ मौजूद हैं तब तक यह आशा है कि आने वाले दशकों की अधिक कठिन परिस्थितियों में भी लोग एक-न-एक दिन व्यक्ति और समाज के बीच समन्वय के लिए नये और प्रभावकारी उपाय निकाल सकेंगे ।

मार्क्सवादी निष्ठान्त और अमेरिकी प्रणाली

कम्युनिस्ट इस तथ्य से इन्कार नहीं करते कि अमेरिकी प्रणाली ने उद्योग-विद्या और प्रबन्ध कौशल के क्षेत्रों में बहुत प्रगति की है और सफलता प्राप्त की है। वे स्पष्ट स्वीकार करते हैं कि इस सम्बन्ध में वे अमेरिकी सफलताओं से सबक ले सकते हैं और लेना भी चाहते हैं। लेकिन उनका यह विश्वास है कि स्वतन्त्र व्यवसाय प्रणाली में ये सफलताएँ जितनी तीव्र गति से प्राप्त होगी, उसका अन्तिम विनाश उतना ही नजदीक आता जायेगा। वे यह मानते हैं कि उद्योग-विद्या के क्षेत्र में हुई प्रगति का उत्पादक उपयोग केवल कम्युनिस्ट ही कर सकते हैं, फिर चाहे उस प्रगति का उद्गम कहीं भी हो।

मार्क्सवाद के अनुसार तथाकथित प्राकृतिक नियम ही पूँजीवाद को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। कम्युनिस्टों का कहना है कि यह विनाश निम्न तर्कसंगत प्रक्रिया के अनुसार होगा

1 उद्योग-विद्या (टैक्नोलॉजी) के क्षेत्र में प्रगति होने से बड़ी फर्में छोटी फर्मों से अधिक अच्छी स्थिति में और उन पर हावी हो जाएँगी।

2 इससे पूँजी कुछ थोड़े-से लोगों के हाथों में केन्द्रित हो जायेगी और उसके परिणामस्वरूप दौलत और आय भी थोड़े-से हाथों में केन्द्रित हो जायेगी। इससे मध्य वर्ग के लोग धीरे-धीरे प्रोलिटेरियत वर्ग (शोषित निम्न वर्ग या सर्वहारा वर्ग) में आ जायेंगे और इस प्रकार मुट्ठी भर धनी और बहुसंख्यक गरीब लोगों के बीच में एक चौड़ी खाई हो जाएगी।

3. इससे अनिवार्य रूप में बेरोजगारी रहेगी और इस बेरोजगारी का लाभ उठाकर श्रमिकों का शोषण किया जाएगा और उससे आम जनता की गरीबी और भी बढ़ेगी।

4 इससे एक ओर उत्पादक शक्ति में वृद्धि होगी और दूसरी ओर लोगों की क्रय-शक्ति कम होती जाएगी और परिणाम यह होगा कि पूँजीवादी व्यवस्था का खात्मा हो जाएगा। इस खात्मे को रोकने के लिए कारखानों को शास्त्रास्त्रों के उत्पादन में लगाया जा सकता है या अन्य साम्राज्यवादी दुसाहस किये जा सकते हैं, पर इनसे पूँजीवाद का

अन्त रुक नहीं सकता, कुछ के लिए समय टल ही सकता है।

हमारा विश्वास है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था के यथार्थ रूप का सर्वेक्षण और विश्लेषण करने से मार्क्सवादियों के इस तर्क का कदम-ब-कदम खंडन हो जाता है। मार्क्सवादी सिद्धान्त उन्नीसवीं शताब्दी के आर्थिक इतिहास की रोशनी में गढ़ा गया था और वह उस समय की घटनाओं की 'बन्धनहीन व्यवसाय' के सिद्धान्त के अनुसार की गई व्याख्या का उत्तर था। परन्तु आज की अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पर यह मार्क्सवादी सिद्धान्त लागू नहीं होता। लेकिन कम्युनिस्ट लोग इस सिद्धान्त का परित्याग नहीं कर सकते क्योंकि यह उनका बुनियादी सिद्धान्त है।

यह सही है कि टैक्नोलॉजी के क्षेत्र में की गई प्रगति से कुछ उद्योगों में बड़ी फर्मों की स्थिति छोटी फर्मों के मुकाबले अच्छी हो गई है, लेकिन यह बात सब उद्योगों के बारे में सही नहीं है। मार्क्सवादियों का यह कहना भी अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में सही सिद्ध नहीं हुआ कि पूँजी और उत्पादन क्षमता कुछ हाथों में केन्द्रित होने से दौलत और आय भी कुछ ही हाथों में केन्द्रित हो जाएँगी और उनके वितरण में बहुत असमानता हो जाएगी। छोटी और मध्यम फर्मों ने अनेक क्षेत्रों में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। मध्यम वर्ग के लोग प्रोलिटेरियत वर्ग में परिणत नहीं हुए। इसके विपरीत मार्क्सवादी जिन लोगों को 'मेहनतकश लोग' कहते हैं, उनकी स्थिति इतनी सुधार गई है कि वे निम्न वर्ग से ऊपर उठकर अधिकतर मध्यम वर्ग में शामिल हो गए हैं। अमेरिका में आज अधिक सख्या इस मध्यम वर्ग की ही है। अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था ने गरीबी को बढ़ावा नहीं, बल्कि सयुक्त राज्य की समूची जनता को प्राचुर्य के युग की देहरी पर पहुँचा दिया है। उसने सम्पत्ति और आय को कुछ थोड़े-से हाथों में केन्द्रित करने के बजाय उन्नति और धनोपार्जन के अवसरों को अधिक व्यापक बनाया है और सभी लोगों को अधिक सन्तोष प्रदान किया है।

यह बात भी सही नहीं है कि उद्योगविद्या (टैक्नोलॉजी) की प्रगति

से बेरोजगारी ज़रूर होगी ही। नैदान्तिक अन्तर्दृष्टि और पिछले दो दशकों के व्यावहारिक अनुभव ने यह सिद्ध कर दिया है कि स्वतन्त्र व्यवसाय वाला समाज चाहे तो बड़े पैमाने पर मन्दी और बेरोजगारी को रोक सकता है। संयुक्त राज्य की सरकार रोजगार को उच्चतम स्तर पर बनाये रखने की नीति से बधी हुई है और दोनों बड़े राजनीतिक दलों, व्यवसायी, कृषक और श्रमिक वर्गों के नेताओं और आम जनता, सभी ने उसे स्वीकार किया है। इस नीति को क्रियान्वित करने के उपायों में निरन्तर सुधार किया जाता है।

अपने देश में मन्दी और बेरोजगारी की आशंका से प्रेरित होकर अमेरिकी सरकार ने आक्रमण और साम्राज्यवाद की नीति भी नहीं अपनाई। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य ने उपनिवेशवाद का अन्त करने के लिए एम रचनात्मक भूमिका अदा की है और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अल्पविकसित देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मुक्तहस्त होकर सहायता दी है।

बड़े पैमाने पर शस्त्रीकरण एक ऐसी आवश्यकता है जो सत्तार की परिस्थितियों ने लोकतन्त्रीय देशों पर ज़बर्दस्ती थोप दी है। वह फालतू उत्पादन क्षमता की निकासी का उपाय नहीं, बल्कि एक बोझ है। इस शस्त्रीकरण की मजबूरी के कारण बहुत-से महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कामों को तब तक के लिए स्थगित करना पड़ा है जब तक कि शस्त्रास्त्रों में कमी करना सम्भव नहीं होता और उत्पादक साधन इन रचनात्मक कामों के लिए मुक्त नहीं होते।

इस प्रकार अमेरिका का अनुभव यह बताता है कि मार्क्सवादी सिद्धान्त के तर्क वास्तव में तर्क नहीं, तर्कभास हैं। अमेरिकी आर्थिक प्रणाली की व्यावहारिकता और नैतिकता पर हमारी गहरी आस्था है और उसका आधार यह अनुभव तो है ही साथ ही हमारा यह विश्वास भी है कि जैफर्सन का व्यक्तिगत स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन का सिद्धान्त मानवीय आत्मा में गहराई तक बद्धमूल है। हमें निश्चय है कि उत्पादन और प्रवन्ध को अधिक कुशल बनाने के लिए अमेरिकी प्रणाली में किसी

भी सत्तावादी प्रणाली से अधिक गुजाइश और क्षमता है। हम जानते हैं कि यह प्रणाली किसी भी तानाशाही प्रणाली से अधिक स्वतन्त्रता और आत्म-उत्तरदायित्व प्रदान करती है।

अमेरिकी आर्थिक प्रणाली का नाम क्या हो ?

तब हमें इस अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को क्या नाम देना चाहिए ? जो लोग परम्परागत आर्थिक विचारधाराओं के अनुसार इसे किसी वर्ग में रखना या कोई पुराना नाम देना चाहते हैं, वे उसके स्वरूप को देख कर चक्कर में पड़ जाते हैं।

अमेरिकी प्रणाली में प्राइवेट व्यावसायिक क्रियाकलापों की मुनाफा कमाने की इच्छा आर्थिक अभिवृद्धि के प्रमुख प्रेरक कारणों में से एक है इसलिए उस हद तक यह प्रणाली पूंजीवादी है। वास्तव में यह स्वतन्त्र व्यवसायियों, स्वतन्त्र श्रमिकों और स्वतन्त्र उपभोक्ताओं वाली आर्थिक प्रणाली है। लेकिन अगर पूंजीवाद का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था है, जिसमें व्यवसायी जो चाहे कर सकता है, जिसमें श्रमिकों और उपभोक्ताओं का शोषण किया जाता है और पूंजीपति ही आर्थिक क्रियाकलाप का मुख्य लाभ उठाता है, तो उस अर्थ में अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था पूंजीवादी नहीं है। यदि पूंजीवाद का अर्थ यह है कि सरकार केवल व्यवसायी के फायदे के लिए ही सब काम करे, तो उस अर्थ में भी अमेरिकी प्रणाली पूंजीवादी नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी में 'बन्वत हीन व्यवसाय' (लैसे फेयर) के निष्ठान्त का जो अभिप्राय था यदि वही पूंजीवाद का अर्थ है तो भी अमेरिकी प्रणाली को पूंजीवादी प्रणाली नहीं कहा जा सकता।

अमेरिकी प्रणाली समाजवादी प्रणाली भी नहीं है, अगर समाजवाद का अर्थ एक ऐसी अर्थ-व्यवस्था हो, जिसमें सभी या अधिकांश कारखाने राज्य की सम्पत्ति हो और राज्य द्वारा चलाये जाते हो और राज्य ही यह निश्चय करता हो कि क्या उत्पादन किया जायें, कौन-से नये संयन्त्र लगाये जाएँ और क्या मजदूरियाँ और वेतन दिये जायें, आदि। यदि समाजवाद का अर्थ ऐसी व्यवस्था है जिसमें राज्य ही सामाजिक और

आर्थिक जीवन का नियामक हो तो भी अमेरिकी प्रणाली समाजवादी नहीं है। लेकिन यदि समाजवाद का अर्थ एक ऐसी प्रणाली हो, जो लोकतंत्रीय पद्धति से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मानव-कल्याण और आर्थिक सुरक्षा के उद्देश्यों और पैमानों को निर्धारित और प्राप्त करती है, तो संयुक्त राज्य को निस्सन्देह समाजवादी समाज कहा जा सकता है। अमेरिकी लोग यह आशा करते हैं कि सरकार प्राइवेट उद्यमों को इनमें से यथासम्भव अधिकतम लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता देगी और जो लक्ष्य रह जायें उनकी प्राप्ति के लिए सरकारी कार्यक्रम बनायेगी। निस्सन्देह इस अर्थ में संयुक्त राज्य कम्युनिस्ट राज्यों से भी कहीं अधिक लोकतन्त्रीय समाजवादी राज्य है।

अमेरिकी प्रणाली में सरकारी और प्राइवेट सभी सस्थाओं से यह आशा की जाती है कि वे आम जन-कल्याण को समुन्नत करेगी। इस प्रकार की प्रणाली में प्राइवेट व्यवसाय अपने आपमें कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि वह सरकारी हस्तक्षेप को न्यूनतम रखते हुए जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला सबसे प्रभावकारी संगठनात्मक साधन है। इस तरह की प्रणाली में सरकार या शासन भी अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, वह भी उन कार्यों को पूरा करने के लिए संगठित किया गया एक साधन है, जिन्हें प्राइवेट व्यवसाय पूरा नहीं कर सकते।

इसलिए जहाँ तक पूँजीवाद और समाजवाद के ऐतिहासिक अर्थों का ताल्लुक है, अमेरिकी प्रणाली को इन दोनों में से किसी भी वर्ग में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसमें न राज्य का प्राधान्य है, न प्राइवेट व्यवसाय का और न किसी अन्य अकेले वर्ग का। इसमें सरकारी और प्राइवेट सभी सस्थाएँ पर्याप्त आत्मनिर्धारण और आत्म-उत्तरदायित्व के साथ अपना-अपना काम निभाती हैं।

तब यह निर्णय कौन करता है कि अन्ततः उत्तरदायित्वपूर्ण रीति से काम करने का पैमाना अमुक है? इस नाजुक प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। यही वजह है कि अमेरिकी प्रणाली की कोई एक निश्चित परिभाषा करना और उसे एक निश्चित वर्ग में रखना कठिन है।

अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की अधिक से अधिक सही परिभाषा यदि कोई हो सकती है तो वह यही कि अमेरिकी आर्थिक प्रणाली अमेरिकी जनता के राष्ट्रीय हितों को पूरा करती है—और वे राष्ट्रीय हित क्या हैं, इसकी अभिव्यक्ति लोकतन्त्रीय राजनीतिक प्रक्रियाओं, जन-मत, बहुसंख्यक प्राइवेट वर्गों और सगठनों और व्यक्तिगत उपभोक्ता की हैसियत से सभी अमेरिकी नागरिकों की पसन्द और रवैयों के जरिये होती रहती है ।

‘राष्ट्रीय हित’ शब्द बहुत अस्पष्ट और अस्थिर धारणा का अभिव्यजक हो सकता है, परन्तु अतीत में यह धारणा काफी स्पष्ट और सुनिश्चित हो गई है । ‘बन्धनहीन व्यवसाय’ के सिद्धान्त के समर्थकों ने कोई निश्चित आर्थिक स्तर निर्धारित करने के प्रयत्नों का हमेशा विरोध किया है । अर्थात् उपभोग का स्तर क्या हो, आवास-व्यवस्था का स्तर क्या हो या आर्थिक विस्तार की गति कितनी होनी चाहिए—इन सब बातों के निर्धारण के प्रयत्नों पर उन्होंने हमेशा नाराजगी जाहिर की है । उनका मत यह रहा है कि यदि हर आदमी केवल अपने हित को पूरा करने का प्रयत्न करे तो उसका जो नतीजा होगा, वही सर्वोत्तम सम्भव परिणाम होगा । लेकिन आज इस बारे में कुछ निश्चित आदर्श और पैमाने निर्धारित हो रहे हैं कि आर्थिक गतिविधि के क्या लक्ष्य होने चाहिए—उदाहरण के लिए उन सब लोगों को काम मिलना चाहिए जिनमें काम करने की शक्ति और इच्छा है, रोजगार, उत्पादन और मूल्यों में बहुत उग्र उतार-चढ़ाव नहीं होने चाहिए ; लोगों के लिए मजदूरी, मकान, पोषक आहार और स्वास्थ्य सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए और आर्थिक अभिवृद्धि की गति ऐसी होनी चाहिए कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुई प्रगतियों का लाभ उठाते हुए वह देश के भीतर बेरोजगारी को दूर कर नके और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व की समस्याओं के हल करने के लिए पारस्परिक सहयोग को सहारा दे सके । आज यह बात नहीं मानी जाती कि यदि हर व्यक्ति को अथवा हर संगठित वर्ग को अपना हित पूरा करने के लिए पूरी छूट दे दी जाय तो उसका जो

परिणाम होगा, वही सर्वोत्तम परिणाम होगा। हर व्यक्ति और वर्ग से यह उम्मीद की जाती है कि वह अपना स्वार्थ-साधन इस ढंग से करेगा कि उससे राष्ट्र का हित-साधन हो।

राष्ट्र-हित के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता है, उनमें से कुछ ही ऐसी हैं जिन्हें कानून का रूप दिया गया है। शेष वस्तुएँ ऐसी हैं जो या तो 'अलिखित कानून' और परम्परा के रूप में विद्यमान हैं या उन नर-नारियों के चुनाव पर छोड़ दी गई हैं जिन्हें राजनैतिक और आर्थिक निर्णय करने की स्वतन्त्रता है। आम जनता बड़े व्यवसायों, बड़ी ट्रेड यूनियनों और बड़े शासन-यन्त्र को तो स्वीकार करती है, परन्तु वह इस बात के लिए राजी नहीं है कि जनता को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को निर्धारित करने का काम इनमें से किसी के भी हाथ में हो। जिन लोगों के हाथ में आज बड़े व्यवसायों, बड़ी ट्रेड यूनियनों या बड़े प्रशासनिक संगठनों के संचालन का उत्तर-दायित्व है, वे जनता के इस रवैये से परिचित हैं और उसका सम्मान करना अधिकाधिक सीखते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर कम्पनी-गुट विरोधी कानूनों में कम्पनियों के आर्थिक शक्ति के किसी खास दुरुपयोग को रोकने की व्यवस्था न हो, तो भी अलिखित कानून और परम्पराएँ ऐसी बन गई हैं कि इस शक्ति का दुरुपयोग कर जन-हित को नुकसान पहुँचाने वाली कम्पनियों को सजा दी जाती है। यह सजा उनके खिलाफ प्रचार के रूप में हो सकती है, जिनसे उनकी विक्री पर बुरा असर पड़ सकता है और यह भी संभव है कि इस प्रकार से उन्हें अपने लिए जिस किस्म के कर्मचारियों की आवश्यकता है वे न मिले। इसके अलावा यह सजा कांग्रेस (संसद्) द्वारा जाँच के अथवा लोकतन्त्रीय प्रणाली में असंतोष प्रकट करने के लिए विद्यमान किसी अन्य विधि के रूप में भी हो सकती है। इसी तरह यदि सरकार पूरी तरह कार्रवाई न करे अथवा ज़रूरत से ज्यादा हस्तक्षेप करे तो उसके विरुद्ध भी जनता चुनावों में मतदान के द्वारा अपना असन्तोष व्यक्त करती है।

यह सारी व्यवस्था लचकीली है। आहिस्ता-आहिस्ता कुछ अलिखित कानून लोकतंत्रीय बहस-मुवाहसे के बाद लिखित कानून का रूप धारण कर लेते हैं। किन्तु कानून ही इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग नहीं हैं। एक तरह से वे सिर्फ यह सकेत ही देते हैं कि किन-किन बातों में यह व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं चल रही थी। यदि प्राइवेट व्यवसायियों ने अपनी आर्थिक सत्ता का कुछ दुरुपयोग न किया होता तो कम्पनी-गुट विरोधी कानून कभी न बनते। अगर मजदूरी की दरे कुछ स्थानों पर एक प्रचलित स्तर से नीची न होती तो मजदूरी-घटा (वेज-अवर) कानून न बनता। अगर औद्योगिक उत्पादन में गम्भीर शिथिलता और मन्दी न आती तो रोजगार कानून कभी न बनाया जाता। प्राइवेट व्यवसायी सामान्य जन-हित की आवश्यकताओं का जितना ध्यान रखेंगे सरकार द्वारा कानून बनाये जाने और निर्धारित स्तरों को लागू किये जाने की गुंजाइश उतनी ही कम होगी।

इस प्रकार संयुक्त राज्य में जो आर्थिक प्रणाली उभर रही है वह अनेक 'शुद्ध' आर्थिक प्रणालियों की विशिष्टताओं का सम्मिश्रण है और उससे यह आशा ब्रधती है कि वह व्यक्ति की आवश्यकताओं और आधुनिक टेक्नोलॉजी की सम्भावनाओं के साथ समन्वय कर सकेगी।

जो लोग यह अनुभव करते हैं कि अमेरिका में एक अद्वितीय किस्म की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था विकसित हो रही है, उन्होंने इन व्यवस्था के लिए अनेक नाम सुभाये हैं। यदि यह कहा जाय कि उनके लिए 'आर्थिक लोकतन्त्र' नाम उपयुक्त होगा तो उसने यह अर्थ तो ध्वनित हो जाएगा कि यह व्यवस्था आम लोक-कल्याण का ध्यान रखती है, परन्तु साथ ही 'आर्थिक लोकतन्त्र' से यह अर्थ भी निकलता है कि उसने श्रमिक और प्रदूषक मिलकर व्यवसाय की प्रवन्ध-सम्बन्धी नीति निर्धारित करते हैं, जब कि इस शब्द में हमारा वैसा अभिप्राय नहीं है। कुछ लोगों ने यह सुझाव दिया है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था को 'जनता का पूंजीवाद' कहा जाय, क्योंकि वह पूंजीवादी साधनों से समस्त जनता के कल्याण और प्रतिष्ठा को साधना चाहती है। यह

नाम इस अभिप्राय को सही रूप में व्यक्त करता है कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था कुछ लोगों का ही नहीं, बल्कि प्रायः सभी लोगों का हित-साधन करती है। किन्तु 'जनता का पूंजीवाद' शब्दों का प्रयोग कभी-कभी इस तथ्य को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है कि साधारण आय वाले करोड़ों अमेरिकियों के पास बड़ी-बड़ी कम्पनियों के शेयर हैं। यह बात नहीं ज़रूर है, लेकिन इससे ये करोड़ों अमेरिकी 'पूंजीवाद' शब्द के परम्परागत अर्थ में, पूंजीवादी नहीं बन जाते और न ही अमेरिकी व्यवसाय प्रणाली, जैसा कि हमने ऊपर बताया है, इस अर्थ में पूंजीवादी कही जा सकती है। जो भी नाम चुना जाय, वह ऐसा होना चाहिए कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं को अभिव्यक्त कर सके, उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के अद्भुत सम्मिश्रण को पूरा कर सके।

हमारे कथन का यह अभिप्राय कदापि नहीं कि अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था में जो मुख्य विशेषताएँ हैं वे केवल संयुक्त राज्य की ही अपनी विशेषताएँ हैं। इनमें से कई महत्वपूर्ण विशेषताएँ ऐसी हैं जिनका जन्म अन्य देशों में हुआ, जहाँ की स्वतंत्र व्यवसाय वाली अर्थ-व्यवस्था भी अमेरिका के समान ही कायाकल्प में से गुजरी। इसलिए संयुक्त राज्य की अर्थ-व्यवस्था को बिलकुल सही और सच्चे रूप में अभिव्यक्त करने वाला कोई एक नाम न होने से हमारा यह सुझाव है कि इसे सिर्फ अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था के नाम से व्यक्त किया जाना चाहिए।

अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था—क्या वह अन्य देशों में भी अपनायी जा सकती है ?

हमने अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था का वर्णन करते हुए बहुत गर्व से बताया है कि उसने क्या-क्या सफलताएँ प्राप्त की हैं और वह कैसे अपने आपको सुधारती और प्रगति की ओर ले जाती है। किन्तु क्या अन्य देश अमेरिका के इस अनुभव से कोई शिक्षा ले सकते हैं ?

क्या यह प्रणाली सम्पूर्ण या आंशिक रूप में अन्य देशों में भी अपनायी जा सकती है ?

अमेरिकी प्रणाली में कुछ तत्व ऐसे हैं जो सभी आर्थिक प्रणालियों में पाये जाते हैं और कुछ तत्व उसके अपने विशिष्ट तत्व हैं। एक ओर वह बहुत-से ऐसे बुनियादी मूल्यों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करती है, जो समस्त मानव-जाति में समान रूप में पाये जाते हैं, और ऐसी आर्थिक विधियों को इस्तेमाल करती है जो ससार में सभी जगह इस्तेमाल किये जाते हैं या किये जा सकते हैं। दूसरी ओर इन मूल्यों को मूर्त रूप प्रदान करने वाली विशिष्ट संस्थाएँ पश्चिमी समाज की, जिसमें वे विकसित हुई हैं, विशिष्ट संस्कृति और परम्पराओं से प्रभावित हैं। साथ ही ये संस्थाएँ अमेरिका की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों से कुछ सीमाओं और सम्भावनाओं के दायरे में भी बंधी हुई हैं।

जो दूसरे राष्ट्र की स्वतन्त्रता, न्याय और जन-कल्याण के उन्हीं मूल्यों को प्राप्त करना चाहते हैं, जिन्हें अमेरिकी लोग चाहते हैं, वे इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अमेरिकी लोगों द्वारा अपनाये जा रहे अनेक रुखों और विधियों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढालकर अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत-से ऐसे देश हैं जो अमेरिका की विचार और कर्म की स्वतन्त्रता और विविधता का आदर करते हैं। काम और कारीगरी, नये आविष्कार और उद्यम, वर्गीय भेद के बावजूद पारस्परिक सहायता और सहयोग, परम्परागत सिद्धान्त के बजाय व्यवहारिक अनुभव के आधार पर कार्य का निश्चय—इन सब के बारे में अमेरिकी लोगों का जो रुख रहता है वह अन्य देशों के भी अनुकूल है और थोड़ा-बहुत उनके लोगों में पाया भी जाता है। इसी प्रकार अमेरिका की उत्पादक तकनीकों और प्रबन्ध विधियाँ, अपनी कार्य-क्षमता के कारण आर्थिक संगठन के विभिन्न रूपों में सारे संसार में फैल रही हैं।

अमेरिका का अनुभव अन्य देशों के लिए कामकर दो कारणों से

बहुत महत्वपूर्ण है

1 वह यह सिद्ध करता है कि वधी-वघाई स्थिर राष्ट्रीय आय का अधिक लोगो मे पुनर्वितरण करने का प्रयत्न समूची जनता के आर्थिक कल्याण को साधने और समाज मे अधिक सामाजिक न्याय की स्थापना करने मे सफल नहीं हो सकता । इसके विपरीत तेज गति से आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना ही उसका अधिक अच्छा और सफल उपाय है ।

2 वह यह भी सिद्ध करता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिक्रम और आत्म-उत्तरदायित्व को बलिदान किये बिना भी काफी आर्थिक विकास किया जा सकता है ।

वास्तव मे अमेरिकी समाज तीन अंशत परस्पर विरोधी मानवीय आदर्शों—आर्थिक कल्याण, सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता—मे समन्वय कर रहा है जो इतिहास मे अनुपम है । यह समन्वय बिल्कुल पूर्ण कभी नहीं हो सकता, किन्तु फिर भी संयुक्त राज्य मे वह बहुत-से अन्य देशो की अपेक्षा कहीं अधिक हुआ है और भविष्य मे उसके और भी आगे बढ़ जाने की आशा है । यह समन्वय इतनी अधिक मात्रा मे हो सकता है, यह नि सन्देह समूचे मानव-समाज के लिए एक अत्यन्त महत्वपूर्ण सन्देश है । यह हो सकता है कि दूसरे देशो को, जिनकी संस्कृतियाँ, परिस्थितियाँ और सम्भावनाएँ भिन्न हैं, अमेरिका मे प्रचलित प्राइवेट व्यवसाय के कुछ सगठनात्मक रूप अपनी परम्पराओं अथवा वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल प्रतीत न हो । इस संक्षिप्त विवरण मे हम यह नहीं बता सकते कि अलग-अलग परिस्थितियों मे कौन-से अलग-किसम के आर्थिक सगठन होने चाहिए । उदाहरण के लिए एक ओर पश्चिमी सांस्कृतिक परम्परा वाले अत्यधिक उद्योग-प्रधान देश के, और दूसरी ओर एक सर्वथा भिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कृषि-प्रधान देश के, आर्थिक सगठनों मे क्या अन्तर होना चाहिए । इसके अलावा, आबादियों मे द्रुत गति से हो रही वृद्धि और निरन्तर बढ़ रही आर्थिक उन्नति की आशाओं के कारण आज ससार के कुछ देशो को, जिनकी आबादी तो बहुत सघन है परन्तु विकास बहुत अपर्याप्त है, उतना आर्थिक

विकास कुछ दशकों के भीतर ही कर लेना होगा, जितना कि संयुक्त राज्य ने एक शताब्दी में किया। ऐसी परिस्थिति में यह संभव है कि इन देशों की सरकारें आर्थिक विकास के लिए उससे कहीं अधिक अभिक्रम करें और उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले जितना कि संयुक्त राज्य की सरकार ने लिया।

इस प्रकार यह आवश्यक है कि अमेरिकी प्रणाली की उन विशेषताओं को, जो अन्य देशों की आवश्यकताओं और सभावनाओं के साथ संगत हैं, उसकी ऐसी विशिष्टताओं से अलग किया जाय जो उनके अनुकूल नहीं हैं। यह भेद न किये जाने के कारण ही अमेरिका में और अन्य देशों में अमेरिकी प्रणाली की अन्य देशों के लिए उपयोगिता के प्रश्न पर गलतफहमी पैदा हो जाती है। कुछ अमेरिकी लोगों का ख्याल है कि अन्य देश तभी काफी प्रगति कर सकते हैं, जब कि वे अमेरिकी अर्थ-व्यवस्था की विशिष्ट किस्म की सस्थाओं और उसके रवैये और औद्योगिक विधियों को अपनाएँ। दूसरी ओर अनेक एशियाई और अफ्रीकी लोगों का ख्याल है कि अमेरिकी अनुभव में ऐसी कोई भी बात नहीं है जो उनकी सर्वथा भिन्न संस्कृतियों और परम्पराओं के साथ संगत होती हो। ये दोनों ही विचार समान रूप में गलत हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी यह स्वीकार करके नहीं चलाता कि अमेरिकी जनता इस शताब्दी में मानव-समाज की प्रगति और कल्याण में जो महत्त्वपूर्ण योग देती रही है, वह स्वतन्त्रता और व्यक्तित्व की रक्षा करते हुए उत्पादकता और रहन-सहन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिए विकसित किये गए रवैयों और तकनीकों का एक अद्भुत सम्मिश्रण है।

यह सही है कि कम्युनिस्ट अधिनायकतन्त्र ने भी सोवियत मंच में आर्थिक विस्तार को अनाधारण तीव्र गति से बढ़ाया है, पूँजी-निर्माण में भारी वृद्धि की है और बहुत तेज रफ्तार से तकनीकी क्षेत्र में उन्नति की है, और यह सम्भव है कि अन्ततः वह अन्य कम्युनिस्ट देशों में भी ये सफलताएँ प्राप्त कर सके। लेकिन इसके लिए उसे केवल राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का वनिदान ही नहीं करना पड़ा है, बल्कि

अपने उत्पादक साधनों को शस्त्रास्त्रों के निर्माण में लगाना और जन-कल्याण को पूर्णतः उपेक्षित भी करना पड़ा है। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि आतंक और अन्याय का सहारा लिये बिना भी, सन्तुलित आर्थिक अभिवृद्धि सम्भव है और वह भी केवल औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में ही नहीं, अन्य देशों में भी।

सारांश

यदि ऐसा कोई एक विषय है, जो समूचे अमेरिकी इतिहास में चाहे जितने परिवर्तन होने पर भी अपरिवर्तित रूप से चर्चा का विषय रहा हो तो वह सिर्फ यही है कि हैमिल्टन के आर्थिक प्रगति के विचार का जैफर्सन के स्वतन्त्रता और आत्म-उत्तरदायित्व के आदर्श के साथ समन्वय किया जाय।

अमेरिका ने आर्थिक क्षेत्र में आशातीत प्रगति की है। आज हर आदमी अपनी आँखों से यह देख सकता है कि राष्ट्र की आय और दौलत में वृद्धि हुई है, कारखाने और साधन बड़े हैं। वह पुराने युग की और अन्य देशों की आय और दौलत के साथ अमेरिका की आज की आय और दौलत की तुलना कर सकता है। लेकिन प्रगति की इस प्रक्रिया में जैफर्सन के स्वावलम्बन के आदर्श का बलिदान हुआ है या उसकी रक्षा हुई है, उसे आँकड़ों से नहीं नापा जा सकता। किन्तु हमने यह देखा है कि उद्योग, परिवहन और वित्त के क्षेत्रों में बड़ी कम्पनियों के प्रभुत्व की आशकाओं को दूर करने और कृषि और छोटे व्यवसायों को संरक्षता देने के लिए अनेक आन्दोलन हुए हैं। इन आन्दोलनों का अमेरिकी कानून पर गहरा असर पड़ा है और 'आम जनता' पर एव व्यवसायियों, श्रमिकों, कृषकों और सरकार के वर्तमान रुखों पर उसका शायद उससे भी अधिक जबरदस्त असर पड़ा है। जैफर्सन के आत्म-उत्तरदायित्व और स्वावलम्बन के आदर्श आज हमारे औद्योगिक समाज में भी सच्चे अर्थों में विद्यमान हैं।

जैफर्सन का यह विश्वास गलत था कि इन आदर्शों की भावना—

जिसे वह अमेरिका का सार कहता था—केवल पारिवारिक फार्मों और कारीगरों के छोटे-छोटे कारखानों में ही रह सकती है। यह सही है कि जिस जमाने में उद्यमी उद्योग संचालक यह दावा करते थे कि 'अपने निज के घर में उन्हें खुद मालिक होने' का पूरा अधिकार है, यानी जिस युग में उद्योग का अर्थ होता था मजदूरों का शोषण, आर्थिक असुरक्षा, गन्दी रिहायशी व्यवस्था और फलतः दुःखपूर्ण पारिवारिक जीवन, उस जमाने में कारखानों में पारस्परिक सम्मान की भावना शायद ही सम्भव थी। पर आज वह जमाना नहीं रहा। आज आधुनिक टेक्नोलॉजी और रहन-सहन और काम की आधुनिक परिस्थितियाँ श्रमिकों के इतनी अनुकूल हैं कि वे समाज में अपने स्थान के लिए गर्व अनुभव करते हैं, और अन्य सभी वर्गों के आदर के पात्र हैं।

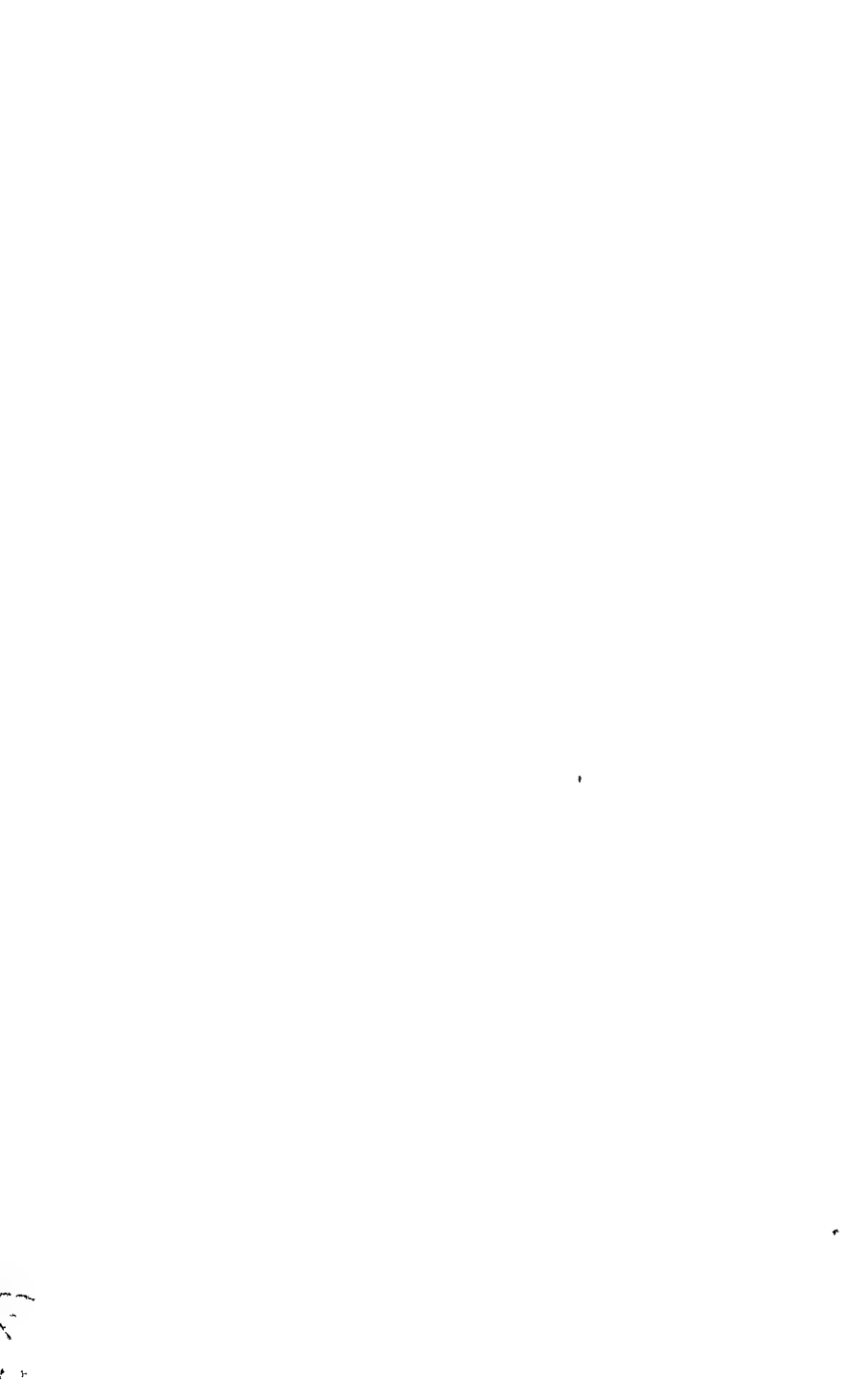
लेकिन इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि यह जैफर्सनवादी भावना, जो आज बहुत प्रबल है, गहरी और औद्योगिक युग के भावी विकास में भी स्वतः जीवित रहेगी। वर्तमान सफलताओं और उपलब्धियों ने यह साबित कर दिया है कि पारस्परिक सहयोग और आदर के साथ मिल कर काम करने वाले प्रबन्धकों और कर्मचारियों में यह भावना रह सकती है। वास्तव में यह भावना सरकारी अधिकारियों में भी विद्यमान है, जो यह अनुभव करते हैं कि उनका काम शासन करना नहीं, बल्कि समस्त जनता के सर्वसामान्य हित को साधना है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि पूर्णतः सुनिश्चित न होने पर भी इस बात की बहुत सम्भावना है कि स्वावलम्बी व्यक्तियों को पूर्ण स्वतन्त्रता से काम के अवसर प्रदान करने वाला संप्रण लोकतन्त्र न केवल जीवित रहेगा, बल्कि औद्योगिक समाज के आगामी युग में और भी शक्तिशाली बनेगा।

अमेरिकी समाज की अतीत और वर्तमान उपलब्धियाँ यह सिद्ध करती हैं कि अमेरिका के लोग तर्कवादी हैं, व्यावहारिक प्रयोजनवादी हैं और साथ ही आशावादी भी हैं। यद्यपि ये गुण अमेरिका के भविष्य के लिए बहुत आशा पदा करते हैं तो भी यह असम्भव नहीं है कि इन गुणों का उपयोग गलत रीति से किया जाय। एक ओर यह सम्भव है

कि लोग बड़े-बड़े मधुर स्वप्न लेने लगे, यह मानने लगे कि सभी व्यक्ति-गत और सामाजिक समस्याएँ मानवीय तर्क-बुद्धि और 'सामाजिक इंजिनियरी' के उपयोग से हल हो सकती हैं। और दूसरी ओर यह भी असम्भव नहीं है कि लोग अब तक की उपलब्धियों में ही पूर्ण सन्तोष मान कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएँ और कोई भी नया परिवर्तन और सुधार करने की आवश्यकता अनुभव न करे। अमेरिकी लोगों के लिए इन दोनों चरम रुखों में से किसी को भी अपना घातक होगा।

पिछले दो दशकों में मानव और समाज के स्वरूप और उनकी सम्भावनाओं के बारे में जो नई और अधिक गहरी अवधारणाएँ विकसित हुई हैं, उन्होंने यह साबित कर दिया है कि इन दोनों चरम मनोवृत्तियों से बचना असम्भव नहीं है। इन अवधारणाओं में ये मान्यताएँ विद्यमान हैं कि मानवीय तर्क-बुद्धि शक्तिशाली होने पर भी सर्वशक्ति-सम्पन्न नहीं है, मानवीय प्रकृति में असीम क्षमताएँ हैं, किन्तु वे अच्छाई की ओर ही नहीं, बुराई की ओर भी जा सकती हैं, और समाज को उन्नत किया जा सकता है, भले ही उसे पूर्णता के स्तर तक कभी न पहुँचाया जा सकता हो। पूर्ण और अन्तिम विजय को असम्भव मानने पर भी उसके लिए उद्योग करना ही व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की रक्षा और मानव-कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सबसे अच्छी गारंटी है।

परिशिष्ट तालिकाएँ



परिशिष्ट तालिका-1

आर्थिक वृद्धि, 1929-1960 (डालर 1960 के मूल्यों के अनुसार)

वर्ष	राष्ट्रीय आय (अरब डालरो मे)	कुल असैनिक कर्मचारी (लाखो मे)	राष्ट्रीय आय प्रति कर्मचारी (डालरो मे)	व्यक्तिगत उपभोग व्यय (अरब डालरो मे)	आवादी (लाखो मे)	उपभोग व्यय (प्रति व्यक्ति)
1929	207.1	476	4351	141.3	1219	1159
1930	187.6	455	4123	132.9	1232	1079
1931	173.4	424	4091	128.8	1241	1037
1932	147.5	389	3792	117.2	1249	938
1933	144.1	388	3714	114.4	1257	910
1934	158.0	409	3866	120.3	1265	951
1935	173.2	423	4095	127.7	1274	1003
1936	197.9	444	4457	140.6	1282	1097
1937	208.2	463	4497	145.6	1290	1129
1938	198.8	442	4498	143.1	1300	1101
1939	215.2	458	4699	151.1	1310	1153
1940	233.0	475	4922	159.2	1321	1205
1941	272.6	504	5409	169.7	1334	1272
1942	311.4	538	5788	166.1	1349	1232
1943	350.8	545	6437	170.5	1367	1247

1944	376 3	540	6969	176 6	1384	1276
1945	369 1	528	6991	188 9	1399	1350
1946	321 7	553	5817	211.6	1414	1497
1947	321 1	578	5555	215.3	1441	1494
1948	333 6	591	5645	219 4	1466	1496
1949	334 2	584	5723	225 0	1492	1508
1950	362 3	597	6069	238 7	1517	1574
1951	392 0	608	6447	240 8	1544	1560
1952	406 8	610	6669	247 0	1570	1573
1953	425 5	619	6874	258 9	1596	1622
1954	416 8	609	6844	262 3	1624	1615
1955	449 7	629	7149	282 0	1653	1706
1956	459 2	647	7097	291.3	1682	1732
1957	467 8	650	7197	299 1	1712	1747
1958	459 9	640	7183	301.0	1741	1735
1959	490 6	656	7479	319 3	1771	1803
1960	504 4	667 ¹	7562	328 9	1807	1820

1 अलास्का और हवाई भी शामिल हैं (इन दोनों राज्यों को अलग कर देने पर 664)।

परिशिष्ट तालिका-2

कुल राष्ट्रीय आय—स्वतन्त्र संसार के देशों का संक्षिप्त विवरण
(सन् 1959 में चालू बाजार मूल्यों के अनुसार डालरों में)

	कुल राष्ट्रीय आय (लाख डालरों में)	राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति (डालरों में)	1959 के मध्य में आवादी (लाखों में)
पश्चिमी यूरोप (ग्रीस और टर्की सहित) ..	29,37,580	838	3,507
अफ्रीका (मिस्र को छोड़कर).....	2,76,070	125	2,210
मध्य पूर्व (ग्रीस और टर्की को छोड़कर और मिस्र को मिला कर).....	1,39,970	188	745
दक्षिण एशिया.....	3,89,470	72	5,413
सुदूर पूर्व.....	5,44,250	167	3,260
ओशेनिया.....	1,82,500	1200	152
लैटिन अमेरिका... ..	5,65,310	285	1,986
संयुक्त राज्य			
महादीपीय संयुक्त राज्य.....	48,21,000	2722	1,771
अन्य संयुक्त राज्यात्मक प्रदेश... ..	38,560	1205	32
कनाडा...	3,45,930	1983	174
वेस्ट इण्डियन अमेरिका.....	130	371	1
कुल योग' ...	1,02,40,770	532	19,250

1 1,00,000 के दल

परिशिष्ट तालिका-3

सन् 1909 से 1959 तक विभिन्न वर्षों का प्रति मानव घटा उत्पादन
(1909=100)

वर्ष	कुल	कृषि	कृषि-भिन्न	निर्माण उद्योग
1909	100 0	100 0	100 0	100 0
1919*	112 8	104 8	114 0	115 0
1929*	140 3	114 8	142 0	198 1
1938*	171 7	138 9	176 5	232 5
1947-49* .. .	209 6	184 5	205 8	280 1
1956*	263 9	252 0	253 9	356 0
1959	305 6	342 6	281 1	385 5

परिशिष्ट तालिका-4

विभिन्न उद्योगों में 1947 से 1950 तक प्रति मानव-घण्टा उत्पादन में
वार्षिक वृद्धि (प्रतिशत वार्षिक)

निर्माण उद्योग

डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ	4.2
सीमेंट	4.5
चीनी मिट्टी की वस्तुएँ	2.2
कागज और लुगदी	3.7
धातु प्रद्रावण और शोधन (ताँबा, सीसा और जस्त)	4.0
रेयन और कृत्रिम वस्त्र	9.6
इस्पात	3.0

खनिज उद्योग

ऐन्थ्रेसाइट कोयला	6.3
बिट्यूमिनी कोयला	5.8
ताँबा	2.8
लोहा	—5

सेवाएँ

रेल परिवहन (यातायात)	4.3
टेलीग्राफ	—1.2

परिशिष्ट तालिका-5

सर्वाधिक आय वाले 5 प्रतिशत अमेरिकी परिवारों और आय-अर्जको
की स्वायत्त आय

वर्ष	आय-अर्जक	परिवार
1914.....	32 0	
1920.....	24 0	
1929.....	33 8	
1939.....	26 8	
1950.....	15 8	19 2
1952.....	15 8	18 2
1958.....		17 8
1959.....		17 8

परिशिष्ट तालिका-6

सघीय व्यक्तिगत आय-कर देने से पूर्व और पश्चात् औसत परिवार
की व्यक्तिगत आय और पूर्णकालिक कर्मचारी की वार्षिक औसत
उपार्जित आय

वर्ष	प्रति परिवार या परिवार- रहित व्यक्ति औसत व्यक्ति- गत आय कर देने से पूर्व				औसत वार्षिक आय प्रति पूर्णकालिक कर्मचारी कर देने के पश्चात्	
	परिवार और	परिवार- रहित के व्यक्ति (दस लाखों मे)	चालू मूल्यों हिसाब से (डालर)	1960 के मूल्यों के हिसाब से (डालर)	1960 के मूल्यों के हिसाब से (डालर)	चालू मूल्यों के हिसाब से (डालर)
1929	36 1	2340	4190	2320	4160	1405
1947	44 7	4130	5370	3720	4840	2589
1948	46 3	4350	5350	4010	4940	2795
1949	47 8	4170	5180	3860	4800	2851
1950	48 9	4440	5440	4070	4980	3008
1951	49.5	4900	5630	4420	5070	3231
1952	50 2	5120	5760	4570	5140	3414

1953	50.5	5390	6000	4810	5350	3587
1954	51.2	5360	5910	4840	5340	3670
1955	52.2	5640	6190	5090	5590	3847
1956	52.8	6010	6490	5400	5830	4036
1957	53.6	6240	6550	5610	5880	4205
1958	54.6	6290	6470	5670	5840	4347
1959	55.3	6610	6730	5930	6040	4553
1960	55.9	6900	6900	6170	6170	4734

परिशिष्ट तालिका-7

विभिन्न उद्योगों में औसत प्रतिघंटा आय, 1939-1960

	डालर प्रतिघण्टा		वृद्धि के सूचक अंक	
	1939	1960	1939	1960
कृषि	0.16	0.97	100	606
वस्त्र	0.46	1.62	100	352
लकड़ी का सामान	0.49	1.99	100	406
फरनीचर	0.52	1.88	100	361
खुदरा व्यापार	0.54	1.78	100	330
कागज और सम्बद्ध उत्पादन	0.59	2.32	100	393
रासायनिक पदार्थ और सम्बद्ध उत्पादन	0.65	2.55	100	393
मशीनरी (विजली के यन्त्रों को छोड़कर)	0.75	2.60	100	347
टेलीफोन	0.82	2.32	100	283
बिद्युत्प्रमोचनी कोयला खनन	0.89	3.26	100	367
मोटर गाड़ियाँ	0.93	2.83	100	304
उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक			100	213

परिशिष्ट तालिका-8

विभिन्न राष्ट्रों में कितने मिनट की मजदूरी से खाद्य पदार्थों
की एक नियत मात्रा खरीदी जा सकती है

वस्तु	संयुक्त राज्य	फ्रांस (पेरिस)	जर्मनी	इटली	रूस (मास्को)
	अक्टूबर, 58	अक्टूबर, 58	अक्टूबर, 58	अक्टूबर 58	15 अगस्त, 1959
गेहूँ का आटा (एक पाउंड)		15	10	17	अज्ञात
डबलरोटी सफेद (एक पाउंड)	6	12	13	17	9
गोमास (एक पाउंड)	29	153	62	166	82
मछली (एक पाउंड)	13	32	33	144	अज्ञात
मक्खन (एक पाउंड)	21	117	81	172	184
दूध (एक क्वार्ट)	7	15	10	23	31
अण्डे (एक दर्जन)	12	108	72	120	144
सेब (एक पाउंड)	4	19	10	15	अज्ञात
आलू (एक पाउंड)	1	5	2	6	12
					(जनवरी, 61)
मार्गरीन (एक पाउंड)	8	42	24	74	अज्ञात
चीनी (एक पाउंड)	3	15	15	30	64

नोट—हर देश में अलग-अलग खाद्य पदार्थ का अलग-अलग महत्व है, इसलिए
उसी दृष्टि से इन तुलनाओं से रहन-सहन के स्तर को आँका जाना चाहिए ।

परिशिष्ट

परिशिष्ट तालिका-9

संयुक्त राज्य की गोरी आवादीमे देशजों और विदेशजों
की संख्या, 1870—1950

देशज और विदेशज				
	कुल	कुल विदेशी	विदेशज	विदेशी या देशी-विदेशी मिश्रित माता- पिता से उत्पन्न देशज
(हजारों में)				
1870	33589	10818	5494	32
1880	43403	14835	6560	8275
1890	55101	20626	9122	11504
1900	66809	25860	10214	15646
1910	81732	32243	13346	18898
1920	94821	36399	13713	22686
1930	110287	39886	13983	25902
1940	118702	34577	11419	23058
1950	134942	33751	10161	23589
(कुल गोरी आवादी का प्रतिशत भाग)				
1870	100 0	32.2	16 4	15.9
1880	100 0	34.2	15 1	19.1
1890	100.0	37 4	16.6	20 9
1900	100.0	38.7	15 3	23.4
1910	100.0	39.5	16.3	23 1
1920	100.0	38 4	14.5	23.9
1930	100.0	36.2	12.7	23.5
1940	100 0	29 1	9 6	19 5
1950	100 0	25.0	7.5	17.5

परिशिष्ट तालिका-10

शिक्षा की स्थिति

शिक्षा संस्थाओं में भर्ती छात्र, 1957-58

अशिक्षित सख्या ² कुल आवादी 5 वर्ष से
(प्र श.) ¹ (दस लाखों का प्रतिशत 19 वर्ष
में) भाग तक की
आयु की
आवादी
का प्रति-
शत भाग

संयुक्त राज्य	2 (1960)	43.2	24	88
पश्चिमी जर्मनी	1-2 (1950)	9.8	19	72
जापान	2 (1950)	21.8	23	72
बेल्जियम	3 (1947)	1.6	18	76
ग्रीस	26 (1951)	1.2	15	56
फिलिपाइन	38 (1948)	4.4	18	51
पुर्तगाल	42 (1950)	1.0	10	42
इक्वेडोर	44 (1950)	0.56	14	अज्ञात
थाईलैंड	46 (1947)	3.7	17	45
ब्राजील	51 (1950)	7.1	11	27
टर्की	65 (1950)	2.6	10	28
स अरब गणराज्य (मिस्र)	75 (1947)	2.8	11	33
भारत	82 (1951)	33.7	8½	अज्ञात
नाइजीरिया	89 (1950)	2.7	8	अज्ञात
हाइटी	89 (1950)	23	7	18

1. इसमें दस वर्ष या इससे अधिक आयु के वे सभी व्यक्ति शामिल किये गए हैं जो लिख या पढ़ नहीं सकते।

2. इसमें वे सभी छात्र शामिल किये गए हैं जो पूर्व-प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक, टैकनिकल, अध्यापक प्रशिक्षण या माध्यमिकोत्तर किसी भी संस्था और कक्षा में भर्ती हों।

परिशिष्ट तालिका-11

काम बन्द होने के कारण प्रति-कर्मचारी¹ वर्बाद दिन
(वार्षिक औसत, 1950-1954)

संयुक्त राज्य ²	1.4	कनाडा	.7
फिन लैण्ड	1.8	बेलजियम	.6
न्यूजीलैण्ड	1.2	पश्चिमी जर्मनी	1
ऑस्ट्रेलिया	.9	नार्वे	1
भारत	9	स्वीडन	.1
इटली	.9	ब्रिटेन	1
फ्रांस	.8	डेनमार्क	3
आयरलैण्ड	8	नीदरलैण्ड्स	3
जापान	8	दक्षिण अफ्रीका	3

- 1 केवल खनन, वस्तु-निर्माण, भवन-निर्माण और परिवहन उद्योगों के आकड़े।
2. 1958-1960 में संयुक्त राज्य के वर्बाद दिनों का औसत 1.0 दिन था।
3. .05 दिन प्रति-कर्मचारी से भी कम।

परिगिष्ट तालिका-12

अमेरिकी निर्माता उद्योगों की कम्पनियों को कर अदा करने से पूर्व मुनाफे की दर (साधारण शेयरों पर प्रतिशत मुनाफा)

वर्ष	2 50 लाख डालर से कम परिसम्पत्तियों वाली कम्पनियाँ	2 5 लाख से 10 लाख डालर तक की परिसम्पत्तियों वाली कम्पनियाँ ¹	एक अरब डालर या इससे अधिक परिसम्पत्तियों ² वाली कम्पनियाँ
1960	अज्ञात	11 9	17 6
1959	अज्ञात	15 5	18 3
1958	8 3	11 4	16 3
1957	14 6	14 9	19 5
1956	19 9	19 4	22 0
1955	10 6	16 3	25 9
1954	7 8	12 5	20 7
1953	13 2	16 1	24 5
1952	17 0	12 8	23 0
1951	17 3	22 0	28 8
1950	16 7	22 9	28 6
1949	9 7	14 2	20 3
1948	16 1	23 5	24 7

1. सन् 1959 के बाद इन वर्ग में 10 लाख डालर से कम परिसम्पत्तियों वाली सभी कम्पनियाँ आ जाती हैं।

2. सन् 1957 से पहले के आकड़े 10 करोड़ डालर या इससे अधिक की परिसम्पत्तियों वाली सभी कम्पनियों के हैं।

परिशिष्ट तालिका-13

विज्ञान और टेक्नोलॉजी की उन्नति

असैनिक श्रमिक संख्या असैनिक वैज्ञानिक और
इंजीनियर श्रमिक
शक्ति का प्र. ग
भाग

वर्ष	(हजारों में)	कुल (हजारों में)	
1930	48600	261	·5
1940	52900	378	·7
1950	60000	740	1·2
1956	67500	950	1·4
1959	69400	1100	1·6

परिगिष्ट तालिका-14

अनुसन्धान और विकास के कामों में लगे वैज्ञानिक और इंजिनियर

उद्योग	मुख्यतः अनुसन्धान और विकास में लगे वैज्ञानिक और इंजिनियर		
	जनवरी, 1954	जनवरी, 1959	जनवरी, 1960
सब उद्योगों में कुल संख्या	157300	277100	301000
खाद्य तथा तत्सम्बन्धी उत्पादन	4000	3700	3700
कपड़ा और तैयार वस्त्र	1800	1300	1300
कागज और सम्बद्ध उत्पादन	1700	2500	2800
रासायनिक पदार्थ और सम्बद्ध उत्पादन	21500	33900	39000
पेट्रोलियम उत्पादन	6800	9500	10000
पत्थर, चीनी मिट्टी और काच का सामान	2100	2700	2100
धातु उद्योग	3700	5900	6200
धातु निर्मित नैतिक-असैनिक सामान	4600	18600	18500
मशीनरी (विजली का सामान छोड़ कर)	16300	26900	29000
विजली की मशीनें	28300	52600	61000
विमान और उनके पुर्जे	27600	60400	64000
वैज्ञानिक और अन्य उपकरण	9100	12300	13000

अन्य वस्तु-निर्माण उद्योग	20400	23800	24500
भवन आदि का निर्माण	1600	1900	2000
परिवहन और अन्य सार्वजनिक सेवाएँ	1200	2300	2600
इंजीनियरिंग और वस्तु- कला सेवाएँ	6200	7200	8000
अन्य निर्माणोत्तर उद्योग	6200	11300	126000

परिशिष्ट तालिका-15

अनुसन्धान और विकास के लिए विभिन्न स्रोतों से व्यय की गई राशियों का विवरण (लाख डालरों में) 1959 60

अनुसन्धान और	अनुसन्धान और विकास के काम करने वाले					
विकास के लिए व्यय की गई राशियों के स्तर	संघीय सरकार	उद्योग	कालेज और विश्व-विद्यालय	लाभ न लेने वाले अन्य सस्थान	कुल	प्रतिशत
संघीय सरकार	18400	54200	7000	1400	81000	64
उद्योग	—	40200	500	500	41200	33
कालेज और विश्वविद्यालय	—	—	2100	—	2100	2
लाभ न लेने वाले अन्य सस्थान	—	—	400	600	1000	1
कुल योग	18400	94400	10000	2500	125300	100
प्रतिशत विभाजन	15	75	8	2	100	

परिशिष्ट तालिका-16

मूल अनुसन्धान के लिए विभिन्न स्रोतों से किये गए व्यय का विवरण
(लाख डालरों में) 1959 60

मूल अनुसन्धान		मूल अनुसन्धान करने वाले				
के लिए किये गए व्यय के स्रोत	संघीय सरकार	उद्योग और विश्व-विद्यालय	कालेज और	लाभ न लेने वाले अन्य सस्थान	कुल योग	प्रतिशत
संघीय						
सरकार	2250	700	3050	400	6400	56
उद्योग	—	2740	200	60	3000	26
कालेज और विश्व-विद्यालय	—	—	1400	—	1400	12
लाभ न लेने वाले अन्य सस्थान	—	—	350	340	690	6
कुल योग	2250	3440	5000	800	11490	100
प्रतिशत विभाजन	19	30	44	7	100	

परिशिष्ट तालिका-17

संयुक्त राज्य में ग्राइवेट विदेशी निवेश—1914 (लाख डालरों में)

स्रोत	रेले	निवेश के प्रकार		
		अन्य अमेरिकी सिक्कूरिटियाँ	विदेशियों द्वारा नियंत्रित व्यवसाय	कुल
ब्रिटेन	28000	8500	6000	42500
जर्मनी	3000	3500	3000	9500
नीदरलैंड्स	3000	2000	1350	6350
फ्रांस	2900	750	450	4100
कनाडा	1300	950	500	2750
अन्य	3500	1400	800	5700
	41700	17100	12100	70900

संयुक्त राज्य में ससार के अन्य भागों की विदेशी परसम्पत्तियाँ और निवेश—1960 दस लाख डालरों में

कुल	पश्चिमी यूरोप	कनाडा	लैटिन अमेरिका	अन्य	अन्तर्राष्ट्रीय
संयुक्त राज्य मे कुल विदेशी					
परिसम्पत्ति और निवेश..... 44682	24048	6196	3726	4837	4965
दीर्घकालिक..... 18438	13004	3303	1153	858	129
सीधा निवेश..... 6931	4713	1949	130	139	—
कम्पनी शेयर..... 9302	6836	1209	728	490	39
कम्पनियों, राज्य सरकारो और					
म्युनिसिपैलिटियों के बॉन्ड 648	449	5	75	38	81
अन्य .. 1557	1006	140	220	191	—
अल्पकालिक परिसम्पत्तियाँ और					
संयुक्त राज्य सरकार की					
देनदारियाँ..... 26244	11044	2893	2573	3979	4845

प्राइवेट.....	... 12113	4893	1981	2211	2709	319
स० रा० सरकार की						
देनदारियाँ... 14131	6151	912	362	1270	4526
दीर्घकालिक	• 2276	803	327	141	114	891
अल्पकालिक ¹	• 11855	5348	585	221	1156	3635

I इसमें वि गया के पास जमा अमेरिकी मुद्रा या शामिल है जा 1959 में 9060 लाख डालर और 1960 में 9100 लाख डालर की। ये दोनों राशियाँ सभी क्षेत्रों का कुल योग हैं।

परिशिष्ट तालिका-19

संयुक्त राज्य का अदायगी सन्तुलन, 1956-1960 (दस लाख डालरों में)

		कैलंडर वर्ष			
		1956	1957	1958	1959 1960
क. स० राज्य सरकार द्वारा किये गए लेन-देन					
1. सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्यात					
फ. सैनिक अनुदान	4912	4921	4667	4302	अज्ञात
ख. फानतू कृषि उत्पादनों की बिक्री	2579	2435	2281	1988	अज्ञात
ग अन्य अनुदान और ऋण	1078	1233	1023	925	1182
सैनिक अनुदान को छोड़कर शेष कुल योग	1255	1253	1363	1389	1507
2. अन्य प्राप्तियाँ	2333	2486	2386	2314	2689
क. ऋण वापसी	954	1374	1289	1800	1431
ख. व्याज	479	659	544	1013	605
ग. सैनिक प्राप्तियाँ	194	205	307	346	346
घ. अन्य	158	372	296	297	326
3. सरकारी कार्यक्रमों के अन्तर्गत अदायगियाँ	123	138	142	144	154
क. सैनिक अनुदान	—8355	—8833	—8824	—8072	अज्ञात
ख. विदेशों से सैनिक व्यय	—2579	—2435	—2281	—1988	अज्ञात
	—2935	—3165	—3412	—3090	—3034

ग	आर्थिक सहायतानुदान	—1733	—1616	—1616	—1623	—1651
घ	दीर्घकालिक पूजी	—545	—993	—1176	—1018	—1174
ङ	विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि	—563	—624	—339	—353	—537
	सैनिक अनुदान को छोड़कर	—5776	—6398	—6543	—6084	—6396
	कुल योग					
4.	अन्य सरकारी अदायगियाँ	—553	—670	—626	—819	—845
क	सरकार की अर्थात्मिक कार्यवाहियाँ	—264	—310	—305	—322	—307
ख	विदेशियों को दिया गया व्याज	—154	—201	—139	—281	—332
ग	पेंशन और अन्य अन्तरण	—135	—159	—182	—216	—206
5	कुल प्राप्तियाँ	5866	6295	5956	6102	अज्ञात
क	कुल योग	3287	3860	3675	4114	4120
ख	सैनिक अनुदानों को छोड़कर					
6	कुल अदायगियाँ	8908	9503	9450	8891	अज्ञात
क	कुल योग	6329	7069	7169	6903	7241
ख.	सैनिक अनुदानों को छोड़कर	—3043	—3208	—3494	—2789	—3121
	सरकारी खाते का सन्तुलन					

ख. लेखक प्राइवेट
संयुक्त राज्यीय लेन देन

1. मनुष्यों और जैवजो के निर्वात	20897	23532	20194	20363	23631
क. आवागमन सामान का निर्वात	15016	16904	13877	13911	16722
ख. जैवजो	5851	6628	6317	6452	6909
2. पशुओं और जैवजो का आयात	16476	07247	17197	19867	19630
क. आवागमन सामान का आयात	12804	13291	12951	15312	14717
ख. जैवजो	3672	3956	4246	4552	4913
3. सामान और जैवजो का मन्तुन	+4421	+6285	+7997	+496	+400
क. सामान का मन्तुन	+2242	+3613	+926	—1404	+200
ख. जैवजो का मन्तुन	+2179	+2672	+2071	+1900	+199
4. मन्तुन राज्य की पाउंड वूजी	—2990	—3175	—3844	—2301	—352
5. पाउंड (निजी) और पर विदेशी को देने की मन्तुन	—530	—543	—540	—563	—61
पाउंड (गैर-मन्तुन)	+901	+2567	—387	—2368	—137
6. मन्तुन राज्य सरकार की निष्पूरितियों को जोड़कर अन्य मन्तुन में मन्तुन राज्य में जोड़ी विदेशी वूजी	+530	+361	+24	+548	+327
7. मन्तुन	+643	+748	+380	+783	+905
8. मन्तुन पाउंड का मन्तुन	—968	+468	—3477	—3826	—3836

परिशिष्ट तालिका-20

राष्ट्र का आर्थिक वजत—1929, 1960 और 1970 (संभावित)
(1960 के मूल्यों के हिसाब से अरब डालरों में)

	1929			1960			1970		
	प्राप्तियाँ	व्यय	घाटा या लाभ	प्राप्तियाँ	व्यय	घाटा या लाभ	प्राप्तियाँ	व्यय	घाटा या लाभ
उपभोक्ता									
स्वायत्त व्यक्तिगत आय	83.1	—	—	351.8	—	—	542.0	—	—
व्यक्तिगत उपभोग व्यय	—	79.0	—	—	328.9	—	—	495.9	—
व्यक्तिगत वचत	—	—	+4.1	—	—	+22.9	—	—	+46.1
व्यवसायी									
कुल प्रतिधारित (रिटेण्ड)									
आय	11.5	—	—	51.7	—	—	78.1	—	—
कुल निजी आन्तरिक निवेश	—	16.2	—	—	72.4	—	—	120.1	—
अतिरिक्त निवेश (—)	—	—	-4.7	—	—	-20.7	—	—	-4.0
अन्तर्राष्ट्रीय									
शुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय	—	.7	-.7	1.5	3.0	-1.5	0.8	5.7	-4.9

सरकार (संघीय, राज्यीय
और स्थानीय

कर या अन्य प्राप्तियाँ	11.2	—	—	139.1	—	—	217.9	—	—
अन्तरण, व्याज और अनुपूर्तिओ की घटाई जाने वाली राशि	1.7	—	—	37.1	—	—	51.0	—	—
शुद्ध प्राप्तियाँ	9.5	—	—	102.0	—	—	166.9	—	—
कुल सरकारी व्यय	—	10.2	—	—	137.2	—	—	217.1	—
अन्तरण, व्याज और अनुपूर्तिओ की घटाई जाने वाली राशि	—	1.7	—	—	37.1	—	—	51.0	—
शुद्ध सरकारी व्यय	—	8.5	—	—	100.1	—	—	166.1	—
अधिशेष (+)	—	—	+1.0	—	—	+1.9	—	—	+0.8
आकड़ों की भूलचूक	+3	—	+3	-2.6	—	-2.6	—	—	—
कुल राष्ट्रीय आय-व्यय	104.4	104.4	—	504.4	504.4	—	787.7	787.7	—

परिशिष्ट तालिका-21

राष्ट्र का मुख्य-मुख्य वर्गों का व्यय, 1960 (अरब डालरो में)

1. बुनियादी उपभोग्य वस्तुएँ

क खाद्य	70 2
ख वस्त्र	31 8
ग आश्रय (मकान)	42 2
घ घरेलू व्यय	17 2

कुल योग	161 4
---------	-------

2. उपभोक्तों की अन्य आवश्यकताएँ

क. घरेलू फरनीचर आदि	28 7
ख व्यक्तिगत व्यावसायिक सेवाएँ	20 6
ग व्यक्तिगत देखभाल	5 2

कुल योग	54 5
---------	------

3 परिवहन

क नई और पुरानी कारों की खरीद	15 8
ख. गाड़ियों के रख रखाव और संचालन का व्यय	21 4
ग. स्थानीय या नागरिक परिवहन गाड़ियों की खरीद	3 5

कुल योग	40 7
---------	------

4 उपभोग्य विलास और अर्ध-विलास सामग्री

क सिगरेट और शराब आदि	17 3
ख टेलीफोन आदि संचार साधन	8 4
ग. खेल-खिलौने	4 5

घ. सिनेमा नाटक आदि	2.0
ड. अन्य मनोरजन साधन	4.5
च. विदेश यात्रा और विदेशो को प्रेषित धन	3.0
छ. जेवर और घड़ियाँ	2.1

कुल योग

41.8

5. शिक्षा

क प्राइवेट व्यय	4.5
ख सरकारी व्यय	18.7

कुल योग

23.2

6. अनुसन्धान और विकास

क. राष्ट्रीय सुरक्षा (मैनिक)	7.2
ख अन्य सरकारी अनुसन्धान	1.3
ग प्राइवेट अनुसन्धान	4.5

कुल योग

13.0

7. चिकित्सा और स्वास्थ्य

क प्राइवेट व्यय	21.3
ख. सरकारी व्यय	6.3

कुल योग

8. प्राइवेट धार्मिक और जन-कल्याण

27.6

4.7

अमेरिकी जनता की अर्थ व्यवस्था

9. प्राइवेट पूंजी निवेश

क. उत्पादकों की मशीनरी आदि	27 5
ख. रिहायशी निर्माण	21 1
ग. गैर-रिहायशी भवन	19.6
घ. व्यावसायिक वस्तुओं (इन्वेंटरी) में परिवर्तन	4.2

कुल योग

72 4

10. राष्ट्रीय रक्षा व्यय (अनुसन्धान को छोड़कर)

40.4

11. अन्य सरकारी व्यय

क. सड़क निर्माण और परिवहन	9 9
ख. सार्वजनिक सेवाएँ (बजली, पानी और डाक सेवा आदि)	1 0
ग. अन्य सार्वजनिक सेवाएँ	12 5

कुल योग

23.4

12. शुद्ध विदेशी निवेश

1 5

कुल राष्ट्रीय व्यय

504 4

परिशिष्ट तालिका-22

विभिन्न देशों में सामाजिक सुरक्षा व्यय—1956-1957
(राष्ट्रीय आय का प्रतिशत भाग)

संयुक्त राज्य अमेरिका	6.0%
पश्चिमी जर्मनी	
फ्रांस	20.8%
बेल्जियम	18.9%
इटली	16.3%
स्वीडन	15.2%
ब्रिटेन	12.9%
डेनमार्क	12.1%
यूगोस्लाविया	12.0%
चिली	10.3%
ऑस्ट्रेलिया	9.7%
कनाडा	9.1%
स्विट्जरलैंड	8.7%
पोलैण्ड	8.0%
जापान	7.7%
ग्वाटेमाला	5.8%
भारत	3.1%
	1.0%

परिशिष्ट तालिका-23

कुल राष्ट्रीय आय में से समाज-कल्याण व्यय का प्रतिशत भाग (1889-90 से 1958-59 तक विभिन्न वर्षों का विवरण)

वित्तीय वर्ष	राष्ट्रीय आय (अरब डालरों में)	कुल	कुल राष्ट्रीय आय में से समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों पर प्रतिशत व्यय				शिक्षा
			सामाजिक बीमा	सरकारी सहायता	स्वास्थ्य और चिकित्सा	ग्रन्थ जन कल्याण	भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास
1889-90	130	24	1	0.3 ²	0.1	2	0.9
1912-13	399	25	1	.3 ²	4	2	5
1928-29	1016	42	0.3	5 ²	.5	2	5
1934-35	687	98	6	4	8	2	7
1939-40	959	93	1.3	38	7	.1	.6
1944-45	2125	42	6	5	.9	.1	.4
1949-50	2640	87	18	9	.9	2	2.5
1954-55	3775	85	26	.8	8	.2	1.2
1956-57	4328	90	29	8	8	2	1.1
1957-58	4389	102	36	.8	8	2	1.1
1958-59	4640	107	39	9	9	2	1.1
1959-60	4946	108	39	8	9	.3	1.0

1 0.05 प्रतिशत से कम ।

2. इसमें सरकारा सहायता से किये गए जन-कल्याण कार्यक्रम भी शामिल हैं ।

परिशिष्ट तालिका-24

आर्थिक विकास की संभावनाएँ, 1960-70

	वास्तविक 1960	सम्भावित 1970
		(दस लाख में)
आवादी.....	180 0	213 8
कुल श्रम शक्ति..	73 1	86 6
सशस्त्र सेना.....	2 5	2 3
असैनिक श्रम शक्ति ..	70 6	84 3
बेकार व्यक्ति.....	3 9	3 4
रोजगार पर लगे असैनिक व्यक्ति ..	66 7	80 9
प्राइवेट ..	59 7	72 3
कृषि.....	5 7	5 0
कृषि-भिन्न.....	54 2	67 3
सरकारी ..	6 8	8 6
		(दस लाख डालरो में)
कुल राष्ट्रीय उत्पादन (1960 के मूल्यो में)....	504 4	787 8
प्राइवेट ..	457 1	717 8
कृषि.....	21 7	19 5
कृषि-भिन्न..	435 4	698 3
सरकारी.....	47 3	70 0
असत साप्ताहिक काम के घंटे		
प्राइवेट	40 5	38 0
कृषि	45 5	40 9
कृषि-भिन्न	40 0	37 8

अमेरिकी जनता की अर्थ-व्यवस्था

प्राइवेट राष्ट्रीय उत्पादन प्रति मानव घण्टा

(डालरो में)

(1960 के मूल्यों के

अनुसार) ... 3 73

5 16

कृषि 1 60

1 84

कृषि-भिन्न 3 95

5 28

औद्योगिक उत्पादन का सूचक

अंक (1957=100) ... 108

175

उपयोगी सेवाएँ 124

26

खनिज 97

153

निर्माण 108

172

कृषि-उत्पादन का सूचक अंक

(1957=100) 113

148

परिशिष्ट तालिका-25

राष्ट्रीय आय और व्यय—1960 और 1970 (संभावित)

(1960 के मूल्यों के हिसाब से अरब डालरो में)

	1960	1970	1970	1970
		(1)	(2)	(3)
कुल राष्ट्रीय आय	504 4	787 7	787 7	819 5
राष्ट्रीय रक्षा व्यय	45 6	56 4	32 6	86 4
व्यक्तिगत उपभोग व्यय	328 9	495 9	509 0	510 7
प्राइवेट आन्तरिक (देशी)				
निवेश	72 4	120 1	120 1	118 6
शुद्ध निर्यात	3 0	5 7	5 7	5 7
सरकार की असेैनिक				
खरीद	54 5	109 6	120 3	98 1

(1) बरातें कि शस्त्रास्त्रों और सेना के व्यय में कोई कमी न हो ।

(2) बरातें कि शस्त्रास्त्रों और सेना के व्यय में एक तिहाई कमी हो जाये ।

(3) बरातें कि शस्त्रास्त्रों और सेना में और भी वृद्धि हो जाये ।

परिशिष्ट तालिका-26

सरकार के असेैनिक व्यय में सभावित वृद्धि 1959-1970
(1960 के मूल्यों के अनुसार अरब डालरो में)

	1959	1970	वृद्धि
शिक्षा और स्कूल निर्माण	16.9		19.4
सडके और सचार-परिवहन साधन	8.8	15.4	6.6
सामुदायिक विकास, आवास और सफाई	2.1	14.7	12.6
स्वास्थ्य और अस्पताल	3.9	12.2	8.3
अनुसन्धान	—	4.0	4.0
प्राकृतिक साधन	3.1	6.1	3.0
सामान्य प्रशासन	5.9	10.0	4.1
अन्य	11.3	12.6	10.3
कुल व्यय	52.0	120.3	68.3

परिशिष्ट तालिका-27

विभिन्न उद्योगों में केन्द्रीकरण (हर उद्योग की चार सबसे बड़ी कम्प-
नियों का प्रतिशत अंश)

निर्माण उद्योग	लदान का मूल्य		रोजगार	
	1947	1954	1950	1954
अधिक केन्द्रीकरण वाले उद्योग				
एल्युमीनियम धातु उत्पादन	100	100	100	100
जिप्सम के उत्पादन	85	90	89	86
टेलीफोन और टेलीग्राफ का				
सामान	96	89	90	88
एल्युमीनियम का सामान	94	88	89	84
भाप के इंजन और टर्बाइन	88	87	87	86
साबुन और ग्लिसरीन	79	85	69	71
सिगरेट	90	82	81	75
टीन के डिब्बे और सामान	78	80	77	78
टायर और ट्यूब	77	79	78	80
ट्रान्सफार्मर	73	78	77	71
मोटर गाड़ियाँ और पुर्जे	56	75	59	72
गणना आदि के यन्त्र	69	74	70	72
ट्रैक्टर	67	73	76	72
घरेलू धुलाई की मशीनें	40	68	53 ¹	60
चीनी शोधन	70	67	69	69
घमन भट्टियाँ	67	65	57 ¹	63
इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबें	73	64	64	63
फोटोग्राफी का सामान	61	63	61	61
विमान-इंजन	72	62	55	51

परिशिष्ट

क्र.सं.	वर्ष	परिशिष्ट	वर्ष	क्र.सं.
27	1950	कोक भट्टियों के उपोत्पादन	53	58
	1954	इस्पात का सामान	45	54
		तावे का सामान	60	53
		मोटर और जेनरेटर	59	50
		कम केन्द्रीकरण वाले उद्योग		
		मिठाई उद्योग	17	19
		कागज और गत्ता	अज्ञात	19
		भवन-निर्माण और खनन यन्त्र	18	19
		मशीनी औजार	20	19
		रुई के चौड़ी बुनती के कपड़े	अज्ञात	18
		समाचार पत्र	21	18
		चमड़ा	27	18
		निर्माण और सजावट के काम	23	18
		अण्डे की चीजे	32	17
		वाल्व और फिटिंग	24	17
		गत्ते के डिब्बे	18	16
		धातु पर मुद्रण	17	14
		पुरुषों के सूट और कोट	9	11
		व्यावसायिक छपाई	9	10
		लकड़ी का फरनीचर	7	8
		मशीन वर्कशाप	अज्ञात	8
		प्लास्टिक का सामान	अज्ञात	8
		आराकशी और रन्दाकशी	5	7
		न्धियों की पोद्याके	अज्ञात	3

